भारतीय रिज़र्व बैंक

बुलेटिन

फरवरी 2021

खंड 75 अंक 2

अध्यक्ष
माइकल देबब्रत पात्र

संपादन समिति
देबा प्रसाद रथ
राजीव रंजन
सितीकांत पट्टनाईक
जी. पी. सामंता
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवाडकर
एस. गंगाधरन

संपादक
शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के
निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा
मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है।
इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए
बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है।
हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए
लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2021

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
https://bulletin.rbi.org.in पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य 1

मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21

मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प, फरवरी 2021 9

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य 13

भाषण

एक स्थिर वित्तीय प्रणाली की ओर
शक्तिकान्त दास 17

लेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति 23

भारत में बैंक ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन: हाल के घटनाक्रम 59

एकदिवसीय सूचकांक स्वैप (ओआईएस) दरों से मौद्रिक नीति के
भावी रुख का आकलन 73

क्या बाजार को ज्यादा पता है? पीबीआर के नजरिए से
भारत का बैंकिंग क्षेत्र 85

वर्तमान सांख्यिकी **93**

हाल के प्रकाशन **139**

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य

*गवर्नर का वक्तव्य**

शक्तिकांत दास

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 3, 4 और 5 फरवरी 2021 को हुई और घरेलू और वैश्विक दोनों स्तर पर, वर्तमान आर्थिक और वित्तीय विकासों पर विचार-विमर्श किया गया। एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया। इसने आगामी लक्ष्य के भीतर मुद्रास्फीति को भी बनाए रखने की सुनिश्चितता से सर्वसम्मति से मौद्रिक नीति के निभावकारी रूख को जितना आवश्यक हो - कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष में - टिकाऊ आधार पर विकास को पुनर्जीवित करने और COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए रखने का निर्णय लिया है। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है। रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित है।

मैं सबसे पहले एमपीसी के निर्णय लेने की प्रक्रिया और इसकी अंतर्निहित प्रेरणा के व्यापक संदर्भों को संक्षेप में बताना चाहूंगा। पिछले दो महीनों में मुद्रास्फीति की वृद्धि दिसंबर की बैठक के समय की उम्मीद से बेहतर रही है। COVID-19 की अवधि के दौरान पहली बार, मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत के ऊपरी सहिष्णुता स्तर से कम हो गई है। आगे जाकर, आगामी महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति ट्रेजेक्टरी को आकार देने वाले कारक, जिसमें बाजारों में संभावित बम्पर खरीफ की फसल की आवक, अच्छी रबी की फसल की बढ़ती संभावनाएं, प्रमुख सब्जियों की सर्दियों में बड़ी आपूर्ति और एवियन फ्लू की आशंका पर कमजोर पोल्ट्री मांग शामिल हैं, सभी एक स्थिर निकट-अवधि के दृष्टिकोण के सूचक है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 7 जनवरी 2021 को जारी जीडीपी के 2020-21 के प्रारंभिक अनुमान एमपीसी के दिसंबर प्रक्षेपण के बहुत करीब पहुंच गए हैं। संवृद्धि पर दृष्टिकोण में काफी सुधार हुआ है, सकारात्मक विकास आवेगों के आधार पर और अधिक व्यापक होते जा रहे हैं, और देश में टीकाकरण कार्यक्रम का रोलआउट महामारी के अंत के लिए अच्छी तरह से बढ़ रहा है। यह देखते हुए कि मुद्रास्फीति सहिष्णुता बैंड के भीतर वापस आ गई है, एमपीसी ने निर्णय किया कि विकास को समर्थन देना, COVID -19 के प्रभाव को आत्मसात करना और अर्थव्यवस्था को उच्च संवृद्धि प्रक्षेपवक्र में वापस लाना समय की जरूरत है।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

भारत के साथ-साथ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में नए साल 2021 को टीकाकरण ड्राइव के साथ एक मजबूत सकारात्मक नोट पर शुरू किया है। COVID-19 के लिए भारत की प्रतिक्रिया हमें महात्मा गांधी के उद्घोषणा के एक अंश की याद दिलाती है कि "अपने मिशन में एक अदम्य विश्वास के साथ दृढ़ आत्माएं इतिहास को बदल सकती हैं"।[1] जबकि वर्ष 2020 ने हमारी क्षमताओं और धीरज का परीक्षण किया, 2021 हमारे इतिहास के पाठ्यक्रम में एक नए आर्थिक युग के लिए मंच स्थापित कर रहा है।

संवृद्धि

महत्वपूर्ण रूप से, एमपीसी की पिछली बैठक के बाद से बहाली के संकेत मजबूत हुए हैं। उच्च आवृत्ति संयोग और समीपस्थ संकेतक बताते हैं कि सामान्यीकरण क्षेत्रों की सूची का विस्तार हो रहा है। रिज़र्व बैंक का सर्वेक्षण पूर्ववर्ती तिमाही में 47.3 प्रतिशत की तुलना में दूसरी तिमाही: 2020-21 में विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग में 63.3 प्रतिशत सुधार की ओर इशारा करता है। उपभोक्ता विश्वास पुनर्जीवित हो रहा है, और विनिर्माण, सेवाओं और बुनियादी ढांचे की कारोबारी उम्मीदें बरकरार हैं। माल और लोगों की आवाजाही और घरेलू व्यापारिक गतिविधियां तेज गति से बढ़ रही हैं। दिसंबर की तुलना में बिजली और ऊर्जा की मांग आर्थिक गतिविधियों के व्यापक सामान्यीकरण को दर्शाती है, जब कि दूसरी लहर के डर की भी आशंका है। प्रमुख महानगरीय केंद्रों में आवासीय इकाइयों की बिक्री और नए लॉन्च के डेटा, रियल एस्टेट क्षेत्र में एक नए आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। विनिर्माण, सेवा और समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) विस्तार क्षेत्रों में हैं - विनिर्माण

* गवर्नर का वक्तव्य, 5 फरवरी 2021

[1] गांधी,एम.के. (1936). हरजिन, नवंबर 19, 1936, pp. 341-2.

गवर्नर का वक्तव्य

पीएमआई दिसंबर 2020 में 56.4 से बढ़कर जनवरी 2021 में 57.7 और सेवा पीएमआई दिसंबर 2020 में 52.3 से बढ़कर जनवरी 2021 में 52.8 पर पहुंच गया। इसके अलावा, टीकाकरण ड्राइव से संपर्क गहन क्षेत्रों की बहाली और वैश्विक बाजार में भारतीय फार्मा उद्योग के लिए अग्रणी बढ़त बनाने की उम्मीद है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हाल के महीनों में बढ़ा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रभावशाली बहाली में विश्वास को दोहराता है। एक व्यापक बुनियादी ढांचे के पुनरुद्धार से आगे, दैनिक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति बढ़ रही है और 2020-21 में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गति वर्ष-दर-वर्ष दोगुनी हो गई है।

इससे अधिक यह है कि, वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के प्रवाह में सुधार हुआ है, विशेष रूप से गैर-खाद्य बैंक ऋण और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) के माध्यम से, आवास वित्त कंपनियों द्वारा ऋण, कॉर्पोरेट बॉन्ड के निजी प्लेसमेंट और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में। इन संसाधनों का कुल प्रवाह इस वर्ष अब तक (15 जनवरी 2021 तक) ₹8.85 लाख करोड़ है जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹7.97 लाख करोड़ था। रिज़र्व बैंक के नवीनतम बैंक ऋण सर्वेक्षण से पता चलता है कि Q2: 2021-22 तक सभी क्षेत्रों में ऋण की मांग पर विचार में क्रमिक सुधार होगा। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक जीडीपी विकास 2021-22 में 10.5 प्रतिशत पर – पहली छमाही में 26.2 से 8.3 प्रतिशत की रेंज में और तीसरी तिमाही में 6.0 प्रतिशत की दर से अनुमानित है।

केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और कल्याण, बुनियादी ढांचे, नवाचार और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इसका आगे एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से निवेश के माहौल को बेहतर बनाने और घरेलू मांग, आय और रोजगार में मजबूती लाने के लिए। आत्मनिर्भर 2.0 और 3.0 (महामारी के चरम के दौरान दिया गया) के तहत निवेश-उन्मुख प्रोत्साहन ने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया है और सार्वजनिक निवेश की गुणवत्ता के साथ-साथ खर्च की गति में सुधार कर रहा है। दोनों ही मध्यावधि में भारत की विकास क्षमता को पुनः प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेंगे। पूंजीगत व्यय में अनुमानित वृद्धि क्षमता निर्माण और निजी निवेश में भीड़ के लिए अच्छी तरह से बढ़ रही है, जिससे संवृद्धि और व्यय की गुणवत्ता के आसपास विश्वसनीयता बनाने की संभावनाओं में सुधार होता है।

मुद्रास्फीति

जून 2020 से ऊपरी सहिष्णुता सीमा को लगातार अतिक्रमण करने के बाद, सीपीआई मुद्रास्फीति लॉकडाउन अवधि के पश्चात पहली बार दिसंबर में 6 प्रतिशत से नीचे चली गई, जो अनुकूल आधार प्रभावों और प्रमुख सब्जियों की कीमतों में तेज गिरावट के कारण समर्थित थी, जो बाद में नवंबर और दिसंबर के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगभग 90 प्रतिशत के गिरावट के लिए जिम्मेदार है। दोनों उच्चतर फ्रेश आगमन और सक्रिय आपूर्ति पक्ष हस्तक्षेपों ने इस अनुकूल विकास में योगदान दिया। यह उम्मीद की जाती है कि निकट अवधि में सब्जी की कीमतें नरम रहेंगी, जबकि कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थों में दबाव जारी रह सकता है। कोर मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण हाल के महीनों में देखे गए लागत-दबाव में वृद्धि से प्रभावित है। केंद्र और राज्यों दोनों में, अप्रत्यक्ष कर के बने रहने से और हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंच गई हैं। औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में तेज वृद्धि के साथ, हाल के महीनों में सेवाओं और विनिर्माण उत्पादों की कीमतों में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है। आगे, केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा अनुकूल नीतिगत कार्रवाई, यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सतत चल रहा लागत निर्माण और आगे नहीं बढ़े । इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, सीपीआई मुद्रास्फीति का प्रक्षेपण जोखिम को व्यापक रूप से संतुलित करके ति4: 2020-21 के लिए 5.2 प्रतिशत, एच1: 2021-22 में 5.2 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत, और ति3:2021-22: के लिए 4.3 प्रतिशत पर संशोधित किया गया।

मार्च 2021 तक, सरकार अगले पांच वर्षों के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य की समीक्षा करेगी। COVID-19 की अवधि को छोड़कर, मुद्रास्फीति के लक्ष्य की रूपरेखा निर्मित करने के

गवर्नर का वक्तव्य

बाद से मौद्रिक नीति के लिए साख प्राप्ति और सफलतापूर्वक मूल्य स्थिरता बनाए रखने का अनुभव, आने वाले वर्षों में सुदृढ़ बनाने की जरूरत है हालांकि हम महामारी से बाहर निकलने और COVID दुनिया के बाद के अवसर का लाभ तलाश कर रहे हैं। मूल्य स्थिरता वह नींव है जिस पर अर्थव्यवस्था उच्च वित्तीय बचत और निवेश के एक गुणी चक्र; निवेश और वेतन निर्णयों में फर्मों के लिए अनिश्चितताओं को कम करना; वित्तीय बाजारों में अवधि और जोखिम प्रीमियर को कम करना; और वर्धित बाहरी प्रतिस्पर्धा से अपनी क्षमता तक पहुंचने का प्रयास कर सकती है।

चलनिधि मार्गदर्शन

रिज़र्व बैंक और बाजारों ने महामारी के दौरान सहकारी समाधानों के प्रति एक साझा समझ विकसित की। एक बड़े सरकारी उधार कार्यक्रम को मूल रूप से प्रबंधित किया गया था। कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करना रिकॉर्ड स्तर (अप्रैल-दिसंबर 2019 के दौरान ₹4.6 लाख करोड़ की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान ₹5.8 लाख करोड़) तक पहुंच गया। 2020-21 के दौरान मौद्रिक नीति के संचालन में स्पष्ट आगे का मार्गदर्शन एक अभिनव विशेषता थी। लगातार उच्च मुद्रास्फीति प्रिंट और सरकारी पेपर की बड़ी आपूर्ति के संबंध में बाजारों के असंतोष को संबोधित करते हुए, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और प्रतिफल वक्र के क्रमिक विकास को बनाए रखना स्पष्ट रूप से सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में माना गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सभी हितधारकों को यह लाभ प्राप्त होना था। रिज़र्व बैंक के बाजार परिचालन ने अनिश्चितता की आशंकाओं को दूर किया और वित्तीय बाजार के भाव को प्रभावित किया। रिज़र्व बैंक के संचार और कार्रवाईयों से सहमत, बाजार सहभागियों ने भी समान और सहकारी रूप से जवाब दिया, जो आगे के मार्गदर्शन की प्रभावशीलता का प्रमाण है।

रिज़र्व बैंक द्वारा सम्मिलित नीतिगत दरों में कटौती, सक्रिय चलनिधि प्रबंधन और वैश्विक स्पिलओवरों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध विनियामक सहिष्णुता और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के माध्यम से किए गए उपायों से बाजार स्पेक्ट्रम में नीतिगत दरों में कटौती का सुचारू प्रसारण, जोखिम स्प्रेड को कम करना और कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार का फिर से शुरुआत सुनिश्चित किया गया। जी-सेक बाजार में, जिसमें जोखिम-मुक्त बेंचमार्क विकसित होता है, आरबीआई की मौद्रिक और चलनिधि प्रबंधन परिचालन की विश्वसनीयता के लिए 5.78 प्रतिशत की रिकॉर्ड भारित औसत लागत और 14.9 वर्षीय की दीर्घित भारित औसत परिपक्वता साक्ष्य रही।

11 जनवरी को, कथित बाजार की इस गलतफहमी के कारण कि रिज़र्व बैंक अपना निभावकारी नीति रुख बदल रहा है, मुद्रा बाजार की दरें और जी-सेक प्रतिफल बढ़ गयी। इस संदर्भ में, यह याद रखना उपयोगी है कि परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामियां संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे के तहत पहले से मुख्य उपकरण के रूप में हमारे लिखतों का भाग है और ये महामारी से पहले सक्रिय उपयोग में थे। वे स्वैच्छिक हैं और, किसी भी मामले में, ओवरनाईट निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो का अवलंब दैनिक आधार पर उपलब्ध है। परिवर्तनीय प्रतिवर्ती रेपो दर नीलामी दीर्घावधि (14-दिन) के मद्देनजर स्थायी दर प्रतिवर्ती रेपो से अधिक प्रतिफल प्रदान करती है। चलनिधि प्रबंधन का रुख निभावकारी बना हुआ है, जोकि पूर्णतः मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप है। रिज़र्व बैंक प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार कर्षण प्राप्त करने के लिए बहाली हेतु अनुकूल वित्तीय स्थितियों को बढ़ावा देता है। यहां यह ध्यान देना उचित होगा कि मुद्रा की मांग के कारण आरक्षित धन 14.5 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष (29 जनवरी, 2021 को) बढ़ा। दूसरी ओर, मुद्रा आपूर्ति (एम 3) 15 जनवरी 2021 को केवल 12.5 प्रतिशत बढ़ी।

नवंबर 2020 की शुरुआत से, टीकाकरण के आशावाद और अतिरिक्त नीति प्रोत्साहन संबंधी समाचार के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। इन कारकों ने जोखिम वहन क्षमता के लौटने और रिटर्न्स के लिए गहन अनुसंधान को उत्पन्न किया है, जिसके परिणामस्वरूप भारत जैसे ईएमई में पूंजी प्रवाह बढ़ता है और परिणामस्वरूप वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ जाती है। हालाँकि, आरबीआई ने सहज घरेलू चलनिधि की स्थिति सुनिश्चित करते हुए वैश्विक स्पिलओवरों और परिणामी अस्थिरता से घरेलू वित्तीय बाजारों को बचाने के लिए कदम उठाए हैं।

गवर्नर का वक्तव्य

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) का दो चरण में सामान्यीकरण - जिसकी मैं घोषणा करने जा रहा हूं - इस संदर्भ में देखने की जरूरत है। हालांकि, प्रणालीगत चलनिधि आगामी वर्ष तक सहज बनी रहेगी। वास्तव में, सीआरआर सामान्यीकरण अतिरिक्त चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार के बाजार परिचालन हेतु अवसर प्रदान करता है। इन क्षेत्रों में हमारे प्रयास का अंतर्निहित विषय वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाले बिना उचित रूप से हमारे आयुधागार के सभी लिखतों का उपयोग करना होगा, जो कि आरबीआई के नीतिगत उद्देश्यों के मूल में है।

2021-22 के लिए केंद्र का सकल बाजार ऋण ₹12 लाख करोड़ बजट किया गया है। सरकार के ऋण प्रबंधक और बैंकर के रूप में, रिज़र्व बैंक गैर-व्यवधानपूर्ण तरीके से बाज़ार उधार कार्यक्रम को पूरा करना सुनिश्चित करेगा। इस संदर्भ में, हम 2021-22 के दौरान बाजार के खिलाड़ियों और रिज़र्व बैंक के बीच आम समझ और सहकारी दृष्टिकोण की निरंतरता के लिए भी तत्पर हैं।

अतिरिक्त उपाय

इस पृष्ठभूमि में, रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था से संबंधित उपायों को पुनर्जीवित करने के अपने सर्वोपरि उद्देश्य के साथ दृढ़ रहेगा जो (i) लक्षित क्षेत्रों और तरलता प्रबंधन के लिए तरलता समर्थन को बढ़ाना; (ii) विनियमन और पर्यवेक्षण; (iii) वित्तीय बाजारों को गहन करना; (iv) भुगतान और निपटान प्रणाली का उन्नयन; और (v) उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने से संबंधित होगा । उपायों का विवरण मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और नियामक नीतियों (भाग-बी) पर वक्तव्य में निर्धारित किया गया है।

(i) तरलता के उपाय

मांग के अनुसार (ऑन टैप) योजना पर टीएलटीआरओ - एनबीएफसी का समावेश

विशिष्ट तनावग्रस्त क्षेत्रों, जिनके पास पिछले और आगे दोनों लिंकेज हैं और वृद्धि पर गुणक प्रभाव हैं, में गतिविधि के पुनरुद्धार का समर्थन करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 9 अक्टूबर 2020 को बैंकों के लिए ऑन टैप योजना पर टीएलटीआरओ की घोषणा की थी। यह देखते हुए कि विभिन्न क्षेत्रों में अंतिम मील तक पहुंचने के लिए एनबीएफसी अच्छी तरह से पहचाने जाने वाले कंडेट्स हैं, अब निर्दिष्ट तनाव वाले क्षेत्रों को वृद्धिशील ऋण देने के लिए एनबीएफसी को ऑन टैप योजना पर टीएलटीआरओ के तहत बैंकों से निधि उपलब्ध करने का प्रस्ताव है।

मार्च 2021 से शुरू होने वाले दो चरणों में सीआरआर की बहाली

COVID-19 के कारण होने वाले व्यवधान को खत्म करने के लिए, 26 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए सभी बैंकों के नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 100 आधार अंकों से घटाकर 3.0 प्रतिशत कर दिया गया। मौद्रिक और तरलता की स्थिति की समीक्षा पर, यह निर्णय लिया गया है कि 27 मार्च 2021 से सीआरआर को दो चरणों में गैर-विघटनकारी तरीके से धीरे-धीरे 3.5 प्रतिशत पर बहाल किया जाए और 22 मई 2021 से 4.0 प्रतिशत प्रभावी हो। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अतिरिक्त तरलता प्रवेश के लिए सीआरआर सामान्यीकरण रिज़र्व बैंक के विभिन्न बाजार परिचालनों के लिए जगह खोलता है।

सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) – रियायत का विस्तार

27 मार्च 2020 को बैंकों को शुद्ध मांग और मीयादी देयताएँ (एनडीटीएल) के अतिरिक्त एक प्रतिशत, अर्थात कुल मिलाकर एनडीटीएल का 3 प्रतिशत,तक सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में गिरावट से सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) के तहत धन का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी । यह सुविधा, जिसे 31 मार्च 2021 तक चरणों में विस्तारित किया गया था, अब एक और छह महीने की अवधि के लिए उपलब्ध होगी, अर्थात् 30 सितंबर 2021 तक ताकि बैंकों को अपनी तरलता आवश्यकताओं पर सहूलियत प्रदान की जा सके। यह वितरण ₹1.53 लाख करोड़ तक की राशि तक पहुंच को बढ़ाता है।

(ii) विनियमन और पर्यवेक्षण

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) में एसएलआर धारिता श्रेणी

1 सितंबर 2020 को, रिजर्व बैंक ने सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पात्र प्रतिभूतियां जो 1 सितंबर 2020 तक या उसके बाद के 31 मार्च 2022 तक प्राप्त की गईं, के संबंध में

गवर्नर का वक्तव्य

शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के लिए परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में सीमा को 19.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत कर दिया। यह वितरण 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध कराया गया था। 2021-22 के लिए केंद्र और राज्यों के उधार कार्यक्रम के संदर्भ में बाजार सहभागियों को निश्चितता प्रदान करने के लिए, अब बढ़ाए गए 22 प्रतिशत के एचटीएम के वितरण को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ताकि 1 अप्रैल, 2021 और 31 मार्च, 2022 के बीच प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को शामिल किया जा सके । 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही से शुरू होने वाले चरणबद्ध तरीके से एचटीएम की सीमा को 22 प्रतिशत से 19.5 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा। यह उम्मीद की जाती है कि बैंक एचटीएल सीमाओं की बहाली के लिए स्पष्ट ग्लाइड पथ के साथ एक इष्टतम तरीके से एसएलआर प्रतिभूतियों में अपने निवेश की योजना बनाने में सक्षम होंगे।

एमएसएमई उद्यमियों को ऋण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के उधारकर्ताओं को नए ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सीआरआर की गणना के लिए उनकी शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से 'नए एमएसएमई उधारकर्ताओं' को संवितरित ऋण में कटौती करने की अनुमति दी जाएगी। इस छूट के उद्देश्य के लिए, 'नए एमएसएमई उधारकर्ता' वे होंगे जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को बैंकिंग प्रणाली से कोई ऋण सुविधा नहीं ली है। यह छूट 1 अक्टूबर 2021 को समाप्त होने वाले पखवाड़े तक विस्तारित ऋण के लिए प्रति उधारकर्ता को ₹25 लाख रुपये तक के लिए उपलब्ध होगी। योजना का विवरण परिपत्र में दिया जाएगा।

पूंजी संरक्षण बफर और निवल स्थायी निधियन अनुपात

रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामक हस्तक्षेप का जोर वसूली का समर्थन और पोषण करने की ओर बढ़ा है। जबकि महामारी के तत्काल बाद में किए गए कुछ नियामक उपायों को धीरे-धीरे चरणबद्ध किया जा रहा है, बैंकों को वसूली की प्रक्रिया को आवश्यक सहायता प्रदान करना जारी रखने के लिए सक्षम करना आवश्यक है। इसीलिए, पूंजीगत संरक्षण बफर (सीसीबी) के अंतिम ट्रांच को 0.625 प्रतिशत के कार्यान्वयन के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है और 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 2021 तक छह महीने के लिए निवल स्थायी निधियन अनुपात (एनएसएफ़आर) के कार्यान्वयन को भी स्थगित कर दिया जाए।

माइक्रोफाइनेंस के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा

जरूरतमंद खंडों को क्रेडिट के अंतिम वितरण में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतिम क्रेडिट की सुपुर्दगी और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए क्षेत्र की विकसित भूमिका और एक मजबूत ढांचे की आवश्यकता के मद्देनजर, रिज़र्व बैंक एक सलाहकार दस्तावेज लेकर आएगा, जो माइक्रोफाइनेंस स्पेस में विभिन्न विनियमित उधारदाताओं (एनबीएफ़सी - माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंक और एनबीएफसी- निवेश और क्रेडिट कंपनियां) के लिए लागू नियामक ढाँचों के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की विशेषज्ञ समिति

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक क्रेडिट संरचना का एक महत्वपूर्ण खंड हैं। रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने और वित्तीय समावेशन में गहनता लाने के लिए हाल के दिनों में कई उपाय किए हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के हालिया संशोधनों ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के बीच नियामक और पर्यवेक्षी शक्तियों के साथ-साथ उनमें भी जो अभिशासन, लेखा परीक्षा और संकल्प से संबंधित हैं, में समानता ला दी है। विधायी संशोधनों पर आधारित क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक मध्यावधि रोड मैप प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति (ईसी) का गठन किया जाएगा। ईसी के गठन और इसके संदर्भ की शर्तों को जल्द ही घोषित किया जाएगा।

उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत आईएफ़एससी को विप्रेषण

वर्तमान में, निवासी व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफ़एससी) को उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विप्रेषण करने की अनुमति नहीं है। आईएफ़एससी को और विकसित करने और उन्हें अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों के बराबर लाने के लिए, आईएफ़एससी में अनिवासी संस्थाओं द्वारा

गवर्नर का वक्तव्य

जारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए आईएफ़एससी को प्रेषण करने हेतु निवासी व्यक्तियों को अनुमति देने का प्रस्ताव है। इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए, निवासी व्यक्तियों को आईएफ़एससी में एक गैर-ब्याज वाले विदेशी मुद्रा खाता (एफ़सीए) खोलने की अनुमति दी जाएगी।

(iii) वित्तीय बाजार में गहनता लाना

खुदरा निवेशकों को रिज़र्व बैंक में गिल्ट खाते खोलने की अनुमति देना

सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार और रिज़र्व बैंक ने कई उपाय किए हैं। इनमें प्राथमिक नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली आरंभ करना, स्टॉक एक्सचेंजों को प्राथमिक खरीद को रूट करने की अनुमति देना और द्वितीयक बाजार में एक विशिष्ट खुदरा खंड की अनुमति देना शामिल है। इन प्रयासों के अनुक्रम में, यह प्रस्तावित है कि खुदरा निवेशकों को सीधे रिज़र्व बैंक ('रिटेल सीधे') के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति बाजार, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों, में ऑनलाइन एक्सेस प्रदान किया जाए। यह निवेशक आधार को व्यापक बनाएगा और खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार में भाग लेने के लिए और अधिक एक्सेस प्रदान करेगा। यह एक प्रमुख संरचनात्मक सुधारहै जो भारत को कुछ प्रमुख देशों, जिसमें समान सुविधाएं हैं, के बीच स्थान दिलाएगा। एचटीएम छूट के साथ यह उपाय, 2021-22 में सरकार के उधार कार्यक्रम को सुचारू रूप से पूरा करने की सुविधा प्रदान करेगा।

चूक (डिफॉल्टेड) बॉण्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफ़पीआई) का निवेश

कॉरपोरेट बॉण्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश को और बढ़ावा देने के लिए, डिफॉल्टेड कॉरपोरेट बॉण्ड में एफपीआई निवेश को अल्पकालिक सीमा और मध्यम अवधि के ढांचे के तहत न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता आवश्यकता से छूट प्रदान किया जाएगा।

(iv) भुगतान और निपटान प्रणाली

डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए 24x7 हेल्पलाइन की स्थापना

डिजिटल भुगतानों की बढ़ी हुई पैठ और दक्षता के साथ, विभिन्न डिजिटल भुगतान उत्पादों के संबंध में ग्राहक के प्रश्नों को संबोधित करने और उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी देने के लिए एक केंद्रीकृत उद्योग-व्यापी 24x7 हेल्पलाइन की सुविधा के लिए प्रमुख भुगतान प्रणाली परिचालकों की आवश्यकता होगी। । आगे बढ़ते हुए, हेल्पलाइन के माध्यम से ग्राहकों की शिकायतों के निवारण की सुविधा पर विचार किया जाएगा। यह प्रयास उपभोक्ता का डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास बढ़ाने के लिए किया गया है।

अधिकृत भुगतान प्रणालियों के परिचालकों और प्रतिभागियों के लिए आउटसोर्सिंग संबंधी दिशानिर्देश

परिचालन जोखिमों के लिए डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को लगातार अद्यतन करने की आवश्यकता है। परिचालन जोखिम का एक संभावित क्षेत्र अधिकृत भुगतान प्रणालियों के परिचालकों (पीएसओ) और प्रतिभागियों के लिए आउटसोर्सिंग से जुड़ा हुआ है। आउटसोर्सिंग में परिचर जोखिमों का प्रबंधन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भुगतान और निपटान संबंधी सेवाओं की आउटसोर्सिंग करते समय आचार संहिता का पालन किया जाता है, रिज़र्व बैंक इन संस्थाओं द्वारा ऐसी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर दिशानिर्देश जारी करेगा।

सभी बैंक शाखाओं में चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) समाशोधन

चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) के कवरेज को सितंबर 2020 तक सभी पारंपरिक समाशोधन गृहों तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, यह देखा गया है कि लगभग 18,000 बैंक शाखाएं अभी भी किसी भी औपचारिक समाशोधन व्यवस्था से बाहर हैं। अब सितंबर 2021 तक इन सभी शाखाओं को सीटीएस समाशोधन के अंतर्गत लाना प्रस्तावित है। इस उपाय के साथ, देश की सभी

गवर्नर का वक्तव्य

बैंक शाखाएँ सीटीएस के अंतर्गत आ जाएंगी। इससे ग्राहक सुविधा बढ़ेगी और कागज आधारित समाशोधन प्रणाली के लिए परिचालन क्षमता के तहत आ जाएगी।

(v) उपभोक्ता संरक्षण

एकीकृत लोकपाल योजना

वर्तमान में, वैकल्पिक विवाद समाधान की रूपरेखा में बैंकों, एनबीएफसी और गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान जारीकर्ताओं (पीपीआई) के लिए तीन अलग-अलग लोकपाल योजनाएं शामिल हैं। ये तीनों योजनाएं रिज़र्व बैंक द्वारा देश भर में स्थित बाईस लोकपाल कार्यालयों से परिचालित की जाती हैं। लोकपाल व्यवस्था को सरल, कुशल और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए, तीन लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करने और 'एक देश एक लोकपाल ' के दृष्टिकोण से शिकायतों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य एक केंद्रीकृत संदर्भ बिंदु के साथ, एकीकृत योजना के तहत ग्राहकों को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम करके शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को आसान बनाने का है। एकीकृत लोकपाल योजना जून 2021 में शुरू की जाएगी।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, मैं यह कहना चाहूंगा कि आगे बढ़ते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था केवल एक दिशा में बढ़ने के लिए तैयार है और वह ऊपर की ओर है। यह हमारा दृढ़ विश्वास है, पूर्वानुमान द्वारा समर्थित, कि 2021-22 में, हम उस नुकसान को कम कर देंगे जो COVID-19 की वजह से अर्थव्यवस्था को झेलना पड़ा है। बीते वर्ष की अस्त-व्यस्तता और निराशा के बाद, जिससे होकर हम एक साथ गुजरे हैं और आगे बढ़ना जारी रखेंगे, समग्र स्थिति को महात्मा गांधी के शब्दों में सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जा सकता है, "हम कल के असंभव की घटना के दैनिक साक्षी हैं जो आज संभव हो रहा है..."।[2]

धन्यवाद। सुरक्षित रहें। स्वस्थ रहें। नमस्कार।

[2] Mahatma Gandhi; XXVI-68 Epigrams From Gandhiji - Compiled by: S.R. Tikekar First Edition: 1971 Published by: Publications Division Ministry of Information & Broadcasting

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21

मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प, फरवरी 2021

*मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प**

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (5 फरवरी 2021) को अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए;

नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाएं।

- यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने एक टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो- कम से कम चालू वित्त वर्ष के दौरान और अगले वित्त वर्ष में निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।

ये निर्णय संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है।

इस निर्णय के समर्थन में प्रमुख विवेचनों को नीचे दिए गए विवरण में वर्णित किया गया है।

आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. अत्यधिक संक्रमक उपभेद सहित कई देशों द्वारा कोविड--19 संक्रमणों की दूसरी लहर को झेलने के कारण वैश्विक आर्थिक सुधार तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के सापेक्ष 2020 की चौथी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में मंद पड़ गया। बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिससे सुधार में आने वाले जोखिम कम हो सकते हैं और 2021 की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। अपने जनवरी 2021 के अपडेट में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2020 में वैश्विक संवृद्धि के अपने अनुमान को (-) 4.4 प्रतिशत से संशोधित करके (-) 3.5 प्रतिशत किया है और 2021 के लिए वैश्विक संवृद्धि के अनुमान को 30 आधार अंकों तक बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत किया है। कुछ उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं को छोड़ दें, तो कमजोर सकल मांग पर मुद्रास्फीति सौम्य बनी हुई है, हालांकि पण्य की बढ़ती हुई कीमतें उच्च जोखिम दर्शाती हैं। वित्तीय बाजार में तेजी देखी गयी, जोकि आसान मौद्रिक स्थितियों, प्रचुर मात्रा में चलनिधि और टीके के रोलआउट से आशावाद द्वारा समर्थित है। 2021 में वैश्विक व्यापार में भी सुधार की उम्मीद है, जिसमें व्यापारिक कारोबार की तुलना में सेवा व्यापार में धीमा सुधार देखा जाएगा।

घरेलु अर्थव्यवस्था

3. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 7 जनवरी 2021 को जारी 2020-21 के लिए जीडीपी के पहले अग्रिम अनुमानों में, एमपीसी के दिसंबर 2020 के संकल्प में दिये (-) 7.5 प्रतिशत के अनुमान के अनुरूप वास्तविक जीडीपी में 7.7% के संकुचन का अनुमान लगाया गया। उच्च आवृत्ति संकेतक - रेलवे माल यातायात; टोल संग्रह; ई-वे बिल; और इस्पात की खपत - सुझाव देती है कि सेवा क्षेत्र के कुछ घटकों के पुनरुद्धार ने तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में कर्षण प्राप्त किया। कृषि क्षेत्र में लचीलापन बना हुआ है - 29 जनवरी 2021 तक रबी की बुवाई 2.9 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) आधार पर अधिक थी, जो सामान्य से ऊपर उत्तर-पूर्व मानसून वर्षा और पूरी क्षमता के 61 प्रतिशत का पर्याप्त जलाशय स्तर (4 फरवरी 2021 तक), जोकि 50 प्रतिशत के 10 वर्ष के औसत से अधिक है, द्वारा समर्थित है।

4. लगातार छह महीनों (जून-नवंबर 2020) के लिए 6 प्रतिशत की ऊपरी सहिष्णुता सीमा का अतिक्रमण करने के बाद, खाद्य कीमतों में कमी और अनुकूल आधार प्रभावों के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति दिसंबर में घटकर 4.6 प्रतिशत रह गई। सब्जी की कीमतों में तेज सुधार और खरीफ की फसल की आवक के साथ अनाज की कीमतों में नरमी के साथ-साथ आपूर्ति पक्ष में व्यवधान

* 5 फरवरी 2021 को जारी किया गया।

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21

के कारण खाद्य मुद्रास्फीति पिछले तीन महीनों (सितंबर-नवंबर) के दौरान 9.6 प्रतिशत के औसत पर रहने के बाद दिसंबर में गिरकर 3.9 प्रतिशत पर पहुंच गई। दूसरी ओर, कोर मुद्रास्फीति, अर्थात् खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति एक महीने पहले के मार्जिनल मॉडरेशन के साथ दिसंबर में 5.5 प्रतिशत पर बढ़ी हुई रही। रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षण के जनवरी 2021 के दौर में, खाद्य मुद्रास्फीति में मोडरेशन के साथ परिवार मुद्रास्फीति की उम्मीदें तीन महीने आगे के क्षितिज पर सौम्य हो गईं; हालांकि, मुद्रास्फीति के एक वर्ष आगे के अनुमान अपरिवर्तित रही।

5. प्रणालीगत तरलता दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में बड़े अधिशेष में बनी रही, जो आसान वित्तीय परिस्थितियों को उत्पन्न करती है। करेंसी की मांग के कारण आरक्षित धन 14.5 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष (29 जनवरी 2021 को) बढ़ा। दूसरी ओर, मुद्रा आपूर्ति ($एम_3$) 15 जनवरी 2021 को केवल 12.5 प्रतिशत बढ़ी, लेकिन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की गैर-खाद्य ऋण वृद्धि के साथ 6.4 प्रतिशत हो गई। अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान ₹5.8 लाख करोड़ के कॉरपोरेट बॉण्ड निर्गम पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹4.6 लाख करोड़ की तुलना में अधिक थे। 29 जनवरी 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 590.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था - मार्च 2020 के अंत तक 112.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई।

संभावनाएं

6. दिसंबर में सब्जी की कीमतों में अनुमानित गिरावट की तुलना में, लक्ष्य के करीब हेडलाइन को कम करने के साथ, यह संभावना है कि खाद्य मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र निकट-अवधि के दृष्टिकोण को आकार देगा। बम्पर खरीफ की फसल, एक अच्छी रबी की फसल की बढ़ती संभावनाएं, सर्दियों में प्रमुख सब्जियों की बृहद आवक और एवियन फ्लू की आशंका पर अंडा और मुर्गी की सौम्य मांग के कारण आने वाले महीनों में सौम्य मुद्रास्फीति के परिणाम बढ़ सकते हैं। दूसरी ओर, दाल, खाद्य तेल, मसाले और गैर-मादक पेय पदार्थों के संबंध में मूल्य दबाव जारी रह सकता है। आपूर्ति श्रृंखलाओं में और अधिक सुगमता से कोर मुद्रास्फीति के आउटलुक प्रभावित होने की संभावना है; हालांकि, औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण सेवाओं और विनिर्माण कीमतों में लागतजन्य दबाव में व्यापक-वृद्धि बढ़ सकती है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक के औद्योगिक संभावनाओं में दर्शाए अनुसार, सेवा और मूलभूत सुविधा संभावना सर्वेक्षणों और क्रय प्रबंधकों के सूचकांकों (पीएमआई) और फर्मों द्वारा मूल्य निर्धारण शक्ति प्राप्त करने के रूप में मांग के सामान्य होने के साथ-साथ उत्पादन मूल्यों में वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें ओपेक प्लस द्वारा टीकाकरण और निरंतर उत्पादन कटौती से आशावाद पर आधारित मांग का समर्थन कर सकती हैं। दिसंबर 2020 से कच्चे तेल का वायदा वक्र नीचे की ओर झुका हुआ है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, सीपीआई मुद्रास्फीति का प्रक्षेपण 2020-21 की चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत, 2021-22 की पहली छमाही में 5.2 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत, 2021-22 की तीसरी तिमाही में 4.3 प्रतिशत:, मोटे तौर पर जोखिम के संतुलन के साथ संशोधित किया गया है। (चार्ट 1)।

7. संवृद्धि की संभावनाओं की ओर मुड़ते हुए, कृषि की अच्छी संभावनाओं पर ग्रामीण मांग में लचीलापन बना रहेगा। कोविड़ -19 मामलों में पर्याप्त गिरावट और टीकाकरण के प्रसार के साथ शहरी मांग और संपर्क-गहन सेवाओं की मांग मजबूत बने रहने की उम्मीद है। उपभोक्ता विश्वास पुनर्जीवित हो रहा है और विनिर्माण, सेवाओं और आधारभूत संरचनाओं की व्यावसायिक उम्मीदें

चार्ट 1: तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान (वर्ष-दर-वर्ष)

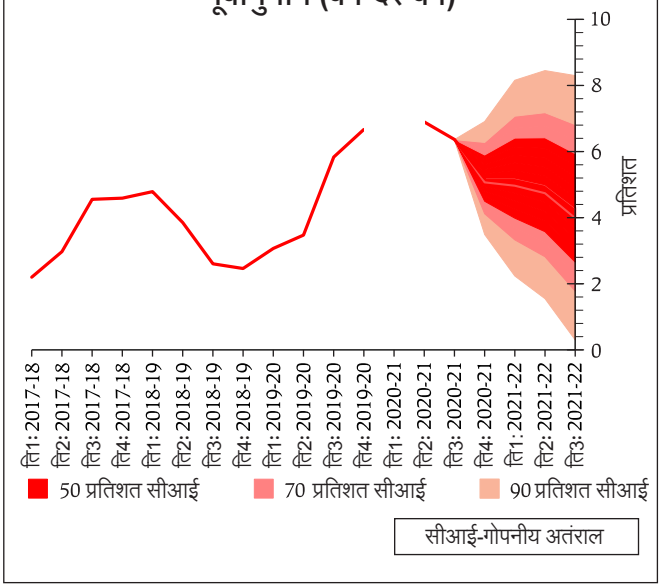

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21

बरकरार हैं। आत्मनिर्भर 2.0 और सरकार की 3.0 योजनाओं के तहत राजकोषीय प्रोत्साहन सार्वजनिक निवेश में तेजी लाएगा, हालांकि निजी निवेश अभी भी कम क्षमता के उपयोग के बीच सुस्त है। केंद्रीय बजट 2021-22 को, अन्य के साथ-साथ स्वास्थ्य और कल्याण, आधारभूत संरचनाए, नवाचार और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों पर जोर देने के साथ, विकास की गति को तेज करने में मदद करनी चाहिए। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2021-22 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 10.5 प्रतिशत - पहली छमाही में 26.2 से 8.3 प्रतिशत की रेंज में और तीसरी तिमाही में 6.0 प्रतिशत का अनुमान है। (चार्ट 2)

8. एमपीसी संज्ञान में लेता है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज सुधार ने खाद्य पदार्थों की कीमतों की संभावनाओं में सुधार किया है, लेकिन कुछ दबाव बने रहते हैं, और मुख्य मुद्रास्फीति उच्च बनी रही। पेट्रोल और डीजल की पंप कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर करों को कम करने से लागत जन्य दबाव को कम

चार्ट 2: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का त्रैमासिक पूर्वानुमान (वर्ष-दर-वर्ष)

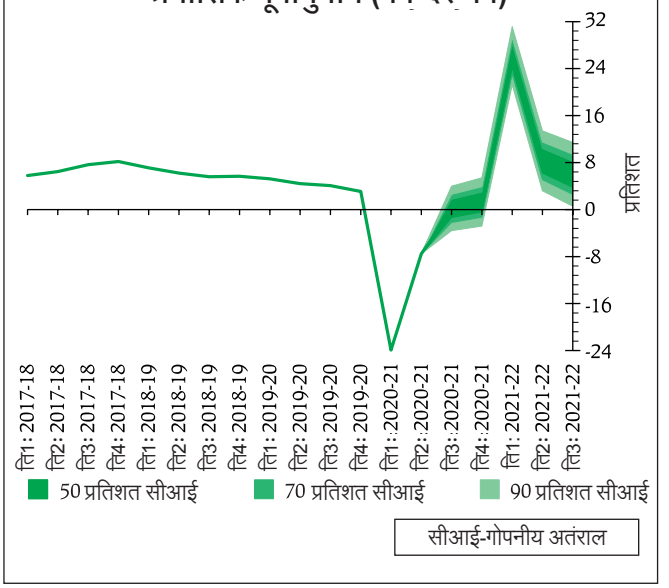

किया जा सकता है। इस बिंदु पर जिस चीज की आवश्यकता होती है, वह ऐसी स्थिति पैदा करना है जिसके परिणामस्वरूप एक टिकाऊ अवस्फीति हो। यह सक्रिय आपूर्ति पक्ष के उपायों पर भी आकस्मिक है। संवृद्धि में सुधार हो रहा है, और देश में वैक्सीन कार्यक्रम के रोलआउट के साथ संभावनाओं में काफी सुधार हुआ है। केंद्रीय बजट 2021-22 ने संवृद्धि को गति प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं। पूंजीगत व्यय में अनुमानित वृद्धि, क्षमता निर्माण के लिए शुभ संकेत है, जिससे व्यय की गुणवत्ता में वृद्धि और निर्माण की विश्वसनीयता के लिए संभावनाओं में सुधार होता है। हालांकि, सुधार को अभी भी पुख्ता कर्षण संग्रह करना है और इसलिए निरंतर नीति समर्थन महत्वपूर्ण है। इन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, मुद्रास्फीति के लिए विकसित संभावनाओं की बारीकी से निगरानी करते हुए, एमपीसी ने आज अपनी बैठक में, जब तक कि एक सतत सुधार की संभावनाएं अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाती, तब तक मौद्रिक नीति के निभावकारी रुख को जारी रखने का निर्णय किया है।

9. एमपीसी के सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, डॉ. आशिमा गोयल, प्रो. जयंत आर. वर्मा, डॉ. मृदुल के. सागर, डॉ. माइकल देवव्रत पात्र और श्री शक्तिकांत दास - ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया। इसके अलावा, एमपीसी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से जब तक आवश्यक हो, तब तक निभावकारी रूख जारी रखने - कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष के दौरान - ताकि यह सुनिश्चित करते हुए कि आगे मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को पुनर्जीवित करने तथा कोविड--19 के प्रभाव को कम करने के लिए वोट किया।

10. एमपीसी की बैठक के कार्यवृत्त 22 फरवरी 2021 तक प्रकाशित किए जाएंगे।

11. एमपीसी की अगली बैठक 5 से 7 अप्रैल 2021 के दौरान निर्धारित की गयी है।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों (i) चलनिधि प्रबंधन और लक्षित क्षेत्रों के लिए समर्थन (ii) विनियमन और पर्यवेक्षण (iii) वित्तीय बाजारों को व्यापक बनाना; (iv) भुगतान और निपटान प्रणाली को उन्नत करना और (v) उपभोक्ता संरक्षण, को निर्धारित करता है।

I. चलनिधि उपाय

1. मांग पर टीएलटीआरओ - एनबीएफसी का समावेश

विशिष्ट क्षेत्रों, जिनका पिछले और आगे दोनों से जुड़ाव और वृद्धि पर बहुस्तरीय प्रभाव हैं, में गतिविधि के पुनरुद्धार पर चलनिधि उपायों पर ध्यान को बढ़ाने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 9 अक्टूबर 2020 को मांग पर टीएलटीआरओ की घोषणा की जो 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध है। 21 अक्टूबर 2020 को योजना के तहत घोषित पांच क्षेत्रों के अलावा, कामथ समिति द्वारा पहचान किए गए 26 दबावग्रस्त क्षेत्रों को भी 4 दिसंबर 2020 को मांग पर टीएलआरओ के तहत पात्र क्षेत्रों के दायरे में लाया गया था। इस योजना के तहत बैंकों द्वारा प्राप्त चलनिधि को संस्थाओं द्वारा इन क्षेत्रों के लिए जारी कॉरपोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पेपर और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में नियोजित किया जाना है। इस योजना के तहत प्राप्त चलनिधि का उपयोग इन क्षेत्रों को ऋण और अग्रिम प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। इस सुविधा के तहत बैंकों द्वारा किए गए निवेश को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यहां तक कि कुल निवेश का 25 प्रतिशत से अधिक एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल करने की अनुमति है। इस सुविधा के तहत सभी एक्सपोज़र को बड़े एक्सपोज़र फ्रेमवर्क (एलईएफ) के तहत गणना से छूट दी जाएगी। यह देखते हुए कि एनबीएफसी को आखरी मील तक ऋण पहुंचाने हेतु प्रख्यात वाहिक समझा जाता है और यह विभिन्न क्षेत्रों में ऋण विस्तार में एक बल गुणक के रूप में कार्य करता है, अब इन क्षेत्रों को वृद्धिशील ऋण देने के लिए एनबीएफसी को मांग पर टीएलटीआरओ योजना के तहत बैंकों से फंड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

2. मार्च 2021 से नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) की दो चरणों में बहाली

कोविड -19 के कारण होने वाले व्यवधान पर बैंकों की मदद करने के लिए, 28 मार्च 2020 के रिपोर्टिंग पखवाड़े से प्रभावी, सभी बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 100 आधार अंकों से घटाकर 3.0 किया गया था। यह वितरण 26 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध था। मौद्रिक और चलनिधि स्थितियों की समीक्षा पर, गैर-विघटनकारी तरीके से सीआरआर को दो चरणों में धीरे-धीरे बहाल करने का निर्णय लिया गया है। बैंकों को अब 27 मार्च 2021 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से प्रभावी एनडीटीएल के 3.5 प्रतिशत पर सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता होगी और 22 मई 2021 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी एनडीटीएल का 4.0 प्रतिशत बनाए रखने की आवश्यकता होगी ।

3. सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) – छूट में विस्तार

27 मार्च 2020 को बैंकों को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत तक की गिरावट अर्थात संचयी रूप से एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत फंड का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी। यह सुविधा, जो शुरू में 30 जून 2020 तक उपलब्ध थी, बाद में 31 मार्च 2021 तक चरणों में विस्तारित की गई थी, जो बैंकों को उनकी चलनिधि आवश्यकताओं पर सहजता और उन्हें उनकी चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बना रही है। यह वितरण ₹1.53 लाख करोड़ की राशि तक पहुंच को बढ़ाता है और एलसीआर के लिए उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्ति (एचक्यूएलए) के रूप में अर्हता प्राप्त करता है। अपनी चलनिधि आवश्यकताओं के लिए बैंकों को सहजता प्रदान करने की दृष्टि से, अब एमएसएफ छूट को छह महीने की अगली अवधि अर्थात् 30 सितंबर 2021 तक के लिए जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

II. विनियमन और पर्यवेक्षण

4. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में एसएलआर धारिता

1 सितंबर 2020 को, रिज़र्व बैंक ने सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पात्र प्रतिभूतियों के संबंध में 1 सितंबर

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

2020 को या इसके बाद ली गई सांविधिक चलनि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों के संबंध में एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) की सीमा 31 मार्च 2021 से 19.5 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक बढ़ा दी। यह वितरण 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध कराया गया था। 2021-22 के लिए केंद्र और राज्यों के उधार कार्यक्रम के संदर्भ में बाजार सहभागियों को निश्चितता प्रदान करने के लिए, अब 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2022 के बीच अधिग्रहित प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए 22 प्रतिशत तक के विस्तारित एचटीएम के वितरण को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही से एचटीएम की सीमा को 22 प्रतिशत से 19.5 प्रतिशत तक चरणबद्ध तरीके से सीमित किया जाएगा। यह उम्मीद की जाती है कि बैंक एचटीएम सीमाओं की बहाली के लिए स्पष्ट ग्लाइड पथ के साथ एक इष्टतम तरीके से एसएलआर प्रतिभूतियों में अपने निवेश की योजना बनाने में सक्षम होंगे।

5. एमएसएमई उद्यमियों को ऋण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के उधारकर्ताओं को नए ऋण प्रवाह प्रोत्साहित करने के लिए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) की गणना के लिए उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से 'नए एमएसएमई उधारकर्ताओं' को दिए गए ऋण में कटौती करने की अनुमति दी जाएगी। इस छूट के उद्देश्य के लिए, "नए एमएसएमई उधारकर्ताओं" को उन एमएसएमई उधारकर्ताओं के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को बैंकिंग प्रणाली से कोई ऋण सुविधा नहीं ली है। यह छूट केवल 1 अक्टूबर 2021 को समाप्त होने वाले पखवाड़े में प्रदान ऋण के लिए प्रति उधारकर्ता के लिए ₹25 लाख तक के उधार के लिए, ऋण की उत्पत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या ऋण की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए उपलब्ध होगी।

6. बासेल III पूंजी विनियमन : पूर्ण रूप से लागू पूंजी संरक्षण बफर का आस्थगन

कोविड -19 के मद्देनजर उठाए गए विनियामक उपायों के हिस्से के रूप में, 0.625 प्रतिशत के पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की अंतिम ट्रांच का कार्यान्वयन, जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होने वाला था, को 1 अप्रैल 2021 तक के लिए आस्थगित कर दिया गया था। कोविड -19 के कारण निरंतर दवाब को ध्यान में रखते हुए, और बहाली प्रक्रिया में सहायता के लिए, 1 अप्रैल 2021 के 0.625 प्रतिशत सीसीबी के अंतिम ट्रांच के कार्यान्वयन को 1 अक्टूबर 2021 तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

7. निवल स्थायी निधियन अनुपात (एनएसएफआर) के कार्यान्वयन का आस्थगन

कोविड -19 के मद्देनजर उठाए गए विनियामक उपायों के एक भाग के रूप में, भारत में बैंकों द्वारा निवल स्थायी निधियन अनुपात (एनएसएफआर) का कार्यान्वयन 1 अप्रैल 2021 तक आस्थगित किया गया था। जबकि बैंकों को चलनिधि के मोर्चे पर सहज रखा गया है, कोविड -19 से संबंधित जारी तनाव को देखते हुए, एनएसएफआर के कार्यान्वयन को 1 अक्टूबर 2021 तक आस्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

8. माइक्रोफाइनेंस के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा

हाल ही में, रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामक ढ़ांचा- एक स्केल आधारित दृष्टिकोण पर एक चर्चा पत्र जारी किया है। वित्तीय क्षेत्र में लगातार विकसित होने वाले परिवेश को ध्यान में रखते हुए, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा करने का प्रस्ताव है। अकेले एनबीएफसी-एमएफआई के लिए इन दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के बजाय, माइक्रोफाइनेंस स्पेस में विभिन्न विनियमित उधारदाताओं जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक और एनबीएफसी- निवेश और क्रेडिट कंपनियां शामिल हैं, के लिए समान नियामक ढांचे के साथ सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक मार्च 2021 में सूक्ष्म वित्त स्पेस में विभिन्न विनियमित उधारदाताओं के लिए नियामक रूपरेखा के सामंजस्य के लिए एक परामर्शी दस्तावेज लेकर आएगा।

9. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक क्रेडिट संरचना का एक महत्वपूर्ण खंड हैं। बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधान प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी)

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

पर 26 जून 2020 से लागू हैं। संशोधनों ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के बीच नियामक और पर्यवेक्षी शक्तियों के साथ-साथ उनमें भी जो अभिशासन, लेखा परीक्षा और संकल्प से संबंधित हैं, में समानता ला दी है। नतीजतन, इन संशोधनों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के प्रति विनियामक / पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की व्यापक समीक्षा आवश्यक है। तदनुसार, यह निर्णय किया गया है कि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक मध्यावधि रोड मैप प्रदान करने, यूसीबी के तेजी से पुनर्वास / समाधान को सक्षम करने के साथ-साथ इन संस्थाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए। समिति के गठन के साथ-साथ संदर्भों की जानकारी अलग से दी जाएंगी।

10. उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को विप्रेषण

वर्तमान में, निवासी व्यक्तियों को आईएफ़एससी को उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विप्रेषण करने की अनुमति नहीं है। आईएफएससी को और विकसित करने और निवासी व्यक्तियों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने का अवसर प्रदान करने हेतु समीक्षा करने पर, योजना के तहत भारत में स्थापित आईएफएससी को विप्रेषण करने के लिए निवासी व्यक्तियों को अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। चूंकि भारत में आईएफएससी के संबंध में चालू खाता लेनदेन में यात्रा, शिक्षा, उपहार और पूंजीगत खाता लेनदेन जैसे अचल संपत्ति की खरीद प्रासंगिक नहीं हैं, इसलिए केवल आईएफएससी में अनिवासी संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए विप्रेषण की अनुमति होगी। एलआरएस के तहत निवेश करने के लिए निवासी व्यक्ति आईएफएससी में एक ब्याजरहित विदेशी मुद्रा खाता (एफसीए) भी खोल सकते हैं। एफसीए में फंड का उपयोग केवल आईएफएससी में अनुमेय निवेश करने के उद्देश्य से किया जाएगा और खाते में निष्क्रिय पड़े किसी भी निधि को भारत में निवेशक के निवासी खाते में प्राप्ति से 15 दिनों की अवधि के भीतर वापस कर दिया जाएगा। विस्तृत दिशानिर्देश जल्द ही एपी डीआईआर परिपत्र के रूप में जारी किए जाएंगे।

III. वित्तीय बाजार में गहनता लाना

11. खुदरा निवेशकों को रिज़र्व बैंक में गिल्ट खाते खोलने की अनुमति देना

सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा भागीदारी को प्रोत्साहित करना भारत सरकार और रिज़र्व बैंक का प्रमुख क्षेत्र रहा है। तदनुसार, कई पहलें अर्थात् प्राथमिक नीलामियों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली की शुरुआत, खुदरा निवेशकों के लिए एग्रीगेटर्स / फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को अनुमति देना और एनडीएस-ओएम द्वितीयक बाजार में ऑड-लॉट सेगमेंट की अनुमति देना, पहले किए जा चुके हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी को बढ़ाने और एक्सेस आसान बनाने के लगातार प्रयासों के तहत, एग्रीगेटर मॉडल से आगे बढ़ने और खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों, तक ऑनलाइन एक्सेस प्रदान करने के साथ-साथ रिज़र्व बैंक में अपना गिल्ट प्रतिभूति खाता ('रिटेल डायरेक्ट') खोलने की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सुविधा का विवरण अलग से जारी किया जाएगा।

12. चूक (डिफॉल्टेड) बॉण्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफ़पीआई) निवेश

वर्तमान में, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफ़पीआई) आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों और ऋण लिखतों में तथा दिवालिया एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया के तहत संस्था द्वारा जारी ऋण लिखतों में निवेश कर सकते हैं और इन निवेशों को कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफ़पीआई द्वारा निवेश के लिए मध्यम अवधि ढांचे (एमटीएफ़) के तहत अल्पकालिक सीमा और न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता की आवश्यकता से छूट दी गई है। कॉरपोरेट बॉन्ड में एफ़पीआई द्वारा निवेश को और बढ़ावा देने के लिए, डिफॉल्टेड कॉरपोरेट बॉन्ड्स के लिए इसी तरह की छूट देने का प्रस्ताव है। तदनुसार, डिफ़ॉल्ट कॉरपोरेट बॉन्ड में एफपीआई निवेश को एमटीएफ के तहत अल्पकालिक सीमा और न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता आवश्यकता से छूट दी जाएगी । विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

IV. भुगतान और निपटान प्रणाली

13. डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन की स्थापना

शिकायतों के निवारण के लिए कई सुरक्षा और सतर्कता सुविधाएँ और उपाय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपयोगकर्ताओं के डिजिटल भुगतान अनुभव को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। रिज़र्व बैंक के भुगतान प्रणाली विज़न दस्तावेज़ में विभिन्न डिजिटल भुगतान उत्पादों के संबंध में ग्राहक के प्रश्नों को संबोधित करने के लिए 24x7 हेल्पलाइन स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। भरोसा और विश्वास के निर्माण के अलावा, हेल्पलाइन, वित्तीय और मानव संसाधन दोनों पर खर्च को कम करती है, जो अन्यथा प्रश्नों और शिकायतों को दूर करने के लिए उपचित किया जाता है। प्रमुख भुगतान प्रणाली परिचालकों को विभिन्न डिजिटल भुगतान उत्पादों के संबंध में ग्राहक के प्रश्नों का निपटान करने और उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी देने के लिए सितंबर 2021 तक एक केंद्रीकृत उद्योग-व्यापी 24x7 हेल्पलाइन स्थापित करने की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते हुए, हेल्पलाइन के माध्यम से ग्राहकों की शिकायतों को पंजीकृत करना और उसके निपटान पर विचार किया जाएगा।

14. अधिकृत भुगतान प्रणालियों के परिचालकों और प्रतिभागियों के लिए आउटसोर्सिंग पर दिशानिर्देश

विभिन्न अधिकृत भुगतान प्रणालियों के परिचालक और प्रतिभागी उनके द्वारा ऑफर किए जाने वाले उत्पादों तथा उनके द्वारा परिचालित की जाने वाली भुगतान प्रणालियों के डिजाइन के लिए विभिन्न विशेष गतिविधियां करते हैं। अक्सर, ऐसी गतिविधियों को इष्टतम दक्षता और कम लागत के लिए आउटसोर्स किया जाता है। हालांकि, इस तरह की आउटसोर्स सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं की प्रणालियों में कमियाँ, मुख्य संस्था के लिए साइबर सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती हैं। आउटसोर्सिंग में अनुवर्ती जोखिमों का प्रबंधन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भुगतान और निपटान संबंधी सेवाओं की आउटसोर्सिंग करते समय आचार संहिता का पालन किया जाता है, रिज़र्व बैंक प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों के परिचालकों और प्रतिभागियों को दिशानिर्देश जारी करेगा।

15. देश के सभी बैंक शाखाओं का सीटीएस समाशोधन में भागीदारी को सक्षम बनाना

चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) 2010 से उपयोग में है और वर्तमान में तीन चेक प्रोसेसिंग ग्रिड में लगभग 1,50,000 शाखाएँ शामिल हैं। तब से सभी 1219 गैर-सीटीएस समाशोधन गृहों को सीटीएस में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह देखा गया है कि लगभग 18,000 बैंक शाखाएं अभी भी किसी औपचारिक समाशोधन व्यवस्था से बाहर हैं। कागज आधारित समाशोधन में परिचालन दक्षता लाने और चेकों के संग्रहण और निपटान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर ग्राहक सेवा हो सके , सितंबर 2021 तक सीटीएस समाशोधन व्यवस्था के तहत ऐसी सभी शाखाओं को लाने का प्रस्ताव है। एक माह के भीतर अलग परिचालन दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

V. उपभोक्ता संरक्षण

16. एकीकृत लोकपाल योजना

वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण ने सभी क्षेत्राधिकार में महत्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकता प्राप्त की है। उपभोक्ता संरक्षण पर वैश्विक पहलों के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं के शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था के रूप में, तीन लोकपाल योजनाएं, (i) बैंकिंग लोकपाल योजना (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना और (iii) डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल योजना पूरे देश में भारतीय रिज़र्व बैंक के 22 लोकपाल कार्यालयों से परिचालन में हैं। रिज़र्व बैंक ने शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीएमएस) पोर्टल को विनियमित संस्थाओं द्वारा नहीं निपटाए गए ग्राहक के शिकायतों के लिए वैकल्पिक विवाद निपटान हेतु एक समाधान के रूप में संचालित किया था। वैकल्पिक विवाद निपटान व्यवस्था को विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के लिए आसान और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि शिकायत निवारण के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, तीन लोकपाल योजनाओं के एकीकरण को लागू किया जाए और 'एक देश एक लोकपाल' दृष्टिकोण को अपनाया जाए। इसका उद्देश्य बैंकों, एनबीएफसी और पीपीआई के गैर-बैंक जारीकर्ताओं के ग्राहकों को एकीकृत योजना के तहत एक केंद्रीकृत संदर्भ बिंदु के साथ अपनी शिकायतों को दर्ज करने में सक्षम करके शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को आसान बनाना है। एकीकृत लोकपाल योजना जून 2021 में शुरू की जाएगी।

भाषण

एक स्थिर वित्तीय प्रणाली की ओर
शक्तिकान्त दास

एक स्थिर वित्तीय प्रणाली की ओर *

शक्तिकान्त दास

प्रारंभ में मैं आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता श्री नानी ए पालकीवाला और उनकी महान विरासत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसके साथ ही मैं श्री पालकीवाला स्मारक व्याख्यान के आयोजन की सतत परंपरा के लिए श्री पालकीवाला फाउंडेशन की सराहना करना चाहता हूँ। मेरे लिए यह बहुत ही सम्मान की बात है कि मुझे 39वां श्री पालकीवाला स्मारक व्याख्यान देने का आज अवसर मिला, अन्य बातों के साथ, इसलिए और भी कि श्री पालकीवाला 1963 से 1970 तक बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान रिजर्व बैंक के साथ बहुत निकटता से जुड़े थे। भारतीय रिजर्व बैंक के इतिहास से मुझे यह पता चला कि, उन्होंने बैंक राष्ट्रीयकरण, बाहरी सहायता और विकास वित्त संस्थान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रीय बोर्ड की चर्चाओं में काफी सक्रियता से भाग लिया। विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श में वे हमेशा एक गहरा दृष्टिकोण रखते थे। श्री पालकीवाला बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और आर्थिक प्रगति के लिए देसी उद्यमिता की क्षमताओं का पोषण करने के बहुत पक्ष में थे। ये मुद्दे वर्तमान में भी प्रासंगिक बने हुए हैं।

भारतीय समाज में श्री पालकीवाला के आजीवन योगदान की व्यापकता जगजाहिर है। वह एक प्रतिभाशाली न्यायविद थे जिन्होंने संविधान, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च सम्मान दिया था। केशवानंद भारती जैसे महत्त्वपूर्ण तथा अन्य कई मामलों में उनके व्यवहार व ईमानदारी ने उनके चरित्र बल, गहरी बुद्धिमता और नागरिकों के प्रति सहानुभूति को रेखांकित किया।

श्री पालकीवाला एक उत्कृष्ट वक्ता थे, अदालत (कोर्ट रूम) के अंदर और बाहर भी। 1958 से बजट के बाद के उनके भाषणों को उनकी बुद्धिमता, कुशाग्रता और वाकपटुता के लिए आज भी याद किया जाता है। बढ़ते दर्शकों के साथ हर साल, बजट पर पालकीवाला के भाषणों का स्थान बड़े स्थानों पर स्थानांतरित होता रहा। जब टेस्ट मैच नए बने वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित होने लगे थे, उस समय 1983 में जब उनका भाषण ब्रैबोर्न स्टेडियम में आयोजित किया गया तब, क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष विजय मर्चेंट ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि "श्री पालकीवाला ने भीड़ को वापस ब्रैबोर्न स्टेडियम में बुला लिया है।"

मेरे आज के व्याख्यान का विषय है, "एक स्थिर वित्तीय प्रणाली की ओर।" बीते हुए वर्ष को मानव समाज के लिए एक बहुत ही मुश्किल के दौर के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली अभूतपूर्व स्वास्थ्य और आर्थिक तबाही ने देशों में आर्थिक और सामाजिक कमज़ोरियों को उजागर किया है। इसलिए, आवश्यक है कि न केवल महामारी के दौरान बल्कि उसके बाद भी वित्तीय प्रणाली के प्रबंधन के प्रति उचित और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित किया जाए।

I. वित्तीय स्थिरता का बदलते स्वरूप

वित्तीय स्थिरता की अवधारणा समय के साथ विश्व स्तर पर विकसित हो रही है। वित्तीय प्रणाली की बढ़ती जटिलता के साथ वित्तीय स्थिरता के ध्यान का केंद्र केवल वाणिज्यिक बैंक तथा उनको जमाराशि निकासी की भगदड़ में तरलता (लिक्विडिटि) प्रदान करना नहीं रहा, बल्कि इसके आगे बढ़कर गैर बैंक वित्तीय संस्थानों, वित्तीय बाजारों और भुगतान प्रणाली इत्यादि तक गया है। इस प्रकार अन्य दबाव बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि वित्तीय अस्थिरता को रोका जा सके। यह आश्चर्यजनक नहीं है, कि मौद्रिक नीति के पारंपरिक और विकसित लक्ष्यों के साथ स्पष्ट या अस्पष्ट रूप में वित्तीय स्थिरता का संरक्षण केंद्रीय बैंकों के लिए उत्तरोत्तर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में उभरा है।

2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद से, केंद्रीय बैंकों की चर्चा में वित्तीय स्थिरता और भी अधिक प्रमुखता से आई है। यह अच्छी तरह से दर्ज है कि कई देश के

---

* शनिवार, 16 जनवरी, 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक में नानी पालकीवाला मेमोरियल लेक्चर श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक।

[1] बख्तियार के दादाभय: सुगर इन मिल्क: लाइव्स ऑफ़ एमिनेंट पारसीज़, रूपा एंड कंपनी, पृष्ठ 359।

केंद्रीय बैंक मूल्य स्थिरता पर संकीर्णता से केंद्रित रह गए और संभवतया बड़ी नरमी की अवधि के दौरान निर्मित हो रही वित्तीय अस्थिरता को नजरअंदाज कर दिया। संकट पूर्व आम सहमति वित्तीय क्षेत्र के अबाध विकास और न्यूनतम विनियमन के लिए थी जिससे कि और भी अधिक वृद्धि का अनुमान था। 2008 के संकट ने यह पर्याप्त स्पष्ट कर दिया कि व्यक्तिगत संस्थान की वित्तीय ताकत के योगफल से प्रणालीगत स्थिरता नहीं मिल जाती। यह स्पष्ट था क्योंकि संकट के पहले, लगभग हर वित्तीय संस्थान ने काफ़ी पूँजी पर्याप्तता रिपोर्ट की। इससे नीति निर्माताओं को अहसास हुआ कि व्यष्टि विवेकपूर्ण विनियम वित्तीय इकाई की ताकत का निर्धारण करने में मदद करेंगे, उनके पूरके के रूप में पर्याप्त समष्टि विवेकपूर्ण विनियमों और प्रणालीगत जोखिम-रोधी उपाय होना चाहिए। इस प्रकार प्रणालीगत स्थिरता का संरक्षण केंद्रीय बैंक की नीतियों की आधारशिला के रूप में सामने आया।

भारतीय संदर्भ में वित्तीय स्थिरता बनाए रखना रिजर्व बैंक के सबसे बड़े उद्देश्यों मे से एक है जो बैंकों, एनबीएफसी और भुगतान प्रणाली के विनियामक; मुद्रा विदेशी मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों और ऋण बाजार के नियामक; और अंतिम ऋणदाता के रूप में भी प्राप्त व्यापक अधिदेश पर आधारित है। जिम्मेदारियों के इस अनूठे संयोजन – मौद्रिक नीति के साथ समष्टि विवेकपूर्ण विनियमन और सूचना व्यष्टि विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण - ने रिजर्व बैंक को विभिन्न आयामों में सहक्रियात्मक ऊर्जा के दोहन का अवसर दिया है।

जीएफसी के बाद विकसित वित्तीय स्थिरता के वैचारिक आधारों में, एक अच्छी तरह से काम करने वाली वित्तीय संरचना, जिसमें ना केवल बैंक बल्कि कुशल और सुरक्षित भुगतान और निपटान प्रणाली वाले अन्य वित्तीय संस्थान भी शामिल हैं, का संरक्षण और पोषण शामिल है। महामारी के दौरान विभिन्न देशों में हाल के अनुभव बताते हैं कि भले ही बैंक, गैर बैंक वित्तीय बाजार और भुगतान प्रणाली वित्तीय स्थिरता के मूल विषय हों, अभी भी पूरी प्रणाली को इसकी संपूर्णता में बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। इस अर्थ में, वित्तीय स्थिरता नीतियों के समग्र उद्देश्य को वास्तविक अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ा जाना चाहिए। अधिक सटीक रूप में कहा जाए तो, यह देखते हुए कि वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच एक धूरी के रूप में काम करती है और सभी क्षेत्र मजबूती से जुड़े हुए हैं, वित्तीय स्थिरता को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है, और इसमें वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और मौद्रिक स्थिरता ही सिर्फ शामिल नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजकोषीय स्थिरता और बाहरी क्षेत्र की व्यवहार्यता भी शामिल होनी चाहिए। यह सभी एक प्रतिक्रिया पाश (फीडबैक लूप) में काम करते हैं और किसी भी एक भाग में हुई गड़बड़ी दूसरे भाग में पहुँच सकती है और पूरे प्रणाली की स्थिरता को क्षतिग्रस्त करने की क्षमता रखती है।

जब हम वित्तीय स्थिरता को इस नजरिए से देखते हैं, तो उसका संरक्षण व पोषण सार्जनिक कल्याण का विषय हो जाता है, जो निरंतर वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल अंतर्निहित स्थितियों के निर्माण और पोषण में सहायक हो। वर्तमान की तरह मुश्किल परिस्थितियों में, यह महत्वपूर्ण है कि सभी हितधारक समग्र रूप में समाज के सामूहिक लाभ के लिए अपनी साझा जिम्मेदारी को पहचाने और उस में भाग लें। इतिहास कठिन परिस्थितियों में किए गए ऐसे प्रयासों के उदाहरणों से भरा है, और यही मानव प्रगति और आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की कहानी का सार रहा है।

II. कोविड-19 के दौरान वित्तीय स्थिरता का संरक्षण

वित्तीय स्थिरता के इस व्यापक स्वरूप ने महामारी के समय रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण को प्रभावित किया। यह महामारी 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से भी अधिक चुनौतीपूर्ण थी जिसने वास्तविक और वित्तीय दोनों क्षेत्रों को गंभीरता से प्रभावित किया। वित्तीय बाजार के खिलाड़ियों तथा अन्य वित्तीय इकाइयों सहित वित्तीय क्षेत्र व अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की परेशानी को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने परंपरागत, अपरंपरागत तथा नए उपकरणों के साथ कई कदम उठाए। मोटे तौर पर कोविड स्थिति से निपटने के लिए हमने निम्नलिखित कदम उठाए;

(क) महामारी के तत्काल प्रभाव को कम करने के लिए उपायः परिसंपत्ति वर्गीकरण विराम के साथ ऋण अधिस्थगन; कार्यशील पूंजी वित्तपोषण में ढील और ब्याज आस्थगन; सूक्ष्म लघु और मध्यम उधमी (एमएसएमई) ऋणों की पुनर्संरचना आदि।

(ख) तरलता (चलनिधि) वृद्धि के उपाय: तनावगस्त क्षेत्रों के साथ विभिन्न क्षेत्रों के लिए दीर्घावधि रेपो ऑपरेशन (एलआरटीओ)/ लक्षित दीर्घावधि रेपो ऑपरेशन (टीएलआरटीओ) पुनर्वित्त योजनाएं; आरक्षित नगदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कमी, और अन्य योजनाएं जो कुल मिलाकर लगभग ₹ 12.81 लाख करोड़ की थी (2019-20 का के नामिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.3 प्रतिशत)।

(ग) उधारकर्ताओं और बैंकिंग प्रणाली के तनाव को कम करने के लिए प्रतिचक्री नियामक उपाय - नियामक अनुपालन में छूट, बैंकों द्वारा पूँजी का संरक्षण, समूह जोखिम मानदंडों में छूट आदि।

(घ) ऋण के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के उपाय- ब्याज दर में महत्वपूर्ण कटौती (115 बीपीएस); बाजार को वित्त पोषण की आसान स्थितियों का आश्वासन; वृद्धिशील खुदरा और एमएसएमई ऋणों के लिए सीआरआर मेंटेनेंस से छूट; बैंक ऋणों के लिए प्राथमिक क्षेत्र वर्गीकरण का गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तक विस्तार; विनियामक खुदरा पोर्टफोलियो और व्यक्तिगत आवास के लिए जोखिम भार का युक्तिकरण इत्यादि ।

(ङ) व्यक्तियों और कारोबारों के लिए कोविड-19 से संबंधित तनाव के समाधान का ढाँचा।

(च) व्यवसायिक प्रक्रिया सुदृढ़ता व निरंतरता, जोखिमों के अग्रसक्रिय प्रबंधन, तनाव परीक्षण और पूंजी की अग्रसक्रिय उगाही आदि पर ध्यान देते हुए पर्यवेक्षित संस्थाओं की बारीक निगरानी।

इस महामारी के दौरान हमारा मुख्य उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करना था; और जब हम पीछे देखते हैं, तो यह स्पष्ट है कि हमारी नीतियों ने महामारी के आर्थिक प्रभाव की गंभीरता को कम करने में मदद की है। मैं स्पष्ट रूप से दोहराना चाहूँगा कि रिजर्व बैंक और कोई भी आवश्यक उठाने पर कायम है, और साथ ही वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध भी।

III. अनुकूलन और सबक : आगे का रास्ता

हाल की अवधि ने हमें आगे बढ़ने के तरीके सीखने और अनुकूलन करने और निर्णय लेने का अवसर दिया। आज के व्याख्यान में, मैं तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ: (i) बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता; (ii) बाह्य क्षेत्र की स्थिरता; और(iii) राजकोषीय स्थिरता। पहले मैं बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा।

अभिशासन सुधार

अभिशासन की सत्यनिष्ठा और गुणवत्ता बैंकों और एनबीएफसी के अच्छे स्वास्थ्य और मजबूती की कुंजी है। हमारे तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य में हाल की घटनाओं के कारण बोर्ड की भूमिका की मुकाबले प्रमोटरों, प्रमुख शेयरधारकों और वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका की अधिकाधिक छानबीन हुई है। रिजर्व बैंक संबंधित विनियमों को मजबूत करने तथा वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण को गहरा करने पर लगातार ध्यान दे रहा है।

एक अच्छी अभिशासन संरचना को प्रभावी जोखिम प्रबंधन, अनुपालन कार्यों और आश्वासन व्यवस्था का सहयोग देना होगा। यह वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता से संबंधित मामलों में ये रक्षा की पहली पंक्ति हैं। बैंकों के जोखिम प्रबंधन ढाँचे के कुछ अभिन्न तत्वों में प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और एक भविष्योन्मुखी तनाव परीक्षण ढांचा शामिल होगा। बैंकों, एनबीएफसी को जोखिमों की जल्द पहचान करने, उनकी बारीकी से निगरानी करने, और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की आवश्यकता है। जैसे- जैसे प्रौद्योगिकी सर्वव्यापी होती जा रही है, बैंकों और एनबीएफसी में जोखिम प्रबंधन कार्य बदलते समय के साथ विकसित होते रहना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ इनका तालमेल होना चाहिए। इस संदर्भ में, संस्थान में एक उपयुक्त जोखिम संस्कृति का समावेश आवश्यक है। बोर्ड और वरिष्ठ

प्रबंधन द्वारा इसकी अगुवाई हो और सभी स्तरों पर प्रभावी जवाबदेही हो।

एक मजबूत जोखिम संस्कृति के अलावा, बैंकों और गैर बैंकों के पास भी उचित अनुपालन संस्कृति होनी चाहिए। नियमों और विनियमों के अनुपालन की लागत को एक निवेश के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में कोई भी अपर्याप्तता हानिकारक साबित होगी। अनुपालन संस्कृति न केवल कानून, नियमों व विनियमों का बल्कि ईमानदारी, नैतिकता और आचार संहिता का भी पालन सुनिश्चित करे।

आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य (ऑडिट फंक्शन) के माध्यम से एक मजबूत आश्वासन व्यवस्था मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन तथा जोखिम प्रबंधन का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है। यह बोर्ड को स्वतंत्र मूल्यांकन और आश्वासन देता है कि इकाई का संचालन निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है। आंतरिक ऑडिट फंक्शन को व्यवस्थित, अनुशासित और जोखिम पर आधारित दृष्टिकोण के साथ संगठन के अभिशासन में सुधार, जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण प्रक्रियाओं का आकलन व इनका उन्नयन करना चाहिए।

इन सभी क्षेत्रों में, रिजर्व बैंक ने कई उपाय किए हैं और समय-समय पर करता रहेगा। इस दिशा में हाल के प्रयासों में पर्यवेक्षी प्रत्याशाओं को स्पष्ट करके और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ दिशानिर्देशों को संरेखित करके अनुपालन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की महत्ता व भूमिका को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बैंकों और एनबीएफसी के अभिशासन में सुधार के कुछ और उपाय आने वाले हैं।

पर्यवेक्षी पहल

पिछले 2 वर्षों में, रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और साथ ही एनबीएफसी पर अपने पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई उपायों की शुरुआत की है। इन क्षेत्रों से संबंधित पर्यवेक्षक कार्यों को अब पर्यवेक्षक दृष्टिकोण के सामंजस्य के उद्देश्य से एकीकृत कर दिया गया है। अलग-थलग काम करने की संभावना को समाप्त कर दिया गया है। हमने कमजोरियों की शीघ्र पहचान की प्रणाली विकसित की है जिससे समय पर अग्रसक्रिय कार्रवाई मे सहायता मिल सके। ऑफ साइट विवरणियों (रिटर्न्स) के कार्य में हम उन्नत डाटा एनालिटिक्स का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि ऑन साइट पर्यवेक्षी (सुपरवाइजरी) टीमों को तेज और अधिक व्यापक इनपुट प्रदान कर सकें। रिजर्व बैंक की निगरानी का जोर अब लक्षणों से निपटने के बजाय कमजोरियों के मूल कारणों पर अधिक है। बैंक-वार तथा प्रणाली-वार पर्यवेक्षी तनाव परीक्षण कमजोर क्षेत्रों की पहचान में एक अग्रगामी आयाम जोड़ता है। वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धन-शोधन निवारण (एएमएल) पर केंद्रित एक जोखिम आधारित पर्यवेक्षण ढाँचा बनाया गया है। विनियमन (रेगटेक) और पर्यवेक्षण (सुप टेक) के लिए नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के रूप में फिनटेक पहल को अपनाया जा रहा है।

जैसा कि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बैंकों में विनियामक हस्तक्षेप का प्रश्न है, हाल के दिनों में हमारा दृष्टिकोण प्रबंधन के साथ मिलकर काम करने योग्य समाधान खोजने का है। जब यह काम नहीं करता है, तो हमने हस्तक्षेप किया है और एक त्वरित समय सारणी के भीतर एक नई व्यवस्था रखी है। वित्तीय स्थिरता और जमाकर्ताओं के हित के संरक्षण को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखते हुए, हम तेजी से दो एससीबी में स्थिति का हल निकाल पाए। सुधार के बावजूद, पर्यवेक्षी ढांचे को बढ़ाना और परिष्कृत करना एक सतत प्रक्रिया के रूप में देख जाता है। रिजर्व बैंक वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता को बनाए रखने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। इस मोर्चे पर जो भी जरूरी होगा हम करेंगे।

बैंकों का पुनर्पूंजीकरण

आगे, भारत के वित्तीय संस्थानों को वित्तीय प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता को संरक्षित करने के अति महत्त्वपूर्ण उद्देश्य के अंतर्गत आर्थिक सुधार के पोषण का संतुलन साधना होगा। मौजूदा कोविड-19 महामारी संबंधी झटके का बैंकों के बैलेंस शीट पर गैर निष्पादित आस्तियों के रूप और में अधिक दबाव पड़ेगा, जिससे पूँजी का क्षरण होगा । बफर्स का निर्माण और बैंकों द्वारा पूंजी जुटाना- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र

में- न केवल ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बल्कि वित्तीय प्रणाली में सुदृढ़ता निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। हमने सभी बैंकों को एनबीएफसी और सभी डिपॉजिट लेने वाली एनबीएफसी को कहा है कि वे अपने बैलेंस शीट, आस्ति गुणवत्ता, तरलता (लिक्विडिटी), लाभअर्जकता और पूंजी पर्याप्तता पर कोविड-19 के असर की जांच करें तथा पूँजी योजना, पूँजी बढ़ाने तथा आकस्मिक चलनिधि (तरलता / लिक्विडिटी) योजना तथा ऐसे अन्य उपाय निकालें जिससे उपर्युक्त असर को कम करने कियाजा सके ।

प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है, कि विनियामक मानदंडों के साथ-साथ वृद्धि पूंजी (ग्रोथ कैपिटल) में सहयोग के लिए संभावित पुनर्पूंजीकरण आवश्यकताएं बैंकिंग प्रणाली के लिए कॉमन इक्विटी टीयर-1 पूँजी अनुपात के 150 बीपीएस की सीमा तक हो सकती हैं[2]। विवेक का परिचय देते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसबी) के कुछ बड़े बैंक और निजी क्षेत्र (पीवीबी) के प्रमुख बैंक पहले ही पूँजी जुटा चुके हैं और कुछ के पास अनुकूल वित्तीय स्थितियों का लाभ उठाते हुए आगे के संसाधन जुटाने की योजना है। इस प्रक्रिया को द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रैक पर) लाना होगा।

बाह्य क्षेत्र की स्थिरता

यह देखते हुए कि घरेलू वित्तीय क्षेत्र विभिन्न चैनलों के माध्यम से बाहरी क्षेत्र के साथ आदान-प्रदान करता है, यह वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण खंड बन जाता है। एक कमजोर बाह्य क्षेत्र वैश्विक आर्थिक वातावरण में तेजी से बदलाव के कारण घरेलू वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकता है जैसा कि जीएफसी (2008) या टेपर टैन्ट्रम अवधि (2013) के दौरान हुआ था। बाहरी क्षेत्र की स्थितियों को आमतौर पर चालू खाता शेष, पूँजी प्रवाह, विनिमय दरों, विदेशी मुद्रा भंडार और बाह्य ऋण के आधार पर देखा जाता है। इनमें से किसी भी संकेतक में वैश्विक झटकों और/या घरेलू घटनाक्रम के कारण अचानक परिवर्तन से बाह्य क्षेत्र की व्यवहार्यता तथा घरेलू अर्थव्यवस्था के साथ संबंध पर प्रभाव पड़ सकता है।

कोविड-19 की शुरुआत से निर्यात और आयात पर बाहरी और घरेलू मांग की बिगड़ती स्थिति के असर के बावजूद भी, भारत का बाह्य क्षेत्र प्रत्यास्थ (सुदृढ़/रेज़िलिएंट) बना हुआ है। आयात में कमी और सेवाओं के सृदृढ़ निवल निर्यात की वजह से कम व्यापार घाटा छ (एच)I:2020-21 में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के 3.1% तक चालू खाता अधिशेष में बदल गया। चालू खाते में अधिशेष के कारण, अर्थव्यवस्था द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेशों की मजबूत आमद के अवशोषण की गुंजाइश सीमित थी, जिसके कारण विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी वृद्धि हुई।

निरंतर विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि ने पारंपरिक मानकों जैसे (I) आयात के लिए कवर (18.4 महीने) (ii) अवशिष्ट परिपक्वता के संदर्भ में अल्पकालिक ऋण की तुलना में आरक्षित निधियों (रिज़र्व्स) के अनुपात (236 प्रतिशत) रिज़र्व पर्याप्तता में सुधार किया है। मजबूत बाह्य क्षेत्र संकेतक संभावित वैश्विक झटके के प्रसार (स्पिल ओवर) के असर या वित्तीय स्थिरता से जुड़ी मामलों के प्रभाव को सीमित करने की दृष्टि से अच्छे होते हैं, क्योंकि निवेशकों और बाजार को संभावित संक्रामक क्षति के खिलाफ बफर का ठोस भरोसा होता है। प्रचुर मात्रा में पूंजी प्रवाह जहाँ मुख्यत: निभावी वैश्विक तरलता की स्थिति और भारत के आशावादी मध्यावधि वृद्धि परिदृश्य से प्रेरित है, वहीं जोखिम विमुखता के वैश्विक कारकों के मजबूत होने की दशा में घरेलू वित्तीय बाजारों को अचानक विराम व विपर्यय के लिए तैयार रहना चाहिए। अनिश्चित वैश्विक आर्थिक माहौल की मार आमतौर पर उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) पर पड़ती है। वैश्विक स्पिलओवर को कम करने के लिए उनके पास अपने विदेशी मुद्रा आरक्षित बफर्स के निर्माण के अलावा कोई सहारा नहीं है भले ही इसकी कीमत अमेरिकी ट्रेजरी की मुद्रा जोड़-तोड़ सूची या निगरानी सूची में शामिल होने के रूप में हो। मुझे लगता है कि इस पहलू पर दोनों ओर अधिक समझ की आवश्यकता है, ताकि ईएमई पूंजी प्रवाह से संबंधित चुनौतियों को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से नीतिगत साधनों का उपयोग कर सकें। रिजर्व बैंक में हम घरेलू समष्टि आर्थिक स्थिति और इसकी सुदृढ़ता के आकलन में प्रतिकूल व अनुकूल वैश्विक हवाओं के रुख को ध्यान से देख रहे हैं।

[2] भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2019-20 पृष्ठ 2

राजकोषीय स्थिरता

कोविड-19 महामारी से सरकार द्वारा मेरिट गुड्स और पब्लिक गुड्स (जन कल्याण की वस्तुओं) पर खर्च करने की आवश्यकता और उभरकर सामने आई है, विशेष रूप से मानव व सामाजिक पूंजी में सुधार और भौतिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र पर। आईएमएफ की गणना के अनुसार, कोविड-19 के जवाब में सितंबर के मध्य तक कुल वित्तीय सहायता वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 12% था। वैश्विक सार्वजनिक ऋण के 2020 में जीडीपी के 100% तक पहुँचने की बात है। परिणाम स्वरूप, अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं अपने साथ उच्च घाटा और ऋण कमजोरियां लेकर इस महामारी से बाहर आएंगी। इन परिस्थितियों में, और आर्थिक पुनरुद्धार की प्रक्रिया में सहायता के लिए व्यय आवश्यकताओं को देखते हुए, राजकोषीय स्थिरता समग्र वित्तीय स्थिरता का एक और भी महत्वपूर्ण घटक बन जाता है।

यद्यपि उम्मीद है कि अल्पावधि में अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय खर्च का पैमाना राजकोषीय विवेक के मात्रात्मक लक्ष्यों उल्लंघन करेगा, पर महामारी के संदर्भ में सार्वजनिक व्यय के कल्याणकारी दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण था। मानव पूंजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर व्यय से न केवल कल्याण में वृद्धि होती है, उनके उच्च गुणक प्रभाव तथा पूँजी और श्रम उत्पादकता दोनों की वृद्धि के माध्यम से उच्च विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इन परिस्थितियों में तथा आगे चलकर, यह जरूरी हो जाता है कि राजकोषीय रोड मैप को न केवल मात्रात्मक मापदंडों जैसे कि जीडीपी की तुलना में राजकोषीय संतुलन अनुपात या जीडीपी की तुलना में ऋण के अनुपात के संदर्भ में परिभाषित किया जाए, बल्कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए व्यय की गुणवत्ता संबंधी मापयोग्य मानकों के संदर्भ में भी । राजकोषीय अनुशासन के पारंपरिक मानदंड जहाँ सार्वजनिक वित्त की मध्यम और दीर्घकालिक निरंतरता सुनिश्चित करेंगे, व्यय की गुणवत्ता संबंधी मापयोग्य मानक यह सुनिश्चित करेगा कि कल्याणवाद महत्वपूर्ण उत्पादक परिणामों और गुणक प्रभावों को लेकर चले। व्यय की गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने से, विकास को सहायता देते हुए राजकोषीय स्थिरता के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

IV. निष्कर्ष

आगे देखें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के पूर्ण जीवनी शक्ति पाने के क्रम में हमारी वित्तीय प्रणाली चुनौतीपूर्ण समय और नए अवसरों दोनों का सामना कर रही है। प्रौद्योगिकी और नए व्यापार मॉडल पर वित्तीय मध्यस्थता के नए अवसर सामने आएंगे। भारत में डिजिटलीकरण और ऑनलाइन वाणिज्य की भारी वृद्धि के साथ रिजर्व बैंक ने सुरक्षित, कुशल, किफायती और मजबूत भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को सुनिश्चित करते हुए अपने नीतिगत प्रयासों को एक आधुनिक राष्ट्रीय भुगतान अवसंरचना के कार्यान्वयन की दिशा में भी लगाया है। रिजर्व बैंक खुद को एक ऐसे समर्थक वातावरण प्रदान करने के लिए तैयार रहा है, जिसमें वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते और संरक्षित करते हुए, विनियमित संस्थाएं इन अवसरों का दोहन करने के लिए उत्प्रेरित हों। अपनी ओर से विनियमित संस्थाओं के लिए आवश्यक है कि वे उभरते जोखिमों की पहचान करने और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अपने आंतरिक बचाव को मजबूत करें। वित्तीय स्थिरता एक सार्वजनिक कल्याण है तथा इसकी प्रत्यास्थता और मजबूती को सभी हित धारकों द्वारा संरक्षित और पोषित करने की आवश्यकता है। हमें आर्थिक पुनरुत्थान और विकास का समर्थन करने की आवश्यकता है; हमें वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने की आवश्यकता है।

धन्यवाद।

लेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारत में बैंक ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन: हाल के घटनाक्रम

एकदिवसीय सूचकांक स्वैप (ओआईएस) दरों से मौद्रिक नीति के भावी रुख का आकलन

क्या बाजार को ज्यादा पता है? पीबीआर के नजरिए से भारत का बैंकिंग क्षेत्र

*अर्थव्यवस्था की स्थिति**

भारत में, कोविड -19 की घटनाओं में कमी आने के कारण आर्थिक गतिविधियाँ तेज हो रही हैं और टीकाकरण के आरंभ होने से उम्मीद जागी है। कुल मांग में भी तेजी आई है ; केवल निजी निवेश न के बराबर है और इसके पुन: आरंभ होने के लिए समय उपयुक्त है। चलनिधि के व्यापक उपाय प्रणाली में मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों के आसान होने को दर्शाते हैं।

समय की पटरियों पर एक दौड़ जारी है - संक्रमण बनाम इंजेक्शन; टीकाकरण बनाम म्यूटेशन। अब तक, पौराणिक ग्रीस की शिकारी एटलांटा की तरह, जिसकी शर्त यह थी कि वह उससे शादी करेगी जो उससे आगे निकाल जाएगा लेकिन जिनसे वह आगे निकाल जाएगी उन्हें वह मार देगी, उसी तरह से अभी संक्रमण आगे चल रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी कोरोनोवायरस रिसोर्स सेंटर के अनुसार, फरवरी 2021 के अंत तक, वैश्विक संक्रमण 192 देशों में 114 मिलियन पर बंद हो गया। फिर भी, इंजेक्शन की दिशा में बेहतर काम हो रहा है। कुल मिलाकर, दुनिया भर के 64 देशों में 50 मिलियन से अधिक लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है। टीकाकरण की गति में वृद्धि जारी है, लगभग 6.17 मिलियन खुराक एक दिन में (ब्लूमबर्ग)। बुरी खबर यह है कि, कोविड -19 म्यूटेशन जो संभवतः टीकों द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी के आंशिक प्रतिरोध को स्वीकार करता है, अब अमेरिका में है, जो लगातार बदलते हुए वायरस से लड़ने के नए तरीकों की जांच के लिए वैज्ञानिकों को प्रेरित कर रहा है और जो वर्षों तक सक्रिय रह सकता है। दक्षिण अफ्रीकी संस्करण पहले से ही अफ्रीकी महाद्वीप में तेजी से फैल गया है और अफ्रीका के बाहर कम से कम 24 देशों में देखा गया है। 29 दिसंबर, 2020 को पहली बार कोलोराडो में देखा गया यूके म्यूटेशन एक महीने से भी कम समय में 29 अमेरिकी राज्यों में पाया गया था। दोनों प्रकारों को मूल स्ट्रेन से अधिक संक्रामक माना जाता है। टीकों के संबंध में लेट-स्टेज ट्रायल्स प्रभावकारिता में एक असमान गिरावट को दर्शाता है। टीके बनाने वालों को अब बूस्टर शॉट या नए एडजस्टेड वैक्सीन पर काम करने के लिए गियर्स को मिड-कोर्स में शिफ्ट करना होगा जो म्यूटेशन के खिलाफ बेहतर काम कर सकते हैं। यह तेजी से काम करने के लिए उकसाने वाला समय है: वायरस म्यूटेट होगा और हमें चुनौती देगा - 100 मिलियन से अधिक संक्रमित लोग होने के कारण, उत्परिवर्तन के लिए 100 मिलियन संभावनाएं हैं।

भारत कम से कम तीन महत्वपूर्ण तरीकों से अनजान मार्ग को अपना रहा है। सबसे पहले, कोविड -19 रोगियों की बढ़ती संख्या, जो सितंबर 2020 में अपने चरम पर पहुँच कर प्रतिदिन 1,00,000 नए पुष्टि किए गए संक्रमणों पर आ गई थी वह फरवरी 2021 में कम हो कर दिन में लगभग 12,500 औसत पर आ गई जिसके चलते डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य फ्रंटलाइन वारियर्स को एक अप्रत्याशित राहत मिली। स्वास्थ्य सर्वेक्षणों से अब पता चलता है कि वायरस का एक्सपोज़र पहले की तुलना में बहुत अधिक था, जिससे यह देखने को मिला कि भारत के भीड़-भाड़ वाले शहर और कस्बे टीके की उपलब्धता से पहले ही हर्ड इम्यूनिटी के शुरुआती चरणों में हो सकते हैं। या कम से कम यह उम्मीद है कि सबसे खराब समय खत्म हो गया है, इस लेख [1] के दिसंबर 2020 के अंक में किए गए पूर्वानुमान की पुष्टि करता है । युवा हमारे पक्ष में हैं - लगभग 95 प्रतिशत आबादी 65 वर्ष से कम आयु की है। इसके अलावा, भारत ने यह पहले भी किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में लक्षणहीन संक्रमणों के उच्च अनुपात का कारण है अन्य पैथोजन के पूर्व संपर्क में आना ; पोलियो और खसरा के खिलाफ हमारी लड़ाई हमारे महत्वाकांक्षी टीकाकरण अभियान में बेहतर है, जिसका लक्ष्य अगस्त के अंत तक 300 मिलियन का टीकाकरण करना है। 500,000 के लक्ष्य (21 दिन) तक पहुंचने के लिए सबसे तेज़ पहुँचने के कारण भारत केवल डेलीवर की गई वैक्सीन की खुराक के मामले में अमेरिका और ब्रिटेन से पीछे है। 16 जनवरी को ही अपना टीकाकरण अभियान शुरू करने के बावजूद, भारत दुनिया के 70 प्रतिशत टीकों की आपूर्ति के लिए अपनी दवा निर्माण क्षमता का उपयोग कर रहा है, अब तक 15 देशों में आपूर्ति की गई है और अन्य 25 देश कतार में हैं, जिनमें पड़ोसियों को दान भी शामिल है - एक शान्तिप्रिय शक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन।

---

* यह लेख माइकल देवव्रत पात्रा, कुणाल प्रियदर्शी, शशिधर एम.लोकरे, कृष्ण मोहन कुशवाहा, के.एम. नीलिमा, अभिनंदन बोरड़, जितेंद्र सोकल, मनु शर्मा, शोभित गोयल, बरखा गुप्ता, सक्षम सूद, प्रियंका सचदेवा, ऋषभ कुमार, ऋग्वेन यंगरोल, राजस सरोय, शाहबाज खान, अशीष थॉमस जॉर्ज, देबा प्रसाद रथ, प्रज्ञा दास और समीर रंजन बहेरा। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

[1] 30 जनवरी, 2021 के फाइनेंशियल टाइम्स ने इस पर ध्यान दिया, क्योंकि 'ईबुलेंस' ऑफ दी 'नोर्मली स्टेड भारतीय रिजर्व बैंक'

नाममात्र जीडीपी के संदर्भ में, 96 प्रतिशत पूर्व-महामारी आर्थिक गतिविधि को बहाल किया गया है, यह मानते हुए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का पहला अग्रिम अनुमान अभी भी लागू है (चार्ट 1)। Q3 के लिए प्रारंभिक कॉर्पोरेट परिणाम: 2020-21 यह दर्शाता है कि बिक्री में सुधार जारी है क्योंकि वे संकुचन से बाहर निकले हैं; कच्चे माल की लागत में गिरावट और कम ब्याज खर्च के कारण बचत के साथ संयुक्त रूप से परिचालन लाभ में उछाल आया है। गैर-वित्तीय क्षेत्र में प्रो-साइक्लिकल उद्योगों - ऑटो, स्टील और सीमेंट - ने वॉल्यूम में तेज पलटाव दर्ज किया, एक मजबूत मूल्य निर्धारण वातावरण में उत्पादन की कीमतों में वृद्धि और लागत में कटौती के उपायों को अपनाया। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र ने स्पष्ट रूप से महामारी-प्रूफिंग का प्रदर्शन किया है, कई वर्षों में इसकी सबसे मजबूत तिमाही बिक्री में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, आईटी की प्रमुख टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर की कीमतों ने बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बनने के लिए एक्सेंचर को पीछे छोड़ दिया। दूसरी ओर, तिमाही के दौरान तेजी से बढ़ते उपभोक्ता सामान (एफएमसीजी) और दवा कंपनियों की बिक्री वृद्धि ने मुनाफे में वृद्धि को दर्शाया। पूरे भारत में, और अधिक बच्चों को स्कूल जाना है, अधिक श्रमिकों पेशेवरों को अपने कार्यस्थलों पर, और बुजुर्गों को बाहर जाना है। संक्रमण और इंजेक्शन के

चार्ट 1 : नोमिनल जीडीपी

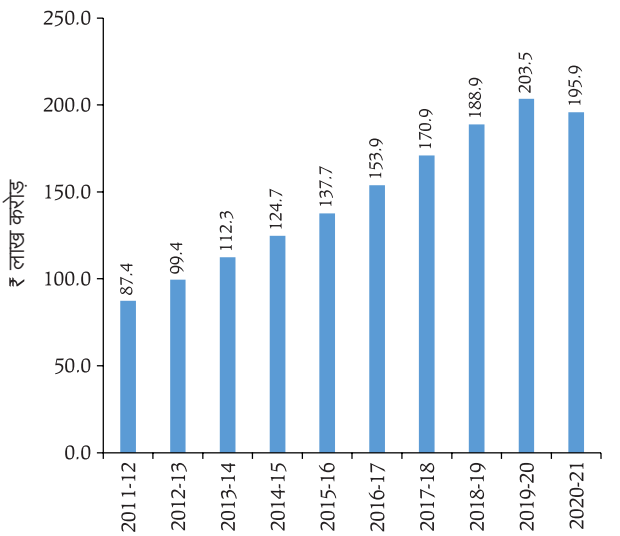

स्रोत: नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (एनएसओ)

बीच में (I से I) अनुपात दिखाता है (चार्ट 2), अभी एक लंबी और कठिन यात्रा तय करनी है और बही संतुष्ट होने की कोई जरूरत नहीं है।

दूसरा, भारत में नीति निर्माता प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसर में बदलने के लिए वायरस से पहल कर रहे हैं। 1 फरवरी, 2021 को वित्त मंत्री ने "विश्वास और आशा" के भारत के बजट का

चार्ट 2: इंजेक्शन टू इन्फेक्शन (आई/आई) अनुपात

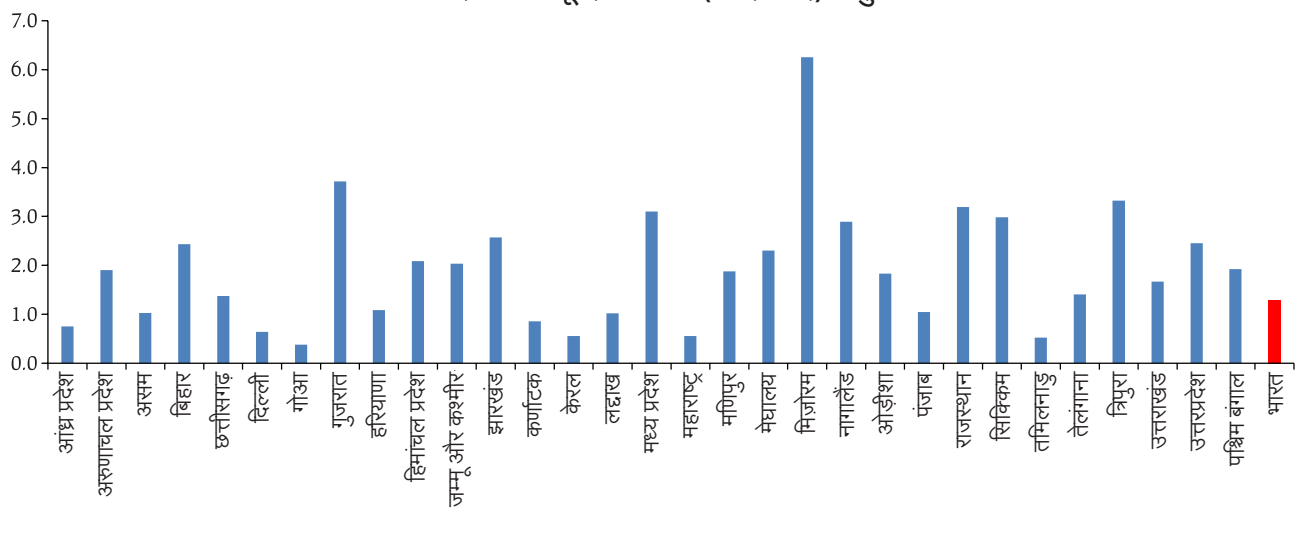

स्रोत : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अनावरण किया। मितव्ययिता को न कहते हुए, केंद्रीय बजट पारदर्शिता और व्यावहारिक विवेक के साथ साहस और आशावाद को संतुलित करने के लिए इतिहास में याद रखा जाएगा। कोई नया कर नहीं, अनुपालन में आसानी और, वास्तव में, अनुपालन से कर उछाल, ऋण की कमी से निपटने के नए तरीके और फिर भी सबसे बड़े पूंजीगत परिव्यय के साथ 5.54 लाख करोड़, यह एक दुर्लभ प्रतिक्रिया में आश्चर्य की बात नहीं है, वित्तीय बाजारों ने एक बजट बनाया। वाहवाह! जैसा कि अरस्तू ने 350 ईसा पूर्व में अपनी पोलिटिका में लिखा था, "अच्छी तरह से शुरुआत मतलब आधा काम हो गया।"

तीसरा, राजकोषीय नीति में वृद्धि के प्रति व्यय के साथ, लेकिन एक लिफाफे के भीतर, जो महामारी उधारों के विंड-डाउन की भी परिकल्पना करता है - सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) को जीडीपी के 9.5 प्रतिशत से नीचे 6.8% तक जाने के लिए बजट दिया जाता है - मौद्रिक नीति वर्ष 2020-21 के लिए अपनी अंतिम द्विमासिक घोषणा में अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा बन गई। यह देखते हुए कि दिसंबर में महंगाई में कमी ने विकास को समर्थन देने की गुंजाइश प्रदान की, मौद्रिक नीति समिति ने 5 फरवरी को नीतिगत दर को अपरिवर्तित छोड़ दिया और चालू वित्त वर्ष के माध्यम से और अगले में अपने समय के आकस्मिक रुख को बनाए रखा। भाग्य बहादुर के पक्ष में होता है - जनवरी 2021 के प्रिंट में, मुद्रास्फीति 4.06 प्रतिशत पर आ गई, नीचे के रास्ते पर लक्ष्य के सिर्फ 6 आधार अंक कम। उसी समय, रिज़र्व बैंक ने समाज के सभी सदस्यों के लिए केंद्र सरकार के उधार कार्यक्रम को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए सभी कार्य आरंभ किए, उपज वक्र के क्रमिक विकास की प्रतिपूर्ति और वित्तीय स्थिरता को गैर-प्रतिद्वंद्विता और उपयोग के लिए बाहर न रखने योग्य बताया। इसने गिल्ट मार्केट में एक नया और सबसे भरोसेमंद निवेशक - भारतीय सेवर, आम आदमी - लाया, जो अब रिज़र्व बैंक के साथ ही गिल्ट सिक्योरिटीज अकाउंट है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय परिवार 2019-20 में शेष अर्थव्यवस्था का एकमात्र ऋणदाता था, जिसके लिए नवीनतम वर्ष पूरी जानकारी उपलब्ध है। दूसरा, इसने बैंकों द्वारा खरीदी गई नई प्रतिभूतियों की परिपक्वता के लिए धारण का विस्तार किया। नतीजतन रुपये 4 लाख करोड़ के स्तर तक प्रतिभूतियों की होल्डिंग ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से अछूता रहेगा और इसलिए बैंकों को 'मार्क-टू-मार्केट' नुकसान से बचाया जाएगा। तीसरा, पहली बार रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने चलनिधि पर आगे मार्गदर्शन प्रदान किया और कहा कि इस पर ध्यान आकर्षित करना सार्थक है:

"मौद्रिक नीति के रुख के साथ चलनिधि प्रबंधन का रुख लगातार और पूरी तरह से मेल खाता है। आरबीआई प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार ट्रैक्शन प्राप्त करने के लिए वसूली के लिए अनुकूल वित्तीय स्थितियों को बढ़ावा देता है। सीआरआर सामान्यीकरण अतिरिक्त चलनिधि को इंजेक्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के बाजार संचालन के लिए स्थान खोलता है। इन क्षेत्रों में हमारे प्रयास का अंतर्निहित विषय वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाले बिना उचित रूप से हमारे पास उपलब्ध सभी लिखतों का लचीले ढंग से उपयोग करना होगा, जो कि आरबीआई के नीतिगत उद्देश्यों के मूल में है। सरकार के ऋण प्रबंधक और बैंकर के रूप में, रिज़र्व बैंक बिना किसी व्यवधान के बाज़ार उधार कार्यक्रम को पूरा करना सुनिश्चित करेगा। इस संदर्भ में, हम बाजार के खिलाड़ियों और आरबीआई के बीच आम समझ और सहकारी दृष्टिकोण की निरंतरता के लिए तत्पर हैं… "

दिया गया संदेश असंदिग्ध है: चलनिधि पर्याप्त बनी रहेगी [25 फरवरी, 2021 को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत कुल अवशोषण रुपये 7.1 लाख करोड़ था] ; रिज़र्व बैंक पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करेगा (19 फरवरी 2021 तक, रिज़र्व बैंक ने रु. 3.0 लाख करोड़ की खुली बाजार खरीद का संचालन किया है जबकि विदेशी मुद्रा संचालन ने 2020-21 में घरेलू चलनिधि रु. 5.4 लाख करोड़ तक बढ़ाई थी)। रिज़र्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) के सामान्यीकरण के माध्यम से वापस ली गई चलनिधि को लगभग रु. 1.6 लाख करोड़ के बराबर कर देगा; और रिज़र्व बैंक एक क्रमबद्ध तरीके से सरकार के उधार कार्यक्रम को पूरा करेगा। अफ़सोस की बात है कि ये संदेश कुछ बांड व्यापारियों द्वारा खो गए थे! रिज़र्व बैंक की

घोषणाओं का उद्देश्य दुनिया को परिवर्तित करना नहीं था, लेकिन हम जो हैं, हम हैं – सभी निर्भीक लोग और एक समान स्वभाव [2]।

II. ग्लोबल सेटिंग

ति.3: 2020 में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में एक मजबूत पलटाव, छुपी हुई खपत की मांग और कार्यालय से दूर रहकर कार्य करने में समायोजन द्वारा संचालित, ति. 4 में दूसरी / तीसरी लहरों के संक्रमण के बाद बंद, विशेष रूप से नए और अधिक संक्रामक स्ट्रेन और सख्त लॉकडाउन का माहौल आया (चार्ट 3)।

वैक्सीन की मंजूरी, कुछ देशों में अतिरिक्त नीति प्रोत्साहन के टीकाकरण और घोषणाओं का शुभारंभ इस उम्मीद को बल देता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था Q1 के करीब और Q2 में गति प्राप्त करेगी। इसने 2021 के लिए दृष्टिकोण को उज्ज्वल किया है। 2021-22 के दौरान अधिकांश देशों में टीके की उपलब्धता की धारणा पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने जनवरी 2021 के अपडेट में वैश्विक जीडीपी अनुमानों को 2021 से 5.5 प्रतिशत तक संशोधित किया है। अक्टूबर रिलीज़ (तालिका 1) में अनुमानित 5.2 प्रतिशत से विश्व आर्थिक आउटलुक (डबल्यूईओ)। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) को वैक्सीन खुराक और अतिरिक्त नीति समर्थन के स्टॉकपिलिंग से एक बढ़त हासिल करने की संभावना है, जिसमें व्यापारिक साझेदारों के लिए अनुकूल स्पिलओवर और उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के लिए जोखिम प्रवाह तेज है। इसलिए, रिकवरी की ताकत और गति, पूरे देशों में असमान और भिन्न बने रहने की उम्मीद कर सकती है। इस संदर्भ में एक भयावह नोट पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने संकेत दिया है कि यदि वैक्सीन की देरी के कारण विकासशील देशों में महामारी फैलती रहती है और यदि टीका वितरण असमान है, तो यह 4.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का क्षरण कर सकता है। विश्व उत्पादन में 2021 में या पूर्व-महामारी वैश्विक आउटपुट 3 का लगभग 5.7

चार्ट 3 : विश्व औद्योगिक उत्पादन और विश्व व्यापार मात्रा में वृद्धि

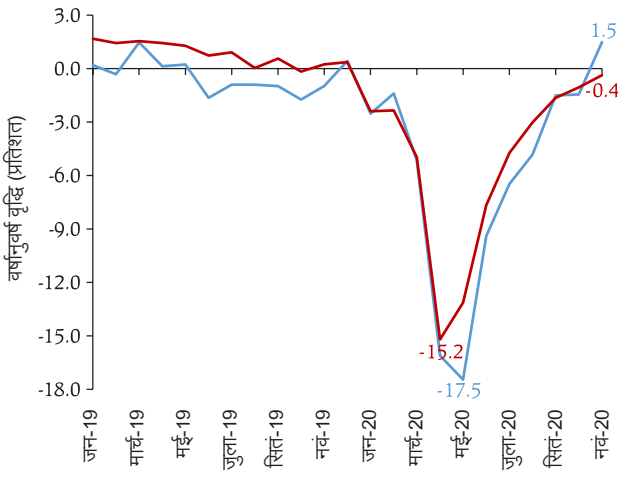

स्रोत : सीपीबी नीदरलैंड्स

[2] लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन अपनी कविता यूलिसिस से।

तालिका 1 : जीडीपी वृद्धि अनुमान – चुनिन्दा एई और ईएमई

(वर्षानुवर्ष, प्रतिशत)

देश	2020		2021	
	अक्टू 2020	जन 2021	अक्टू 2020	जन 2021
विश्व	-4.4	-3.5	5.2	5.5
विकसित अर्थव्यवस्थाएँ				
यूएस	-4.3	-3.4	3.1	5.1
यूरो एरिया	-8.3	-7.2	5.2	4.2
यूके	-9.8	-10.0	5.9	4.5
जापान	-5.3	-5.1	2.3	3.1
उदीयमान मार्केट अर्थव्यवस्थाएँ				
ब्राज़ील	-5.8	-4.5	2.8	3.6
रूस	-4.1	-3.6	2.8	3.0
भारत	-10.3	-8.0	8.8	11.5
चीन	1.9	2.3	8.2	8.1
साउथ अफ्रीका	-8.0	-7.5	3.0	2.8

स्रोत : विश्व बैंक

प्रतिशत। एई को इस नुकसान का खामियाजा भुगतने की उम्मीद है: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और व्यापारिक गतिविधियों में परिणामी व्यवधान के परिणामस्वरूप महामारी का यूएस $ 2.4 ट्रिलियन या 3.5 प्रतिशत वार्षिक नुकसान हो सकता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट (जीएफ़एसआर) के आईएमएफ के जनवरी 2021 के अपडेट से यह अनुमान भी लगता है - टीकों की असमान पहुंच वित्तीय अस्थिरता के जोखिमों को बढ़ा सकती है।

वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) जनवरी 2021 में लगातार तीसरे महीने में कम हुआ क्योंकि विनिर्माण और सेवा गतिविधि दोनों ने वर्ष की शुरुआत में (चार्ट 4) गति खो दिया था । वैश्विक विनिर्माण पीएमआई 53.5 के तीन महीने के निचले स्तर पर गिर गया, जबकि पीएमआई सेवाओं के छह महीने के निचले स्तर 51.6 पर पहुंच गया, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि और नए आदेश नए निर्यात आदेशों के साथ-साथ गतिरोध में फिसल गए। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं गंभीर रूप से फैली हुई हैं, जिसमें वेंडर लीड समय पीएमआई सर्वेक्षण के इतिहास में सबसे अधिक है। आपूर्ति की गड़बड़ी के मद्देनजर, खरीद मूल्य में वृद्धि हुई है, जैसा कि उच्च उत्पादन शुल्क में प्रकट होता है, जबकि इनपुट मूल्य दबाव का निर्माण जारी है।

प्रोत्साहन घोषणाओं और वैक्सीन रोलआउट के द्वारा 2021 की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी रही। अमेरिका में गिरते कच्चे माल की सूची के बीच आपूर्ति में और अधिक वृद्धि हुई है। फरवरी और मार्च में प्रति दिन 1 मिलियन बैरल से उत्पादन में कटौती की, सऊदी अरब की घोषणा ने दोनों भावनाओं और कीमतों को हटा दिया - जनवरी में औसतन $ 54.5 प्रति बैरल, ब्रेंट क्रूड जनवरी (चार्ट 5) में 9.4 प्रतिशत महंगा था। इसके अलावा, कच्चे तेल का वायदा दिसंबर 2020 के बाद से पिछड़ेपन में चला गया, जो कच्चे तेल के बाजार में मजबूती को दर्शाता है। वर्ष की दूसरी छमाही में मांग में पर्याप्त सुधार की उम्मीद है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के साथ-साथ भारी माल की आपूर्ति में कटौती से ऐसे परिदृश्य में गिरावट आ रही है जहां शेल उत्पादन की प्रतिक्रिया म्यूट रहने की संभावना है, कीमतों को बनाए रख रहे हैं।

चार्ट 4 : ग्लोबल पीएमआई इंडाइसेस

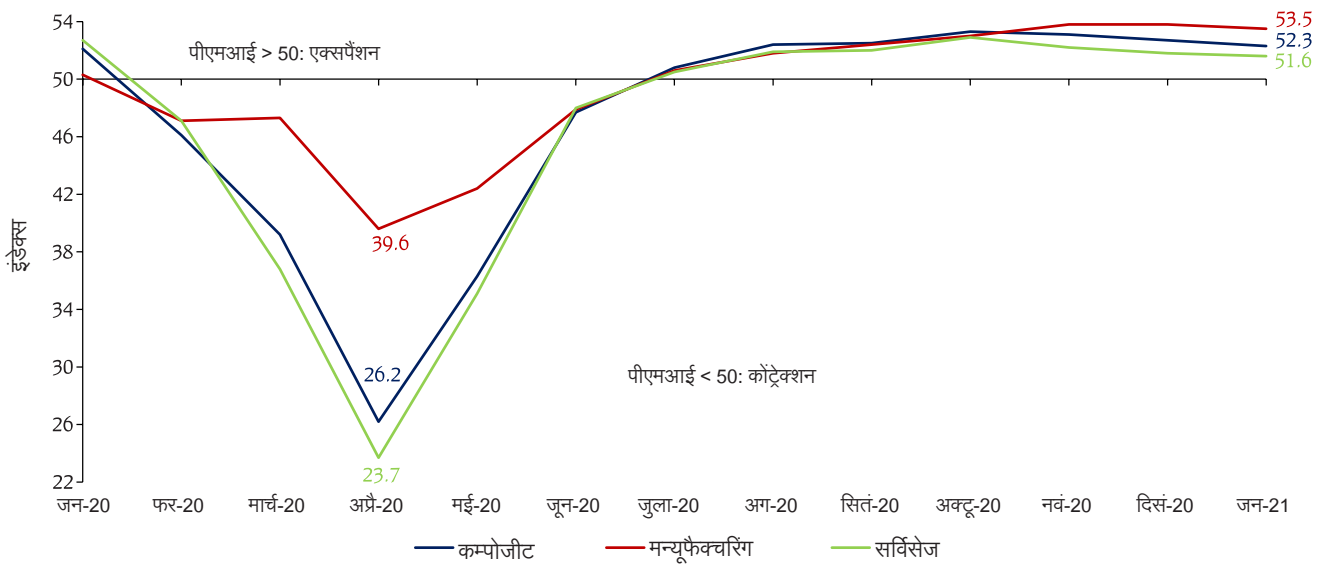

स्रोत : आईएचएस मार्केट

[3] *https://www.ft.com/content/53c668bc-1066-4d8c-8c8d-5d29ba34a06e.*

चार्ट 5 : ब्रेन्ट फ्यूचर्स

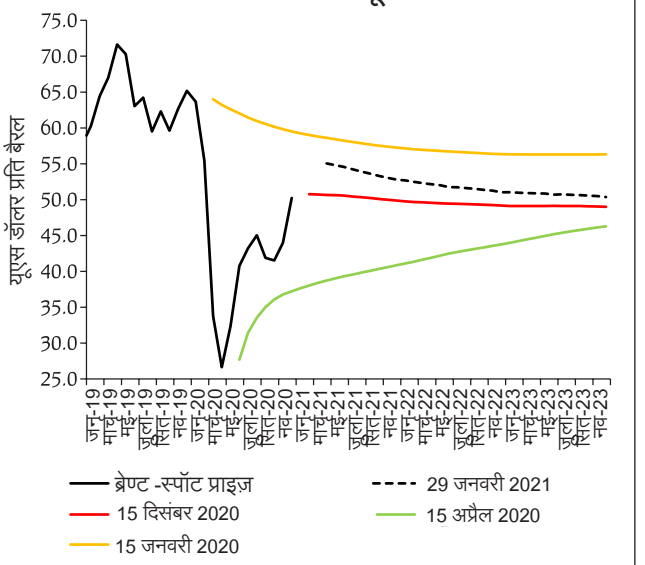

स्रोत : ब्लूमबर्ग

चार्ट 6 : गोल्ड फ्यूचर्स

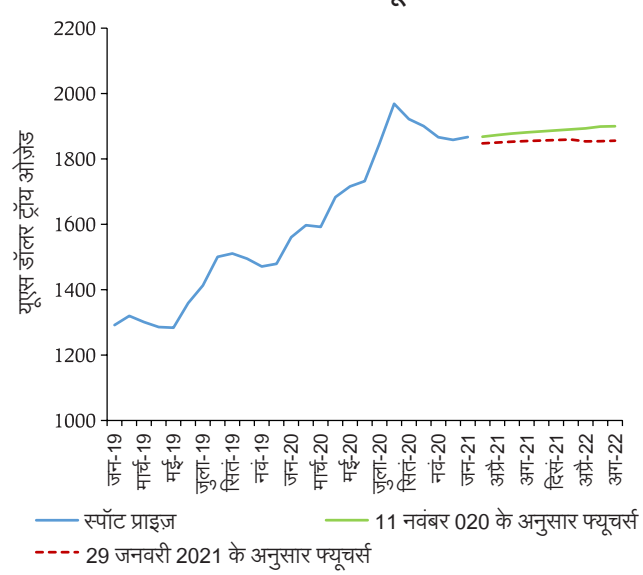

स्रोत : ब्लूमबर्ग

सोने ने 2021 में अपनी जीत की लकीर को खो दिया, जिसमें 2.7 प्रतिशत (चार्ट 6) की कीमतों में सुधार हुआ। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने, अमेरिकी बॉन्ड की पैदावार में वृद्धि और मजबूत जोखिम की भावनाओं ने पीली धातु की चमक को कम कर दिया है। दूसरी ओर, चीन की फैक्ट्री गतिविधि में रिकवरी और ट्रैक्शन, जैसा कि वैश्विक विनिर्माण पीएमआई में दिखाया गया है, ने आधार धातुओं की कीमतों को बढ़ावा दिया है।

व्यापार मोर्चे पर, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा दिनांक 26 जनवरी, 2021 को जारी नवीनतम रिपोर्ट ने ति.3: 2020 में वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के व्यापार में 24 प्रतिशत सालाना (वर्षानुवर्ष) में संकुचन की सूचना दी, जिसमें पिछली तिमाही में 30 प्रतिशत से गिरावट आई है। माल व्यापार में गिरावट अपेक्षाकृत मध्यम थी - 5.6 प्रतिशत। सेवाओं के व्यापार में मंदी नवंबर के अनुमान के अनुसार प्रारंभिक अनुमान के अनुसार जारी रहने की उम्मीद है। अधिकांश उप-क्षेत्र संकुचन क्षेत्र में बने हुए हैं, जिसमें यात्रा क्षेत्र को ति.3: 2020 में वैश्विक स्तर पर 68 प्रतिशत की गिरावट आई है। दूसरी ओर, गुड्स ट्रेड ने नवंबर, 2020 में मूल्य में क्रमिक सुधार को अपने 2019 स्तरों की तुलना में 4 प्रतिशत बढ़ा दिया। दो कारकों ने मुख्य रूप से इस वसूली को सहायता प्रदान की है, वर्ष के शुरुआती हिस्से में खरीद को स्थगित कर दिया और एक अनुकूल आधार प्रभाव।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निवेश रुझान मॉनिटर के अनुसार, वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) ने 2020 तक यूएस $ 1.5 ट्रिलियन से 2020 तक अनुमानित रूप से $ 859 बिलियन के मुकाबले 42 प्रतिशत की गिरावट के साथ, एक प्राथमिक गिरावट दर्ज की। (यूएनसीटीएडी) 24 जनवरी, 2021 को जारी किया गया। विभिन्न प्रभाव दिखाई दे रहे थे क्योंकि विकसित देश सबसे कठिन प्रभाव में बने रहे, प्रवाह में 69 प्रतिशत की गिरावट के साथ अनुमानित अमरीकी $ 229 बिलियन, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 12 प्रतिशत की अधिक मध्यम यूएस $ 616 बिलियन प्रतिधारण देखी गई।2021 में वायरस के दौरान लगातार अनिश्चितता के कारण गिरावट के बावजूद, विकासशील देशों में एफडीआई प्रवाह कुल वैश्विक एफडीआई प्रवाह का 72 प्रतिशत है - रिकॉर्ड पर सबसे अधिक हिस्सेदारी - चीन और भारत 2020 में सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में उभर रहे हैं।

जनवरी के अंतिम सप्ताह में कुछ सुधार के साथ वित्तीय बाजारों ने आगे बढ़त हासिल की। सुधार कारकों के मिलने के कारण था, अर्थात, अधिक संक्रामक वेरिएंट के तेजी से फैलने के बीच पैच वैक्सीन की तैनाती पर बढ़ती चिंताएं; यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए कमजोर आर्थिक डेटा; और अमेरिकी शेयर बाजारों में खुदरा निवेशकों द्वारा किए गए कार्यों ने कुछ हेज

फंडों को अभिभूत कर दिया। कुल मिलाकर, ईई के लिए मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) स्टॉक इंडेक्स ने महीने को लाल रंग में समाप्त कर दिया, जबकि उभरते बाजारों के लिए, एमएससीआई स्टॉक इंडेक्स ने शुद्ध लाभ (चार्ट 7) के साथ

चार्ट 7 : वित्तीय बाजार

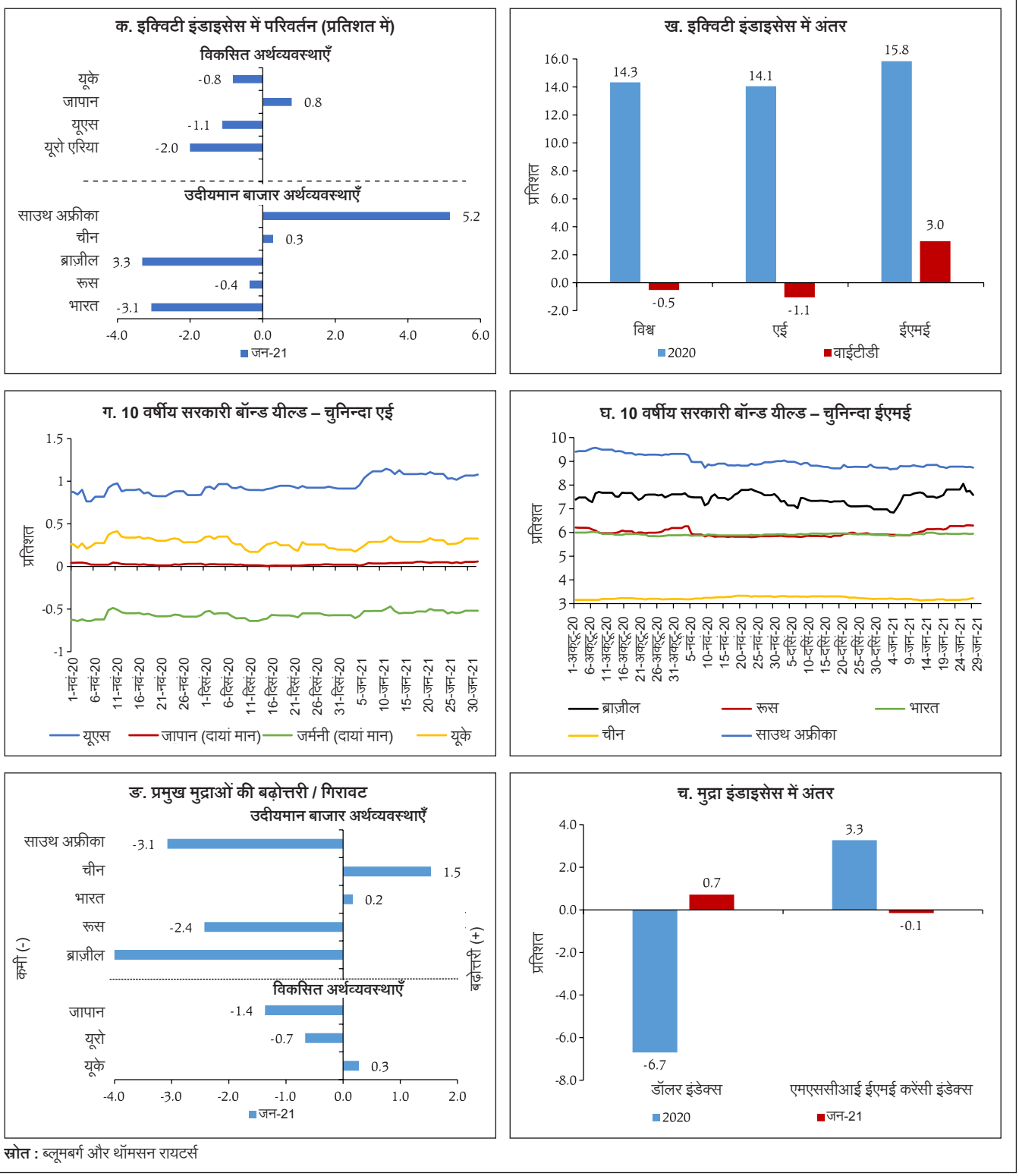

स्रोत : ब्लूमबर्ग और थॉमसन रायटर्स

महीने को समाप्त कर दिया। सेफ हैवेन परिसंपत्तियों की मांग में कमी के साथ, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बांड यील्ड कठिन हो गई, मार्च 2021 में पहली बार मार्च 2020 के बाद से 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड 1.0 प्रतिशत से अधिक हो गई। दूसरी ओर, उभरते बाजार में बॉन्ड यील्ड ने अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में मिश्रित गति का प्रदर्शन किया, जो देश-विशिष्ट कारकों को दर्शाता है। मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी डॉलर जो 2020 में काफी कमजोर हो गया था, जनवरी में प्रमुख एई मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ, जो कि 0.7 प्रतिशत की बढ़त के साथ था। इसके अलावा, जनवरी में एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स (एमएससीआई-एम) इंडेक्स में 0.1 फीसदी की गिरावट आई, हालांकि कैपिटल इनफ्लो के चलते भारतीय रुपया और चीनी युआन मजबूत हुआ।

मौद्रिक नीति के मोर्चे पर, जनवरी 2021 (चार्ट 8) में ब्याज दरों पर यथास्थिति रखने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अत्यधिक व्यवस्थित बने हुए हैं । तुर्की, एकमात्र अपवाद, जिसने जनवरी 2021 में एक ठहराव बनाए रखने से पहले संचयी 875 आधार अंकों की दर से सितंबर 2020 के बाद से तीन चरणों में दरों को बढ़ाया है। ब्राजील के केंद्रीय बैंक ने अपनी जनवरी की बैठक में एक ठहराव बनाए रखा, लेकिन आगे दिए गए मार्गदर्शन को वापस ले लिया

चार्ट 8 : पॉलिसी रेट एक्शन – चुनिन्दा केंद्रीय बैंक

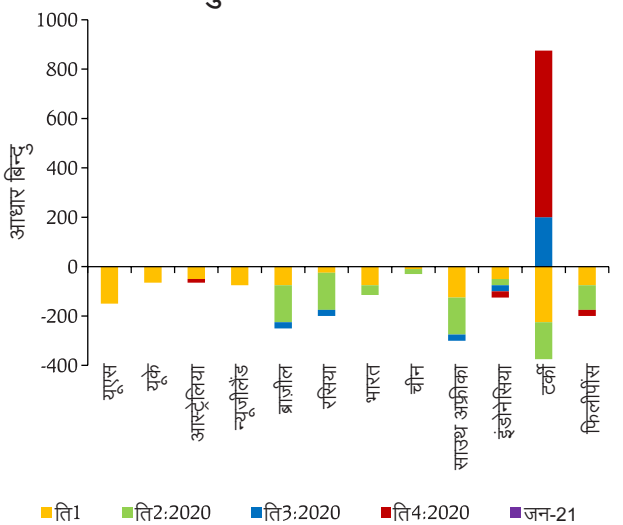

स्रोत : केंद्रीय बैंक वेबसाइट

जो इसने अगस्त 2020 में मुद्रास्फीति की उम्मीदें और अनुमान लक्ष्य के करीब पहुंचने पर दिया था। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह कहा कि आगे के मार्गदर्शन को हटाने से ब्याज दर में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि विकास के संबंध में मौजूदा अनिश्चितताओं को असाधारण रूप से मजबूत मौद्रिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। राजकोषीय मोर्चे पर, दिसंबर 2020 तक वैश्विक स्तर पर कुल वित्तीय सहायता 14 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (आईएमएफ़, फिस्कल मॉनीटर अपडेट) या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 13.5 प्रतिशत थी, जिसमें से 7.4 प्रतिशत राजस्व अग्रिम सीमा के रूप में था। अतिरिक्त खर्च और चलनिधि समर्थन के रूप में 6.1 प्रतिशत, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ऋण, गारंटी और इक्विटी इंजेक्शन शामिल हैं।

III. घरेलू विकास

भारत में, कोविड -19 की घटनाओं में कमी आने के कारण आर्थिक गतिविधियाँ समाप्त हो रही हैं और चल रहे वैक्सीन रोलआउट ने छुपा हुआ आशावाद दर्शाया है। संकेतकों से प्राप्त जानकारी सामान्यीकरण की तेज गति से जुड़ी है। 31 जनवरी, 2021 तक भारत की साप्ताहिक कोविड -19 की मृत्यु दर 1000 से नीचे चली गई, जो पिछले 8 महीनों में सबसे कम थी। दोहरीकरण दर [4] घटकर 578.3 दिन हो गई, सक्रिय मामलों में कुल मामलों का सिर्फ 1.4 प्रतिशत हिस्सा था। वास्तव में, 31 जनवरी, 2021 को सक्रिय मामलों की संख्या 1.7 लाख से नीचे चली गई थी। ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,05,34,505 हो गई है, जिससे ठीक होने की दर 97.0 प्रतिशत से अधिक हो गई है। फरवरी के मध्य से, हालांकि, कोविड -19 मामलों में उछाल आया है, जिसके परिणामस्वरूप दोहरीकरण दर 600 दिनों से कम हो गई है और सक्रिय मामले 27 फरवरी, 2021 तक 1.6 लाख अंक से अधिक है। भारत में उन लोगों में फिर से संक्रमण हो सकता है, जो पहले से ही एंटी-बॉडी विकसित कर चुके हैं।

जैसे कि दुनिया भर में टीकाकरण की गति तेज हो रही है, कोविड -19 टीकाकरण की कुल संख्या ने भारत सहित विश्व स्तर पर (चार्ट 9 ए) कोविड 19 के कान्फर्म्ड मामलों की संख्या

[4] दोहरीकरण दर को ln2 / ln (1 + r) के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां r संचयी मामलों में वृद्धि के पिछले सात दिनों का औसत है।

चार्ट 9 : कोविड 19 वैक्सीन अपडेट

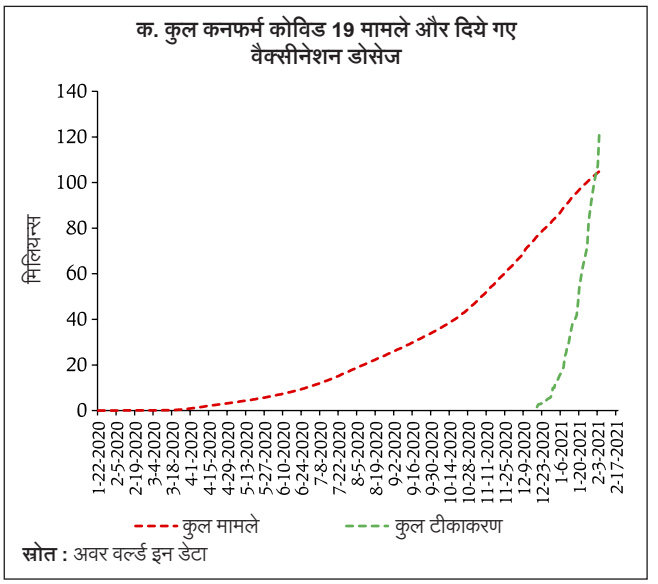

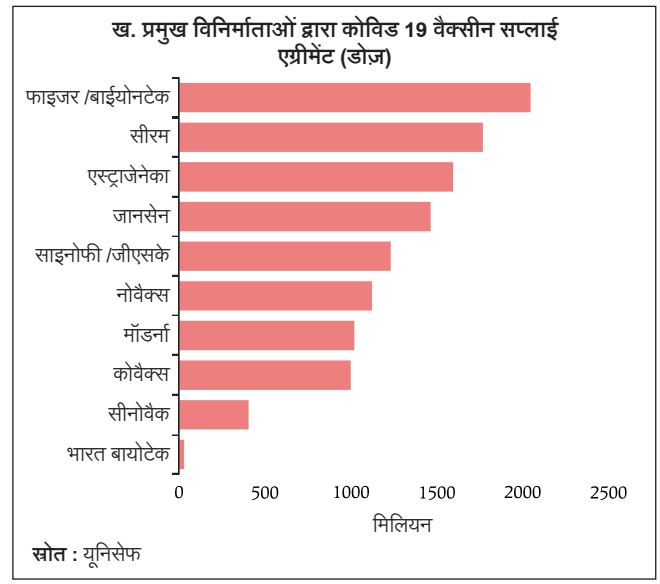

को पार कर लिया है। वैक्सीन निर्माण में भारत वैश्विक अग्रणी होने के साथ, कई घरेलू वैक्सीन निर्माताओं ने मौजूदा बुनियादी ढांचे, विदेशी सहयोग और एक कुशल श्रम शक्ति (चार्ट 9 बी) का लाभ उठाकर कई देशों / एजेंसियों के साथ आपूर्ति समझौते किए हैं। "वैक्सीन मैत्री " पहल के तहत, अन्य विकासशील देशों के लिए पहल का विस्तार करने की योजना के साथ, पड़ोसी देशों को नि: शुल्क वैक्सीन की आपूर्ति की गई है। कई अन्य देशों ने भारतीय फार्मा फर्मों से टीके आयात करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया है, जिससे लागत प्रभावी तरीके से बड़ी संख्या में खुराक के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ हुआ है।

गतिशीलता संकेतक बताते हैं कि जनवरी और फरवरी 2021 में सभी प्रमुख शहरों में लोगों की आवाजाही पूर्व-महामारी के स्तर (चार्ट 10) की तुलना की जा सकती है। जबकि किराने के सामान और फार्मेसियों के आसपास की गतिशीलता जनवरी 2020 के स्तर से ऊपर हो गई है, देश के कुछ हिस्सों में प्रचलित छुट्टियों और कठोर सर्दियों की स्थिति के कारण ट्रांज़िट स्टेशनों के आसपास गतिशीलता में कमी आई है। फरवरी 2021 में कार्यालयों में महामारी पूर्व के फुटफाल्स का स्तर 84 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो पिछले महीने (मिंट-ट्रैकर) में 82 प्रतिशत था। इसके साथ-साथ माल की आवाजाही काफी बढ़ गई, ई-वे बिल जनवरी में 10.5 प्रतिशत और फरवरी में 12.5 प्रतिशत बढ़ गया - अंतर-राज्य 13.0 प्रतिशत और 15.1 प्रतिशत: अंतर-राज्य 6.8 प्रतिशत और 8.8 प्रतिशत क्रमशः। उत्पाद और कारक गतिशीलता पूर्व-महामारी के स्तर पर तेजी से पहुँच गई और अर्थव्यवस्था में मांग में सुधार की गुंजाइश है।

कुल मांग

कुल मांग की स्थिति एक ऊंचे स्तर पर है। बिजली की चरम मांग 30 जनवरी को 189.6 गीगावाट तक पहुंच गई, जो 30 जनवरी को 189.6 गीगावाट तक पहुँच गया जिसने पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया। पांचवें और छठे क्रमिक महीनों के लिए जनवरी और फरवरी 2021 के माध्यम से बिजली की खपत का विस्तार जारी रहा, क्रमशः 4.8 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 11 ए)। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) की निर्धारित नीतियों के परिदृश्य (एसटीईपीएस) के अनुसार, जो 2021 में धीरे-धीरे नियंत्रण में लाया जाएगा, भारत की कुल ऊर्जा मांग 2010 से 2040 तक (चार्ट 11 बी) 124.7 प्रतिशत तक बढ़ने वाली है।

चार्ट 10 : मोबिलिटी इंडिकेटर्स

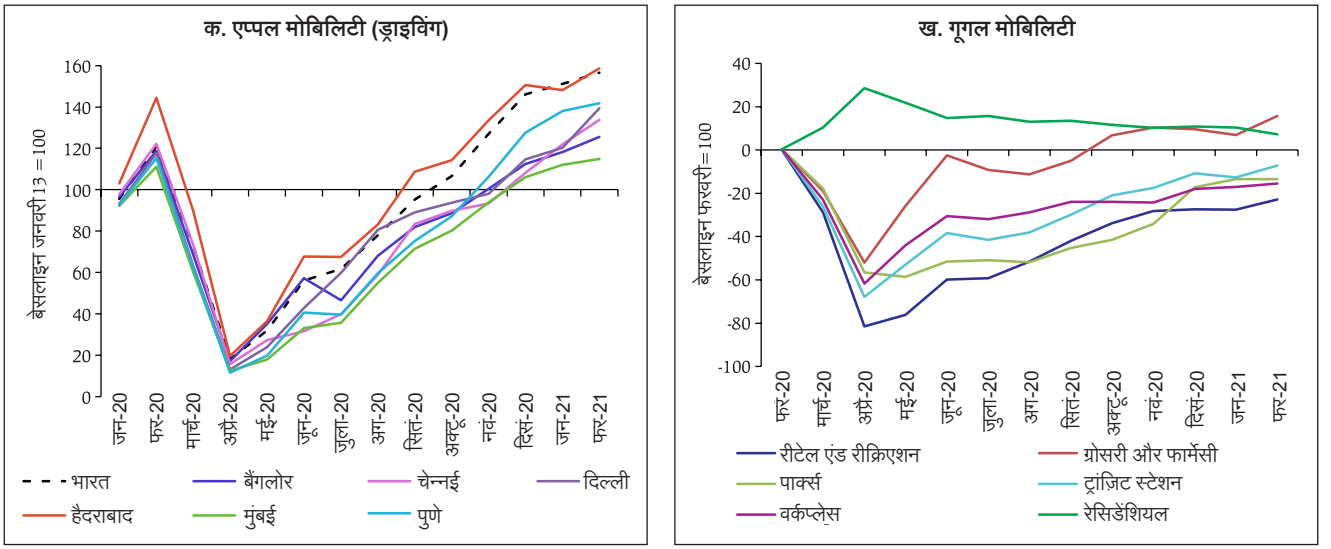

स्रोत : गूगल और सीईआईसी

माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत संग्रहण जनवरी 2021 में चौथे महीने के लिए 1 लाख करोड़ की सीमा से ऊपर 1,19,847 करोड़ पर रहा। 8.1 फीसदी की वृद्धि के साथ, जीएसटी ने श्रृंखला (चार्ट 12) में उच्चतम मासिक संग्रह दर्ज किया । यह बेहतर कर अनुपालन के अलावा त्यौहारी सीज़न से आगे बढ़ते व्यापार और व्यापारिक कारोबार को प्रतिबिंबित करता है। असंतुष्ट अंतर-राज्य और अंतर-राज्य विश्लेषण से पता चलता है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु हैं, जबकि गतिविधि मुख्य भूमि में कैच-अप मोड में रहती है जिसमें राजस्थान, दिल्ली, यूपी और हरियाणा (तालिका 2) शामिल हैं।

उपभोग की मांग की ओर रुख करते हुए, रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के जनवरी 2021 के राउंड में टीकाकरण के आरंभ होने के कारण उत्पन्न सकारात्मक माहौल परिलक्षित

चार्ट 11: इलेक्ट्रिसिटी डिमांड

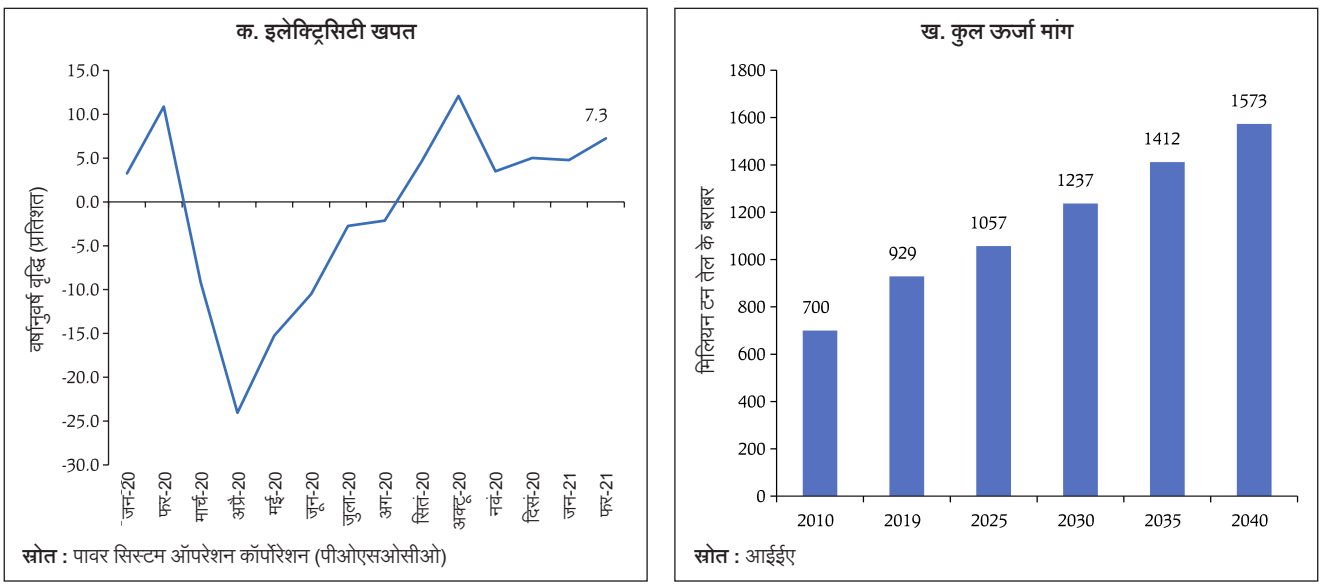

स्रोत : पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन (पीओएसओसीओ)

स्रोत : आईईए

चार्ट 12 : जीएसटी संग्रहण

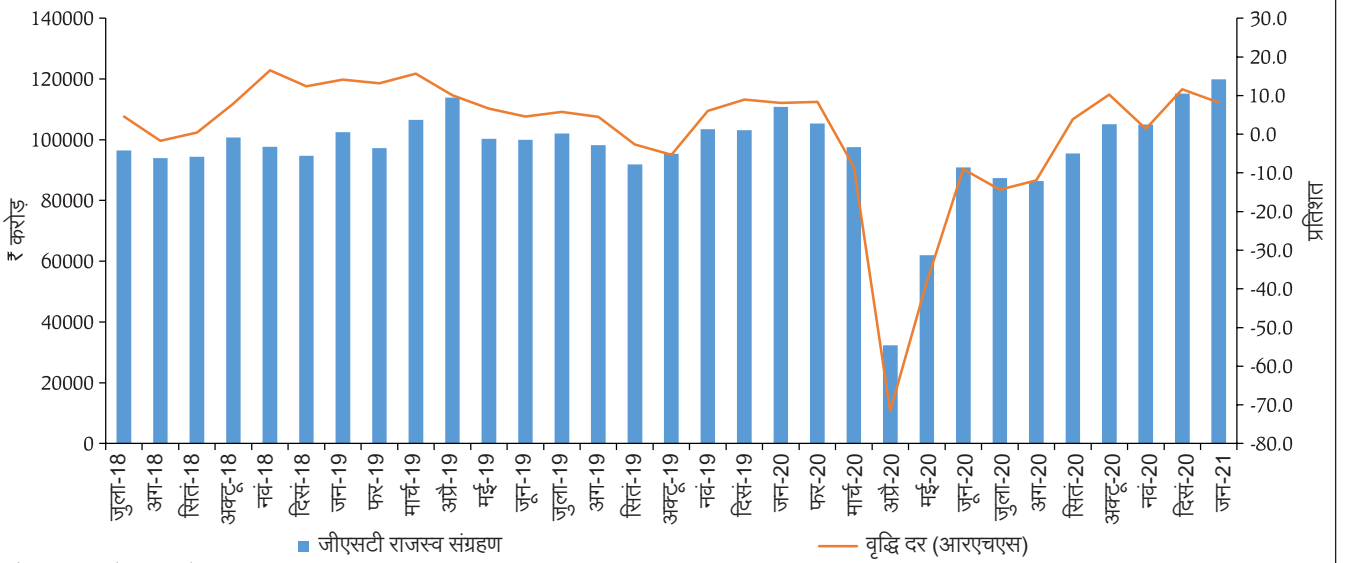

स्रोत : प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो

हुआ है। सितंबर 2020 से आयोजित सभी पूर्ववर्ती राउंड में धारणाओं में काफी सुधार हुआ है। आने वाले वर्ष के लिए, उपभोक्ताओं को सामान्य आर्थिक स्थिति और रोजगार की स्थिति में समग्र सुधार की उम्मीद है। जबकि आवश्यक चीजों पर खर्च करने में सुविधा है, गैर-जरूरी खर्च के बारे में अनिश्चितता बनी रहती है। तेजी से बढ़ती उपभोक्ता सामान (एफ़एमसीजी) कंपनियां बढ़ती गतिशीलता, आर्थिक गतिविधियों की बहाली, उपभोक्ता-प्रासंगिक नवाचारों और बाजार विकास में निवेश (चार्ट 13) की मांग में वृद्धि की रिपोर्ट कर रही हैं । अधिकांश कंपनियों ने विवेकाधीन खर्चों में भी सुधार का अनुभव किया है जो गैर-टिकाऊ वस्तुओं की मांग में वृद्धि दर्शाता है। नील्सन इंडिया के अनुसार, स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में नए लॉन्च किए गए हैं, जिसमें प्रतिरक्षा एक 'न्यून नॉर्मल' के रूप में ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें हैंड सैनिटाइटर, फर्श क्लीनर, शौचालय क्लीनर और एंटीसेप्टिक लिक्विड जैसी श्रेणियां शामिल हैं। इन नए लॉन्च ने कोविड -19 अवधि में सभी नए लॉन्च के लिए मूल्य के संदर्भ में

सारणी 2 : ई वे बिल वृद्धि

	इंटर स्टेट (प्रतिशत में)									अंतर राज्य (प्रतिशत में)									
	अप्रै-20	मई-20	जून-20	जुला-20	अग-20	सितं-20	अक्टू-20	नवं-20	दिसं-20		अप्रै-20	मई-20	जून-20	जुला-20	अग-20	सितं-20	अक्टू-20	नवं-20	दिसं-20
तेलंगाना	-87	-59	-5	0	-5	16	27	18	32	तेलंगाना	-53	-15	27	27	23	47	41	39	33
पश्चिम बंगाल	-92	-74	-22	-20	-27	2	14	7	30	मध्य प्रदेश	-82	-34	19	30	33	47	37	20	27
तमिलनाडु	-92	-66	-35	-23	-13	-2	32	10	23	पश्चिम बंगाल	-76	-52	6	8	6	18	35	18	27
आंध्र प्रदेश	-83	-57	-9	-7	0	15	28	9	23	तमिलनाडु	-88	-54	-26	-16	-7	11	21	5	24
गुजरात	-89	-66	-28	-16	-11	13	28	1	15	आंध्र प्रदेश	-65	-30	8	6	6	21	19	16	22
महाराष्ट्र	-90	-68	-33	-24	-16	-4	11	7	14	कर्णाटक	-77	-35	1	-8	2	19	25	16	17
कर्णाटक	-91	-62	-17	-18	-7	0	14	3	13	पंजाब	-82	-32	13	22	23	22	23	11	16
पंजाब	-88	-52	-5	8	3	4	21	13	13	उत्तरप्रदेश	-78	-46	-3	2	-4	10	17	3	14
मध्य प्रदेश	-91	-62	-15	-3	0	12	27	12	11	गुजरात	-81	-50	-12	-2	1	18	36	7	14
राजस्थान	-93	-68	-19	0	4	6	19	6	10	दिल्ली	-82	-62	-25	-13	-11	0	8	0	14
हरियाणा	-90	-63	-18	-5	-4	7	21	9	10	महाराष्ट्र	-85	-60	-23	-19	-7	7	17	6	12
उत्तरप्रदेश	-91	-69	-10	-1	-4	0	18	10	8	हरियाणा	-91	-66	-20	-5	6	15	29	7	11
दिल्ली	-90	-74	-37	-21	-21	-12	4	-2	6	राजस्थान	-81	-40	2	12	7	12	16	3	8

स्रोत : सीईसी

चार्ट 13 : एफ़एमसीजी वैल्यू ग्रोथ

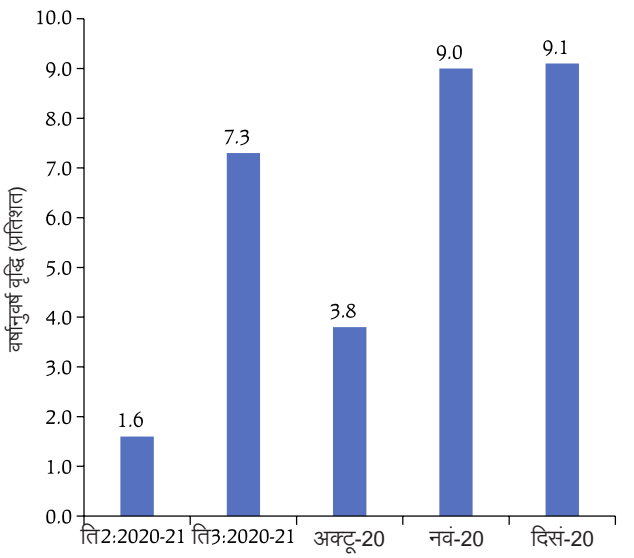

स्रोत : एसी नेल्सन

37 प्रतिशत का योगदान दिया। बड़ी एफएमसीजी कंपनियों के विज्ञापन / प्रचार खर्च पूर्व-महामारी स्तरों से अधिक थे। यात्री वाहनों के संबंध में, थोक बिक्री ने जनवरी 2021 में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले महीने में यह 13.6 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्र ने जून 2020 से ट्रैक्टरों की बिक्री में परिलक्षित होने वाली स्थिरता का प्रदर्शन किया है। लगातार 19 महीनों तक संकुचन में रहने के बाद, मोटरसाइकिल की बिक्री अगस्त 2020 में बढ़ गई और यह जनवरी 2021 में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए स्थिर बनी हुई है। 2021 जनवरी में रेलवे द्वारा किए गए माल ढुलाई में 8.7 प्रतिशत का विस्तार हुआ, जबकि माल ढुलाई से होने वाली कमाई में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो माँग में प्रतिक्षेप के निरंतर स्थानिक विस्तार को रेखांकित करती है। ऑनलाइन खरीदारी की ओर उपभोक्ताओं के बीच एक बोधगम्य बदलाव भी आया है। एक यूनीकामर्स -कीरनी की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 की आखिरी तिमाही (अक्टूबर - दिसंबर) में क्रमशः ऑर्डर वॉल्यूम और ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (जीएमडबल्यू) के मामले में 36 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। सबसे बड़े लाभार्थी व्यक्तिगत देखभाल, सौंदर्य और कल्याण उत्पाद थे।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के घरेलू सर्वेक्षण में पाया गया है कि रोजगार की स्थिति जनवरी 2021 तक सुधरी है, जिसमें औसत रोजगार दर एक महीने पहले 36.9 प्रतिशत से बढ़कर 37.9 प्रतिशत थी। रियल एस्टेट, निर्माण और सेवाओं जैसे क्षेत्रों, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान रोजगार के नुकसान का सामना करना पड़ा है, जाहिर तौर पर पूर्व-कोविड स्तरों पर वापस आ गए हैं। नतीजतन, जनवरी 2021 में औसत बेरोजगारी दर घटकर दिसंबर 2020 (चार्ट 14) में 9.1 प्रतिशत हो गई । सुधार की गति शहरी क्षेत्रों की

चार्ट 14 : रोजगार और बेरोजगारी दर

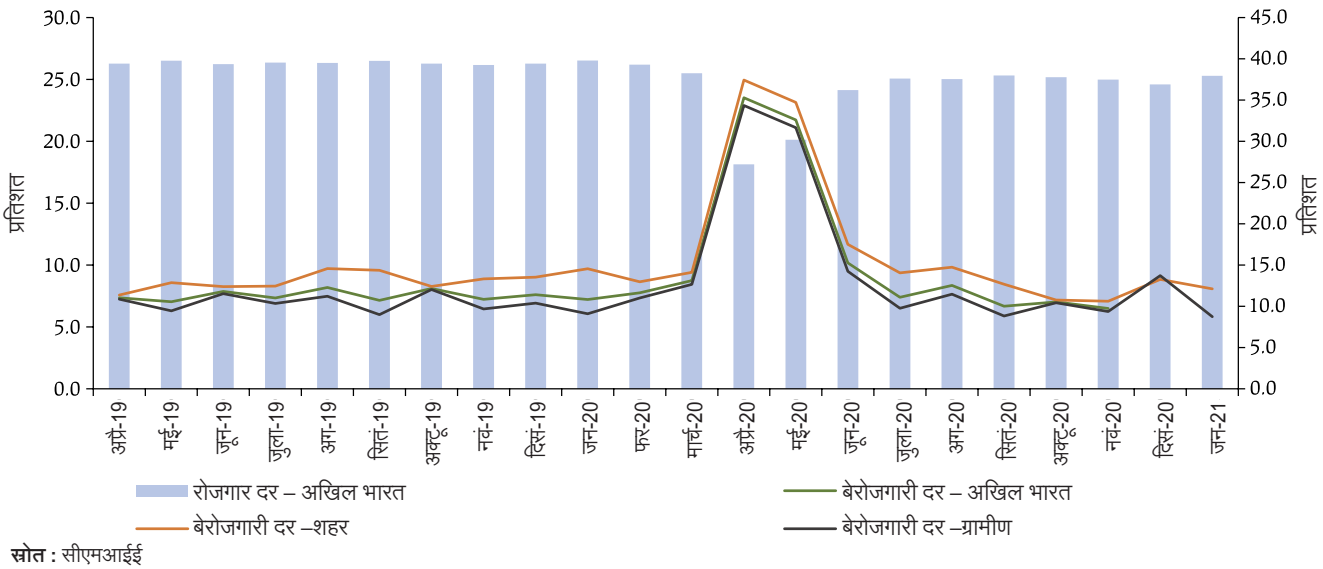

स्रोत : सीएमआईई

तुलना में ग्रामीण रोजगार के मामले में अधिक मजबूत थी, जो बताता है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था जल्द ही कोविड-19 की दुर्बलतापूर्ण प्रतिबंधों को दूर कर रही है। वास्तव में, 5.8 प्रतिशत पर ग्रामीण बेरोजगारी दर जुलाई 2018 के बाद से सबसे कम है। हालांकि पिछड़ा हुआ शहरी रोजगार अब ठीक हो रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत रोजगार महामारी के दौरान लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ। तथापि, हाल ही में मनरेगा के तहत नौकरियों की मांग में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो वर्षानुवर्ष दिसंबर में 56.5 प्रतिशत से घटकर जनवरी में 37.3 प्रतिशत और फरवरी में 18.8 प्रतिशत हो गई (अब तक) जो अन्य गतिविधियों में बेहतर रोजगार के संकेत हैं। एक्स्फ़ीनों के एक्टिव जॉब आउटलुक सर्वे के अनुसार जनवरी में कुल नौकरियों के अवसर पर एक महीने पहले से लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एंट्री लेवल जॉब्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर ने इन जॉब ओपनिंग में सबसे ज्यादा योगदान दिया है।

बाहरी एनेमिक वातावरण को चुनौती देते हुए, भारतीय व्यापारिक निर्यातों में सतत वृद्धि परिलक्षित हुई, जो जनवरी 2021 में 6.2 प्रतिशत (वर्षानुवर्ष) से बढ़ रहा था - विस्तार का लगातार दूसरा महीना। निर्यात में पिक-अप व्यापक आधारित रहा है, जो दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और लौह अयस्क के निर्यात के मजबूत प्रदर्शन द्वारा समर्थित है। एक अच्छा विकास यह है कि गैर-तेल निर्यात में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो लगातार पांचवें महीने के विस्तार (चार्ट 15 ए) को चिह्नित करता है। कुल मिलाकर, 30 प्रमुख वस्तुओं में से 22 या कुल निर्यात के 71.3 प्रतिशत समग्र निर्यात वृद्धि (चार्ट 16) में प्रमुख था। हाल के महीनों में, भारत एशियाई साथियों में एक व्यापक स्वैथ में शामिल हो गया है, जिसने इस क्षेत्र को महामारी के बाद निर्यात बहाली के मामले में दूसरों से ऊपर उठा दिया है।

जनवरी 2021 में भारत के माल आयात में लगातार दूसरे महीने 2.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो स्थायी (चार्ट 15 बी) हो रही घरेलू अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित विकास आवेगों की बढ़ती ताकत का प्रमाण है । लंबे समय तक संकुचन से बाहर आयात में छूट भी 30 प्रमुख वस्तुओं में से 18 के साथ व्यापक आधारित रही है या कुल आयात का 60.7 प्रतिशत विस्तार दर्ज किया है। हालांकि वर्षानुवर्ष तेल आयात में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण गिरावट रही, गैर-तेल गैर-सोने के आयात में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोती और कीमती पत्थर शीर्ष तीन उच्च विकास आयात किए जाने योग्य वस्तुए थीं, अनिवार्य रूप से घरेलू अंतिम उत्पादन और निर्यात में मध्यवर्ती थे।

चार्ट 15 : इंडियाज़ मर्चेंडाइज़ ट्रेड

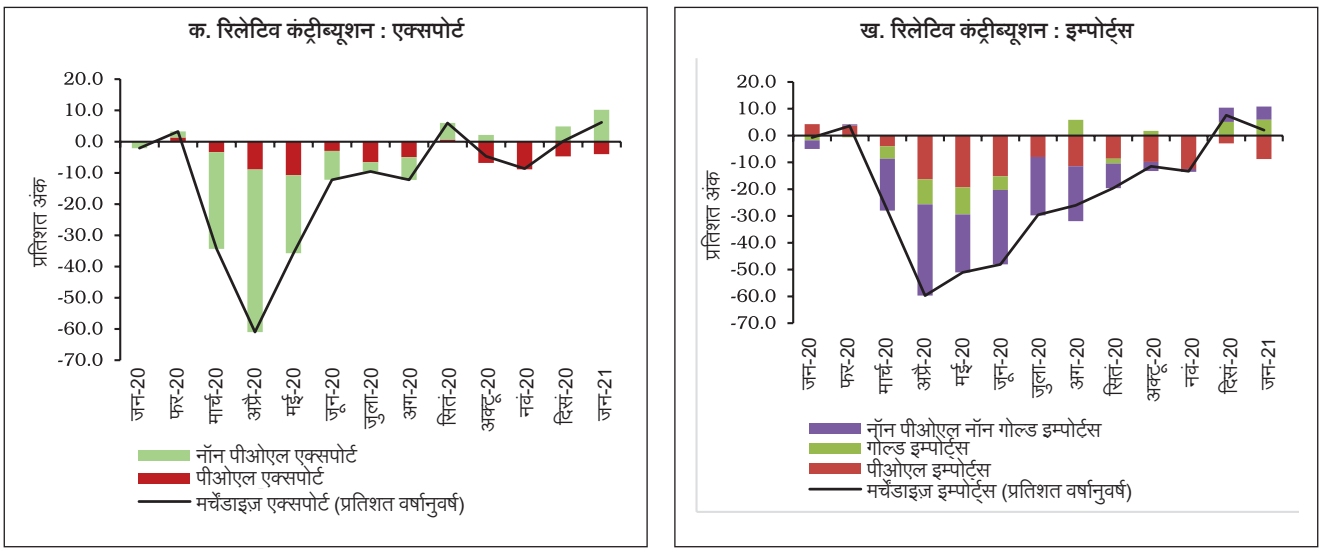

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस

चार्ट 16 : रिकवरी प्रोसेस एक्रोस सेक्टर्स – कनवरजेंस टू लोंग टर्म एवरेज

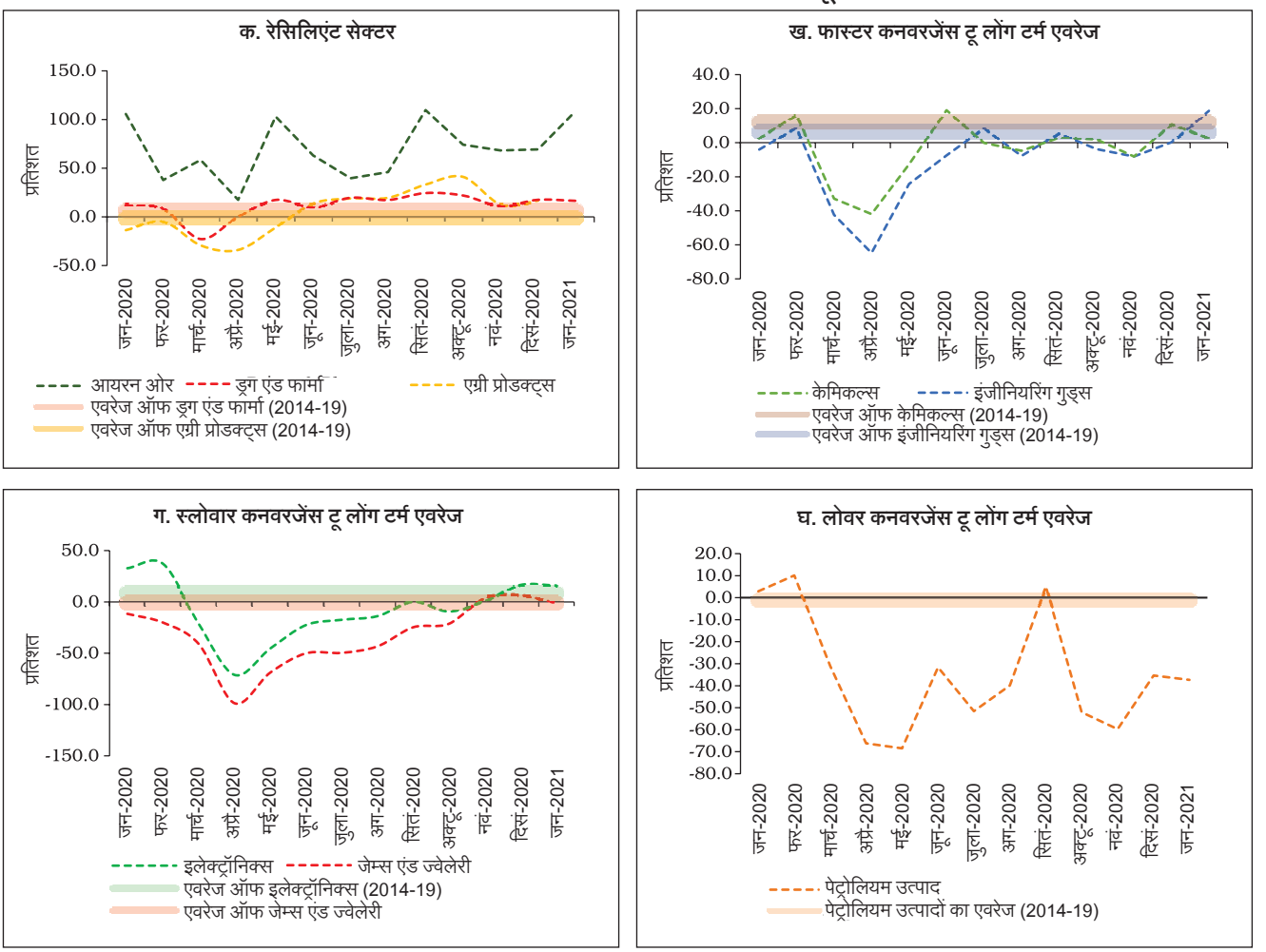

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस और लेखक की गणना

भारत के कृषि निर्यात में पिछले आठ महीनों में प्रभावशाली वृद्धि हुई है, यानी, कोविड -19 के बावजूद, मई 2020 से लगातार, अनाज निर्यातों में एक शानदार प्रदर्शन के साथ। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, विशेषकर गैर-बासमती किस्मों का। कोविड -19 प्रेरित लॉकडाउन का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय देशों में घरों में चावल के स्टॉक के कारण अंतरराष्ट्रीय मांग मजबूत हुई है, वियतनाम और थाईलैंड सहित अन्य प्रमुख निर्यातक आपूर्ति की गड़बड़ी से प्रभावित हुए हैं। गेहूं के संबंध में, यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट (यूएसडीए) ने 14 जनवरी 2021 को 1 मिलियन टन के अपने पहले के अनुमान के अनुसार, 2020-21 (जुलाई-जून) के लिए भारतीय गेहूं निर्यात के पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए 1.8 मिलियन टन (मीट्रिक टन) कर दिया है। 2020-21 में 3-4 मीट्रिक टन तक के निर्यात की संभावना वाले उद्योग प्रतिनिधियों के साथ। अगर देखा जाए, तो यह पिछले छह वर्षों में गेहूं का सबसे अधिक निर्यात होगा।

खाद्य प्रसंस्करण एक उदीयमान निर्यात क्षेत्र है जिसमें कृषि के साथ मजबूत संबंध हैं और यह उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत आता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हमारे निर्यात प्रोफ़ाइल को कम-मूल्य वाले कच्चे माल के निर्यात एकाग्रता से उच्च-मूल्य वाले संसाधित माल निर्यात विशेषज्ञता में बदल सकता है। जैसा कि खाद्य प्रसंस्करण एक पूंजी-गहन उद्योग है, इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करना गेम चेंजर हो सकता है।

एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार माहौल और संरक्षणवाद के बढ़ते ज्वार के अलावा, भारत का विदेशी व्यापार वर्तमान में विकट तार्किक चुनौतियों का सामना कर रहा है। कोविड -19 प्रेरित व्यवधानों और कंटेनरों की जमाखोरी के बाद कंटेनर माल की कीमतों में निरंतर वृद्धि ने निर्यातकों (चार्ट 17 ए) पर उच्च लागत लगाई है। वर्तमान में, भारत शिपिंग बेड़े (चार्ट 17 बी) के स्वामित्व के मामले में विश्व स्तर पर 18 वें स्थान पर है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में वैश्विक शिपिंग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय शिपिंग कंपनियों को समर्थन देने की योजना प्रस्तावित की गई है। इस प्रस्ताव से विदेशी संचालित शिपिंग कंपनियों पर भारतीय व्यापारियों की निर्भरता कम होने और कंटेनर उपलब्धता में आसानी होने की उम्मीद है।

आगे बढ़ते हुए, केंद्रीय बजट 2021-22 में सीमा शुल्क ड्यूटी स्ट्रक्चर के यौक्तिकीकरण पर प्रस्ताव, व्यापार सुगमता उपायों में सुधार, और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने पर इसका ध्यान (ईओडीबी) बुनियादी ढाँचे के लिए एक बड़े प्रोत्साहन के साथ मिलकर भारतीय विनिर्माण की संभावनाओं को अनलॉक करके निर्यात को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

केंद्रीय बजट ने व्यय के एक प्रमुख पुनर्मूल्यांकन के भीतर आत्म निर्भार भारत के विषय को आगे बढ़ाते हुए सुधार की रणनीति के लिए एक अलग निवेश-समर्थक फोकस प्रदान किया

सारणी 3: प्रमुख राजकोषीय संकेतक
(सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

	2019-20	2020-21		2021-22
	वास्तविक	बीई	आरई	बीई
1. सकल राजकोषीय घाटा	4.6	3.5	9.5	6.8
2. राजस्व की कमी	3.3	2.7	7.5	5.1
3. प्राथमिक कमी	1.6	0.4	5.9	3.1
4. सकल कर राजस्व	9.9	10.8	9.8	9.9
5. गैर-कर राजस्व	1.6	1.7	1.1	1.1
6. राजस्व व्यय	11.6	11.7	15.5	13.1
7. पूंजीगत व्यय	1.6	1.8	2.3	2.5
8. केंद्र सरकार ऋण	52.3	50.6	64.3	62.5

स्रोत: केंद्रीय बजट

है। 2010-20 के दौरान पूंजीगत व्यय जीडीपी के 2.5 प्रतिशत के औसत से 2021-22 में 1.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, यहां तक कि राजस्व व्यय को भी 2020-21 में अपने स्तर से जीडीपी के अनुपात के रूप में अनुबंधित करने के लिए निर्धारित है (आरई) (तालिका 3)।

2020-21 में सामान्य सरकारी खपत व्यय में तिमाही गतिविधियों से पता चलता है कि ति.3 में राजस्व व्यय पर नए सिरे से जोर दिया गया है, जो कि ति.4 में और बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि राज्यों को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में उच्च व्यय प्राप्त होता है। केंद्र के लिए, ति.4 में लगभग 110 प्रतिशत

चार्ट 17 : ग्लोबल फ्रेट इंडिकेटर्स

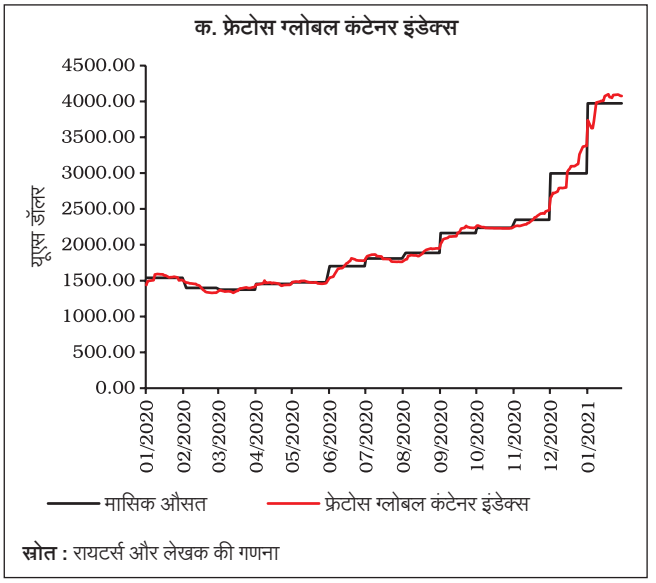

स्रोत : रायटर्स और लेखक की गणना

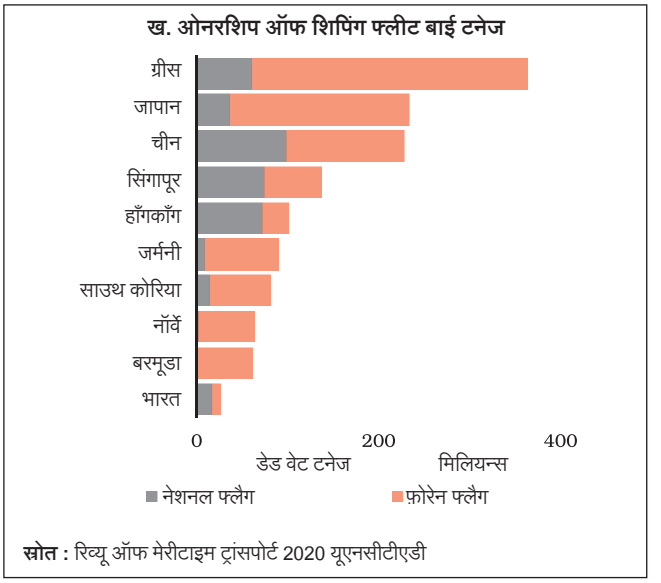

स्रोत : रिव्यू ऑफ मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2020 यूएनसीटीएडी

चार्ट 18: सरकारी व्यय में तिमाहीवार वृद्धि

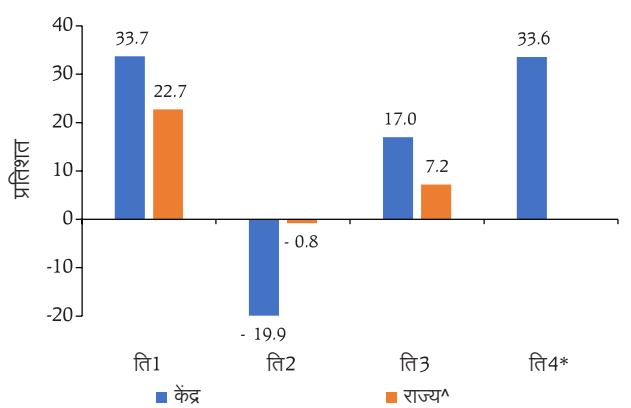

टिप्पणियाँ : * तिमाही 4 के लिए वृद्धि दर राज्यों के संबंध में उपलब्ध नहीं है और केंद्र के लिए यह संशोधित अनुमान 2020-21 के आधार पर ली गए है
^ सरकारी उपभोग व्यय में राजस्व व्यय शामिल है और इसमें ब्याज भुगतान और केंद्र के लिए मुख्य सब्सिडीज़ शामिल नहीं है और राजस्व व्यय में 23 राज्यों का ब्याज भुगतान शामिल नहीं है।
स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज़, कंट्रोलर जनरल ऑफ एकाउंट्स एंड कोम्प्ट्रोलर एंड आडिटर जनरल ऑफ इंडिया

चार्ट 19 : आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ एफ़सीआई फ्रम एनएसएसएफ़

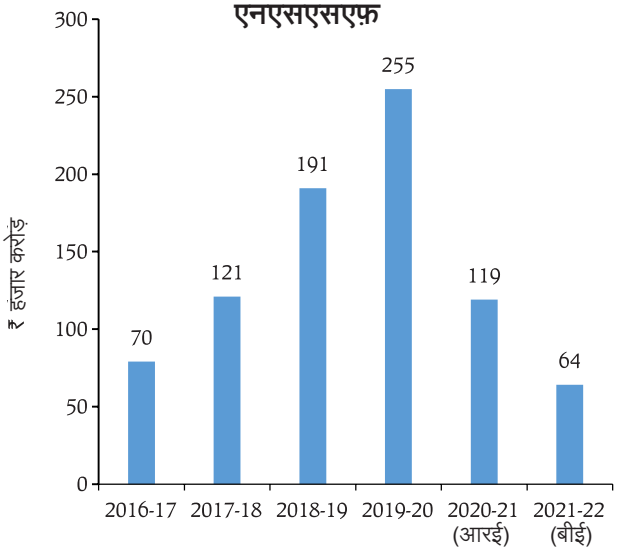

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज़

की राजस्व व्यय वृद्धि की परिकल्पना की गई है। हालांकि, इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण अनुपात सब्सिडी के बजट पर / पिछले बकाया की मंजूरी के कारण है; इसलिए राजस्व व्यय कम ब्याज भुगतान और प्रमुख सब्सिडी, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय का एक बेहतर संकेतक, ति. 4 (चार्ट 18) में 33.6 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है ।

निवेश के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन बेहतर अनुपालन के माध्यम से कर राजस्व की उछाल को बढ़ाकर (i) हासिल करना चाहता है; और (ii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) और सरकारी मंत्रालयों / विभागों के साथ अधिशेष भूमि सहित परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से प्राप्तियां जुटाकर । इसके अलावा, विनिवेश से प्राप्तियां रु. 1.75 लाख करोड़ हैं, जिसमें दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का निजीकरण शामिल है।

कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट मुद्रास्फीति विरोधी बने रहने की उम्मीद है। व्यय में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नेशनल स्मॉल सेविंग फंड (एनएसएसएफ़) से भारतीय खाद्य निगम (एफ़सीआई) द्वारा सब्सिडी के एवज में प्राप्त बकाया ऋणों के ऑन-बजट के कारण है, जो 2016-17 के बाद से चली आ रही प्रथा है (चार्ट 19)। वास्तव में, कुल व्यय में केवल 1 प्रतिशत का विस्तार होने का अनुमान है, राजस्व व्यय में 2.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। नए कृषि अवसंरचना विकास उपकर (एआईडीसी) के मुद्रास्फीति प्रभाव को पेट्रोल और डीजल के मामले में आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क और संघ उत्पाद शुल्क में कटौती / युक्तिकरण द्वारा काफी हद तक ऑफसेट किया जाता है।

जब केंद्र के सकल और शुद्ध बाजार उधार दोनों को एक साल पहले की तुलना में जीडीपी के संदर्भ में कम किया जाता है (चार्ट 20)।

सकल आपूर्ति

जनवरी 2021 के माध्यम से सकल आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ। रबी की बुआई का मौसम पूरा होने के साथ, फसल की बुआई 684.6 लाख हेक्टेयर में पूरी हो गई है - पिछले वर्ष की तुलना में 2.9 प्रतिशत अधिक और पूर्ण सीजन की सामान्य एकरेज (5-वर्ष की औसत) की तुलना में 10.4 प्रतिशत अधिक (तालिका 4)। यह आजादी के बाद सबसे अधिक बोया गया क्षेत्र है, जो एक और रिकॉर्ड उत्पादन के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

चार्ट 20 : केंद्र सरकार की बाजार उधारियाँ

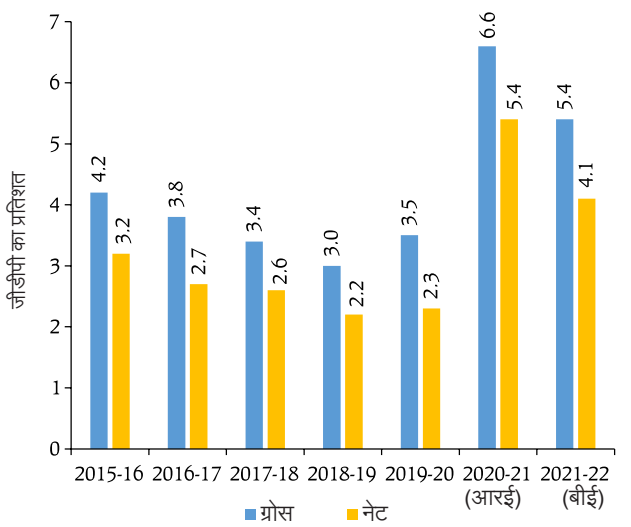

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज़

गेहूं के नीचे की कवरेज प्रभावशाली रही है, जो सामान्य बुवाई से 14.1 प्रतिशत अधिक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), पर्याप्त सिंचाई और अनुकूल मिट्टी की नमी की स्थिति जारी रखने की प्रतिबद्धता कृषि (चार्ट 21) के लिए अच्छी है । इंटररेग्नम में, अनाज का स्टॉक बफर मानदंडों से 3.9 गुना अधिक हो गया है।

चार्ट 21 : वर्तमान वर्ष के गेंहू के क्षेत्र का एक वर्ष पिछड़े हुए पब्लिक प्रोक्योरमेंट का को - मूवमेंट

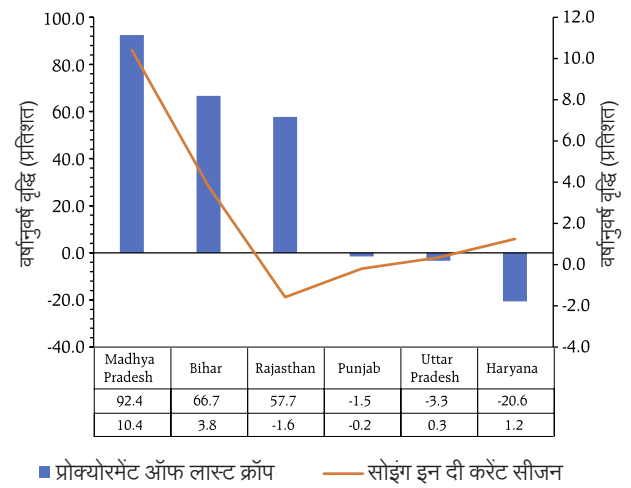

स्रोत : एमओएएफ़डबल्यू और एफ़सीआई

तालिका 4: अखिल भारतीय फसल स्थिति - रबी (2020-21)
29 जनवरी, 2021 को

(लाख हेक्टेयर में)

फसल का नाम	पूरे सीजन के लिए सामान्य क्षेत्र	तिथि के अनुसार बुवाई करें		सामान्य पूर्ण मौसम पर प्रतिशत भिन्नता
		इस वर्ष (2021)	पिछले साल (2020)	
1. गेहूँ	**303.3**	**346.4**	**336.4**	**14.2**
2. चावल	**41.8**	**35.2**	**30.2**	**-15.7**
3. मोटे अनाज	**57.1**	**51.7**	**56.1**	**-9.6**
ए. ज्वार	33.4	27.2	30.2	-18.6
बी. जौ	6.4	6.8	7.8	7.3
सी. मक्का	17.4	16.9	17.5	-2.5
4. कुल दालें	**144.9**	**167.4**	**162.9**	**15.5**
ए. ग्राम	92.8	112.0	107.3	20.7
बी. मसूर	14.2	16.5	16.1	16.2
सी. मटर	8.8	10.7	11.0	21.7
डी. कुल्थी (हॉर्स ग्राम)	2.2	3.9	5.2	79.7
इ. उड़द	8.9	8.1	7.5	-9.4
एफ. मूंग	9.9	6.6	6.7	-33.1
जी. लेथिरस	4.0	3.1	3.3	-21.8
I. कुल खाद्यान्न (1+2+3+4)	**547.1**	**600.6**	**585.6**	**9.8**
5. तिलहन	**73.2**	**84.0**	**80.0**	**14.7**
ए. रेपसीड एंड मस्टर्ड	59.4	73.9	69.1	24.4
बी. मूंगफली	7.3	4.8	4.8	-34.6
सी. सूरजमुखी	2.4	1.0	1.0	-56.9
डी. तिल	0.0	0.5	0.6	0.0
इ. कुसुम	1.2	0.6	0.6	-50.6
एफ. अलसी का बीज	2.7	2.9	3.5	6.9
सभी फसलें (1+2+3+4+5)	**620.3**	**684.6**	**665.6**	**10.4**

नोट: क्षेत्र के आंकड़े राज्य के कृषि विभागों के आंखों देखे आकलन के अनुसार हैं।
सामान्य क्षेत्र: 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान औसत क्षेत्र।
स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफ़डबल्यू)

तिलहनों के बीच, सरसों और रेपसीड ने इस साल बोए जाने वाले क्षेत्र के समंध में एक रिकॉर्ड दर्ज किया - सामान्य क्षेत्र की तुलना में 14.7 प्रतिशत अधिक। दालों के क्षेत्र में वृद्धि भी इस साल बेहतर उत्पादन का संकेत देती है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होती है।

कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रीय बजट का ध्यान, संबद्ध क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के साथ-साथ मत्स्य पालन और समुद्री शैवाल की खेती को प्रोत्साहन रोजगार बढ़ाकर और किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करके कृषि विकास को और अधिक बढ़ा सकता है। बजट में 'ऑपरेशन ग्रीन' को वर्तमान में कवर करने वाली 3 फसलों (प्याज,

टमाटर और आलू) से 22 खराब होने वाली वस्तुओं के विस्तार का प्रस्ताव है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, अत्यधिक मूल्य को कम करने और खराब कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) के लिए कृषि अवसंरचना कोष का विस्तार और पहले से ही विकसित 1,000 मंडियों के शीर्ष पर ई-एनएएम [5] के साथ अतिरिक्त 1,000 एपीएमसी मंडियों के एकीकरण से विपणन दक्षता को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे आने वाले वर्षों में बेहतर पहुंच और पारिश्रमिक रिटर्न वाले किसानों को लाभ होगा। बीमा में एफडीआई की सीमा में वृद्धि से किसानों और ग्रामीण बाजारों के लिए अधिक अनुकूल बीमा विकल्प लाने में सक्षम होने के लिए स्टार्ट-अप के लिए बाजार का विस्तार करने में मदद मिलनी चाहिए।

उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र (चार्ट 22) में बिक्री में तेजी के कारण नए ऑर्डर और आउटपुट में एक महीने पहले जनवरी 2021 में हेडलाइन विनिर्माण पीएमआई 56.7 से बढ़कर 57.7 हो गई । ति.3: 2020-21 में रिज़र्व बैंक के औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण (आईओएस) के 92 वें दौर के उत्तरदाताओं ने सकारतमकता को समाप्त कर दिया, जिसमें व्यापारिक उम्मीद सूचकांक लगातार दो तिमाहियों में उभर रहा था। विनिर्माणकर्ता आगे के महीनों में उत्पादन, ऑर्डर बुक और रोजगार को मजबूत करते हैं, जो व्यवसायों के अनलॉक और पुन: प्रारंभ द्वारा संचालित होते हैं। बैंकों और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से वित्त की उपलब्धता पर उनकी भावनाओं में सुधार हुआ। अगली तीन तिमाहियों में, अर्थात ति. 4: 2020-21 और 2021-22 की ति. 1 और ति. 2, फर्म मांग की स्थिति और रोजगार के संबंध में उत्साहित हैं।

सेवा क्षेत्र में, वसूली व्यापक-आधारित प्रतीत होती है। पीएमआई सेवाओं का विस्तार जनवरी 2021 में लगातार चौथे महीने (52.3 से एक महीने पहले) के लिए किया गया, जो नए काम और बढ़ी हुई व्यावसायिक गतिविधि द्वारा समर्थित है। मूल्य छूट, विपणन रणनीति, और कुछ दुकानों के फिर से खोलने के साथ-साथ समग्र मांग में बिक्री में वृद्धि हुई है। टीकाकरण अभियान के प्रकाश में, जनवरी 2021 में व्यावसायिक उम्मीदों में ग्यारह महीने के उच्च स्तर 59.0 पर सुधार हुआ। यह सुधार रिज़र्व बैंक की सेवाओं और बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण सर्वेक्षण (एसआईओएस) के 27 वें दौर में भी दिखाया गया था जो ति.3: 2020-21 में आयोजित किया गया था। फर्मों को ति.4: 2020-21 में कारोबार में और उन्नति की उम्मीद है।

चार्ट 22 : पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई)

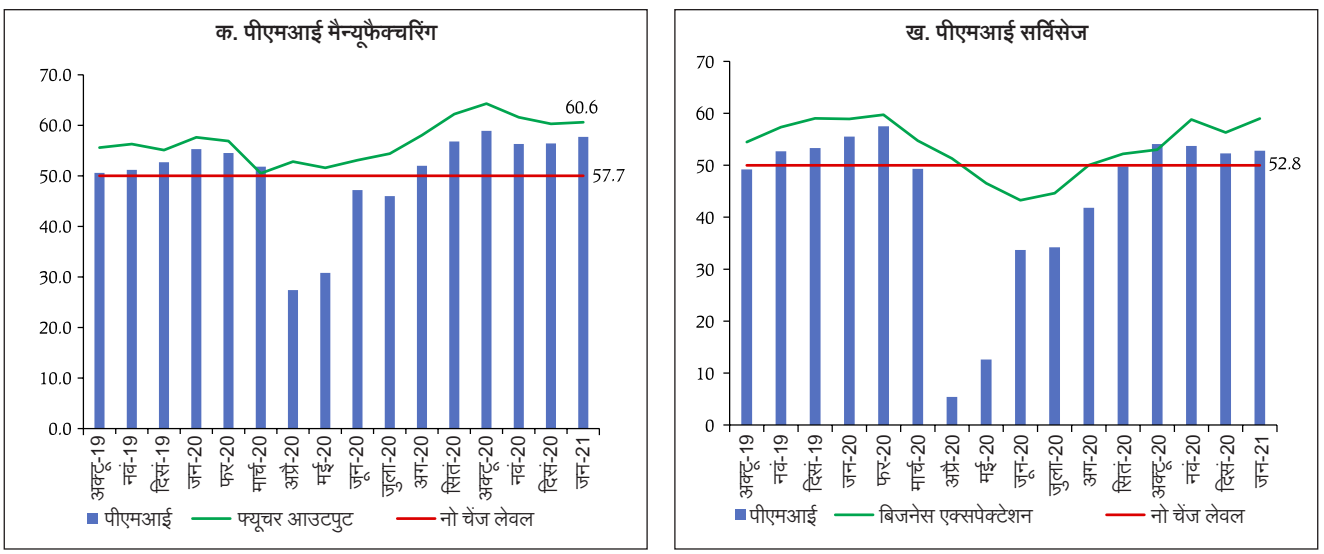

स्रोत : आईएचएस मार्केट

[5] राष्ट्रीय कृषि बाजार (ईनाम) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो मौजूदा एपीएमसी मंडियों को कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए नेटवर्क प्रदान करता है।

बिक्री मूल्य में वृद्धि की संभावना इनपुट लागत में वृद्धि की भरपाई होगी, जिससे लाभ मार्जिन बढ़ेगा।

सेवाओं की विशिष्ट श्रेणियों में, निर्माण गतिविधि गति प्राप्त कर रही है, इस्पात की बढ़ती खपत से यह स्पष्ट है, जनवरी 2021 में इसमें 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। सड़क परिवहन और महामार्ग मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2020-21 (अप्रैल-15 जनवरी) के दौरान 28.16 किलोमीटर की दूरी का दैनिक सड़क निर्माण किया गया, जो पिछले साल के 26.11 किलोमीटर से अधिक है। इसी अवधि के दौरान निर्माण के लिए प्रदान की गयी 7,573 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई भी दोगुनी हो गई। 15 जनवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान, 534 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गों की रिकॉर्ड लंबाई का निर्माण किया गया था। 31 मार्च तक 11,000 किलोमीटर निर्माण की गति का लक्ष्य बढ़ने की उम्मीद है, जिसके चलते चालू वित्त वर्ष के शेष महीने निर्माण गतिविधि के लिए अनुकूल हैं। राष्ट्रीय महामार्गों की निर्माण के लिए प्रदान की गई और निर्मित लंबाई की तुलना से यह संकेत मिलता है कि निर्माण के लिए प्रदान की गयी तथा निर्मित दोनों लंबाई में निर्मित लंबाई ने शुरुआती महीनों [6] में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बावजूद वृद्धि दर्ज की (चार्ट 23)।

रियल एस्टेट क्षेत्र में, दिसंबर 2020[7] को समाप्त तिमाही में नवीनतम रिलीज से संकेत मिलता है कि आवास में आठ तिमाहियों में पहली बार वृद्धि की शुरूआत हुई है, जिससे बाजार के मनोभाव तीन साल के उच्च स्तर [8] पर पहुंच गए है। रियल एस्टेट सेंटिमेंट्स इंडेक्स, जो 2020 की दूसरी तिमाही में अब तक के सबसे निचले स्तर तक गिर गया था, आवासीय इकाइयों और कार्यालय दोनों की मांग बढ़ने के कारण 2020 की चौथी तिमाही में आशा बढ़ी है। देश के पश्चिमी भाग में भावी मनोभाव सूचकांक में सबसे तेज उछाल निकट भविष्य में देश भर में और हितधारकों में आशावाद को दर्शाता है। 27 जनवरी को जारी नाइट फ्रैंक-फिक्की-नारेडको रियल एस्टेट सेंटीमेंट इंडेक्स सर्वेक्षण ने संकेत दिया कि रियल एस्टेट क्षेत्र अगले छह महीनों में तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है और उत्तर भारत की तुलना में "मनोभाव" पूर्व, दक्षिण और पश्चिम भारत में बहुत अधिक है। (चार्ट 24)।

महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्टांप शुल्क कम करने जैसे उपायों ने भी आवास की मांग को बढ़ावा देने में मदद की है। राज्यवार मासिक स्टाम्प और पंजीकरण राजस्व प्राप्तियां भी रियल एस्टेट क्षेत्र में एक स्थिर पिकअप की पुष्टि करता हैं (चार्ट 25) ।

चार्ट 23: राष्ट्रीय महामार्ग: अवार्ड और निर्माण

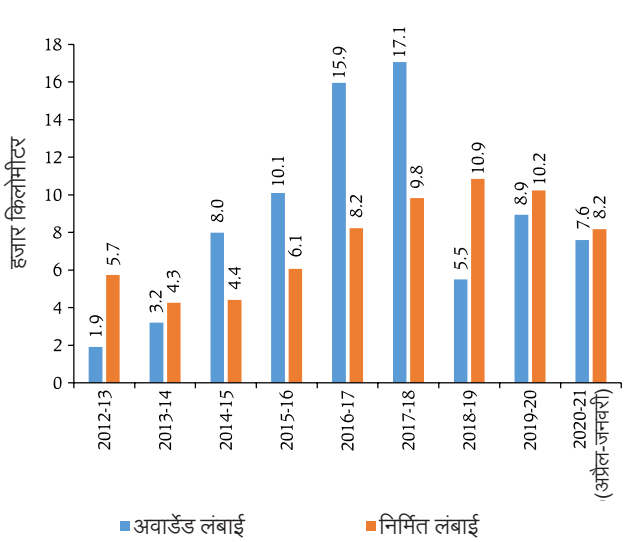

स्रोत: पीआईबी

चार्ट 24: रियल एस्टेट मनोभाव सूचकांक

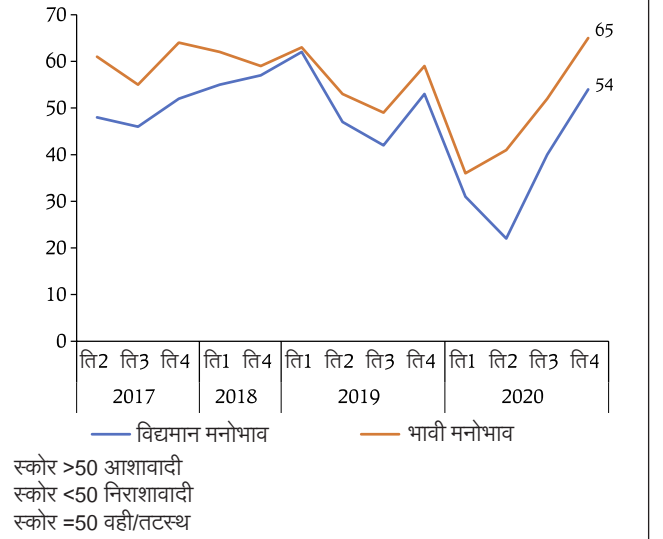

स्रोत: नाइट फ्रैंक - फिक्की नारेडको

[6] *https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1689402*

[7] प्रॉपटीगर डेटा रिलीज

[8] रियल एस्टेट मनोभाव सूचकांक- नाइट फ्रैंक, नारेडको और फिक्की

चार्ट 25: स्टाम्प तथा पंजीकरण राजस्व प्राप्तियां

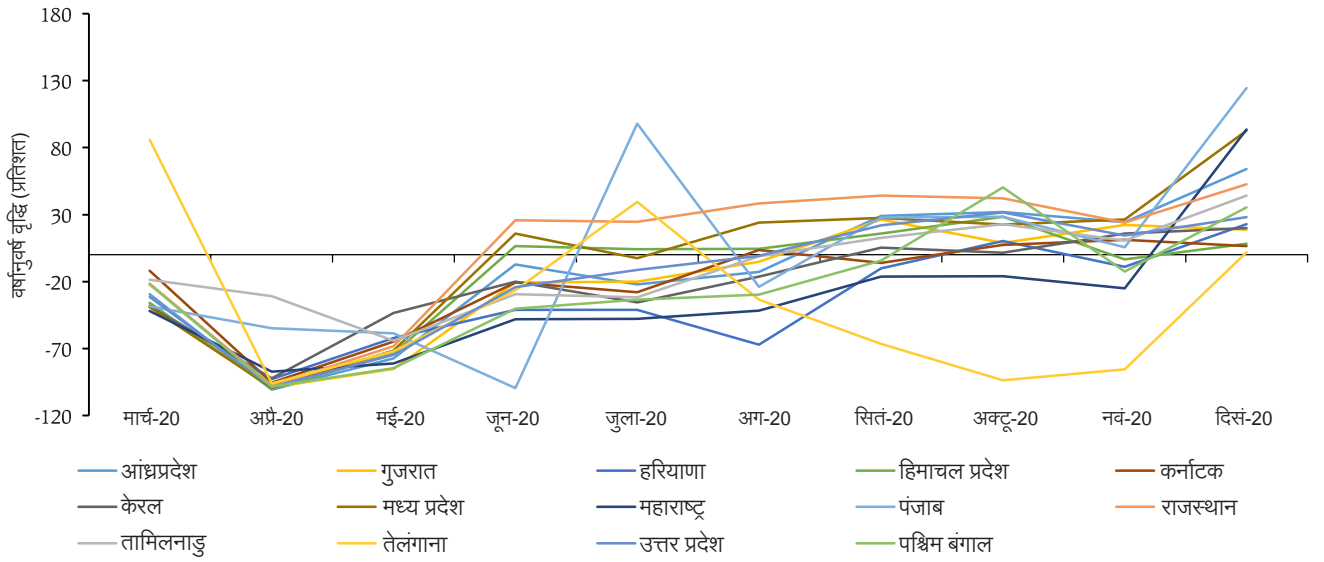

स्रोत: सीईआईसी

मुद्रास्फीति

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति में जनवरी 2021 में भी लगातार नरमी जारी रही, जो एक महीने पहले के 4.6 प्रतिशत से घटकर 4.1 प्रतिशत हो गई। इसके पीछे खाद्य मुद्रास्फीति में दिसंबर के 3.9 प्रतिशत में-120 आधार अंक (बीपीएस) की तीव्र गिरावट है (चार्ट 26 ए)। सब्जियों और चीनी की कीमतों में गिरावट, अनाज, अंडे, मांस, मछली, दूध, दाल और मसालों की कीमतों में गिरावट ने इस बहाली में पर्याप्त योगदान दिया। हालांकि, दिसंबर में ईंधन की महंगाई दर 2.9 प्रतिशत से घटकर 3.9 प्रतिशत हो गई, जो मुख्य रूप से एलपीजी मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण हुई। 5.5 प्रतिशत पर खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई स्वास्थ्य, पेट्रोल, डीजल, मोटर वाहनों,

चार्ट 26: सीपीआई मुद्रास्फीति

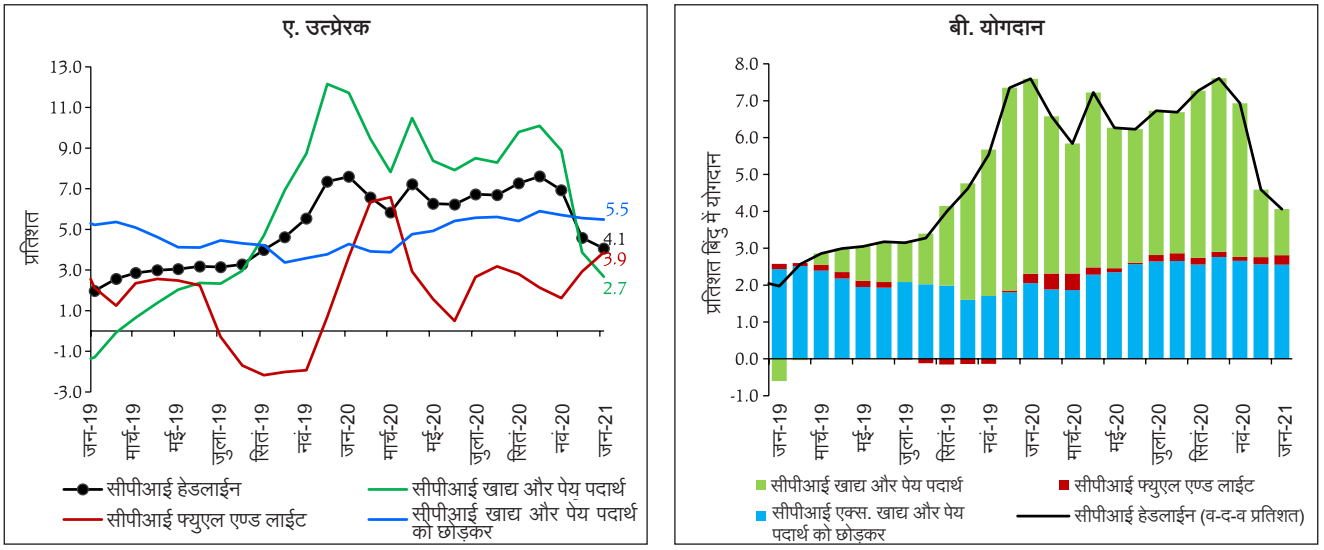

स्रोत: एनएसओ तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान

परिवहन किरायों और मनोरंजन सेवाओं में मूल्य दबाव जारी रहा। लॉकडाउन के पश्चात निजी देखभाल के सामान, सोना, पान, तंबाकू और नशिले पदार्थों की कीमतों के कारण दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति जारी रही। जहां कपड़ों में मुद्रास्फीति ज्यादा रही, वही आवास, घरेलू सामान तथा सेवाओं और शिक्षा में मुद्रा सफीति कम रही। खाद्य और ईंधन के अलावा सीपीआई ने (47.3 प्रतिशत भार के साथ) समग्र हेडलाइन मुद्रास्फीति में 63 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट 26 बी)।

उपभोक्ता मामलें, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामलें विभाग) से उच्च आवृत्ति खाद्य मूल्य डेटा फरवरी के लिए अब तक (1-12 फरवरी) अनाज और सब्जियों के संबंध में मूल्य दबावों में महीने-दर-महीने नरम होने का संकेत देते हैं। दालों की कीमतों में समान रूप से नरमी दर्ज की है, हालांकि अभी भी ऊंचे स्तर पर है। सब्जियों में, आलू और टमाटर की कीमतों में मौसमी गिरावट देखी गयी; यद्यपि, बेमौसम बारिश के कारण प्याज की कीमतों में तेजी आई है। फरवरी में खाद्य तेल की कीमतें और बढ़ गईं (चार्ट 27)।

भारतीय बास्केट कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई, जनवरी के 55 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से फरवरी में अब तक (1-12 फरवरी) 59 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल का औसत रहा। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि को प्रतिबिंबित करते हुए, पेट्रोल और डीजल के लिए पंप की कीमतें जनवरी के स्तर से अब तक फरवरी में लगभग ₹2 प्रति लीटर बढ़कर क्रमशः लगभग ₹90 प्रति लीटर और ₹81 प्रति लीटर हो गई हैं। मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष करों

चार्ट 27: डीसीए आवश्यक वस्तु कीमतें

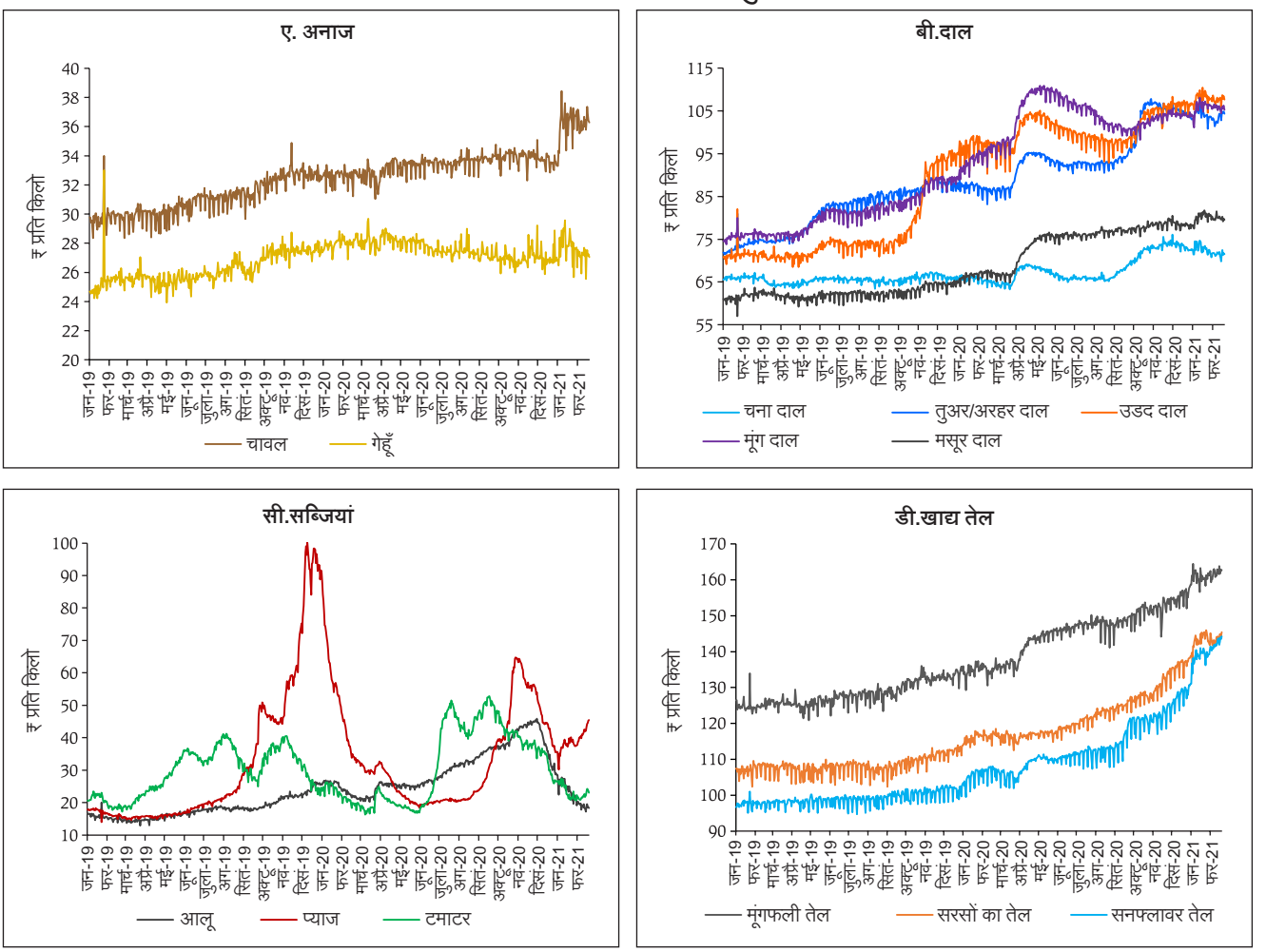

स्रोत: उपभोक्ता कार्य विभाग, भारत सरकार तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान

सारणी 5: पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें (चार प्रमुख महानगरों का औसत)

मद	युनिट	घरेलू कीमतें			महीना-दर महीना (प्रतिशत)	
		फर-20	जन-21	फर-21 ^	जन-21	फर-21
पेट्रोल	₹/लीटर	75.01	87.57	89.60	1.5	2.3
डीजल	₹/लीटर	67.35	78.97	81.11	1.8	2.7
केरोसीन	₹/लीटर	29.51	25.83	27.36	11.3	5.9
एलपीजी	₹/सिलेंडर	866.25	704.63	729.63	0.0	3.5

^: 1 -12 फरवरी 2021 की अवधि के लिए

टिप्पणी: चार प्रमुख महानगरों (चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता) में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा लगाए जाने वाले कीमतों का औसत।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

में बढ़ोतरी के कारण यह घरेलू पंप की कीमतों के लिए एक ऐतिहासिक उच्चांक है। घरेलू केरोसीन और एलपीजी की कीमतों में भी फरवरी 2021 में वृद्धि दर्ज की गई (सारणी 5)।

कच्चे तेल की कीमतें 2014 के मध्य में लगभग 110 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से गिरकर अप्रैल 2020 में लगभग 20 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के निचले स्तर पर आ गई थीं, जो जनवरी 2021 में 55 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ी थी (चार्ट 28ए)। इस अवधि के दौरान, अंतरराष्ट्रीय पेट्रोल की कीमतों (विनिमय दर [9] और शिपिंग लागत के लेखांकन के बाद) में भी लगभग ₹19 प्रति लीटर की गिरावट आई। हालांकि,पेट्रोल की पंप कीमतें (दिल्ली की कीमत) जुलाई 2014 के लगभग ₹ 74 प्रति लीटर से बढ़कर फरवरी 2021 की शुरुआत में ₹86 रुपये प्रति लीटर हो गई, लगभग प्रति लीटर ₹12 रुपये की वृद्धि है, जो पेट्रोल पर केंद्रीय करों में ₹23 रुपये प्रति लीटर और राज्य वैट (दिल्ली) में ₹8 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि के कारण है (चार्ट 28बी)। पेट्रोल पंप की कीमतों (दिल्ली) में उत्पाद शुल्क और वैट जुलाई 2014 के लगभग 30 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2021 की शुरुआत में 60 प्रतिशत हो गई। नतीजतन, समय के साथ, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के अनुरूप घरेलू पेट्रोल पंप की उच्च कीमतों में कमी आयी। सितंबर 2013 में कच्चे तेल की कीमत ₹80 रुपये प्रति लीटर थी, जो जून-अगस्त 2018 के दौरान 73 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल और जून 2020 में 41 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी। हेडलाइन मुद्रास्फीति में सीपीआई पेट्रोल (सीपीआई में 2.2 प्रतिशत भार के साथ) का प्रत्यक्ष योगदान जुलाई 2014 के1.6 प्रतिशत से जनवरी 2021 में 4.8 प्रतिशत हो गया।

चार्ट 28: पेट्रोलियम उत्पाद कीमतें

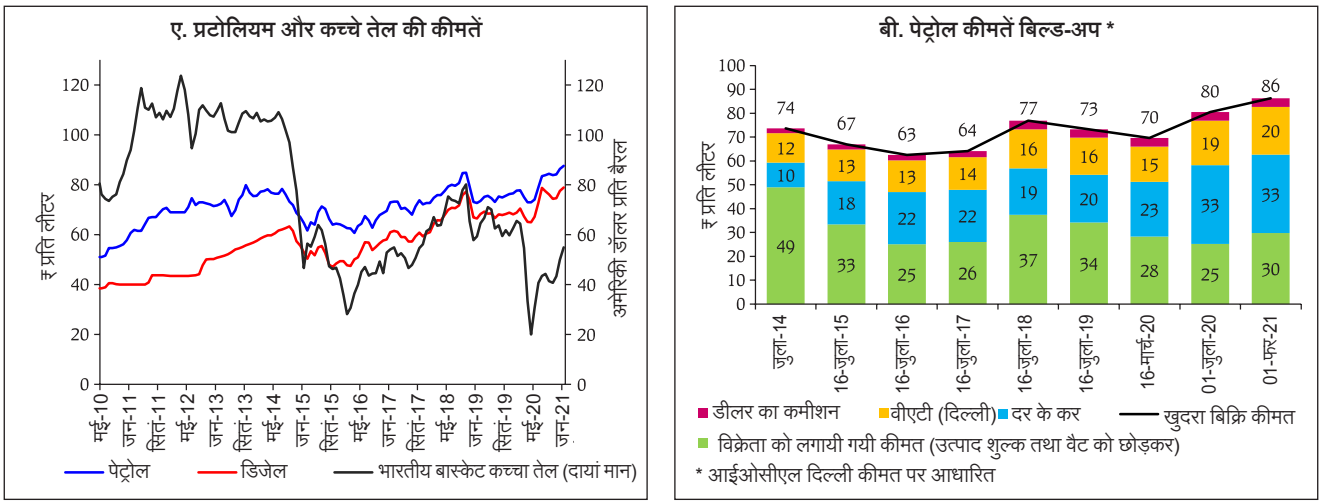

टिप्पणी: चार्ट 28 ए में दर्शायी गयि पेट्रोल और डीजल की कीमते चार प्रमुख महानगरों (चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता) में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा लगाए जाने वाले कीमतों का औसत।

स्रोत: पीपीएसी; आईओसीएल; ब्लुमबर्ग तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

[9] जुलाई 2014 में अमेरिकी डॉलर एक्सचेंज लगभग ₹ 60 प्रति अमेरिकी डॉलर था जो अप्रैल 2020 में लगभग ₹ 76 प्रति अमेरिकी डॉलर हुआ और उसके बाद जनवरी 2021 में लगभग ₹ 73 प्रति अमेरिकी डॉलर तक मूल्य वद्धि हुई।

आगे बढ़ते हुए, बंपर खरीफ फसल के साथ-साथ अच्छी रबी फसल की संभावना से अनाज मुद्रास्फीति पर काबू पा सकते हैं। रबी फसल की आवक शुरू होने के साथ ही प्याज के दाम भी बढ़ने शुरू हो सकते हैं। हालांकि, खाद्य तेल में देखा गया मूल्य दबाव अंतरराष्ट्रीय कीमतों में नरमी पर निर्भर है। महंगाई का दबाव और बढ़ने की संभावना है। मूल मुद्रास्फीति के दबाव के बने रहने की संभावना है क्योंकि लागतजन्य दबाव और तेज हो गया है। रिकॉर्ड स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ औद्योगिक कच्चे माल और अंतवर्ती की लागत में व्यापक वृद्धि, निवेश कीमतों में वृद्धि को फर्मों द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं तक बढ़ाने का खतरा है, खासकर जब तक आर्थिक बहाली में गति मिले और गतिविधियां पूर्व-कोविड स्तर तक सामान्य हो।

एक क्रॉस-कंट्री परिप्रेक्ष्य में, भारत ने 2010 के दशक की दूसरी छमाही में सबसे कम पास-थ्रू-आउट देखा था जब कच्चे तेल की कीमतों में काफी नरमी आई थी। लॉकडाउन के बाद अतिरिक्त करों के कारण, अंतरराष्ट्रीय पेट्रोल की कीमतें और बढ़ गयी तथा भारतीय उपभोक्ता द्वारा दी गयी पंप कीमतें दुनिया में सबसे अधिक रही (चार्ट 29) ।

IV. वित्तीय स्थिति

एलएएफ के तहत जनवरी 2021 में लगभग ₹5.95 लाख करोड़ रुपये और फरवरी 2021 में ₹6.40 लाख करोड़ रुपये (25 फरवरी तक) दैनिक निवल चलनिधि अवशोषण से प्रणालीगत चलनिधि बड़े अधिशेष के रूप में प्रस्तुत किया गया। चलनिधि प्रबंधन परिचालन के क्रमिक सामान्यीकरण के भाग के रूप में, रिजर्व बैंक ने सामान्यीकरण शुरू करने के लिए 15 जनवरी को किए गए समान परिचालन के अनुक्रम में 29 जनवरी 2021 को ₹2 लाख करोड़ रुपये की राशि कीऔर एक परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी आयोजित की।दूसरी नीलामी को अच्छा प्रतिसाद मिला, जिसमें बोली लगाने के प्रस्ताव ₹2 लाख करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि से 1.5 गुना अधिक थे। इस तरह की दो और नीलामियां 12 और 26 फरवरी 2021को आयोजित की गई थीं, जिन्हें अच्छा प्रतिसाद मिला। 15 जनवरी 2021 से स्थीर दर रिवर्स रेपो के माध्यम से अवशोषित चलनिधि 16-29 जनवरी 2021 के दौरान ₹4.33 लाख करोड़ रुपये के पाक्षिक औसत से बढ़कर 30 जनवरी-25 फरवरी के दौरान ₹5.21 लाख करोड़ रुपये हो गई है (चार्ट 30)।

चार्ट 29: अंतरराष्ट्रीय गेसोलिन की कीमतें

ए. स्थानीय मुद्रा में गैसोलिन की कीमतें

	यूनिट	जुलाई -14	जनवरी -21
ब्राजील	रील/लीटर	3.0	4.6
रूस	रुबल/ लीटर	32.3	42.4
भारत	रुपया/लीटर	78.3	87.5
चीन	यूआन/लीटर	8.0	6.0
यूएस	यूएसडी/ गैलन	3.6	2.3
यूरोजोन	यूरो/ लीटर	1.6	1.4
ब्रेंट	यूएसडी/ बैरल	107.0	54.6

बी. गेसोलिन कीमतें: जुलाई 2014 से परिवर्तन

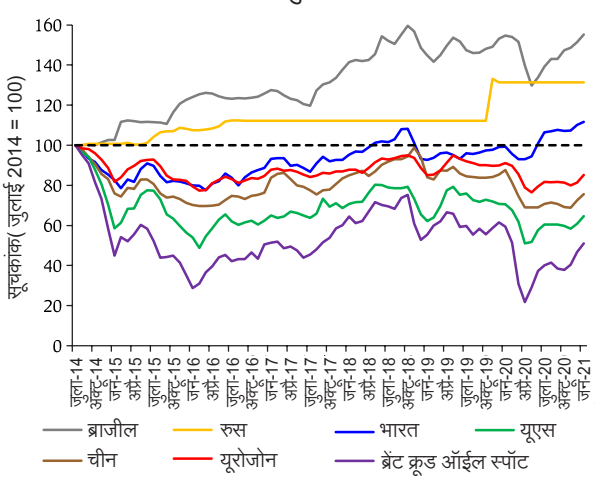

स्रोत: ब्लूमबर्ग तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान

चार्ट 30: नियत दर रिवर्स रेपो, निवल चलनिधि समायोजन सुविधा तथा मुद्रा बाजार स्प्रेड

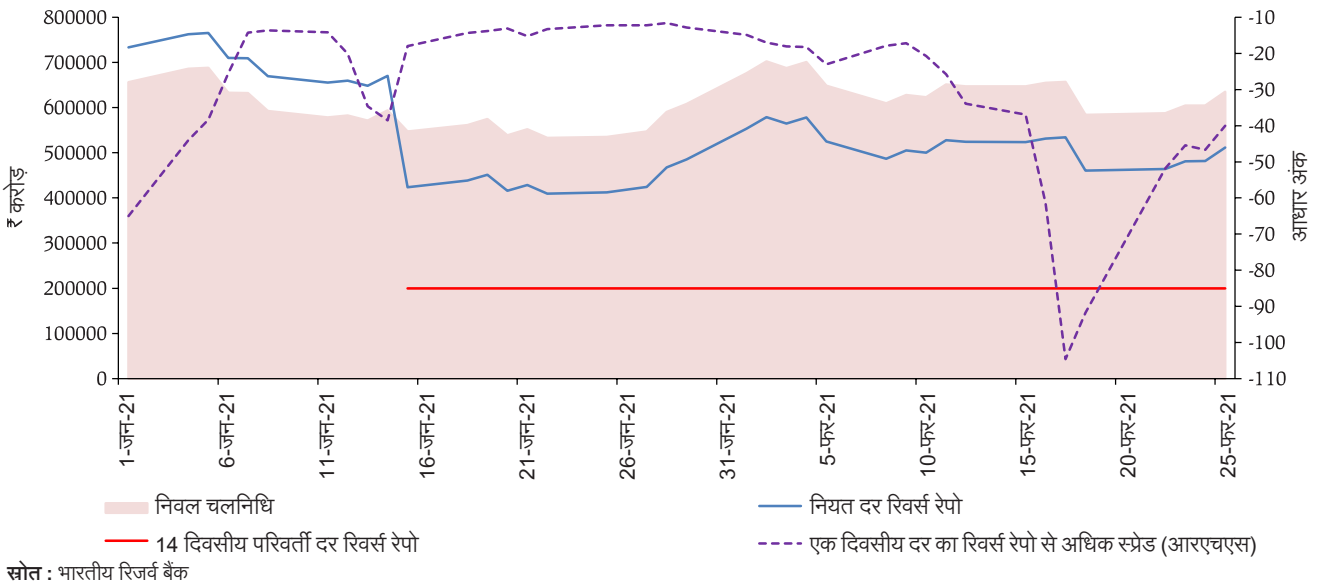

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का पालन करते हुए रिजर्व बैंक ने 21 जनवरी 2021 को एक खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) का संचालन किया जिससे प्रणाली में ₹10000 करोड़ की स्थायी चलनिधि डाल दी गई। बैंक ने 7 तथा 14 जनवरी 2021 को दो विशेष ओएमओ (ऑपरेशन ट्विस्ट) संचालित किए जिनमें प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद और बिक्री की गई। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने 5 फरवरी 2021 को अतिरिक्त चलनिधि उपाय किए जिनमें (i) मांग के अनुसार प्राप्य (ऑन टैप) लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचलन (टीएलटीआरओ) योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दबावग्रस्त क्षेत्रों को वर्धित उधार देने के लिए बैंकों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधार देने की अनुमति (ii) गैर-विघटनकारी तरीके से दो चरणों में नकद आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) की क्रमिक बहाली की घोषणा की जिसके अनुसार 27 मार्च, 2021 से यह एनडीटीएल का 3.5 प्रतिशत और 22 मई, 2021 से 4.0 प्रतिशत होगा; और (iii) निवल मांग तथा मियादी देयताओं (एनडीटीएल) के 3.0 प्रतिशत तक एसएलआर को घटाकर, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) के तहत निधियों का लाभ उठाने की सुविधा 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाना शामिल था। रिजर्व बैंक ने अनुकूल वित्तीय स्थिति को बढ़ावा देने के लिए 10 फरवरी 2021 को ₹20,000 करोड़ की वर्धित राशि के लिए एक ओएमओ खरीद नीलामी तथा 25 फरवरी 2021 को विशेष ओएमओ (ऑपरेशन ट्विस्ट) भी संचालित किए।

अतिरिक्त चलनिधि को प्रतिबिंबित करते हुए एक दिवसीय मुद्रा बाजार दर अर्थात भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर), ट्राई-पार्टी रेपो दर तथा बाजार रेपो दर का औसत रूप से जनवरी में क्रमशः 16 आधार अंक, 22 आधार अंक, तथा 23 आधार अंक तथा फरवरी में (25 फरवरी 2021 तक) क्रमशः 12 आधार अंक, 35 आधार अंक तथा 50 आधार अंक रिवर्स रेपो दर के नीचे रहना जारी रहा। गैर- बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा जारी की गए 3-माह के वाणिज्यिक पेपर (सीपी), 3-माह के टी-बिल तथा 3-माह के जमा प्रमाणपत्र (सीडी) की दरें दो महीने के अंतराल के बाद जनवरी 2021 में रिवर्स रेपो दर से अधिक थी (चार्ट 31)। सीपी (एनबीएफसी) दर को छोड़कर उपर्युक्त दर फरवरी 2021 में रिवर्स रेपो दर से काम हो गए जो कि अतिरिक्त चलनिधि को प्रतिबिंबित करते हैं।

कॉर्पोरेट बॉन्ड के प्रतिफल स्थिर रहे और रेटिंग स्पेक्ट्रम तथा जारीकर्ता श्रेणियों के बीच के अंतर कम हो गए जो कि कम होते हुए जोखिम प्रीमियम तथा अनुकूल नीतिगत परिवेश को दर्शाते है। निम्नलिखित अर्थात, (i) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं (एफआई), (ii) कॉर्पोरेट, तथा (iii) एनबीएफसी द्वारा जारी 3-वर्ष के AAA रेटेड कॉर्पोरेट

चार्ट 31 : नीतिगत कॉरिडर तथा मुद्रा बाजार दर

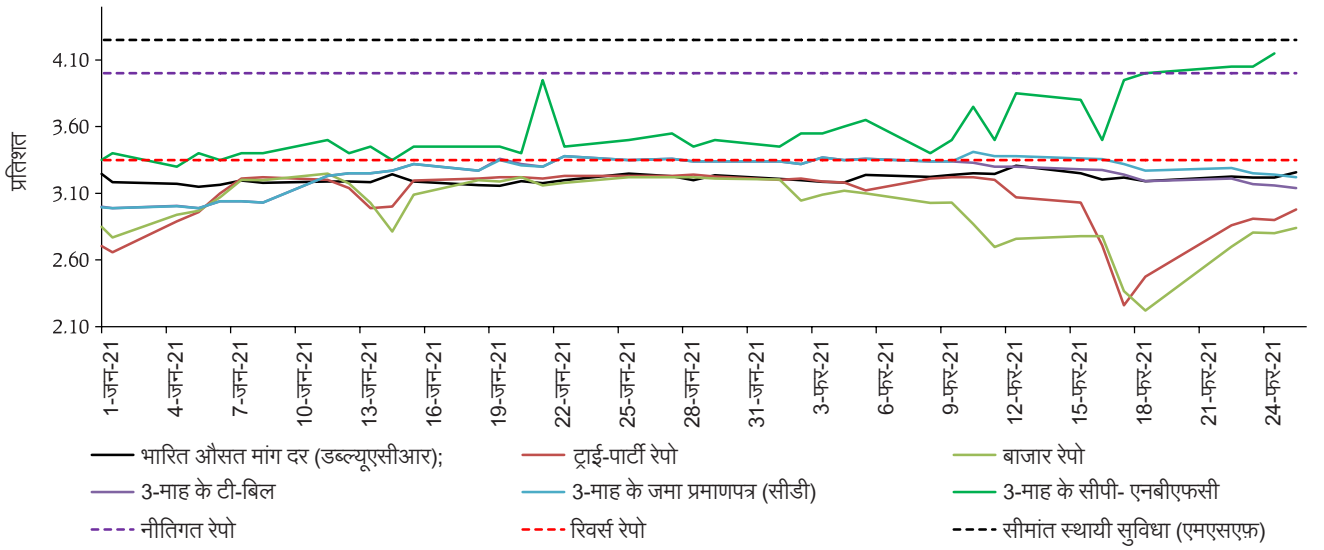

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक तथा ब्लूमबर्ग

बॉन्ड का तदनुरूपी परिपक्वता वाले सरकारी बॉन्डों के प्रतिफल से अधिक औसत अंतर जनवरी में क्रमशः 17 आधार अंक, 14 आधार अंक तथा 21 आधार अंकों से कम हो गया। इन संस्थाओं द्वारा जारी की गए 3-वर्ष के बीबीबी रेटे बॉन्डों – सबसे निम्नतर रेट की गए निवेश ग्रेड बॉन्ड- पर स्प्रेड भी क्रमशः 25 आधार अंक, 12 आधार अंक तथा 19 आधार अंकों से कम हो गया जो घटती हुई जोखिम विमुखता तथा चलनिधि से समृद्ध प्रणाली को दर्शाते हैं (सारणी 6)।

सारणी 6: कॉर्पोरेट बॉंड प्रतिफल और स्प्रेड

जारीकर्ता	प्रतिफल				स्प्रेड		
	रेटिंग	दिसं-20	जन-21	घट-बढ़	दिसं-20	जन-21	घट-बढ़
		(प्रतिशत)		(आधार अंक)	(आधार अंक)		
पीएसयू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं	एएए	4.89	4.96	7	43	26	-17
	एए	5.56	5.62	6	114	92	-22
	बीबीबी-	8.76	8.75	-1	430	405	-25
कॉर्पोरेट	एएए	4.76	4.85	9	30	16	-14
	एए	5.62	5.74	12	116	105	-11
	बीबीबी-	9.57	9.69	12	512	500	-12
एनबीएफसी	एएए	4.94	4.96	2	48	27	-21
	एए	6.28	6.34	6	182	164	-22
	बीबीबी-	10.56	10.62	6	611	592	-19

टिप्पण: प्रतिफल तथा स्प्रेड माह के औसत हैं।
स्रोत: एफआईएमएमडीए

चलनिधि के व्यापक उपाय भी प्रणाली में मौद्रिक तथा ऋण स्थितियों के सुकर होने के संकेत देते है। आरक्षित मुद्रा (आरएम) जिसे आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित किया गया था, में वर्ष-दर-वर्ष (19 फरवरी 2021) (चार्ट 32) आधार पर 18.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण था संचलनगत मुद्रा (CiC) में 20.3 प्रतिशत की वृद्धि (एक साल पूर्व 11.9 प्रतिशत)। मुद्रा में उच्च विस्तार सहित समग्र जमाराशियों में 11.1 प्रतिशत (12 फरवरी 2021) पर हो रही वृद्धि के कारण मुद्रा आपूर्ति (M3) में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर (एक साल पूर्व 9.5 प्रतिशत) 12.6 प्रतिशत विस्तार हुआ। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी)द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में 12 फरवरी 2021 को 6.6 प्रतिशत (एक साल पूर्व 6.4 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई।

समग्र ऋण वृद्धि में होने वाली क्रमिक लेकिन स्थिर बहाली के भीतर कुछ उज्ज्वल बिन्दु उभर रहे हैं। दिसंबर 2020 में कृषि, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों, परिवहन सेवाओं, थोक व्यापार, खुदरा व्यापार तथा अन्य सेवाओ के लिए ऋण तथा वाहनों की खरीद के लिए व्यक्तिगत ऋण जो कि कुल ऋण का 35 प्रतिशत थे, में तेज गति से वृद्धि हुई। व्यक्तिगत ऋण खंड के दूसरे सबसे बडे घटक, अन्य व्यक्तिगत ऋण (10), में दिसंबर 2020 में 15

चार्ट 32: मौद्रिक तथा ऋण की कुल राशियाँ

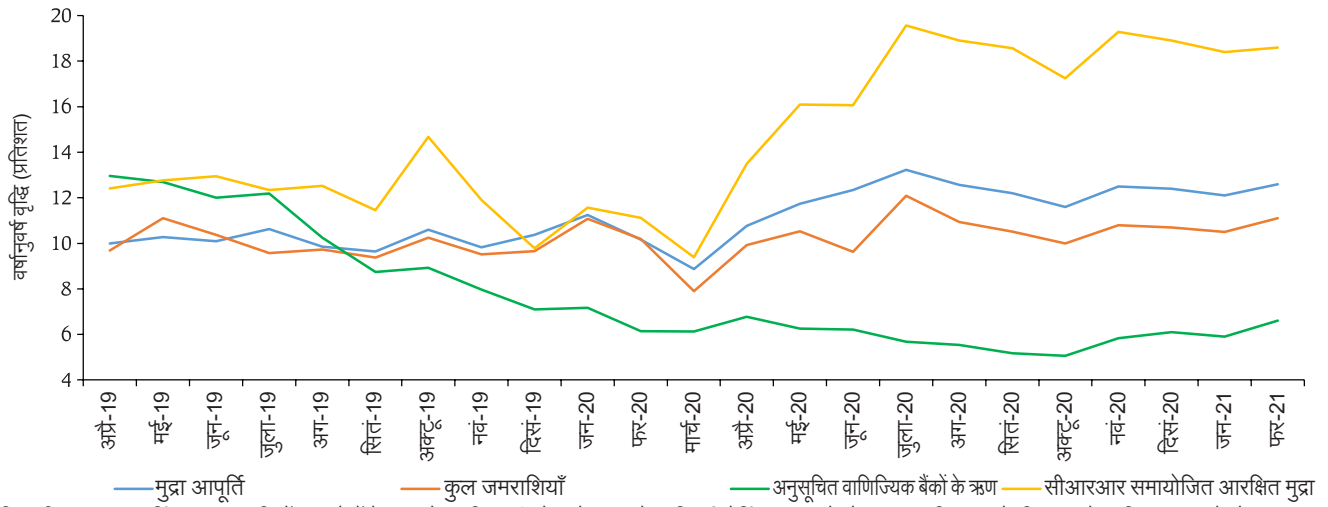

टिप्पणी: 1. मुद्रा आपूर्ति, कुल जमाराशियों तथा बैंकों के ऋण से संबंधित आँकड़े प्रत्येक माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के हैं; तथा आरक्षित मुद्रा के लिए माह के अंतिम शुक्रवार के हैं।
2. फरवरी माह के लिए आरक्षित मुद्रा संबंधी आँकड़े 19 फरवरी 2021 के अनुसार हैं तथा 12 फरवरी 2021 के अनुसार मुद्रा आपूर्ति, कुल जमराशियाँ, तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया है।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

प्रतिशत की तेज गति से वृद्धि हुई। बड़े उद्योगों को बैंक ऋण की मात्रा कम ही रही, लेकिन इन में से बहुत सारे उधारकर्ता, विशेष रूप से उच्च रेटिंग वाले उधारकर्ता प्रचलित कम ब्याज दर वाले दौर का लाभ उठाने तथा पिछले उच्च लागत वाले कर्ज को समाप्त करने के लिए बॉन्डों, डिबेन्चर तथा अन्य बाजार आधारित लिखतों के माध्यम से निधियाँ जुटा रहे हैं। व्यावसायिक सेवाओं के लिए ऋण भी कम थे। गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक ऋण भी एक वर्ष पूर्व की 28 प्रतिशत (चार्ट 33) की सुदृढ़ वृद्धि की तुलना में दिसंबर 2020 में 8 प्रतिशत तक घट गया। हालही में टीएलटीआरओ ऑन टैप योजना के अंतर्गत बैंकों को एनबीएफसी को उधार देने के लिए अनुमति देने की पहल से दबावग्रस्त क्षेत्रों को ऋण में वृद्धि होने की अपेक्षा है।

चार्ट 33: क्षेत्रवार ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि, प्रतिशत)

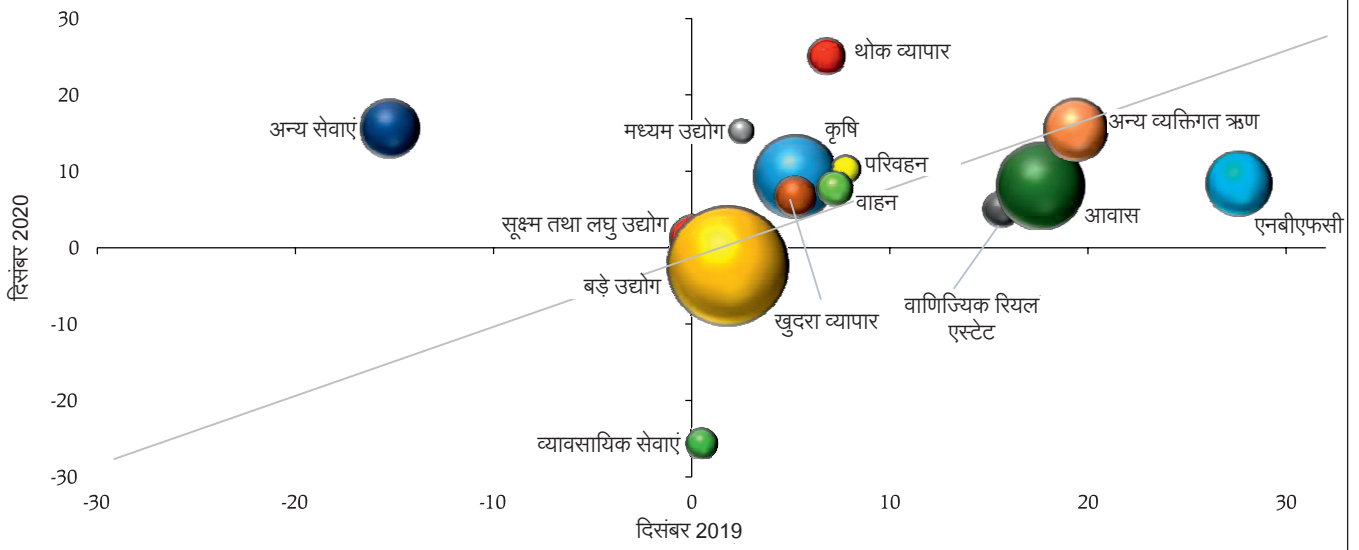

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

[10] अन्य व्यक्तिगत ऋणों में अन्य बातों के साथ साथ घरेलू उपभोग, चिकित्सकीय व्यय, यात्रा, ब्याह तथा अन्य सामाजिक समारोह शामिल हैं।

ऋण बाजार में, एससीबी की 1-वर्षीय माध्यिक निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत में 91 बीपीएस (मार्च 2020 से जनवरी 2021 तक) की गिरावट आई है। माध्यिक मीयादी जमा दर में भी 146 बीपीएस की कमी हुई। निधि की लागत में कमी इसके उधार दरों की ओर संचरण के लिए अच्छा संकेत है (सारणी 7)।

सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) पर प्रतिफल दशकीय निम्न स्तर पर ट्रेड करते रहे, जिसमें अधिशेष तरलता और कोविड-19 के मद्देनजर रिज़र्व द्वारा उठाए गए कदमों से सहायता मिली। तथापि नए 10-वर्षीय जी-सेक बेंचमार्क (5.85 जीएस 2030) और पुराने 10-वर्षीय जी-सेकंड बेंचमार्क (5.77 जीएस 2030) पर प्रतिफल क्षणिक दबाव में आया, जो जनवरी 2021 के अंत में क्रमश: 5.91 प्रतिशत और 5.95 प्रतिशत पर बंद हुआ। अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में बढ़ोतरी, माह के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और केंद्रीय बजट में 2021-22 के लिए ₹12 लाख की सकल बाजार ऋण योजना और साथ ही 2020-21 की शेष अवधि के लिए ₹80,000 करोड़ के अतिरिक्त उधार की घोषणा से बाज़ार की धारणा दबाव में रही। बाद में प्रतिफल सहज हुए, जिसके कारण थे: (i) रिज़र्व बैंक द्वारा 10 फरवरी 2021 को ₹20,000 करोड़ की बढ़ी हुई राशि के लिए ओएमओ खरीद की घोषणा और संचालन, जिसमें से अधिकतर खरीद 10-वर्षीय खंड के लिए थी; (ii) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) में एनडीटीएल के 22 प्रतिशत की बढ़त की छूट को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाना; (iii) खुदरा निवेशकों को सीधे रिज़र्व बैंक ('रिटेल डायरेक्ट') के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति बाजार– प्राथमिक और द्वितीयक दोनों- तक ऑनलाइन पहुंच देना), जिससे निवेशक आधार में बढ़ोतरी और घरेलू बचत के दोहन से सरकार के ऋण लेने की लागत कम हो सकती है; तथा (iv) अनुकूल वित्तपोषण स्थितियों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त तरलता प्रदान करने के लिए स्पष्ट भावी मार्गदर्शन। इन उपायों से प्रोत्साहित होकर, नए और पुराने 10- वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल, केंद्रीय बजट के बाद आई तेजी के बाद, 11 फरवरी, 2021 के अनुसार क्रमशः 17 बीपीएस और 13 बीपीएस कम हो गए (चार्ट 34 और 35)। तथापि इसके बाद, ये बेंचमार्क प्रतिफल फरवरी 2021 के अंत में क्रमश: 6.23 प्रतिशत और 6.32 प्रतिशत तक चढ़ गए, जो मुख्य रूप से वैश्विक कारकों जैसे कि कड़े होते अमेरिकी प्रतिफल और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण है। जैसा कि इस आलेख में पहले बताया गया है आरबीआई ने 25 फरवरी को ₹10,000 करोड़ का विशेष ओएमओ (ऑपरेशन ट्विस्ट) चलाया जिसे खरीद पक्ष में 4.9 और बिक्री पक्ष में 3.3 के नीलामी- कवर अनुपात के साथ काफी

सारणी 7: रेपो दर से बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार अंक)

अवधि	रेपो दर	मीयादी जमा दर		उधार दर		
		मध्यम अवधि जमा दर	डब्ल्यू-एडीटीडीआर	1-वर्ष माध्यिक एमसी-एलआर	डब्ल्यू-एएलआर-बकाया रुपया ऋण	डब्ल्यू-एएलआर-नए रुपया ऋण
फर 2019 - सितं 2019	-110	-9	-7	-30	2	-40
अक्टू 2019 - जन 2021*	-140	-175	-127	-118	-91	-144
मार्च 2020 - जन 2021*	-115	-146	-88	-91	-73	-113
फर 2019 - जन 2021*	-250	-209	-134	-145	-89	-184

*: डब्ल्यूएएलआर और डब्ल्यूएडीटीडीआर पर नवीनतम डेटा दिसंबर 2020 से संबंधित है।
डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर।
डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू अवधि जमा दर;
एमसीएलआर: निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दरें।
स्रोत: आरबीआई

चार्ट 34: 10 वर्षीय बेंचमार्क जी-सेक प्रतिफल

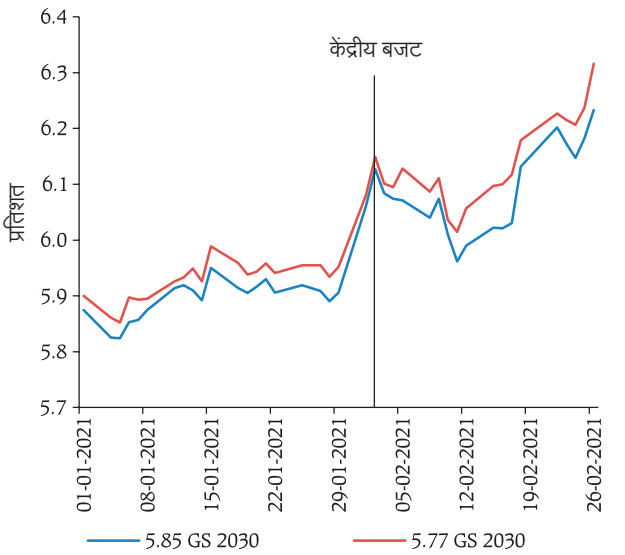

स्रोत: सीसीआईएल और ब्लूमबर्ग

चार्ट 35: 2021 में 10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल पर विभिन्न घटनाओं की घोषणा का प्रभाव

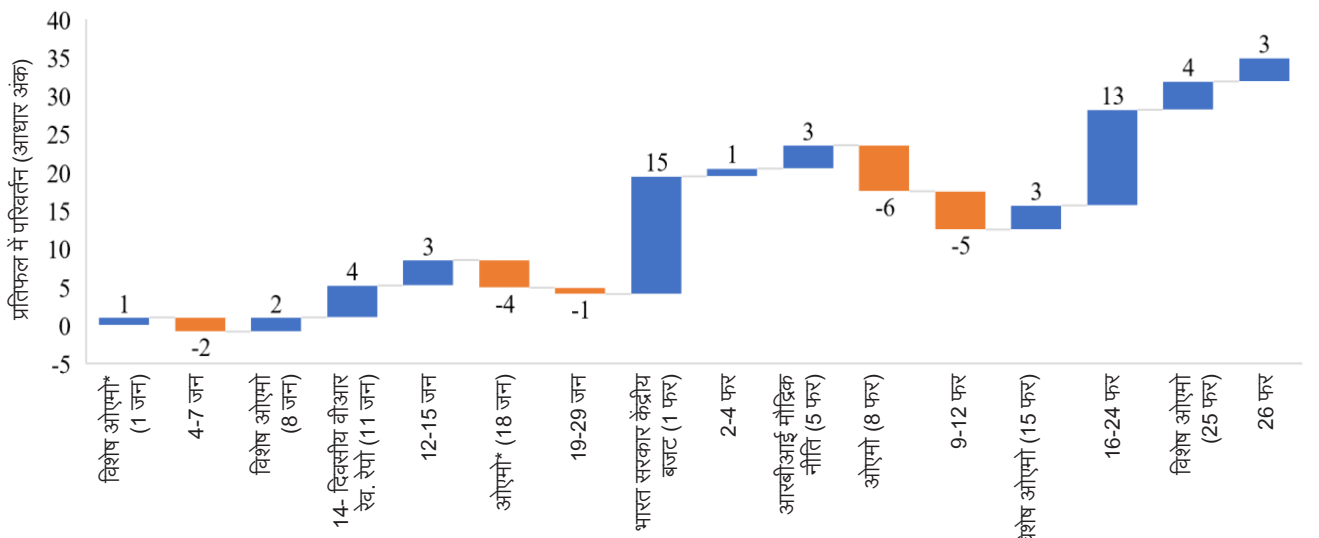

*घोषणाएं पिछले ट्रेडिंग दिन को बाजार ट्रेडिंग घंटे समाप्त होने पर की गई।
स्रोत: ब्लूमबर्ग

अच्छी प्रतिक्रिया मिली। अपने उपायों को जारी रखते हुए ₹15,000 करोड़ की बढ़ाई गई राशि के लिए ऐसा एक और परिचालन 4 मार्च, 2021 को किया जाना है।

भारतीय इक्विटी बाजार ने जनवरी 2021 में नई उंचाईयां छुईं, जब माह के अंत में सभी लाभों का मिलान करने के बाद हानि दर्ज करने से पहले, बीएसई सेंसेक्स ने इंट्रा-डे ट्रेड में थोड़े समय के लिए ऐतिहासिक 50,000 अंक को पार किया (21,जनवरी 2021 को)। प्रारंभ में, इक्विटी बाजार अच्छी खबरों के बल पर बढ़ गया - दिसंबर 2020 के लिए विनिर्माण पीएमआई में विस्तार; देश में दो टीकों और उनके रोलआउट के लिए सरकार का अनुमोदन; और 2020-21 की तीसरी तिमाही के लिए कॉर्पोरेट आय परिणामों के प्रति आशावाद। माह के अंत तक यह गति उलट गई जब अमेरिका में खुदरा विक्रेताओं द्वारा सट्टे की ट्रेडिंग और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा बिकवाली के कारण उत्पन्न हुए कमजोर वैश्विक संकेतों पर बाजार अस्थिर हुआ।

फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि भारत के बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स ने केंद्रीय बजट के बाद अपनी अब तक की सबसे तीव्र बढ़त (निश्चित रूप में) दर्ज की, जबकि वित्त मंत्री ने करों में बिना किसी बड़े बदलाव के आर्थिक पुनरुद्धार को प्रोत्साहित करने और सभी क्षेत्रों में खर्च को बढ़ावा देने के लिए उपायों की घोषणा की। 1 फरवरी 2021 को सेन्सेक्स 2,315 अंकों (5 प्रतिशत) से बढ़कर 48,601 पर बंद हुआ (चार्ट 36)। स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र में शुरू की गई योजनाओं, जिसमें अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के प्रबंधन के लिए एक आस्ति पुनर्रचना कंपनी का गठन शामिल है, पीएसयू का रणनीतिक विनिवेश, दो सरकारी बैंकों और एक जनरल बीमा कंपनी का निजीकरण, और बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की सीमा 74 प्रतिशत तक बढ़त के कारण निवेशक धारणा बेहतर हुई। पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि से समग्र धारणा में तेजी आई|

फरवरी 2021 में बीएसई-सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण ने ₹200 लाख करोड़ का ऐतिहासिक आंकड़ा पहली बार पार किया, जो निरंतर तेजी द्वारा निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण धन निर्माण दर्शाता है। देश का बाजार पूंजीकरण के प्रति जीडीपी अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक है। वस्तुतः, जनवरी 2021के बाद से, दुनिया के शीर्ष 10 बाजारों में केवल हांगकांग को छोड़कर भारत के इक्विटी बाजारों में सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ। भारत का शेयर बाजार अब बाजार मूल्य के मामले में, दुनिया में आठवां सबसे बड़ा बाजार हो गया है।

चार्ट 36 : बीएसई सेंसेक्स और संस्थागत प्रवाह

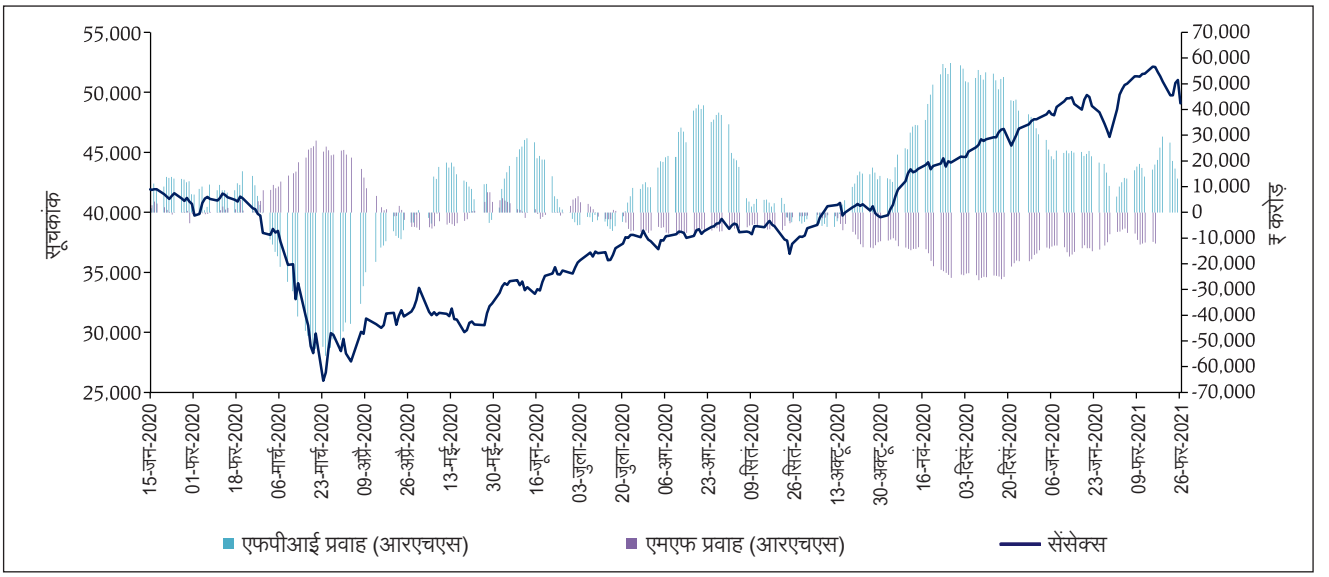

नोट : एफपीआई और एमएफ निवेश 15 दिवसीय रोलिंग सम बेसिस पर प्रस्तुत
स्रोत : ब्लूमबर्ग

भारतीय सूचीबद्ध कॉरपोरेट द्वारा 2020-21 की तीसरी तिमाही के लिए घोषित आय परिणाम आर्थिक गतिविधि की मजबूत वापसी का प्रमाण देता है। परिणाम घोषित करने वाली 3,014 गैर-वित्तीय सूचीबद्ध कंपनियों के लिए हालांकि तीसरी तिमाही[11] में निवल बिक्री वृद्धि में संकुचन बना रहा, लेकिन पूर्ववर्ती तीन-तिमाहियों की तुलना में इसकी गति मध्यम रही। फिर भी, कम ब्याज खर्च के कारण कच्चे माल की लागत और लागत बचत में गिरावट के कारण बिक्री की तुलना में व्यय तेजी से गिरा और परिचालन लाभ में इजाफा हुआ। (चार्ट 37)।

चार्ट 37 : सूचिबद्ध गैर-वित्तीय कंपनी

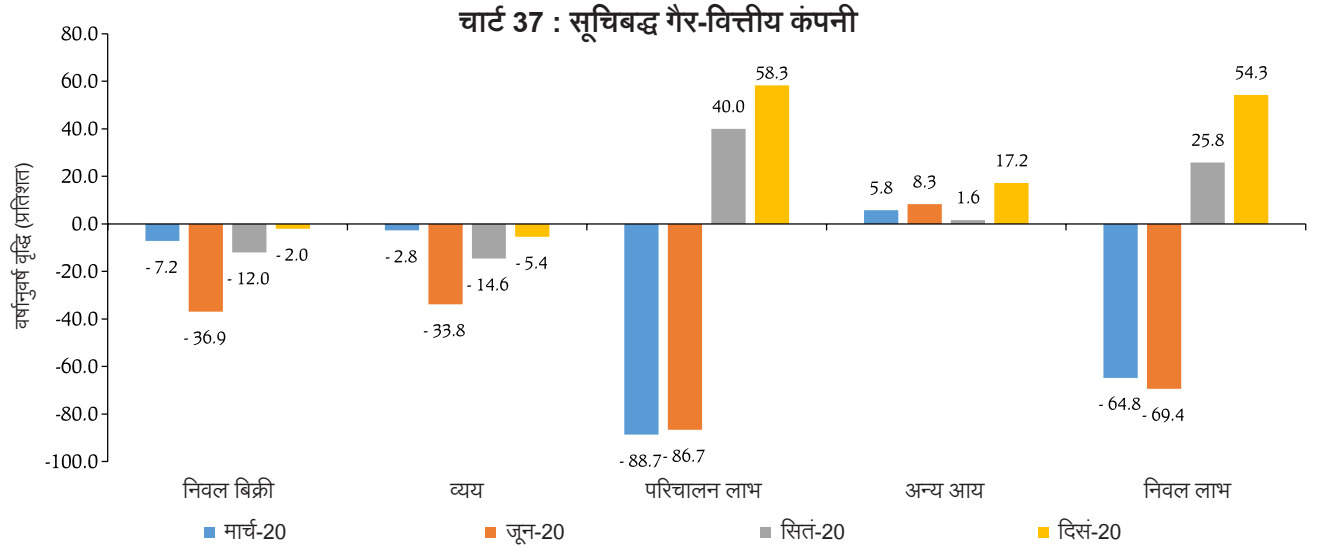

नोट : असमान्य वस्तुओं को छोड़कर
स्रोत : प्रावोस एवं आरबीआई स्टाफ गणना

[11] तीसरी तिमाही : 2020-21 के दौरान रिफाइनिंग सेक्टर को छोड़कर बाकी गैर-वित्तीय कंपनी की निवल बिक्रि में, दूसरी तिमाही : 2020-21 के दौरान 8.4% के संकुचन के बाद, साल-दर-साल 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सारणी 8 : क्षेत्रवार कॉरपोरेट प्रदर्शन

चयनित सेक्टर	निवल बिक्री वृद्धि (साल-दर-साल, प्रतिशत)				परिचालन लाभ वृद्धि (साल-दर-साल, प्रतिशत)				निवल लाभ वृद्धि (साल-दर-साल, प्रतिशत)			
	मार्च-20	जून-20	सितं-20	दिसं-20	मार्च-20	जून-20	सितं-20	दिसं-20	मार्च-20	जून-20	सितं-20	दिसं-20
आईटी	7.4	4.3	4.5	6.0	20.2	12.5	19.0	24.1	15.4	6.3	12.5	18.4
रिफाइनिंग	-5.0	-49.2	-25.2	-17.4	-170.8	-37.8	65.2	27.5	-143.5	-6.1	85.5	29.2
एफएमसीजी	0.2	-6.4	7.5	6.9	-16.7	-13.1	16.2	12.7	-20.2	-2.1	7.4	8.1
फार्मास्युटिकॉल	5.5	5.5	9.8	10.2	2.1	28.0	38.8	45.1	9.8	16.2	33.9	63.7
स्टील	-18.7	-39.1	10.5	16.8	-28.9	-401.3	n.m.	n.m.	46.3	-604.3	34.2	n.m.
ऑटो एण्ड ऑटो एन्सिलियरिज़	-17.2	-65.2	3.4	20.3	-55.0	-198.0	8.5	56.7	-37.5	-157.6	-11.3	50.8
सिमेंट	-11.8	-33.4	4.6	11.2	5.3	-44.8	83.9	107.4	12.7	-36.9	70.6	111.7

नोट : असमान्य वस्तुओं को छोड़कर, उल्लिखित नहीं का अर्थ महत्त्वपूर्ण नहीं
स्रोत : प्रावोस एवं आरबीआई स्टाफ गणना

गैर-वित्तीय क्षेत्र पर किए गए अलग-अलग विश्लेषण से पता चलता है कि ऑटो, स्टील और सीमेंट जैसे आर्थिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में 202 0-21की तीसरी तिमाही के दौरान प्रभावशाली प्रदर्शन दर्ज किया गया, जैसा कि पहले शुरू हुआ था (सारणी 8)। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की कंपनियों ने 2020-21 की तीसरी तिमाही के दौरान पिछले कई वर्षों की तुलना में सबसे मजबूत तिमाही प्रदर्शन दर्ज करते हुए अपनी बिक्री में तेज वृद्धि की।

इसी प्रकार, भारत में 853 सूचीबद्ध बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के) : 2020-21 की तीसरी तिमाही के दौरान कमाई के परिणाम मजबूत प्रदर्शन का संकेत देते हैं (चार्ट 38) । निवल बिक्री, जिसमें मुख्य रूप से ब्याज आय शामिल है, में स्वस्थ वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अन्य आय, जिसमें परिसंपत्तियों और निवेश की बिक्री से लाभ / हानि जैसे प्रवाह शामिल हैं, तिमाही के दौरान पूंजी बाजार में तेजी बनाए रखा। कर्मचारी लागत में वृद्धि के कारण कुल व्यय में वृद्धि हुई, जिससे परिचालन लाभ में मामूली वृद्धि हुई। इसके अलावा, 2020-21 की तीसरी तिमाही में निजी बैंकों द्वारा भारी प्रावधान के कारण बेहतर आधार प्रभावों के कारण ऋण और अग्रिमों के प्रावधान में भारी गिरावट के कारण निवल लाभ में तेज वृद्धि हुई।

24 जनवरी को जारी यूएनसीटीएडी के 'इनवेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर' के अनुसार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के संबंध

चार्ट 38 : सूचीबद्ध वित्तीय कंपनी का प्रदर्शन

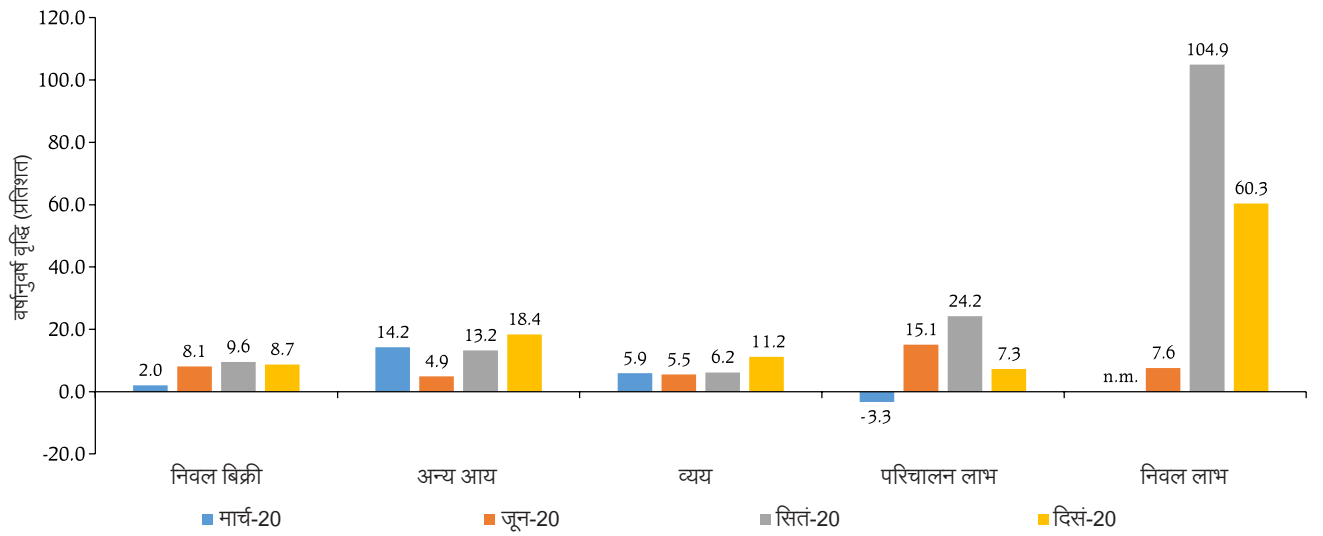

नोट : असमान्य वस्तुओं को छोड़कर, परिचालन लाभ प्रोवेजनिंग और कंटेंजेन्सिज से पूर्व परिचालन लाभ को दर्शाता है, उल्लिखित नहीं का अर्थ महत्त्वपूर्ण नहीं
स्रोत : प्रावोस एवं आरबीआई स्टाफ गणना

में भारत का स्थान अन्य की तुलना में उज्ज्वल बना रहा जबकि 2020 में साल दर साल वैश्विक प्रवाह 42% तक (यूएस $ 859 बिलियन) गिर गया, जो 1990 के बाद से सबसे निचला स्तर है। भारत ने सार दर साल 13% (यूएस $ 57 बिलियन) वृद्धि दर्ज की, बाकी देशों की तुलना में यह सबसे अधिक वृद्धि है और यह बढ़ोतरी डिजिटल क्षेत्र में प्रवाह के कारण रही। अगस्त-नवंबर 2020 के दौरान देखी गई तेजी के कारण दिसंबर 2020 में निवल एफडीआई प्रवाह मजबूत बना रहा। परिणामस्वरूप, निवल एफडीआई पिछले साल के यूएस $ 31.1 बिलियन से अप्रैल-दिसंबर 2020 में बढ़कर यूएस $ 40.5 बिलियन हो गया (चार्ट 39)। अगस्त-दिसंबर 2020 में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में वृद्धि काफी हद तक डिजिटल सेवाओं में हुए कुछ बड़े सौदों से प्रेरित थी(चार्ट 40)।

चार्ट 39 : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

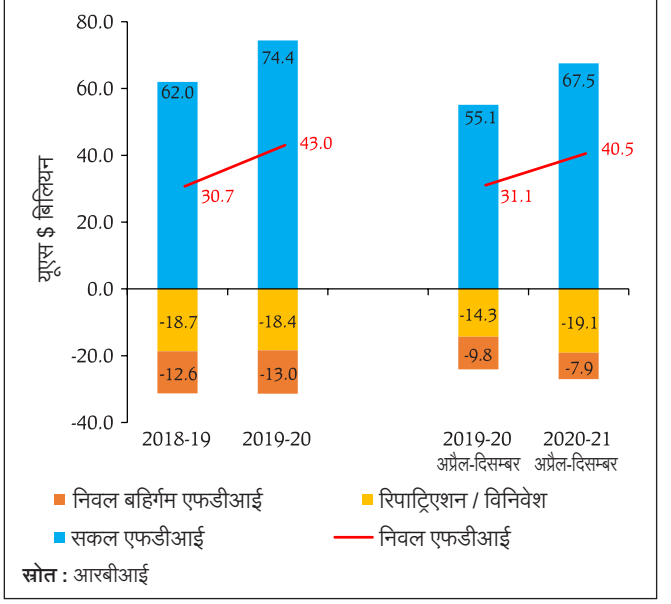

स्रोत : आरबीआई

जनवरी 2021 में एफपीआई घरेलू पूंजी बाजार में निवल खरीदारों के रूप में बने रहे, हालांकि पिछले महीने की तुलना में इसमें मामूली कमी आई। जबकि अपेक्षा से बेहतर आय, आर्थिक पुनरुद्धार के संकेत, कोविड के घटते संक्रमण और चल रहे टीकाकरण अभियान ने एफपीआई को उत्साहित करना जारी रखा, फिर भी उन्होंने इस दौरान मुख्य रूप से बजट-पूर्व लाभ बुकिंग से अपने जोखिम को कम किया। जबकि यूएस $ 1.2 बिलियन का निवल शुद्ध एफपीआई प्रवाह मुख्य रूप से यूएस $ 2.0 बिलियन की इक्विटी खरीद से प्रेरित था, वे डेब्ट सेगमेंट (चार्ट 41) में निवल विक्रेता बने रहे। जबकि जनवरी 2021 में एफपीआई प्रवाह में बजट-पूर्व अस्थिरता देखी गई, पूंजीगत व्यय और पीएसयू के निजीकरण पर अधिक ध्यान देने वाला सुधार परस्त बजट के कारण फरवरी 2021 में एफपीआई अंतर्वाह को बढ़ावा दिया। कुल मिलाकर 2020- 21 में अबतक इक्विटी में एफपीआई का निवल निवेश यूस $ 36.1 बिलियन रहा जो, 2012 -13 के बाद से अब तक का सर्वाधिक है।

चार्ट 40 : एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह – शीर्ष 5 कंपनियों का हिस्सा

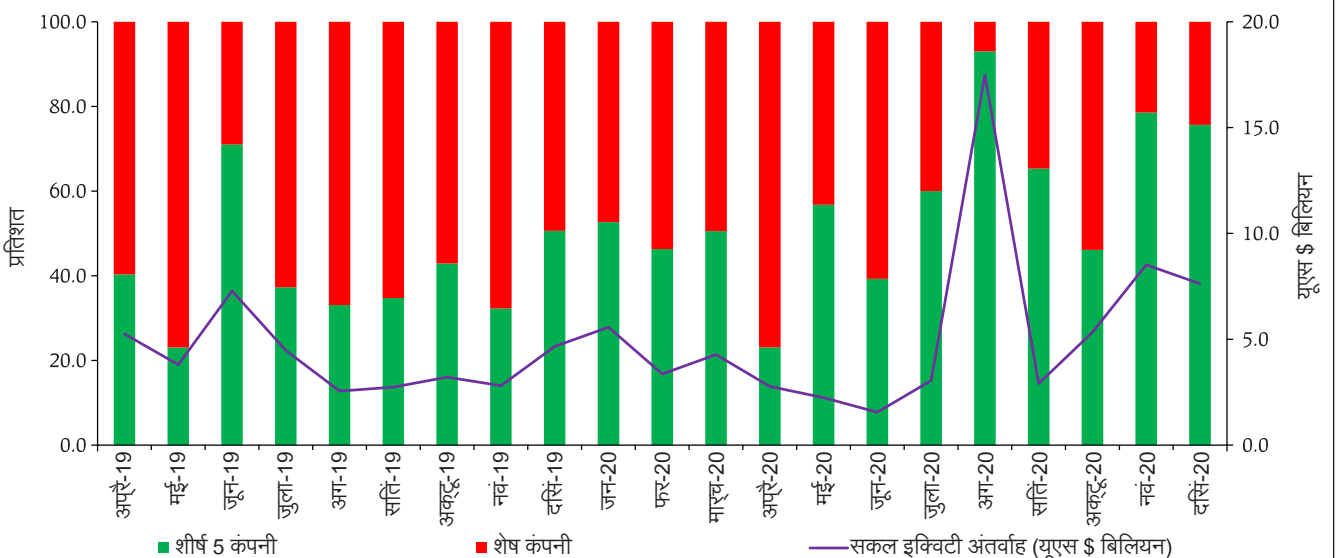

स्रोत : आरबीआई

चार्ट 41 : निवल विदेशी पॉर्टफोलियो निवेश

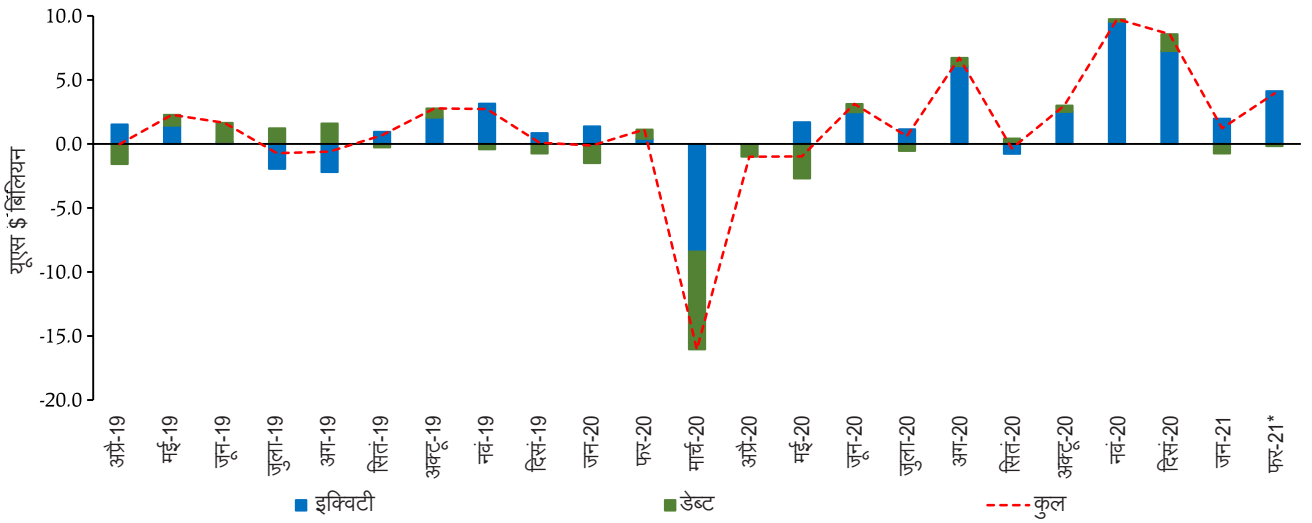

*25 तक
स्रोत : नेशनल सिक्युरिटिज़ डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)

हाल के केंद्रीय बजट प्रस्ताव ने एफपीआई द्वारा रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्टों (InvITs) में डेब्ट वित्तपोषण की अनुमति दी है जिससे इन संस्थाओं के लिए धन के वैकल्पिक स्रोत का दरवाजा खुलेगा और इससे धन की लागत को कम करने के अलावा विदेशी निवेशकों के लिए भारत में अपेक्षाकृत सुरक्षित कर्ज निवेश विकल्प उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार ने कैपेक्स को तेज गति प्रदान करने के संकेत के साथ, भारत द्वारा देश की सड़कों, बंदरगाहों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ऑफर किए जा रहे ग्रीन बॉन्ड ने विदेशी निवेशकों के बीच पहले से अधिक रुचि पैदा की है।

29 जनवरी 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार यूएस $ 590.2 बिलियन के उच्च स्तर को छू गया और 19 फरवरी 2021 को यह यूएस $ 583.9 बिलियन रहा (चार्ट 42)।

चार्ट 42 : आरक्षित विदेशी मुद्रा विनिमय एवं आयात कवर

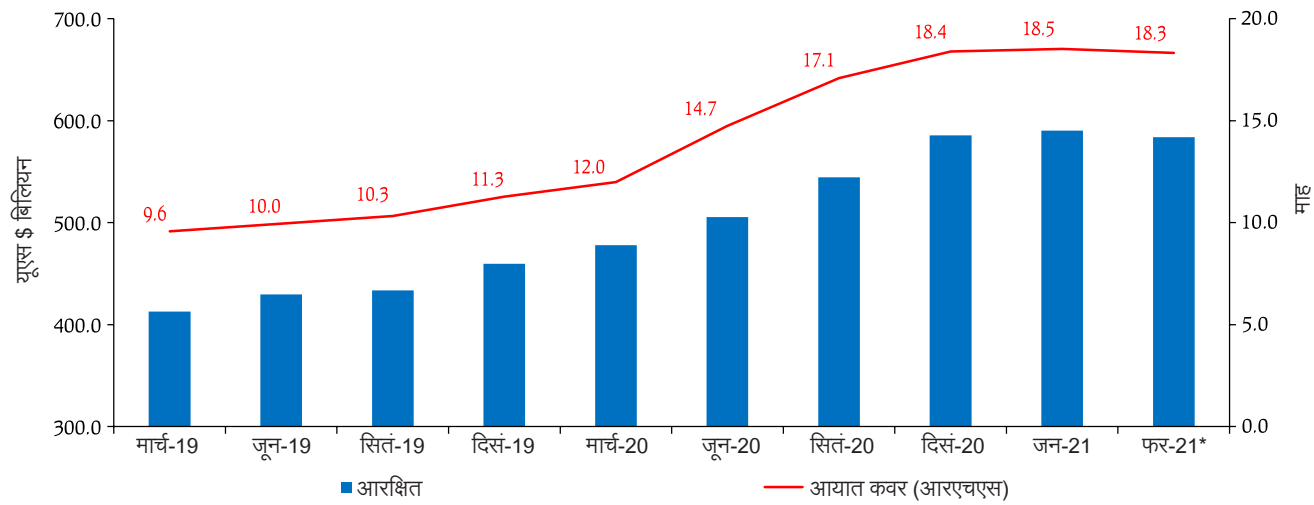

*19 फरवरी 2021 के अनुसार
नोट : दिसम्बर 2020 और जनवरी 2021 के लिए आयात कवर के आंकड़े दूसरी तिमाही : 2020-21 और पिछली तिमाही के लिए जारी बेलेंस ऑफ पेमेंट्स के आंकड़े पर आधारित हैं।
स्रोत : आरबीआई

चार्ट 43: 40-मुद्राओं के वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर)में मासिक उतार-चढ़ाव
(आधार: 2015-16 = 100)

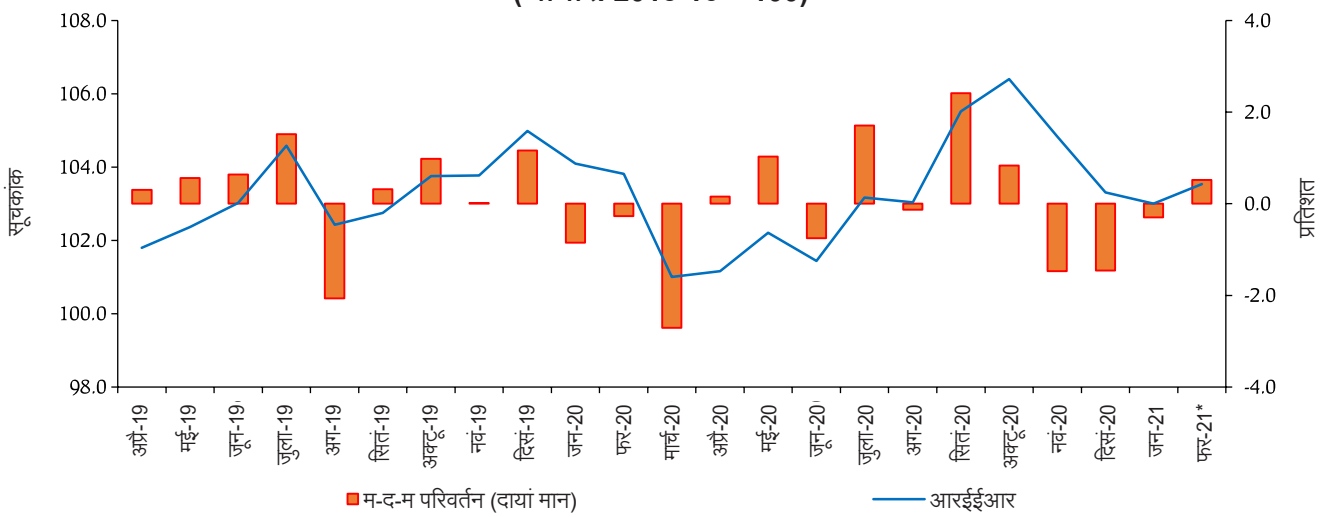

*: 19 तक
स्रोत:आरबीआई

विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपया (आईएनआर) लगातार मजबूत होता रहा और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने और टीकाकरण रोल आउट के कारण एक महीने पहले फरवरी 2021 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.5 प्रतिशत अधिक रहा। मार्च 2020 के अंत में अपने स्तर से अधिक आईएनआर में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह पिछले साल सितंबर 2020 के शुरुआत में देखे गए स्तर से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹73.04 तक पहुंच गया। 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक के संदर्भ में, मार्च 2020 के अपने स्तर से अधिक फरवरी 2021 में आईएनआर में 2.5% की वृद्धि हुई।

भुगतान प्रणाली

भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र ने आर्थिक पुनरुद्धार में उत्प्रेरक के रूप में सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। तदनुसार, इसने जनवरी 2021 में पिछले महीने के थोक और खुदरा दोनों क्षेत्रों में हुए शानदार प्रदर्शन के विकास गति को बनाए रखा। बाजार का अनुमान है कि 2025 तक, वित्तीय समावेशन और व्यापारियों के तेजी से डिजिटलीकरण[12] का उपयोग करने की नीतियों के कारण भारत में डिजिटल भुगतान तीन गुना से अधिक ₹7,000 ट्रिलियन की वृद्धि हो सकती है।

जनवरी 2021 के आते-आते, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली के माध्यम से थोक लेन-देन की मात्रा में 14.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की दोहरी अंकों की वृद्धि जारी रही, जो इस महीने में बढ़कर 20.2 प्रतिशत से अधिक रही (टेबल 9)।

सारणी 9: वर्ष 2020-21 में लेन-देन का मूल्य
(₹ करोड में)

	आरटीजीएस	एनईएफटी	यूपीआई	आईएमपीएस
अप्रै-20	64,43,653	13,06,406	1,51,141	1,21,141
मई-20	70,41,869	14,81,750	2,18,392	1,69,402
जून-20	86,51,978	19,06,586	2,61,835	2,06,951
जुला-20	83,35,279	19,63,113	2,90,538	2,25,775
अग-20	72,92,380	19,30,552	2,98,308	2,35,137
सितं-20	94,89,066	21,65,515	3,29,032	2,48,662
अक्टू-20	84,96,046	22,35,389	3,86,107	2,74,645
नवं-20	79,87,655	22,18,252	3,90,999	2,76,459
दिसं-20	1,06,59,120	25,58,304	4,16,176	2,92,325
जन-21	91,70,162	21,65,869	4,31,182	2,88,538

स्रोत: आरबीआई

[12] "2025 तक भारत में डिजिटल भुगतान बाजार 3 गुना बढ़कर ₹7,092 ट्रिलियन होने की संभावना : रिपोर्ट", इकोनॉमिक टाइम्स, 23 अगस्त, 2020

दो महीने पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के माध्यम से खुदरा क्षेत्र में लेन-देन और मूल्य की मात्रा में क्रमशः 10.3 प्रतिशत और 12.3 प्रतिशत तेजी का अनुमान है। तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) के माध्यम से मात्रा और मूल्य में लेन-देन में पिछले महीने दर्ज की गई 38.7 और 38.6 प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 33.5 प्रतिशत और 33.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दिसंबर 2020 तक 6 प्रतिशत अंक की छलांग के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन की मात्रा में 76.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मूल्य वृद्धि दर 99.4 प्रतिशत पर स्थिर रही। इस समय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की संभावना को देखते हुए और नवाचार, सुलभता और ग्राहक सुविधा को मजबूत करने और उसे बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा हाल ही में यूपीआई पर थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स (टीपीएपी) पर किए गए लेन-देन पर मात्रा कैप लागू की गई है।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से बिल भुगतान में तेजी आई, जिसमें मात्रा में 84 प्रतिशत (पिछले महीने 86.2 प्रतिशत) और मूल्य में 106 प्रतिशत (पिछले महीने 97.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सिस्टम पर ऑनबोर्डिंग द्वारा डिजिटल मोड और बिलर्स के तेजी से प्रतिसाद के कारण उपभोक्ता संबंध में वृद्धि होने से बीबीपीएस गतिविधि सीमित की गयी है।

अग्रानुक्रम में आर्थिक पुनरुद्धार गति को दर्शाते हुए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) के वृद्धि में पिछले महीने में क्रमशः मात्रा में 60.4 प्रतिशत और मूल्य में 115.2 प्रतिशत और 83.3 प्रतिशत के शीर्ष पर 48.1 प्रतिशत का क्रमिक सुधार देखा गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत निधियों के वितरण के कारण आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (एइपीएस) और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के टर्नओवर से ग्रामीण इलाकों से मांग में वृद्धि का पता चलता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस योजना के तहत त्रैमासिक किश्तों के रूप में लाभार्थी किसानों के खातों में धन के संवितरण के आधार पर 2020 के अप्रैल, अगस्त और दिसंबर के महीनों में एनएसीएच वृद्धि में तेजी आई। इन ऋण-व्यवस्थाओं की मिररिंग करते हुए इन महीनों में एईपीएस के माध्यम से या उसके तुरंत बाद नकद निकासी में जनवरी 2021 में मात्रा में 89.1 प्रतिशत और मूल्य में 92.3 प्रतिशत अपटिक्स (पूर्ववर्ती लेनदेन की कीमत से अधिक मूल्य पर शेयर बाजार में एक लेनदेन) देखा गया। त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड, एइपीएस और ऑफ़लाइन जैसे भुगतान विकल्पों के आने से, ग्रामीण भारत निकट भविष्य में डिजिटल भुगतानों का नतिपरिवर्तन बिंदु बन सकता है, जिसके लिए रिज़र्व बैंक डिजिटल समावेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सक्षम नीति वातावरण प्रदान करने का प्रयास कर रहा है।

जनवरी 2021 का महीना भी नियामक मोर्चे पर महत्वपूर्ण कार्यों से भरा हुआ था। कुछ अनधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल ऐप द्वारा अपनाई जा रही अनुचित उधार प्रथाओं का संज्ञान लेते हुए रिज़र्व बैंक ने वित्तीय नवाचार और उपभोक्ता संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए एक उचित नियामक दृष्टिकोण की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु विनियमित और अनियमित वित्तीय संस्थाओं के बीच डिजिटल ऋण गतिविधियों के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया है। फरवरी में, रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं के लिए न्यूनतम मानकों को लागू करते हुए "डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निर्देश" जारी किया है। एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में, चेक-आधारित लेनदेन की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए चेक के लिए पोजेटिव पे सिस्टम 1 जनवरी 2021 से शुरू हो गई है। डिजिटल इंडिया के विज़न को प्राप्त करने की दिशा में काम करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से प्रभावी, अपने भुगतान अवसंरचना विकास निधि का संचालन किया है, जिसका उद्देश्य टियर III से VI केंद्रों में डिजिटल भुगतान अवसंरचना को बढ़ाना है। त्वरित शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए, रिज़र्व बैंक 24X7 डिजिटल भुगतान हेल्पलाइन स्थापित करेगा और वर्तमान के तीन लोकपाल सुविधाओं को एक में एकीकृत करने के लिए "वन नेशन, वन लोकपाल" योजना शुरू करेगा। इनोवेशन स्पेस से 'खुदरा भुगतान' के साथ विनियामक सैंडबॉक्स के दल और 'सीमा पार से भुगतान' के साथ दूसरे दल की घोषणा' विषय के साथ का पहला परीक्षण चरण की शुरुआत का समाचार प्राप्त हो

रहा है। महामारी के दौरान संपर्क रहित भुगतान की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से ₹2,000 से ₹5,000 तक कार्ड (और यूपीआई) के माध्यम से आवर्ती लेनदेन के लिए संपर्क रहित कार्ड लेनदेन और ई-जनादेश की सीमा बढ़ा दी है।

निष्कर्ष

वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखने का नज़रिया अचानक से आए वायरस के नए, तेज संचारी योग्य स्ट्रेन से घिरा हुआ है, जिसके खिलाफ वैक्सीन निर्माताओं को तेजी से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। यह इस संदर्भ में है कि विश्व स्तर पर टीकों का फैलाव के लिए एक अच्छी समन्वित और तेज रणनीति की अबिलंब आवश्यकता है। भारत, कुछ अन्य देशों की तरह, तेजी से फैलाव कार्यक्रम शुरू किया जिसमें पहले से ही 20 से अधिक देशों को अनुदान और वाणिज्यिक आपूर्ति के रूप में शामिल किया गया है। हाल ही में कुछ राज्यों में संक्रमण में वृद्धि और एक भारतीय उत्परिवर्तन के अलगाव के बावजूद अधिक आपूर्ति और अधिक टीके पाइपलाइन में हैं। हालांकि संतुलन पर, काफी अनिश्चितता ने हमारे आउटलुक को चारों ओर से घेर लिया है, लेकिन इसके रिकवरी की शक्ति और इसके व्यापक दायरे आशावाद और जीवित रहने और संभलने की जिजीविषा रखती है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 26 फरवरी को जारी किए गए राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमानों – तीसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी ने पहली छमाही के संकुचन को हटा दिया है और सकारात्मक क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया - को इस लेख ने पुष्टि की है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमानों में 2020-21 का खाद्यान्न उत्पादन 303 मिलियन टन रखा गया, जोकि अब तक की सभी प्रमुख फसलों और रबी और खरीफ दोनों मौसमों के लिए है। इस मंदी से उभरने के साथ कारोबार फिर से खुलने और उपभोक्ताओं का कार्यालयों और दुकानों में वापस आने से भारतीय अर्थव्यवस्था ने मुसीबत के दिन पार कर लिया है। ये सभी मुद्रास्फीति सकारात्मक गतिविधियां हैं। एक साल पहले की तुलना में दालों का उत्पादन 6 प्रतिशत अधिक है, खाद्यान्न के क्षेत्र में मुद्रास्फीति कम निर्धारित की गई है, लेकिन मूल मुद्रास्फीति की कमी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जबकि पेट्रोलियम उत्पादों पर अत्यधिक उच्च उत्पाद शुल्क सार्वजनिक वित्त की स्थिति के लिए मुसीबत बनी हुई है, लेकिन राजस्व के अन्य प्रमुखों में उछाल इस स्ट्रगल को ढीला कर सकता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने की गैस की पंप कीमतों को और अधिक तुलनीय स्तर पर ला सकता है, मुद्रास्फीति दृष्टिकोण में सुधार और उपभोक्ता कल्याण का विस्तार कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण से भी, भारत के लिए महंगाई की स्थिति से उबरना महत्वपूर्ण है और उत्पादकता और दक्षता के लाभ को पुनः प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था को पुन: तैयार करे और संरचनात्मक सुधार करे।

वर्ष 2020-21 की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थितियों का विकास करीब आ रहा है और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हमारे लिए एक चुनौती खडा करेगी। राजकोषीय नीति अधिकारियों को अर्थव्यवस्था को उभारने में आनेवाले मुसीबत और स्थायी वित्त सुनिश्चित करने की लठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मौद्रिक अधिकारियों को अभी भी बढ़े हुए ऋण की आवश्यकता के समक्ष ब्याज दर संरचना के क्रमबद्ध विकास के लिए समझौतापरक और वसूली का समर्थन करना पड़ता है। जबकि नीति अधिकारी अपनी प्रतिबद्धता का पूर्णता से प्रदर्शन कर रहे हैं, बाजार अनिश्चितता का शिकार हो रहे हैं और रिटर्न के लिए छिटपुट बदलाव कर सुरक्षित स्थान की ओर लौट रहे हैं। एक साझा समझदारी और सामान्य अपेक्षाएं इस हलचल में सहारा दे सकता है। बाजार और संस्थानों को कार्यशील बनाए रखने के लिए, उधार लेने और लागत को आसान बनाने में; वित्त प्रवाह को बनाए रखने के लिए अधिकारियों के ट्रैक रिकॉर्ड पर - वास्तव में बहुत कम निर्भर करना है- निर्भर रहना पड़ता है। प्रतिफल वक्र का एक क्रमिक विकास सभी कार्य करता है। उभरती अर्थव्यवस्था के कारण सभी लोग उससे लाभ प्राप्त करेंगे और बाजार तरक्की पाने के लिए संघर्ष कर रहे नीति अधिकारियों को समर्थन देने से बेहतर कोई कार्य नहीं कर सकते।

आज इसमें थोड़ा संदेह है कि खपत की बहाली पर आधारित वसूली चल रही है। इस तरह की उथले और अल्पकालिक वसूली की ओर निर्णायकों का ध्यान जा रहा है। निवेश के लिए रूचि बढ़ाने में तेजी लाना महत्वपूर्ण है, जिंदादिली को जागृत करना ना कि निष्क्रियता के बजाय कार्रवाई के लिए एक सहज आग्रह, और

मात्रात्मक संभावनाओं से गुणित मात्रात्मक लाभों के भारित औसत के परिणाम के रूप में [13] कुल मांग के सभी इंजनों को चालू किया जा रहा है; केवल निजी निवेश कार्यशील नहीं है। यह समय निजी निवेश के क्रियाशील रहने के लिए उपयुक्त है। राजकोषीय नीति, अब तक के सबसे बड़े कैपेक्स बजट और बेहतर व्यवसाय करने पर जोर देते हुए, इसमें निजी निवेश का अंतर्गमन की पेशकश की है। क्या भारतीय उद्योग और उद्यमिता मिलकर इसका लाभ उठाएंगे?

[13] जॉन मेनार्ड कीन्स द जनरल थ्योरी ऑफ एंप्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936

*भारत में बैंक ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन: हाल के घटनाक्रम**

बैंक ऋण में वर्ष 2019-20 में मंदी देखी गई, जिसे कोविड-19-प्रेरित तालबंदी (लॉकडाउन) के कारण वर्ष 2020-21 में एक और झटका लगा। हालांकि, आर्थिक गतिविधियों के धीरे-धीरे पुनरारंभ के साथ, कृषि और सेवा क्षेत्रों के ऋण ने हालिया अवधि में त्वरित वृद्धि दर्ज की है। औद्योगिक क्षेत्र में भी मध्यम उद्योगों को अधिक ऋण प्रदान किए जा रहे हैं। अनुभवजन्य अनुमानों से संकेत मिलता है कि खाद्येतर ऋण एक अंतराल में ब्याज दर में बदलाव के प्रति संवेदनशील है, वहीं उद्योग और सेवा क्षेत्रों में कहीं अधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित होती है।

भूमिका

भारत जैसे विकासशील देश में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए वित्त का प्रमुख स्रोत बैंक ऋण है, हालांकि वित्त के बाजार-आधारित स्रोतों ने भी हाल के वर्षों में महत्व प्राप्त किया है। अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के बीच बैंक ऋण का पर्याप्त और समान वितरण शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के बीच लगातार चिंता का विषय रहा है (याकुबू और अफोइ, 2014; मकिंडे, 2016)।

खाद्येतर ऋण में 2018-19 में काफी वृद्धि हुई थी और नवंबर 2019 में इसमें सबसे अधिक 15% की साल-दर-साल (y-o-y) की वृद्धि दर्ज की गई। आर्थिक विकास में मंदी के फलस्वरूप 2019-20 के दौरान यह काफी धीमा हो गया। कोविड-19 जन्य लॉकडाउन में मंदी के आसार तीव्र हो गए थे और दो क्रमिक तिमाहियों, अर्थात् ति1 और ति2: 2020-21 में नकारात्मक आर्थिक वृद्धि देखी गयी। आर्थिक गतिविधियों के बंद होने के कारण ऋण की मांग पर गंभीर प्रभाव पड़ा और परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण संवृद्धि में कमी आई। भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक समुत्थान को बढ़ावा देने हेतु अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त और बेरोक ऋण-प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं, क्योंकि बैंक ऋण चैनेल भारत में मौद्रिक नीति संचारण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों के लिए बैंक ऋण प्रवाह के महत्व को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक लगभग एक महीने के अंतराल पर प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस पर बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन के डेटा का संकलन और प्रकाशन करता आ रहा है। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करने वाले इन आंकड़ों को चुनिंदा बैंकों से एकत्र किया जा रहा है, इन बैंकों में क्षेत्रवार और औद्योगिक बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न के माध्यम से भारत में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा विस्तारित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा है।

यह आलेख कोविड-19 महामारी से पहले की अवधि के दौरान बैंक ऋण के क्षेत्रवार विनियोजन में हुए विकास का विश्लेषण प्रस्तुत करता है और उसकी तुलना कोविड-19 की अवधि के दौरान, यानी अप्रैल से नवंबर, 2020-21 के दौरान हुई गतिविधियों से करता है।

यह आलेख ब्याज दर में बदलाव के प्रति खाद्येतर ऋण की संवेदनशीलता के बारे में प्रायोगिक अनुमान देता है। यह आलेख निम्नानुसार संयोजित किया गया है: खंड II 2020-21 के दौरान खाद्येतर ऋण वृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियाँ प्रस्तुत करता है। खंड III हालिया अवधि में सेक्टरवार ऋण में प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने पर रुझान प्रस्तुत करता है। खंड IV में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के प्रति ऋण की ब्याज-दर संवेदनशीलता पर प्रायोगिक निष्कर्ष की प्रस्तुति खंड V में समापन टिप्पणियों के साथ हुई है।

II. वर्ष 2020-21 में खाद्येतर ऋण संवृद्धि: महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

खाद्येतर ऋण में 2018-19 में तेजी से वृद्धि हुई थी, जबकि 2019-20 में यह काफी धीमी हो गई; मार्च 2020 में यह वृद्धि 6.1 प्रतिशत थी, जबकि एक साल पहले यह 13.4 प्रतिशत थी। नवंबर 2020 में इसमें 5.9 प्रतिशत तक की गिरावट आयी,

* यह आलेख भारतीय रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग के आनंद प्रकाश और सुजीश कुमार द्वारा तैयार किया गया है। डॉ. राजीव रंजन द्वारा मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए लेखक आभारी हैं। इस आलेख को तैयार करने में श्री सागर सुनील बाधे द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए लेखक उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और ये भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं।

चार्ट 1: खाद्येत्तर ऋण में वृद्धि- प्रमुख क्षेत्र

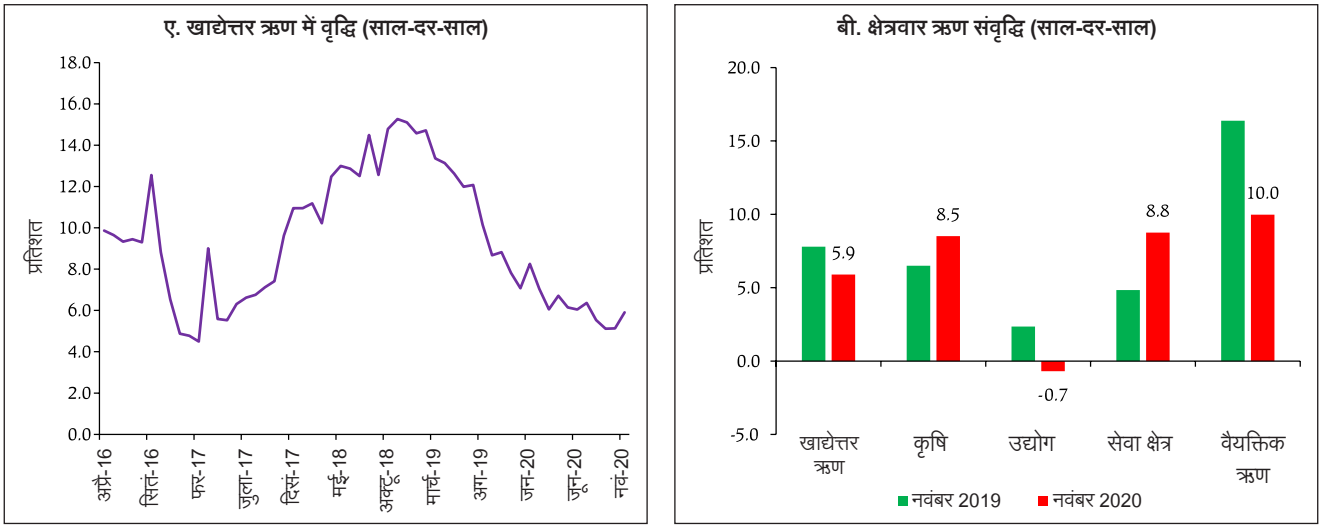

टिप्पणियाँ: खाद्येत्तर ऋण आंकड़े सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले धारा 42 विवरणी पर आधारित हैं।
क्षेत्रवार ऋण आंकड़े चुनिन्दा बैंकों से संबन्धित हैं, जो कि सभी एससीबी द्वारा विस्तारित कुल खाद्येत्तर ऋण का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा है।

जबकि एक साल पहले यह 7.8 प्रतिशत थी (चार्ट 1ए)। इस व्यापक गिरावट का कारण आर्थिक मंदी के कारण सभी प्रमुख क्षेत्रों में हो रही निम्नतर वृद्धि थी। महामारी-जन्य तालाबंदी (लॉकडाउन) के परिणामस्वरूप 2020-21 की पहली छमाही में समग्र आर्थिक गतिविधियों में तीव्र संकुचन हुआ। हालांकि, हाल के महीनों कृषि क्षेत्र के लिए ऋण संवृद्धि में कायापलट हुआ है। सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि 2019-20 की दूसरी छमाही में बहुत मंद हो गयी थी, उसमें भी हालिया महीनों में तेजी आई है (चार्ट 1बी और 2ए)।

ऋण वृद्धि में सकारात्मक बदलाव के कारण, सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में नवंबर 2019 और नवंबर 2020 के बीच वृद्धिशील ऋण प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई (चार्ट 2बी)। औद्योगिक क्षेत्र में नवंबर 2019 और नवंबर 2020 के मध्य ऋण वृद्धि ऋणात्मक हो

चार्ट 2: ऋण संवृद्धि और अंश - प्रमुख क्षेत्र

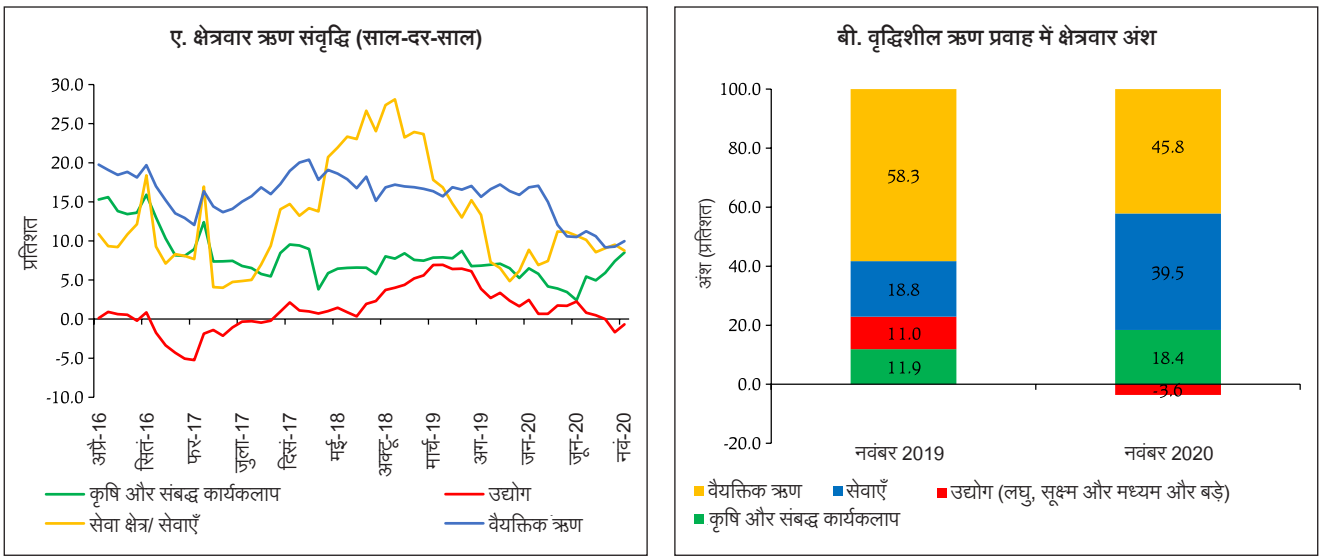

टिप्पणियाँ: आंकड़े चुनिन्दा बैंकों से सबंन्धित हैं, जो कि सभी एससीबी द्वारा विस्तारित कुल खाद्येत्तर ऋण का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा हैं।

गई और इस अवधि के दौरान वृद्धिशील ऋण प्रवाह में ऋणात्मक हिस्सेदारी दर्ज की गई। कुल वृद्धिशील ऋण प्रवाह में व्यक्तिगत ऋणों की हिस्सेदारी भी नवंबर 2019 में 58 प्रतिशत से घटकर नवंबर 2020 में लगभग 46 प्रतिशत हो गई, जिससे इस क्षेत्र में ऋण की वृद्धि में गिरावट आई।

क्षेत्रवार ऋण डेटा के एक और विश्लेषण से पता चलता है कि निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) ने नवंबर 2020 में खाद्येत्तर ऋण में 31.9 प्रतिशत की हिस्सेदारी दर्ज करते हुए, ऋण में आई शिथिलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीवीबी द्वारा दिये गये खाद्येत्तर ऋण नवंबर 2020 में घटकर 9.0 प्रतिशत हो गया, जबकि एक साल पहले यह 13.5 प्रतिशत था। हालांकि, खाद्येत्तर ऋण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का हिस्सा लगभग 65 प्रतिशत था, जिन्होंने नवंबर 2019 में 4.5 प्रतिशत की तुलना में नवंबर 2020 में 5.2 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्ज की। हालिया समय में कृषि और सेवा क्षेत्रों के लिए ऋण में त्वरित वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को जाता है, वे समग्र औद्योगिक ऋण में संकुचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैयक्तिक ऋण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की महत्वपूर्ण उपस्थिति होने के कारण ने वैयक्तिक ऋण की वृद्धि में तीव्र मंदी को प्रेरित किया है। इससे स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) महामारी अवधि में ऋण संवृद्धि के पुनःप्रवर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं (सारणी 1)।

सारणी 1: प्रमुख क्षेत्रों की ऋण संवृद्धि के साथ कुल ऋण में उनका शेयर

प्रमुख क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		सभी बैंक	
	नवंबर-2019	नवंबर-2020	नवंबर-2019	नवंबर-2020	नवंबर-2019	नवंबर-2020
खाद्येत्तर ऋण	4.5 (65.4)	5.2 (64.8)	13.5 (31.1)	9.0 (31.9)	7.2 (100)	6.0 (100)
कृषि	4.4 (76.4)	7.6 (75.7)	13.1 (22.2)	10.7 (22.7)	6.5 (100)	8.5 (100)
उद्योग	0.4 (67.8)	-2.1 (66.9)	8.0 (27.8)	4.3 (29.2)	2.4 (100)	-0.7 (100)
सेवाएँ	3.2 (62.7)	9.1 (62.9)	7.0 (32.3)	8.8 (32.3)	4.8 (100)	8.8 (100)
वैयक्तिक ऋण	12.1 (59.9)	9.1 (59.4)	25.6 (37.8)	12.5 (38.7)	16.4 (100)	10.0 (100)

टिप्पणियाँ: खाद्येत्तर ऋण आंकड़े सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले धारा 42 विवरणी पर आधारित हैं। कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कुल हिस्से में शेयर दर्शाते हैं। कुल शेयरों का मूल्य 100 नहीं है क्योंकि इसमें विदेशी बैंकों का शेयर नहीं लिया गया है।

वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के बाद से ऋण संवृद्धि में तीव्र ह्रास के परिणामस्वरूप मार्च 2019 और सितंबर 2020 के बीच ऋण-जमा (सीडी) अनुपात में तेजी से गिरावट आई है। ऋण संवृद्धि की तुलना में जमाराशि में अधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष तरलता आयी है, जिसके कारण बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक निवेश कर रहे हैं। ऋण-जमा (सीडी) अनुपात में गिरावट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी), दोनों के मामले में देखी गई थी (सारणी 2)।

II.1 वर्ष 2020-21 के दौरान ऋण प्रवाह (अक्टूबर 2020 तक)

अप्रैल-फरवरी 2019-20 से संबंधित ऋण प्रवाह डेटा महामारी-पूर्व की अवधि का वर्णन करते हैं, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2020 महामारी की अवधि से संबंधित हैं।[1] महामारी-पूर्व की अवधि में 22.8 प्रतिशत संवृद्धि की तुलना में महामारी की अवधि के दौरान संवितरित नए ऋण की संवृद्धि (वर्षानुवर्ष) तेजी से घटकर 8.1 प्रतिशत पर आ गई (चार्ट 3)। महामारी-पूर्व की अवधि के दौरान पूर्वभुगतान में 32.4 प्रतिशत की उच्चतर वर्षानुवर्ष संवृद्धि हुई, जबकि महामारी की अवधि में यह 17.8 प्रतिशत थी। यहां तक कि पुनर्भुगतान में भी कमी आयी है और महामारी-पूर्व की अवधि की तुलना में महामारी की अवधि के दौरान रोलओवर बढ़े हैं। इस प्रकार, महामारी-पूर्व की अवधि में होने वाली डीलिवरेजिंग की सीमा महामारी के दौरान कम होती लग रही है। यह भी प्रतीत होता है कि कंपनियाँ (कॉरपोरेट्स) और परिवारों ने ऋण चुकौती पर अधिस्थगन (लोन रिपेमेंट पर मोराटोरियम) का उपयोग संकट के कारण उत्पन्न निधियन दबाव से उबरने के लिए कर लिया है।

सारणी 2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का ऋण-जमा अनुपात

बैंक समूह	कोविड-पूर्व अवधि		कोविड की अवधि में
	मार्च-19	मार्च-20	सितंबर-20
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	72.85	70.18	66.40
निजी क्षेत्र के बैंक	91.36	90.45	86.73
सभी बैंक	78.18	76.00	72.04

स्रोत: आरबीआई, डीबीआईई

[1] ऋण प्रवाह डेटा को नियमित एसआईबीसी विवरणी के भाग के रूप में नहीं मांगा जा रहा है और आवश्यकतानुसार चुनिन्दा बैंकों से एकत्र किया जा रहा है।

चार्ट 3: वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान ऋण प्रवाह में संवृद्धि (वर्षानुवर्ष)

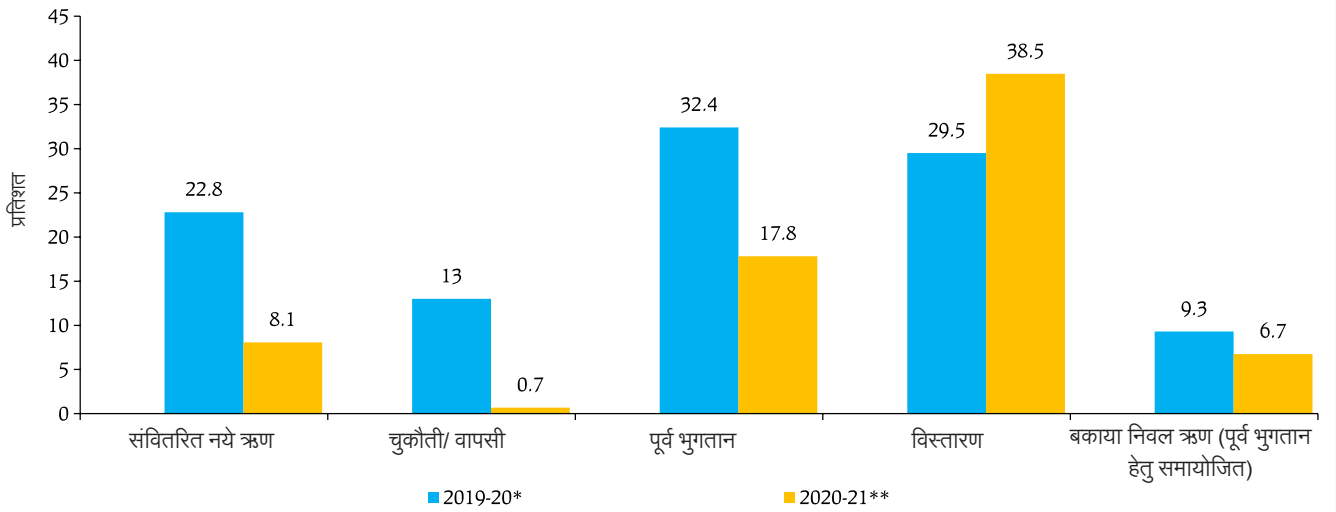

टिप्पणियाँ: आंकड़े चुनिन्दा बैंकों द्वारा विस्तारित ऋण पर आधारित हैं, जो कि फरवरी 2020 और अक्टूबर 2020 के अंत में बकाया खाद्येत्तर ऋण का क्रमशः लगभग 72 प्रतिशत और 83 प्रतिशत है।
*वर्ष 2019-20 के लिए ऋण प्रवाह संवृद्धि दरें, अप्रैल-फरवरी की अवधि के लिए हैं,
**वर्ष 2020-21 के लिए ऋण प्रवाह संवृद्धि दरें, अप्रैल-अक्टूबर की अवधि के लिए हैं,

III. अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के लिए बैंक ऋण

III.1 कृषि और संबद्ध कार्यकलाप

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक साल पहले की तुलना में नवंबर 2020 में कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए ऋण संवृद्धि में तेजी आई। हालिया महीनों में इस क्षेत्र में ऋण संवृद्धि बढ़ रही है जो कि जून 2019 के बाद से नवंबर 2020 में सबसे अधिक रही है। कृषि क्षेत्र, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार का एक हिस्सा है, जिसके लिए ऋण में वृद्धि इस क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन का सूचक है।

पीएसबी के कुल ऋण पोर्टफोलियो में कृषि की हिस्सेदारी पीवीबी की तुलना में अधिक थी। जबकि पीएसबी और पीवीबी दोनों के लिए कृषि ऋण वृद्धि में बढ़ोतरीहुई, पीवीबी के मामले में यह वृद्धि अधिक रही। उच्च वृद्धि के कारण, एससीबी के बकाया खाद्येतर ऋण में यद्यपि कृषि का हिस्सा लगभग 13 प्रतिशत रहा, नवंबर 2019 और नवंबर 2020 बैंक के बीच वृद्धिशील ऋण में इसकी हिस्सेदारी में काफी तेजी आई । लॉकडाउन के बावजूद, कृषि क्षेत्र ने 2019-20 में रिकॉर्ड उत्पादन के बूते पर अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया है। कृषि क्षेत्र का अच्छा प्रदर्शन ग्रामीण उपभोग और औद्योगिक क्षेत्र में पुनरुत्थान के लिए अच्छा संकेत है जिसका आगे चलकर औद्योगिक क्षेत्र के लिए ऋण पर एक अच्छा प्रभाव पड़ सकता है (चार्ट 4, अनुलग्नक-टी1 और टी2)।

III.2 उद्योग

औद्योगिक ऋण (इंडस्ट्रियल क्रेडिट) के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को दिया जाने वाला ऋण आता है। यह विभाजन प्लांट और मशीनरी में फर्मों के निवेश और उनके कारोबार (टर्नओवर) के अनुसार होता है।[2] नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाले ऋण का लगभग 82 प्रतिशत हिस्सा बड़े उद्योगों को था और शेष सूक्ष्म, लघु और मध्यम को। हाल के वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाला ऋण सामान्यत: कमजोर रहा है। अप्रैल 2019 में 6.9 प्रतिशत की ऊँचाई हासिल हुई थी, लेकिन तब से ऋण उठाव (क्रेडिट ऑफटेक) में लगातार गिरावट है, और अक्टूबर 2020 में ऋण वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी। ऋण वृद्धि में हालिया गिरावट मुख्य रूप से बड़े उद्योगों के कारण थी। बड़े उद्योगों में दबावग्रस्त आस्तियों के कारण, इन उद्योगों को उधार देने के मामले में बैंकरों

[2] मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) प्रणाली/ राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) में वर्गीकरण के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र की 18 व्यापक उप-श्रेणियों पर बकाया ऋण की जानकारी को एसआईबीसी रिटर्न के माध्यम से एकत्र किया जाता है।

चार्ट 4: कृषि के लिए ऋण संवृद्धि

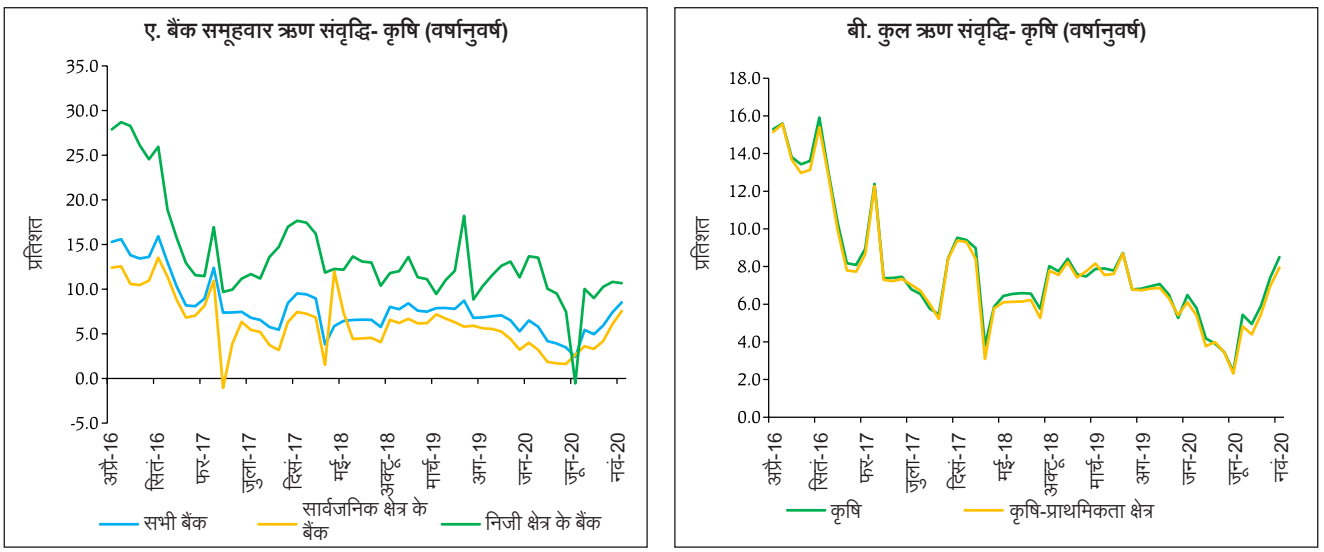

टिप्पणियाँ: आंकड़े चुनिन्दा बैंकों से संबन्धित हैं, जो कि सभी एससीबी द्वारा विस्तारित कुल खाद्येत्तर ऋण का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा है।

की ओर से एक सामान्य अनिच्छा थी तथा इस समस्या को और जटिल बना दिया महामारी ने।

यद्यपि नवंबर 2020 में बड़े उद्योगों को जाने वाली ऋण में वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी, लेकिन इसके बीच आशा की किरण मध्यम उद्योगों के लिए ऋण की मजबूत वृद्धि रही है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण ने नवंबर 2019 और नवंबर 2020 (चार्ट 5.ए) के बीच मामूली वृद्धि दर्ज की।

पीएसबी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दिए गए क्रेडिट (ऋण) में संकुचन दिसंबर 2019 में शुरू हुआ और 2020 में अबाध जारी है। पीवीबी द्वारा औद्योगिक ऋण वृद्धि जून 2020 तक अधिकांशत:

चार्ट 5: उद्योग के लिए ऋण संवृद्धि

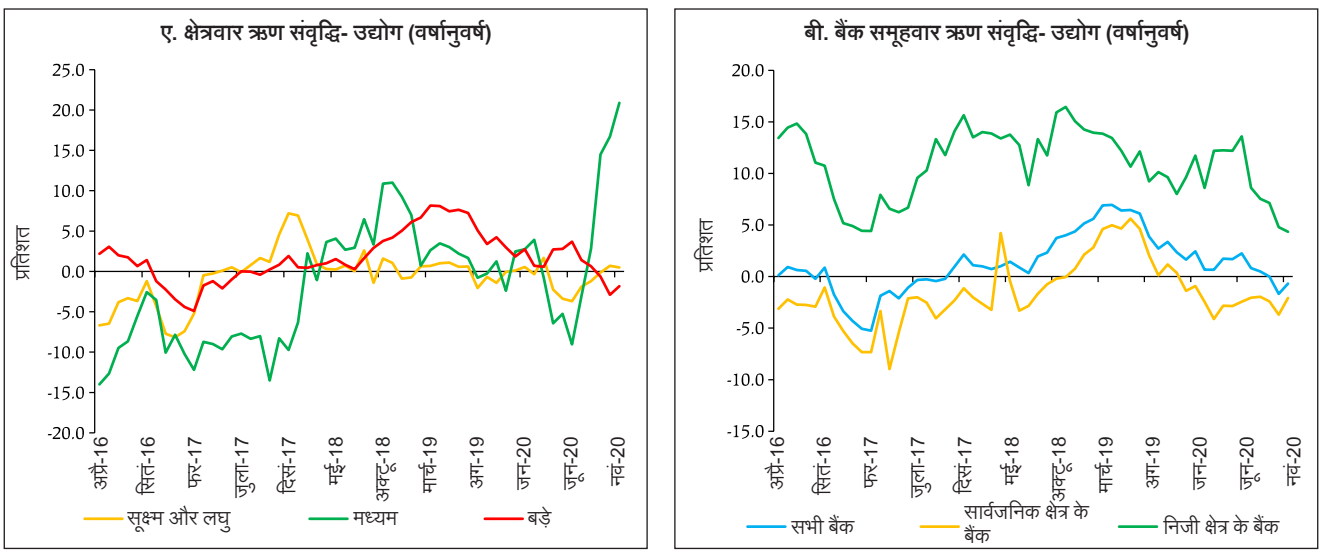

टिप्पणियाँ: आंकड़े चुनिन्दा बैंकों से संबन्धित हैं, जो कि सभी एससीबी द्वारा विस्तारित कुल खाद्येत्तर ऋण का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा है।

दोहरे अंकों में थी। तथापि, तब से इसमें काफी तेजी से ह्रास हुआ है और नवंबर 2020 में यह 4.3 प्रतिशत के निम्न स्तर को छू गया (चार्ट 5.बी)। 2021 में और उसके बाद समुत्थान के लिए तैयार भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हुए, औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाले ऋण में बेहतरी की प्रत्याशा है।

III.2.ए. औद्योगिक उपक्षेत्र को ऋण

जहां तक औद्योगिक उपक्षेत्र में ऋण का सवाल है, 'खाद्य-प्रसंस्करण', 'पेट्रोल', 'कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन', 'चमड़ा तथा चमड़े के उत्पाद', 'कागज़ और कागज़ के उत्पाद', 'खनन और उत्खनन', 'काँच और काँच के बने पदार्थ', 'कपड़े', 'पेय पदार्थ और तंबाकू', और 'वाहन, वाहन के पुर्ज़े और परिवहन उपकरण', के ऋण ने नवंबर 2020 में त्वरित वृद्धि दर्ज की। हालांकि, 'रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद', और 'निर्माण' की ऋण वृद्धि में गिरावट आयी, जबकि 'सीमेंट और सीमेंट के उत्पाद', 'सभी अभियांत्रिकी', 'रत्न एवं आभूषण', 'आधारिक संरचना', और 'मूल धातु और धातु के उत्पाद', में ऋण वृद्धि सिकुड़ गयी (चार्ट 6)।

III.2.बी. सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

नवंबर 2020 के औद्योगिक ऋण में 18 प्रतिशत तथा एससीबी द्वारा विस्तारित खाद्येत्तर ऋण में 5 प्रतिशत भाग एमएसएमई क्षेत्र का था। एमएसएमई ऋण का विकास हाल के वर्षों में कम ही था, महामारी की वजह से और कम हो गया। हालांकि, इस क्षेत्र के ऋण में कुछ बदलाव रहा है, हाल के महीनों में ख़ास कर मध्यम उद्योगों के लिए विस्तारित ऋण वृद्धि में तेज़ी से बढ़ोतरी के कारण।

मध्यम उद्योगों के लिए ऋण वृद्धि में तेज़ी से बढ़त के कारण, एक साल पहले जो पूरा ऋण एमएसएमई क्षेत्र के लिए 0.6 प्रतिशत पर सिकुड़ गया था, उसकी तुलना में नवंबर 2020 में यह बढ़कर 5.0 प्रतिशत हो गया। यह भारत सरकार तथा रिज़र्व बैंक द्वारा इस क्षेत्र में महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। पीएसबी तथा पीवीबी दोनों के द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण वितरण में जुलाई 2020 से कुछ सुधार देखे गए (चार्ट 7ए और 7बी)।

III.2.सी. आधारिक संरचना

नवंबर 2020 के औद्योगिक ऋण में करीब 36.6 प्रतिशत भाग आधारिक संरचना का था। आधारिक संरचना क्षेत्र के ऋण, ने 2009-10 के समय से काफी गिरावट देखी तथा 2016-17 और 2017-2018 के समय तो सिमट-सा गया था। 2018-19 में वापसी की। 2018-19 में आधारिक संरचना क्षेत्र में ऋण वृद्धि में

चार्ट 6: प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

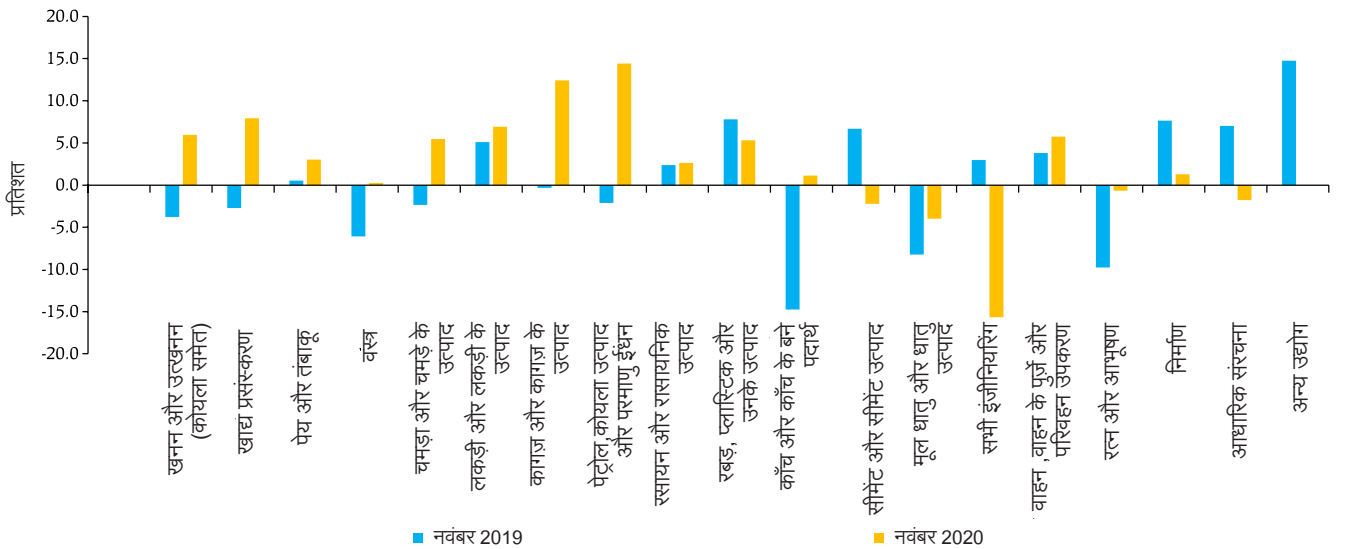

टिप्पणी: आंकड़े चनिुन्दा बैंकों से सबंन्धित हैं, जो कि सभी एससीबी द्वारा विस्तारित कुल खाद्येत्तर ऋण का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा है।

चार्ट 7: एमएसएमई को ऋण

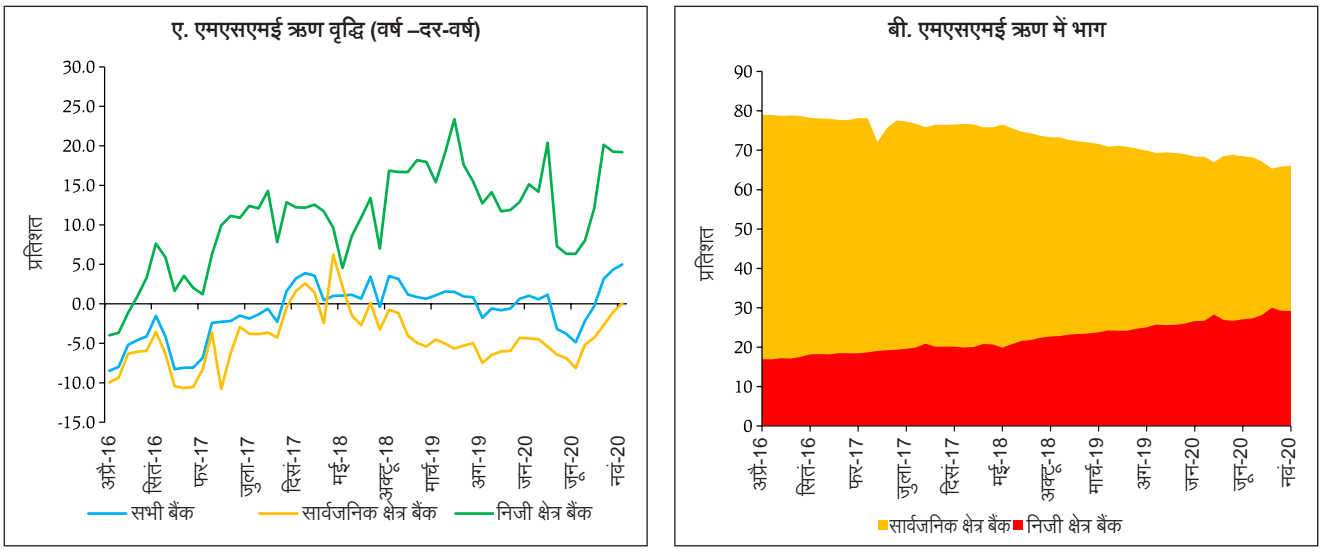

टिप्पणी: आंकड़े चुनिन्दा बैंकों से सबंन्धित हैं, जो कि सभी एससीबी द्वारा विस्तारित कुल खाद्येत्तर ऋण का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा है।

तेज़ी से उछाल बैंकों द्वारा ख़ास कर निवेशकों को बिजली, सड़क और बंदरगाह, दूरसंचार, और अन्य आधारिक संरचना क्षेत्र जैसे निर्माण, रेलवे, तेल टर्मिनल और जलमार्ग क्षेत्र में ऋण वितरण के पीछे था। हालांकि, 2019-20 और 2020-21 तक यह गति बरकरार नहीं रह सकी।

आधारिक संरचना ऋण में सबसे ज़्यादा भाग बिजली क्षेत्र का है जो कि 55 प्रतिशत है उसके बाद सड़क और बंदरगाह (करीब 20 प्रतिशत) और दूरसंचार (10 प्रतिशत) हैं। सड़क और बंदरगाह तथा दूरसंचार क्षेत्र के ऋण अब तक के आधारिक संरचना ऋण वृद्धि के प्रमुख चालक रहे हैं लेकिन हाल के समय में, सड़क और बंदरगाह क्षेत्र में केवल ऋण वृद्धि हो रही है, जबकि दूरसंचार और बिजली क्षेत्र में गिरावट देखी गयी (चार्ट 8ए)।

पीएसबी, जो कि सबसे आगे है, आधारिक संरचना ऋण के 76 प्रतिशत के साथ, ने गिरावट का नेतृत्व किया। पीवीबी, ने भी जो कि काफी सुदृढ़ थे पहले, हाल के महीनों में आधारिक संरचना क्षेत्र की ऋण वृद्धि में काफी तेज़ी से गिरावट देखी (चार्ट 8बी)।

III.3 सेवा क्षेत्र

हालांकि 2018-19 में सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि काफी मजबूत थी, 2019-20 में इसकी रफ्तार जाती रही। जबकि, महामारी की वजह से औद्योगिक ऋण और व्यक्तिगत ऋण वृद्धि में साफ़ कमी देखी गयी, इसके विपरीत सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि नीचे की ओर गयी और त्वरित विकास दिखाया गया, यह तेज़ी मुख्यत: 'व्यापार' और 'परिवहन संचालक' के वजह से थी। इसके अलावा 'पर्यटन, होटल, और रेस्तरां' ने भी महामारी के बावजूद भी त्वरित वृद्धि दर्ज की। हालांकि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफ़सी), जो कि सबसे क्षेत्र के सबसे बड़े घटक हैं, उनकी ऋण वृद्धि में तेज़ी से गिरावट आयी (चार्ट 9ए)। महत्वपूर्ण रूप से, पीएसबी और पीवीबी दोनों के द्वारा सेवा क्षेत्र को दिया हुआ ऋण 2020-21 तक सुदृढ़ता दिखायी दी (चार्ट 9बी)।

चार्ट 8: आधारिक संरचना के लिए ऋण

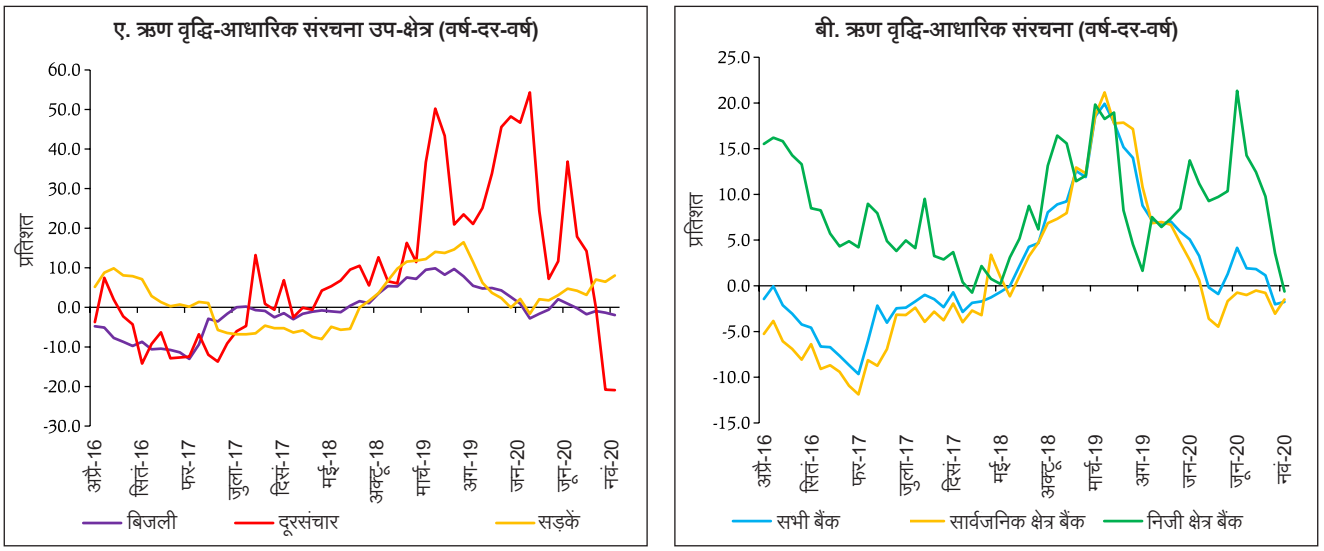

टिप्पणी: आंकड़े चनिुन्दा बैंकों से सबंन्धित हैं, जो कि सभी एससीबी द्वारा विस्तारित कुल खाद्येत्तर ऋण का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा है।

III.3.ए एनबीएफ़सी क्षेत्र

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफ़सी) वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए वित्त के वैकल्पिक चैनल के रूप में काम करती हैं। एससीबी द्वारा विस्तारित ऋण वृद्धि को इस क्षेत्र में पिछले दशक से ही कम किया गया और 2007-08 की तुलना में 2017-18 में तो करीब आधा ही कर दिया गया। नवम्बर 2016 से इस क्षेत्र में ऋण वृद्धि में काफी गिरावट आयी, हालांकि 2018-19 में इस क्षेत्र में तेज़ी देखी गयी। एससीबी द्वारा इस क्षेत्र में विस्तारित ऋण वृद्धि में 2019-20 में कमी आने का कारण अगस्त 2018 में इनफ्रास्ट्रक्चर लीज़िंग और फाईनेंशियल सर्विसेज़ (आईएलएफ़एस) संकट के बाद एनबीएफ़सी का तरलता तनाव तथा रेटिंग का गिर जाना और साथ ही बैंकों का इस क्षेत्र में वित्त पोषण में सतर्क हो जाना था।

चार्ट 9: सेवा (क्षेत्र) के लिए ऋण

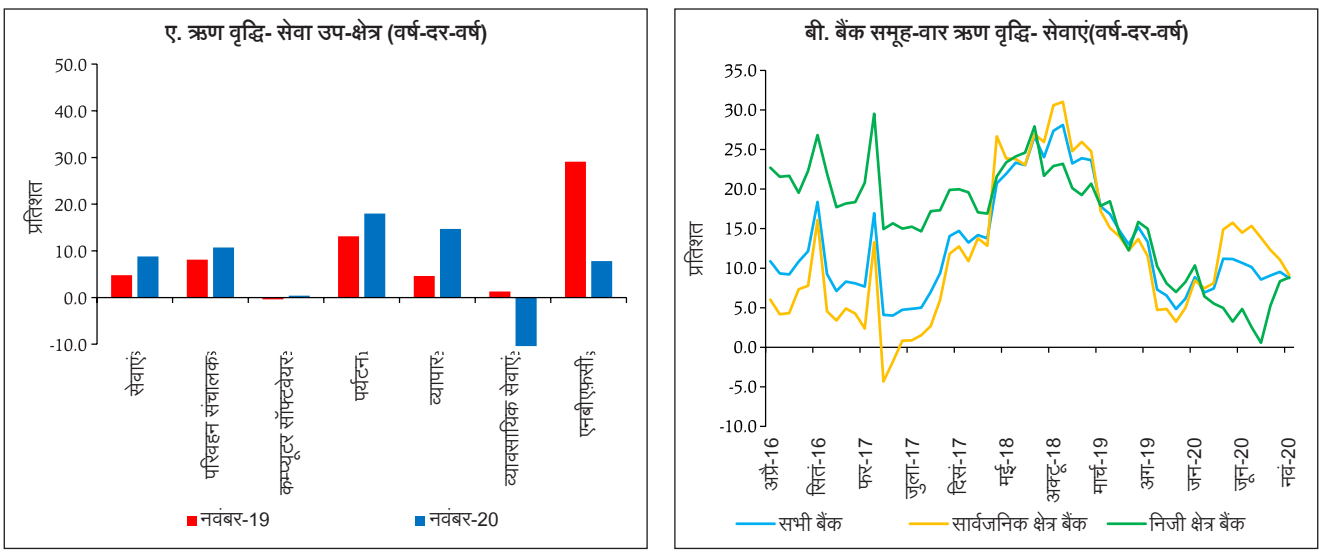

टिप्पणी: आंकड़े चनिुन्दा बैंकों से सबंन्धित हैं, जो कि सभी एससीबी द्वारा विस्तारित कुल खाद्येत्तर ऋण का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा है।

नतीजतन, एनबीएफ़सी क्षेत्र ने मार्च 2020 में ऋण वृद्धि में गिरावट देखी। लॉकडाउन ने इस क्षेत्र में ऋण वृद्धि को और धीमा कर दिया और नवम्बर 2020 तक तो यह और नीचे आ गया।

रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र की तरलता की समस्या को दूर करने के लिए कई कदम उठाए, लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की शुरुआत भी उसमें शामिल है, जिसका लक्ष्य एनबीएफ़सी, ख़ास कर छोटे और सूक्ष्म वित्तीय संस्थान (एमएफ़आई) को तरलता सहायता देना है। 5 फरवरी, 2021 की मौद्रिक नीति वक्तव्य में एमएसएमई उद्यमियों को ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करने के उपाय और सदा-सुलभ योजना पर टीएलटीआरओ में एनबीएफ़सी का समावेश इस दिशा में उठाए गए कदम हैं।

III.3.बी व्यापार

व्यापार क्षेत्र ने महामारी की अवधि में जुलाई 2020 से ऋण वृद्धि में निरंतरता के साथ बढ़ते हुए अच्छा प्रदर्शन किया। थोक एवं खुदरा व्यापार में ऋण वृद्धि अच्छी रही, ख़ास कर तबके समय में जब लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खुली। इस क्षेत्र ने वार्षिक आधार पर भी वृद्धि देखी जैसे मार्च 2020 से उपर नवम्बर 2020. परिणामस्वरूप, वार्षिक वृद्धिशील बैंक ऋण में व्यापार के भाग में नवम्बर 2019 के थोड़े से 3.8 प्रतिशत से नवम्बर 2020 तक 14.1 प्रतिशत तक तेज़ी से वृद्धि हुई (अनुबंध सारणी-टी2)।

III.4. व्यक्तिगत ऋण

व्यक्तिगत ऋण क्षेत्र ने हाल के वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया है, दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज करायी है। 2019-20 के समय आवास ऋण वृद्धि तथा क्रेडिट कार्ड बकाया में गिरावट के कारण कुछ कमी देखी गयी थी। हालांकि, लॉकडाउन लगने के बाद, व्यक्तिगत ऋण ने निरंतर गिरावट दर्ज करायी। इस क्षेत्र में, हालांकि, 'वाहन ऋण' अच्छा प्रदर्शन करता रहा। आवास ऋण, जो कि वैयक्तिक ऋण का सबसे बड़ा घटक है, नवंबर 2020 तक वृद्धि की गति खो दी (चार्ट 10 ए)।

पीवीबी आगे रहा है व्यक्तिगत ऋण क्षेत्र में। जबकि, महामारी ने पीवीबी के व्यक्तिगत ऋण वृद्धि को धीमा कर दिया। हालांकि, अक्तूबर 2020 की तुलना में नवंबर 2020 में कुछ सुधार हुआ है (चार्ट 10बी)।

III.4.ए वाहन ऋण

वाहन ऋण क्षेत्र सामान्य रूप से निजी उपयोग के लिए वाहन ऋण कवर करता है, जैसे कार और दो पहिये के लिए। यद्यपि नियामक शर्तों जैसे भारत VI मानदंड, नए बीमा मानदंड, और

चार्ट 10: व्यक्तिगत ऋण (पर्सनल लोन)

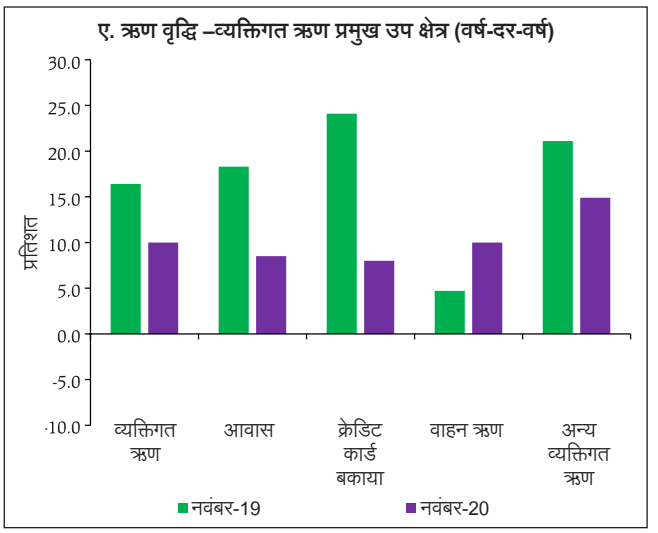

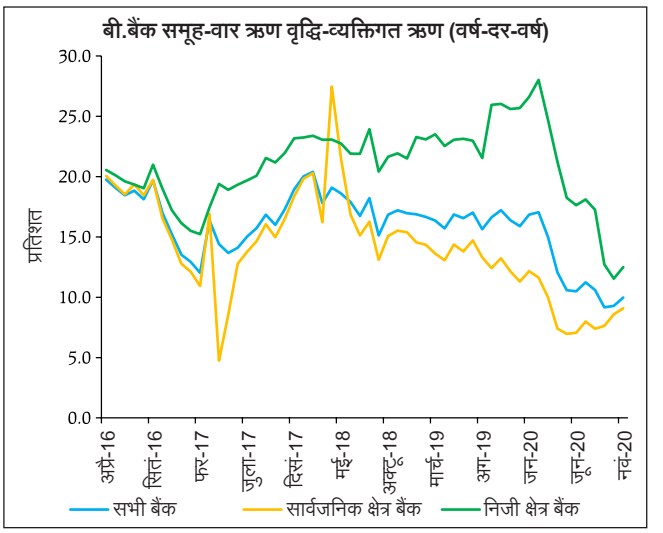

टिप्पणी: आंकड़े चुनिन्दा बैंकों से सबंन्धित हैं, जो कि सभी एससीबी द्वारा विस्तारित कुल खाद्येत्तर ऋण का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा है। वैयक्तिक ऋण से तात्पर्य उन ऋण से है जो घरेलू खपत, चिकित्सा ऋण, यात्रा, शादी, सामाजिक समारोह या ऋण चुकाने आदि के लिए जाते हैं।

जीएसटी के कार्यान्वयन ने प्रभावित किया था वाहन की बिक्री को, वाहन ऋण वृद्धि 2019-20 में थोड़ा पीछे चली गयी। महामारी के कारण व्यक्तिगत वाहन की ज़्यादा प्राथमिकता सार्वजनिक परिवहन की तुलना में होने की वजह से इस क्षेत्र ने 2020-21 में वापसी दिखायी।

III.4.बी क्रेडिट कार्ड बकाया

हाल के वर्षों में डिजिटल भुगतान कि वजह से क्रेडिट कार्ड क्षेत्र का महत्व और बढ़ गया है। महामारी के पहले क्रेडिट कार्ड बकाया 20 प्रतिशत से अधिक की मजबूत दर से बढ़ रहा था लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से इसके विकास में तेज़ी से गिरावट आयी। ऐसा इसलिए था क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स पोर्टल सहित अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद थे। अर्थव्यवस्था के खुलने के बाद क्रेडिट कार्ड बकाया वृद्धि में फिर से बढ़ोतरी होने लगी; इसमें रिज़र्व बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड बकाया के भुगतान पर स्थगन ने भी कुछ हद तक मदद की।

III.4.सी. आवास ऋण

नवंबर 2020 में आवास ऋण बैंकों द्वारा दिए गए कुल व्यक्तिगत ऋण का 50 प्रतिशत से भी अधिक था। व्यक्तिगत ऋण क्षेत्र में यह क्षेत्र वृद्धि का प्रमुख संचालक है। आवास ऋण वृद्धि में मार्च 2020 में गिरावट देखी गयी और यह गिरावट महामारी की वजह से 2020-21 तक और बढ़ गयी। तेज़ी से गिरावट चिंता का विषय है क्योंकि यह स्टील, सीमेंट, और निर्माण आदि पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। कुछ घुमाव के चिन्ह हैं, जैसा देखा गया है कि सरकार द्वारा संपत्ति की ख़रीदारी में सहायता देने की वजह से इस क्षेत्र में उछाल के संकेत हैं। जैसे ही 2021 या उसके बाद अर्थव्यवस्था की गति बढ़ती है, आवास ऋण में उछाल की आशा की जा सकती है।

IV. क्षेत्रीय ऋण मांग की ब्याज दर संवेदनशीलता: कुछ अनुभवजन्य खोजें

ऋण मांग की ब्याज दर संवेदनशीलता, कुल गैर-खाद्य ऋण और साथ ही अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के लिए ऋण, औसत रूप से भारित कॉल दर (डबल्यूएसीआर) में बदलाव के संबंध में अनुमान लगाया गया है। चूंकि डबल्यूएसीआर मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य है और इसे नीति दर के साथ निकटता से जोड़ा गया है, इसलिए इसे अनुभवजन्य विश्लेषण में नीति दर के लिए एक प्रॉक्सि के रूप में इस्तेमाल किया गया है।

ऋण मांग की ब्याज दर संवेदनशीलता निम्नलिखित समीकरण द्वारा अनुमानित की जाती है:

$$\Delta credit_t = cons + \sum_{i=1}^{2} \alpha_i \Delta credit_{t-i} + \sum_{j=0}^{p} \beta_j \Delta gdpn_{t-j} + \sum_{k=0}^{q} \gamma_k call_{t-k} + \sum_{l=0}^{r} \delta_l gnpa_{t-l} + dum + \varepsilon_t$$

जहाँ $\Delta credit$ तिमाही के दौरान (नाममात्र) ऋण में तिमाही (तिमाही-दर-तिमाही) की वृद्धि को मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक रूप से संदर्भित करता है; $\Delta credit_t = \ln(\frac{credit_t}{credit_{t-1}}) \times 400]$; Δgdp एक तिमाही के दौरान नाममात्र जीडीपी में मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक तिमाही-दर-तिमाही विकास को संदर्भित करता है $\Delta gdpn_t = \ln(\frac{gdpn_t}{gdpn_{t-1}}) \times 400]$; भारित औसत कॉल मनी दर के लिए कॉल स्टैंड, जीएनपीए है कुल अग्रिम अनुपात के लिए सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति; 2016-17 के लिए डम वैल्यू 1 लेता है ; 03 और शून्य, अन्यथा विमुद्रीकरण अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। पैरामीटर γ ब्याज दर में परिवर्तन के लिए ऋण वृद्धि की लोचता मापता है। पी, क्यू, आर चर की लैग लंबाई हैं।[3] ये अनुमान 2007-08 की पहली तिमाही से लेकर 2019-20 की चतुर्थ तिमाही के डेटा पर आधारित हैं। 2020-21 के पहले वाले दो तिमहई के डेटा के गैर होने की वजह से, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है अनुमान के लिए क्योंकि अर्थव्यवस्था महामारी की वजह से तेज़ी से सिकुड़ती हुई अवस्था में थी। प्रतिगमन में प्रयुक्त अंतर्निहित चर नाममात्र शब्दों में हैं। प्रतिगमन परिणाम अनुबंध सारणी- टी3 में दिये गए हैं।

अनुभवजन्य अनुमानों से संकेत मिलता है कि खाद्येत्तर ऋण उद्योग और सेवा क्षेत्रों में अधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करने के साथ, लैग के साथ ब्याज दरों में बदलाव के प्रति संवेदनशील है। हालांकि, विश्लेषण कृषि क्षेत्र में ऋण की मांग पर ब्याज दर में

[3] ऋण, जीडीपी तथा मांग दर (कॉल रेट) ऋण को दो अवधियों तक के प्रभावित करते हैं, जबकि जीएनपीए एक अवधि तक के अंतराल के साथ ऋण को प्रभावित करता है।

परिवर्तन के किसी भी सांख्यिकीय महत्वपूर्ण प्रभाव का परिणाम नहीं पा सका। यह संभवत: इसलिए है क्योंकि कृषि को ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कवर किया गया है और ब्याज दर के हस्तक्षेप का लाभ मिलता है, और इसलिए, ब्याज दरों में बदलाव के लिए बहुत संवेदनशील नहीं हो सकता है। एनपीए का खाद्येत्तर ऋण विकास के साथ-साथ औद्योगिक ऋण वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

V. निष्कर्ष

क्षेत्रवार ऋण के डेटा का विश्लेषण अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ऋण के प्रवाह में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हाल के दिनों में ठप्प पड़े ऋण उठाव को आर्थिक मंदी के साथ-साथ कोविड-19 जनित लॉकडाउन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। बैंक ऋण वृद्धि, जो पहले से ही 2019-20 में घटनी शुरू हो गयी थी, महामारी के मद्देनज़र 2020-21 में इसे और एक झटका लगा। हालांकि, आर्थिक गतिविधि के धीरे-धीरे फिर से शुरू होने के साथ, कृषि और सेवा क्षेत्रों के ऋण ने हाल की अवधि में तेज़ी दर्ज की है। औद्योगिक क्षेत्र में भी, मध्यम उद्योगों के ऋण में तेज़ी आयी, जो कि सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के सकारात्मक प्रभाव का संकेत है। हालांकि, बड़े उद्योगों और बुनियादी ढांचे के लिए ऋण में संकुचन चिंता का कारण बना हुआ है। रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, खासकर एमएसएमई, और एनबीएफ़सी क्षेत्रों को ऋण प्रवाह की सुविधा के लिए कई उपाय किए हैं। टीएलटीआरओ में एनबीएफ़सी को शामिल करना टैप योजना पर और 5 फरवरी 2021 की मौद्रिक नीति वक्तव्य में एमएसएमई उद्यमियों को ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करने के उपाय इस दिशा में कदम हैं। वृद्धि को गति देने के लिए सरकार द्वारा 2021-22 के केन्द्रीय बजट में घोषित उपायों के अलावा कोविड संक्रमणों में गिरावट और टीकाकरण कार्यक्रम को तेज़ी से लागू किए जाने के फलस्वरूप अच्छे समुत्थान के लिए तैयार भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हुए, ऋण उठाव में बेहतरी की प्रत्याशा है।

संदर्भ:

Makinde, H.O. (2016), "Implications of Commercial Bank Loans on Economic Growth in Nigeria'', *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, 7(3):124-136.

Yakubu, Z. and Affoi, A. Y. (2014), "An Analysis of Commercial Banks' Credit on Economic Growth in Nigeria", *Current Research Journal of Economic Theory*, 6(2): 11-15.

अनुबंध सारणी टी 1: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन

(वार्षिक भिन्नता प्रतिशत में)

क्रम संख्या.	क्षेत्र	नवं.19/नवं.18	दिसं.19/दिसं.18	जन. 19/ जन. 20	फर. 20/ फर. 19	मार्च 20/ मार्च 19	अप्रै. 20/ अप्रै. 19	मई 20/ मई 19	जून 20/ जून 19	जुला. 20/ जुला. 19	अग. 20/ अग. 19	सितं. 20/ सितं. 19	अक्टू. 20/ अक्टू. 19	नवं.20/नवं.19
गैर-खाद्य ऋण (1 to 4)		**7.2**	**7.0**	**8.5**	**7.3**	**6.7**	**7.3**	**6.8**	**6.7**	**6.7**	**6.0**	**5.8**	**5.6**	**6.0**
1	**कृषि गतिविधियां**	**6.5**	**5.3**	**6.5**	**5.8**	**4.2**	**3.9**	**3.5**	**2.4**	**5.4**	**4.9**	**5.9**	**7.4**	**8.5**
2	**उद्योग (सूक्ष्म, मध्यम और बड़े)**	**2.4**	**1.6**	**2.5**	**0.7**	**0.7**	**1.7**	**1.7**	**2.2**	**0.8**	**0.5**	**0.0**	**-1.7**	**-0.7**
	2.1 सूक्ष्म	-0.1	0.1	0.5	-0.4	1.7	-2.2	-3.4	-3.7	-1.9	-1.2	-0.1	0.7	0.5
	2.2 मध्यम	-2.4	2.5	2.8	3.9	-0.7	-6.4	-5.3	-9.0	-3.1	2.8	14.5	16.7	20.9
	2.3 बड़े	3.0	1.8	2.8	0.7	0.6	2.7	2.8	3.7	1.4	0.6	-0.6	-2.9	-1.8
3	**सेवाएँ**	**4.8**	**6.2**	**8.9**	**6.9**	**7.4**	**11.2**	**11.2**	**10.7**	**10.1**	**8.6**	**9.1**	**9.5**	**8.8**
	3.1 परिवहन संचालक	8.1	7.8	6.1	5.3	4.3	5.5	5.5	3.5	5.5	5.2	3.5	6.5	10.7
	3.2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-0.4	-2.8	-0.4	0.1	8.2	8.2	7.6	12.5	16.2	7.1	5.6	1.6	0.4
	3.3 पर्यटन, होटल, और रेस्तरां	13.1	15.3	17.4	16.9	17.9	15.0	17.6	16.8	18.8	17.6	19.7	12.0	18.0
	3.4 शिपिंग	5.1	5.0	-10.9	-11.8	-15.4	0.1	-16.0	-15.2	-11.9	-16.3	-14.5	-9.0	-20.5
	3.5 व्यावसायिक सेवाएँ	1.3	0.5	2.0	-2.9	3.2	1.2	1.5	3.1	6.2	3.6	2.2	5.0	-24.7
	3.6 व्यापार	4.6	5.8	4.8	6.7	4.6	7.5	6.1	6.1	9.2	12.5	11.5	14.0	14.7
	3.6.1 थोक व्यापार (खाद्यान्न खरीद के अलावा)	2.8	6.8	8.6	13.6	5.1	10.0	11.4	10.9	16.5	19.9	21.2	22.6	26.5
	3.6.2 खुदरा व्यापार	6.0	5.0	1.7	1.2	4.1	5.4	1.9	2.2	3.2	6.7	4.2	7.5	5.7
	3.7 वाणिज्यिक अचल संपति	17.6	15.6	14.7	15.1	13.6	14.8	13.6	11.6	11.8	6.6	5.5	3.5	5.6
	3.8 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	29.1	27.6	32.2	22.3	25.9	30.3	29.0	25.7	24.6	17.1	12.5	9.2	7.8
	3.9 अन्य सेवाएँ	-19.5	-15.2	-8.4	-6.8	-8.6	-2.4	-0.2	1.2	-3.7	-2.3	7.0	10.8	15.8
4	**व्यक्तिगत ऋण**	**16.4**	**15.9**	**16.9**	**17.0**	**15.0**	**12.1**	**10.6**	**10.5**	**11.2**	**10.6**	**9.2**	**9.3**	**10.0**
	4.1 टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ	68.0	66.2	41.3	43.4	47.6	43.7	43.5	53.3	62.3	65.1	22.3	23.8	26.2
	4.2 आवास (प्राथमिकता क्षेत्र आवास सहित)	18.3	17.6	17.5	17.1	15.4	13.9	12.9	12.5	12.3	11.1	8.5	8.2	8.5
	4.3 सावधि जमा के नामे अग्रिम (एफ़सीएनआर (बी),एनसीएनआर,जमा आदि,सहित)	-7.7	-7.0	-2.2	6.9	-4.1	0.8	-4.3	-8.4	-4.0	-0.1	-1.6	-2.3	2.6
	4.4 व्यक्तियों को शेयर, बंधपत्रों आदि के नामे अग्रिम	-16.5	-17.8	-11.2	-11.6	-14.9	-15.4	-18.5	8.1	18.5	24.1	23.9	24.5	-6.6
	4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	24.1	25.3	31.6	33.0	22.5	4.8	-0.8	2.8	7.9	7.4	6.3	4.9	8.0
	4.6 शिक्षा	-3.3	-3.2	-3.1	-3.4	-3.3	-3.4	-3.3	-3.9	-3.8	-5.2	-4.5	-2.7	-2.6
	4.7 वाहन ऋण	4.7	7.2	9.8	10.3	9.1	8.6	6.3	7.1	8.1	8.4	8.8	8.4	10.0
	4.8 अन्य वैयक्तिक ऋण	21.1	19.4	20.7	20.6	19.7	13.7	12.3	12.1	13.3	13.0	13.2	14.3	14.9
5 *(मेमो)*	**प्राथमिकता क्षेत्र**	**3.5**	**6.1**	**4.0**	**0.3**	**5.8**	**3.0**	**2.5**	**1.9**	**4.1**	**4.4**	**4.5**	**5.9**	**8.9**
	5.1 कृषि गतिविधियां	6.3	5.4	6.1	5.4	3.8	4.0	3.4	2.3	4.8	4.4	5.5	7.0	7.9
	5.2 सूक्ष्म उद्यम	6.2	5.7	8.1	6.7	7.7	3.3	1.5	6.5	5.1	5.4	6.7	6.8	6.1
	5.2(a) विनिर्माण	-0.1	0.1	0.5	-0.4	1.7	-2.2	-3.4	-3.7	-1.9	-1.2	-0.1	0.7	0.5
	5.2(b) सेवाएँ	9.8	8.9	12.4	10.7	11.0	6.2	4.0	11.9	8.7	8.8	10.2	10.0	9.1
	5.3 आवास	12.3	11.9	7.6	6.3	4.0	6.4	7.0	5.4	5.1	6.4	2.2	1.5	1.9
	5.4 सूक्ष्म ऋण	45.7	47.0	53.8	50.1	58.7	28.6	26.1	24.9	3.9	2.4	0.8	0.7	-2.6
	5.5 शिक्षा ऋण	-6.0	-6.1	-6.2	-6.4	-3.8	-3.4	-3.8	-4.1	-4.1	-3.6	-3.8	-3.6	-3.6
	5.6 राज्य प्रायोजित संगठन अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए	13.5	16.9	7.8	35.1	-2.3	0.8	3.9	4.2	6.5	10.2	25.6	36.0	51.9
	5.7 कमजोर वर्ग	16.7	18.3	17.5	14.1	10.4	9.9	8.9	5.6	9.5	9.0	6.8	3.3	9.8
	5.8 निर्यात ऋण	-28.7	-18.1	-22.9	-13.2	3.5	9.7	20.8	17.1	7.6	6.2	2.6	-1.4	-2.3

टिप्पणी: 1. डेटा अनंतिम है, और उन बैंकों से संबंधित है, जो एससीबी द्वारा विस्तारित किए गए कुल खाद्येत्तर ऋण का 90 प्रतिशत तक कवर करते हैं।
2. प्राथमिकता क्षेत्र के तहत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंकों से संबंधित है।
3. मद 2.1 में सूक्ष्म और लघु के तहत विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण शामिल हैं।
4. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के मद 5.2 के अंतर्गत विनिर्माण के साथ सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण शामिल है।
5. प्राथमिकता क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है, और एफ़आईडीडी के परिपत्र एफ़आईडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.54/04.09.01/2014-15 दिनांक 23 अप्रैल 2015 के अनुरूप नहीं है।

अनुबंध सारणी टी-2 : वृद्धिशील गैर-खाद्य बैंक ऋण की संरचना

(वार्षिक भिन्नता प्रतिशत में)

क्रम संख्या.	क्षेत्र	नवं.19/नवं.18	दिसं.19/दिसं.18	जन. 19/ जन. 20	फर. 20/ फर. 19	मार्च 20/ मार्च 19	अप्रै. 20/ अप्रै. 19	मई 20/ मई 19	जून 20/ जून 19	जुला. 20/ जुला. 19	अग. 20/ अग. 19	सितं. 20/ सितं. 19	अक्टू. 20/ अक्टू. 19	नवं.20/नवं.19
गैर-खाद्य ऋण (1 to 4)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100
1	**कृषि गतिविधियां**	**11.9**	**9.9**	**10.1**	**10.4**	**8.0**	**7.0**	**6.6**	**4.8**	**10.5**	**10.7**	**13.4**	**17.4**	**18.4**
2	**उद्योग (सूक्ष्म, मध्यम और बड़े)**	**11.0**	**7.9**	**9.7**	**3.1**	**3.4**	**7.9**	**8.2**	**11.1**	**4.0**	**2.6**	**0.0**	**-9.7**	**-3.6**
	2.1 सूक्ष्म	0.0	0.1	0.3	-0.2	1.1	-1.3	-2.1	-2.4	-1.2	-0.8	-0.1	1	0.3
	2.2 मध्यम	-0.4	0.5	0.4	0.7	-0.1	-1.1	-1.0	-1.7	-0.6	0.6	3.1	4	4.1
	2.3 बड़े	11.5	7.3	9.0	2.6	2.4	10.4	11.3	15.1	5.8	2.9	-3.0	-14	-8.0
3	**सेवाएँ**	**18.8**	**24.0**	**28.4**	**25.9**	**31.0**	**41.8**	**44.1**	**42.7**	**40.9**	**39.2**	**43.1**	**46.4**	**39.5**
	3.1 परिवहन संचालक	1.8	1.8	1.2	1.2	1.0	1.3	1.3	0.9	1.4	1.4	1.0	2	2.9
	3.2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0	0.0
	3.3 पर्यटन, होटल, और रेस्तरां	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.6	1	1.5
	3.4 शिपिंग	0.1	0.1	-0.1	-0.1	-0.2	0.0	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	0	-0.3
	3.5 व्यावसायिक सेवाएँ	0.4	0.2	0.5	-0.9	1.0	0.3	0.4	0.9	1.8	1.2	0.7	2	-8.0
	3.6 व्यापार	3.8	4.9	3.4	5.6	4.2	6.1	5.4	5.5	8.2	12.3	11.7	15	14.1
	3.6.1 थोक व्यापार (खाद्यान्न खरीद के अलावा)	1.0	2.5	2.7	5.0	2.2	3.7	4.5	4.4	6.6	8.6	9.3	10	11.0
	3.6.2 खुदरा व्यापार	2.8	2.4	0.7	0.6	2.0	2.5	0.9	1.1	1.6	3.7	2.4	4	3.1
	3.7 वाणिज्यिक अचल संपति	5.7	5.2	4.2	4.9	4.8	4.8	4.7	4.2	4.3	2.8	2.4	2	2.4
	3.8 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	28.3	27.5	25.8	21.1	28.7	30.5	31.2	28.6	27.3	22.6	17.9	14	10.9
	3.9 अन्य सेवाएँ	-22.1	-16.5	-7.4	-7.0	-9.9	-2.4	-0.2	1.2	-3.8	-2.6	7.7	12	16.0
4	**व्यक्तिगत ऋण**	**58.3**	**58.2**	**51.8**	**60.6**	**57.6**	**43.2**	**41.0**	**41.5**	**44.6**	**47.5**	**43.4**	**45.9**	**45.8**
	4.1 टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.2	0	0.3
	4.2 आवास (प्राथमिकता क्षेत्र आवास सहित)	34.0	33.7	28.1	31.9	30.9	26.2	26.3	26.1	25.8	26.2	21.5	22	20.7
	4.3 सावधि जमा के नामे अग्रिम (एफ़सीएनआर (बी),एनसीएनआर,जमा आदि,सहित)	-0.9	-0.9	-0.2	0.8	-0.6	0.1	-0.5	-1.0	-0.5	0.0	-0.2	0	0.3
	4.4 व्यक्तियों को शेयर, बंधपत्रों आदि के नामे अग्रिम	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0	-0.1
	4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	3.5	3.7	3.8	4.5	3.4	0.7	-0.1	0.5	1.3	1.4	1.3	1	1.6
	4.6 शिक्षा	-0.4	-0.4	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.4	-0.7	-0.6	0	-0.3
	4.7 वाहन ऋण	1.6	2.5	2.8	3.4	3.2	2.8	2.2	2.5	2.9	3.3	3.6	4	4.0
	4.8 अन्य वैयक्तिक ऋण	20.3	19.3	17.3	20.2	20.6	13.6	13.3	13.2	14.8	16.3	17.5	20	19.3
5 *(मेमो)*	**प्राथमिकता क्षेत्र**	**15.6**	**27.9**	**15.5**	**1.2**	**27.4**	**13.1**	**11.8**	**9.1**	**19.5**	**23.6**	**25.0**	**34.0**	**45.8**
	5.1 कृषि गतिविधियां	11.5	10.2	9.4	9.7	7.2	7.1	6.5	4.5	9.3	9.5	12.3	16	17.1
	5.2 सूक्ष्म उद्यम	10.6	10.0	11.9	11.3	14.2	5.6	2.7	12.2	9.3	10.9	14.2	15	12.3
	5.2(a) विनिर्माण	0.0	0.1	0.3	-0.2	1.1	-1.3	-2.1	-2.4	-1.2	-0.8	-0.1	1	0.3
	5.2(b) सेवाएँ	10.7	9.9	11.6	11.5	13.1	7.0	4.8	14.6	10.5	11.8	14.3	14	12.0
	5.3 आवास	8.6	8.5	4.7	4.5	3.0	4.5	5.3	4.2	3.9	5.5	2.0	1	1.6
	5.4 सूक्ष्म ऋण	1.8	2.0	1.8	2.0	2.4	1.3	1.2	1.3	0.2	0.1	0.1	0	-0.2
	5.5 शिक्षा ऋण	-0.6	-0.6	-0.5	-0.6	-0.4	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	0	-0.4
	5.6 राज्य प्रायोजित संगठन अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
	5.7 कमजोर वर्ग	17.2	19.2	15.3	14.2	11.9	10.8	10.4	6.8	11.2	11.9	9.5	5	13.0
	5.8 निर्यात ऋण	-0.9	-0.6	-0.6	-0.4	0.1	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1	0	-0.1

टिप्पणी: 1. .डेटा अनंतिम है, तथा उन बैंकों से संबंधित हैं, जो एससीबी द्वारा विस्तारित खाद्येत्तर ऋण का 90 प्रतिशत तक कवर करते हैं।

2. प्राथमिकता क्षेत्र के तहत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंकों से संबंधित है।

3. मद 2.1 सूक्ष्म और लघु के तहत विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण शामिल हैं।

4. मद 5.2 सूक्ष्म और लघु उद्यमों के तहत विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण शामिल हैं।

5. प्राथमिकता क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है, और एफ़आईडीडी के परिपत्र एफ़आईडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.54/04.09.01/2014-15 दिनांक 23 अप्रैल 2015 के अनुरूप नहीं हैं।

अनुबंध सारणी-टी 3: अनुमानित प्रतिगमन गुणांक

चर	खाद्येत्तर ऋण		उद्योग		सेवाएँ		कृषि	
	गुणांक	पी-वैल्यू	गुणांक	पी-वैल्यू	गुणांक	पी-वैल्यू	गुणांक	पी-वैल्यू
$cons$	18.82	0.00	19.29	0.01	31.91	0.00	31.89	0.00
$\Delta credit_{t-1}$	-0.05	0.66	0.04	0.77	-0.16	0.22	-0.37	0.01
$\Delta credit_{t-2}$	0.34	0.01	0.38	0.00	0.36	0.00	-0.00	0.97
$\Delta gdpn_{t-1}$			0.30	0.08	-0.24	0.37	0.03	0.84
$\Delta gdpn_{t-2}$	0.07	0.61						
$call_{t-1}$	-1.13	0.04	-1.61	0.02			-0.51	0.48
$call_{t-2}$					-2.45	0.03		
$gnpa_{t-1}$	-0.58	0.09	-1.18	0.04	-0.24	0.64	-2.00	0.00
$dummy$					-30.23	0.00	-20.5	0.00
R^2	0.47		0.61		0.37		0.40	
एलएम टेस्ट –(पी-वैल्यू)	0.61		0.43		0.77		0.36	
एआरसीएच टेस्ट –(पी-वैल्यू)	0.84		0.66		0.85		0.29	

टिप्पणी: डेटा उन बैंक से संबंधित है, जो कुल एससीबी द्वारा विस्तारित खाद्येत्तर ऋण का 90 प्रतिशत तक कवर करते हैं। यह आकलन तिमाही डेटा अवधि 2007-2008;ति1 के द्वारा 2019-20;ति4. पर आधारित है।

*एकदिवसीय सूचकांक स्वैप (ओआईएस) दरों से मौद्रिक नीति के भावी रुख का आकलन**

इस लेख में भारत में मौद्रिक नीति की भावी कार्यप्रणाली की बाजार की प्रत्याशाओं को समझने के लिए भारत में एकदिवसीय सूचकांक स्वैप (ओआईएस) दरों के व्यवहार की जांच की गयी है। इसमें ओआईएस नियत दर और अस्थायी एकदिवसीय संदर्भ दर के बीच अंतर के रूप में वास्तविक "अतिरिक्त प्रतिलाभ" की गणना की गयी है और उनके सांख्यिकीय गुणों का अध्ययन किया गया है। इसमें पाया गया है कि 1, 9 और 12 माह की अवधि की ओआईएस दरें नीतिगत रिपो दर की भावी रुख के बारे में बाजार की प्रत्याशाओं की विश्वसनीय पैमाना प्रदान करता है, विशेष रूप से सामान्य समय के दौरान।

भूमिका

हाउसहोल्ड्स, फर्म और सरकार के मौजूदा आर्थिक निर्णय अक्सर मुख्य समष्टि-वित्तीय चर के सन्निकट अनुमानों के बारे में प्रत्याशाओं पर आधारित होते हैं। भावी ब्याज दर की प्रत्याशा एक ऐसा महत्वपूर्ण चर है जो एजेंटों के निर्णय को प्रभावित कर सकता है कि अभी उधार लेना है या बाद में। यदि वे निकट भविष्य में ब्याज दरों में वृद्धि (या गिरावट) की 'प्रत्याशा' करते हैं, तो वे उधार लेने संबंधी अपने निर्णय को आगे बढ़ा (या स्थगित) सकते हैं।

एजेंटों की एक श्रेणी, जो अर्थव्यवस्था की बारीकी से निगरानी करते हैं और निर्णय लेने की दिशा में प्रगतिशील होते हैं, वित्तीय बाजारों में भागीदार होते हैं, जैसे कि बैंक और गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थ, जिनमें पेंशन/म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां और प्राथमिक डीलर शामिल हैं। ये बाजार प्रतिभागी भावी ब्याज दरों की अपनी अपेक्षाओं को उन सूचनाओं पर आधारित करते हैं जो उनके साथ-साथ उन चरों के पूर्वानुमानों पर आधारित होती हैं जो आम तौर पर मौद्रिक नीति ब्याज दर का मार्ग निश्चित करती है।

केंद्रीय बैंक विभिन्न तरीकों से मौद्रिक नीति के बाजारों की प्रत्याशाओं का उपयोग करते हैं। जबकि कुछ मुद्रास्फीति और जीडीपी (जॉइस और मेलड्रम, 2008) जैसे मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतकों के पूर्वानुमान के लिए एक इनपुट के रूप में नीति दर प्रत्याशाओं संबंधी जानकारी का उपयोग करते हैं। अन्य लोग मौद्रिक नीति के निर्माण में एक इनपुट के रूप में बाजारों की प्रत्याशित नीतिगत दर का उपयोग करते हैं।

जहां मौद्रिक नीति सामान्यता प्रभावी होने के लिए अनुमानित होने का अभिप्राय रखती है, वहीं समय-समय पर केंद्रीय बैंक बाजार को आश्चर्यचकित करते हैं। जब वे ऐसा करते हैं, तो यह आमतौर पर बाजार में उतार-चढ़ाव (फिशर, 2017) की ओर जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किए गए अध्ययनों से पता चला कि फेड फंड्स दर में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव ने ट्रेजरी बिल की प्रतिफल (कुट्टनर, 2001) और स्टॉक की कीमतों (बर्नानके और कुट्टनर, 2005) को काफी प्रभावित किया। हालांकि, बाजार आमतौर पर तब स्थिर हो जाते हैं जब केंद्रीय बैंक अपने फैसलों के लिए तर्क को प्रभावी ढंग से बता पाता है। फ़िशर (2017) ने हालांकि, तर्क दिया कि 'अनपेक्षित आश्चर्य' से बचना दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है: केंद्रीय बैंक के प्रतिक्रिया कार्य के बारे में स्पष्टता होने पर वित्तीय बाजार सुचारू रूप से बदल जाते हैं, जिससे केंद्रीय बैंक को नीतिगत लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। इसके अलावा, केंद्रीय बैंक और वित्तीय बाजार के बीच संबंध बेहतर बना हुआ है, जिससे केंद्रीय बैंक का कार्य अपने नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करने में आसान हो जाता है।

साहित्य भावी अल्पावधि ब्याज दरों के बाजार की प्रत्याशा का अनुभवजन्य मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न तरीकों की पहचान करता है। लॉयड (2018) ने इन तरीकों को तीन व्यापक (हालांकि, पारस्परिक रूप से गैर-अनन्य) श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया: सर्वेक्षण-आधारित; मॉडल आधारित; और वित्तीय बाजार आधारित। सर्वेक्षण-आधारित और वित्तीय बाजार-आधारित तरीकों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है।

सर्वेक्षण-आधारित विधि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें विभिन्न आर्थिक और वित्तीय सर्वेक्षणों के माध्यम से नीतिगत दर

---

* यह लेख वित्तीय बाजार विनियमन विभाग के ऋतुराज और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के अरुण विष्णु कुमार द्वारा तैयार किया गया है। लेखकों को सीसीआईएल के डॉ. गोलक नाथ, ओआईएस बाजार के कुछ डीलरों और दो अनाम रेफरी की आलोचनात्मक टिप्पणियों और सुझावों से लाभ मिला। हालांकि, इसमें रह गयी किसी भी त्रुटि के लिए लेखक जिम्मेदार हैं। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को व्यक्त करते हों।

की प्रत्याशाओं के सवालों का तलाशना शामिल है (समीक्षा के लिए ज़ुलेन और विबिसन (2018 देखें)। मिसाल के तौर पर, इंडोनेशिया के बैंक नीतिगत दर संबंधी प्रत्याशा जुटाने के लिए ब्लूमबर्ग सर्वे के नतीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, क्रिस्टीनसन और क्वान (2014) ने फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफ़ओएमसी) की प्रत्याशाओं के साथ बाजार सहभागियों की प्रत्याशाओं के गठजोड़ का आकलन करने के लिए मासिक ब्लू-चिप वित्तीय पूर्वानुमान सर्वेक्षण और प्राथमिक व्यापारियों के सर्वेक्षण के परिणामों का उपयोग किया। भारत में, रिज़र्व बैंक सितंबर 2007 से व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं (एसपीएफ़) का सर्वेक्षण कर रहा है। विश्लेषकों के एक पैनल से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को प्रमुख चर के लिए तिमाही मार्गों के साथ पूर्वानुमान के औसत मूल्यों के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। नीतिगत रिपो दर प्रमुख समष्टि-आर्थिक संकेतकों में से एक है जिसके लिए सर्वेक्षण के माध्यम से तिमाही पूर्वानुमान एकत्र किए जाते हैं।

वित्तीय बाजार आधारित उपाय वित्तीय बाजार लेनदेन डेटा से ब्याज दर की प्रत्याशाओं का आकलन करते हैं। मौद्रिक नीति प्रत्याशा के एक उपाय के रूप में एकदिवसीय सूचकांक स्वैप (ओआईएस) दर का उपयोग साहित्य में लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है, विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए। ओआईएस एक ब्याज दर व्युत्पन्न संविदा है जिसमें दो संस्थाएं संविदा अवधि के दौरान अनुमानित मूलधन के ऊपर गणना की गई अस्थिर ब्याज दर भुगतान की तुलना में नियत ब्याज दर भुगतान (ओआईएस दर) को स्वैप/एक्सचेंज करने के लिए सहमत होती हैं। अस्थिर दर आमतौर पर एकदिवसीय (बेजमानती) अंतरबैंक दर[1] है। फ्लोटिंग लेग इंटरेस्ट पेमेंट का निर्माण एकदिवसीय संदर्भ दर में अनुमानित मूलधन के निवेश की योजना से प्राप्त ब्याज भुगतानों की गणना करके किया जाता है और संविदा की अवधि के लिए एकदिवसीय आधार पर इसे दोहराते हुए, हर बार मूलधन के साथ-साथ ब्याज को निवेश किया जाता है (लॉयड, 2018) , पृष्ठ 4)।

सर्वेक्षण-आधारित पद्धति के बाजार-आधारित पद्धति के मुक़ाबले कुछ फायदे हैं। पहले वाले के मामले में विश्लेषण सरल है। सभी सर्वेक्षण उत्तरदाताओं की नीतिगत दर संबंधी प्रत्याशाओं को एकत्र करने के लिए औसत या औसत मूल्य की गणना कर सकता है। उदाहरण के लिए, बाद वाले की पद्धति का उपयोग करते हुए एक अध्ययन में बैंक ऑफ़ कनाडा की नीतिगत दर में परिवर्तन की संभावना का अनुमान लगाने के लिए तीन अलग-अलग वित्तीय बाजार लिखतों की कीमतों का उपयोग किया गया था। इसके अलावा, उत्तरदाताओं का प्रतिशत निकालने के लिए सर्वेक्षण-आधारित पद्धति में उत्तरदाताओं की प्रत्याशाओं के आवृत्ति वितरण की गणना करना संभव है, जो कटौती या बढ़ोतरी की उम्मीद करते हैं या नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं करते हैं। यह बाजार-आधारित पद्धति में संभव नहीं है (क्रिस्टेंसन और क्वान, 2014)। ओआईएस दरों या किसी अन्य वित्तीय बाजार-आधारित पैमाने का उपयोग करने का एक और संभावित नुकसान जोखिम प्रीमिया की मौजूदगी है। हालांकि, लॉयड (2018) ने तर्क दिया कि औसतन ये प्रीमिया छोटे सीमा में कोई खास मसला नहीं हैं। उन्होंने तर्क दिया कि एक ओआईएस संविदा में कुछ विशेष विशेषताएं हैं: 'प्रतिपक्षी जोखिम' न्यूनतम है क्योंकि अनुमानित मूलधन राशि का कोई विनिमय नहीं है।[2] इसके अलावा, 'चलनिधि जोखिम' भी कम है क्योंकि कोई प्रारंभिक नकदी प्रवाह नहीं है और केवल निपटान के दौरान एजेंटों के बीच निवल नकदी प्रवाह का आदान-प्रदान होता है।

हालांकि, बाजार आधारित पद्धति के भी अपने फायदे हैं। ऐसा माना जाता है कि यह बाजार में वास्तविक प्रत्याशा को ग्रहण करता है। लिखत की कीमत (वीक्षाधीन) बाजार की प्रत्याशा के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि बाजार के भागीदार लिखत में अपना पैसा लगाकर "जोखिम" उठाते हैं (यानी, अपना "पैसा दांव पर" लगाते हैं)। दूसरी ओर, सर्वेक्षण-आधारित पद्धति की व्यक्तिपरक प्रकृति को देखते हुए, कई बार संभावना है कि उत्तरदाता अपनी वास्तविक प्रत्याशा के अनुसार ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इसके अलावा, सर्वेक्षण सभी बाजार सहभागियों को कवर नहीं कर सकते हैं और गलत सूचना भी दे सकते हैं। यदि संदर्भित लिखत व्यापक रूप से कारोबार करते हैं तो बाजार-आधारित पद्धति में, बाजार की प्रत्याशा की गणना दैनिक आधार पर या यहां तक कि घंटे-दर-घंटे आधार पर की जा सकती है।

[1] भारतीय ओआईएस संविदाओं के लिए संदर्भ दर मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (माइबोर) है।

[2] हम डॉ. गोलक नाथ के आभारी हैं कि उन्होंने हमें जानकारी दी कि "ओआईएस विश्व स्तर पर केंद्रीकृत काउंटर-पार्टी (सीसीपी) निपटान की ओर बढ़ रहा है और इसलिए संविदा से काउंटर-पार्टी जोखिम को हटाया जा रहा है। जिस मामले में ओआईएस छूट की शुरुआत की गई थी, वह लाइबोर डिस्काउंटिंग के विषय में शुरू हुआ था, क्योंकि वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप स्वैप संविदा के सीसीपी समाशोधन के बाद भारी बदलाव आया है। भारत में, लगभग 60 प्रतिशत सौदे काउंटर-पार्टी जोखिम मुक्त संविदा हैं। इसलिए, जोखिम प्रीमियम घटक इस अर्थ में समझौता कर लेता है कि यद्यपि सीसीपी समाशोधन एकल इकाई में जोखिम को केंद्रित करता है, तथापि सीसीपी के लिए संरचनाएं प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली स्वचालित रूप से जोखिम घटक को कम करती हैं। इसलिए ओआईएस कोई नुकसान नहीं है।"

सर्वेक्षण-आधारित पद्धति में, ऐसी उच्च आवृत्ति (दैनिक कह सकते हैं) जानकारी एकत्र करना संभव नहीं हो सकता है और महंगा भी हो सकता है।

इस पृष्ठभूमि में, लॉयड (2018) की कार्यप्रणाली को अपनाते हुए, यह लेख आनुभविक रूप से परीक्षण करता है कि क्या अलग-अलग परिपक्वता कालों (1 महीने से 10 साल तक) के भारत में तटीय ओआईएस व्यापार अल्पावधिक ब्याज दरों के बाजार की प्रत्याशा के प्रभावशाली पैमाना हैं। हम पाते हैं कि एक वर्ष तक (विशेष रूप से, 1, 9 और 12 महीने के परिपक्वता काल) के ओआईएस दरों में औसतन, भावी अल्पावधिक ब्याज दरों के अनुमानित बाजार की प्रत्याशा है। लेख के बाकी हिस्सों को चार खंडों में विभाजित किया गया है। खंड II में भारत में ओआईएस बाजार के संबंध कुछ शोधपरक तथ्यों को रिपोर्ट किया गया है। खंड III में प्रयुक्त डेटा और कार्यप्रणाली को प्रस्तुत किया गया है। अनुभवजन्य परिणाम और उनकी चर्चा खंड IV में दी गई है। खंड V में निष्कर्ष दिया गया है।

II. भारत में ओआईएस बाजार: कुछ शोधपरक तथ्य

भारत में ब्याज दर डेरिवेटिव (आईआरडी) की अनुमति 7 जुलाई 1999 को दी गई थी। आईआरडी का व्यापार या तो संगठित एक्सचेंजों या ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) बाजारों में किया जाता है। रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर, विभिन्न आईआरडी उत्पादों जैसे कि ब्याज दर स्वैप (आईआरएस), वायदा दर करार (एफआरए), ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ), ब्याज दर ऑप्शन (आईआरओ) और मनी मार्केट फ्यूचर (एमएमएफ) को कवर करने वाले नियमों को जारी किया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक डीलर और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं अपनी तुलन-पत्र प्रबंधन और बाजार निर्माण के उद्देश्यों के लिए एफआरए/आईआरएस का कार्य कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं और बाजार निर्माताओं के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए वर्ष 2007 में डेरिवेटिव संबंधी दिशा-निर्देशों का एक व्यापक सेट जारी किया गया था। आईआरएस संविदाओं को 28 जनवरी 2013 को मानकीकृत किया गया था। हालांकि, आईआरएस बाजार को छोड़कर, अन्य डेरिवेटिव बाजारों में गतिविधि बल्कि अत्यल्प और सीमित रही है।

आईआरएस बाजार भारत में ओटीसी डेरिवेटिव (ओटीसीडी) बाजार का सबसे बड़ा क्षेत्र बनाता है। आईआरएस बाजार में दो

चार्ट 1: अंतर-बैंक ओटीसीडी – बकाया मूल्यों में हिस्सेदारी (प्रतिशत)

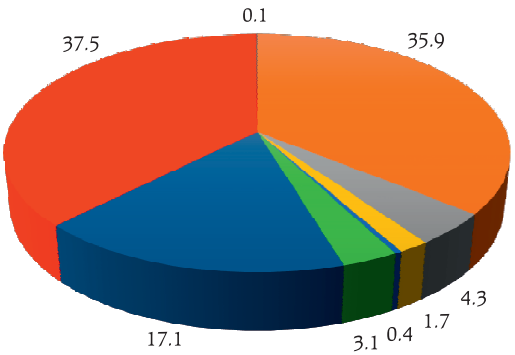

स्रोत: सीसीआईएल, मार्च 2020 तक के आंकड़े

मुख्य क्षेत्र अंतर-बैंक और ग्राहक लेनदेन से संबंधित हैं। पहला वाला प्रमुख क्षेत्र है जिसमें सकल अनुमानित राशि के बकाया मूल्यों में लगभग 38 प्रतिशत की हिस्सेदारी है (चार्ट 1)। अंतर-बैंक सेगमेंट, प्रमुख सेगमेंट है जिसमें विदेशी बैंकों और प्राथमिक डीलरों (पीडी) से प्रमुख भागीदारी देखने को मिलती है, जिसके बाद निजी क्षेत्र के बैंक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भागीदारी जहां बढ़ रही है, वही अभी भी यह नगण्य है।

भारत में आईआरएस बाजार का दबदबा माइबोर- ओआईएस के साथ मुंबई अंतर-बैंक एकमुश्त दर (माइबोर) के रूप में है, जो अस्थिर ब्याज दर है, इसके बाद मुंबई अंतर-बैंक वायदा एकमुश्त दर (माइफोर) और भारतीय बेंचमार्क स्वैप (आईएनबीएमके) है (सारणी 1)। अंतर-बैंक माइबोर-ओआईएस बाजार में गतिविधि हाल के वर्षों से अधिक बढ़ी है (चार्ट 2)।

सारणी 1: बेंचमार्क-वार सकल राष्ट्रीय बकाया

(₹ करोड़ में)

बेंचमार्क	कुल बकाया
माइबोर ओआईएस	31,34,039
माइफोर	6,57,371
आईएनबीएमके	2,560

स्रोत: सीसीआईएल, मार्च 2020 तक के आंकड़े

चार्ट 2: अंतर-बैंक आईएनआर आईआरएस बकाया मात्रा

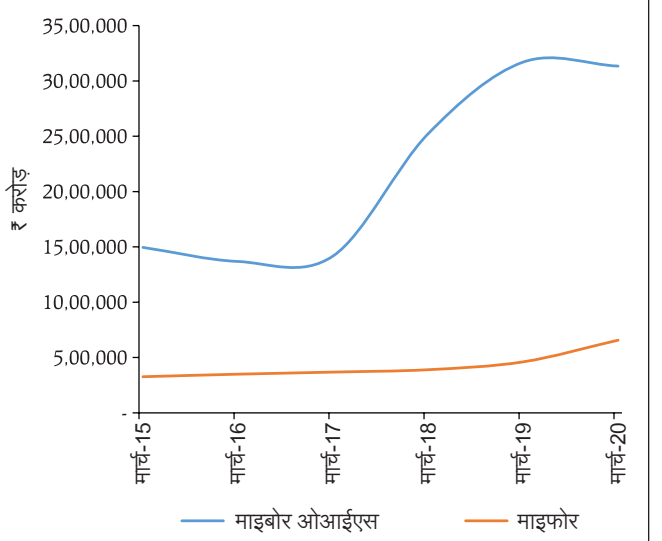

स्रोत: सीसीआईएल।

भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला आईआरएस, माइबोर एक ऐसा उत्पाद है, जिसमें स्वैप का फ़्लोटिंग लेग एकदिवसीय सूचकांक से जुड़ा होता है, जिसे भुगतान की अवधि में हर दिन मिलाना होता है। जैसा कि इसकी मूल संरचना से अंदाजा लगाया जा सकता है, ओआईएस उत्पाद का व्यापार ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के भावी रुख के बारे में व्यापार करने वाले पक्षकारों की प्रत्याशाओं के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार, ब्याज दर में कोई भी परिवर्तन के बाद स्वैप में उनकी स्थिति के आधार पर लाभ या हानि होती है। जी-सेक प्रतिफल और ओआईएस दरों में उच्च सहसंबंध दिखाया गया है। इस प्रकार, जी-सेक में निवेशकों के लिए प्राथमिक बचाव उपकरण के रूप में ओआईएस का उपयोग किया जा सकता है। अतिरिक्त लाभों में कॉर्पोरेट्स के लिए क्रेडिट जोखिम में कमी और सिंथेटिक ओवरनाइट-इंडेक्स-लिंक्ड देयता का सृजन शामिल है। ओआईएस वित्तीय संस्थानों को उनकी पसंद के आधार पर ब्याज दर में लचीलेपन की अनुमति देता है, उनके ऋण पोर्टफोलियो की विभिन्न विशेषताओं और निवेश पोर्टफोलियो की अवधि का प्रबंधन करता है।

III. आंकड़े एवं कार्य-पद्धति

इस खंड में परीक्षण किया गया है कि क्या अलग-अलग परिपक्वता काल के भारत में ऑनशोर माइबोर ओआईएस व्यापारों को मौद्रिक नीति के बाजार की प्रत्याशाओं को मापने में मदद करते हैं, विशेष रूप से चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत पॉलिसी रिपो दर। हम 03 अगस्त 1999 से 31 मई, 2019 की अवधि के लिए 1 महीने से 10 साल तक के परिपक्वता काल के लिए दैनिक माइबोर-ओआईएस दरों का उपयोग करते हैं। शुरुआती तारीख डेटा उपलब्धता के अनुसार तय की गई है। डेटा ब्लूमबर्ग से प्राप्त किया गया है।

हमने लॉयड (2018) द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि को अपनाया है।

सबसे पहले, एन-महीने (एन-दिन) में से प्रत्येक के लिए ओआईएस निर्धारित दर (i_n^{fixed}) हमने नीचे दी गयी अभिव्यक्ति का प्रयोग करके प्रतिदिन वार्षिक वास्तविक प्राप्त (निवल) प्रतिलाभ उसी संविदा (i_n^{float}) के अस्थिर लेग से निकाला है (एफ़आईएमएमडीए, 2016 और लॉयड, 2018):

$$1.\quad i_n^{float} = \left[\prod_{j=1}^{d_0}\left(1+\frac{n_j * MIBOR_j}{365}\right)-1\right]\times\frac{365}{d}$$

यहां, प्रासंगिक गणना अवधि में कारोबारी दिनों की संख्या d_0 है; n_j गणना अवधि में कैलेंडर दिनों की संख्या है जिसके लिए उपयोग की गई दर $MIBOR_j$ है; और d प्रासंगिक गणना अवधि में कैलेंडर दिनों की संख्या है। भारतीय ओआईएस संविदाओं के लिए स्पॉट लैग *शून्य* दिन है।

इस प्रकार, n-माह ओआईएस संविदा पर स्पष्ट वास्तविक प्राप्त (वार्षिक) 'अतिरिक्त प्रतिलाभ (ईआर)' है:

$$2.\quad ER_t = i_n^{fixed} - i_n^{floating}$$

लॉयड (2018, पृष्ठ 5-6) ने दर्शाया कि *"किसी एजेंट के दृष्टिकोण से जो कि काल्पनिक मूलधन x पर अस्थायी दर के लिए निश्चित ब्याज भुगतान को स्वैप करता है, $(ER \times x)$ शून्य लागत पोर्टफोलियो के भुगतान को दर्शाता है। इसलिए, यदि प्रत्याशा अनुमान सच होता है, तो ओआईएस संविदा को निश्चित फ्लोटिंग लेग के प्रत्याशित मूल्य के पूर्वानुमान के बराबर होना चाहिए, अर्थात, $i_{n,t}^{fixed} = E_t(i_n^{float})$। इस प्रकार, यदि वास्तविक प्राप्त अतिरिक्त प्रतिलाभ शून्य माध्य है, तो प्रत्याशा अनुमान के अंतर्गत प्रत्याशित पूर्वानुमान त्रुटि पूर्व-पूर्व पूर्वानुमान त्रुटि का भी शून्य माध्य है, और n-माह के ओआईएस संविदा को भावी अल्पावधि ब्याज दरों की सटीक माप प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है।"*

इस प्रकार, यह जांचने के लिए कि क्या ओआईएस संविदा (ER_t) पर वास्तविक अतिरिक्त प्रतिलाभ है, हम ER_t को एक

स्थिर (α_n) पर प्रतिगमन करते हैं और परीक्षण करते हैं कि α_n शून्य से काफी अलग है या नहीं।

3. $ER_t = \alpha_n + \varepsilon_n$

उपरोक्त प्रतिगमन के लिए मानक त्रुटियों और टी-सांख्यिकी की गणना नेवी वेस्ट (बार्टलेट कर्नेल) द्वारा हेटेरोसेडासिटी और ऑटोकॉरेलेशन कंसिस्टेंट (एचएसी) प्रक्रिया द्वारा की गई है।

IV. अनुभवजन्य परिणाम और विमर्श

स्पष्ट औसत वास्तविक अतिरिक्त प्रतिलाभ 03 अगस्त 1999 से 31 मई 2019 की अवधि के लिए, 1 महीने से 10 साल तक के ओआईएस दरों के विभिन्न परिपक्वता काल के लिए गणना की गई थी, और अनुबंध सारणी 1 में दिए गए हैं।

हम पाते हैं कि एक वर्ष तक के परिपक्वता के ओआईएस ट्रेडों के अतिरिक्त प्रतिलाभ 2 आधार अंक (बीपीएस) और 20 बीपीएस[3] के बीच कम थे, जो दर्शाता है कि ये ओआईएस दरें औसतन, मौद्रिक नीति की भावी रुख की दिशा का एक उचित संकेत थीं। विशेष रूप से, हम पाते हैं कि औसतन, इन परिपक्वता कालों के अतिरिक्त प्रतिलाभ शून्य से बहुत भिन्न नहीं होने से 1, 9 और 12 महीने के परिपक्वता काल की ओआईएस दरें भावी अल्पावधिक ब्याज दरों की प्रत्याशाओं को अधिक सटीक रूप से मापती हैं (अनुबंध चार्ट 1)[4]

दूसरी ओर, 3-महीने और 6 महीने के ओआईएस ट्रेडों के लिए, अतिरिक्त प्रतिलाभ क्रमशः 7.81 बीपीएस और 6.51 बीपीएस पर कम था, हालांकि शून्य से काफी अलग था।

भावी अल्पावधिक ब्याज दरों के अधिक सटीक माप के रूप में उभरने वाले 9 महीने और 12 महीने की ओआईएस दरों का एक संभावित कारण यह हो सकता है कि बाजार मौद्रिक नीति की दिशा का अनुमान लगाने में सक्षम है लेकिन सटीक समय का नहीं। उदाहरण के लिए, 2-महीने के समय में 25 बीपीएस की दर में वृद्धि की बाजार की प्रत्याशा 6 महीने के बाद ही मूर्त रूप ले सकती है। ऐसा परिदृश्य 3 महीने और 6 महीने के ओआईएस लेन-देन के लिए गैर-शून्य होने के बाद अतिरिक्त प्रतिलाभ देने के लिए प्रेरित कर सकता है, जबकि लंबे समय तक ओआईएस के लिए, अर्थात, 9-महीने और 12-महीने, उस सीमा तक प्रभावित नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार, यह उल्लेख किया जा सकता है कि ओआईएस दरें नीतिगत कार्रवाई के वास्तविक समय के बजाय मौद्रिक नीति की दिशा का एक बेहतर भविष्यवक्ता हैं। प्रतितथ्यात्मक रूप में, यह प्रत्याशा की जाएगी कि यदि मौद्रिक नीति कार्रवाई बाजार को आश्चर्यचकित करती है, तो ओआईएस दरें तुरंत समायोजित हो जाएंगी (सारणी 2 कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं)।

इसके अलावा, कुछ अवधि के दौरान मुद्रा बाजार में अस्थिरता के कारण, हमने डमी प्रयुक्त किया है विशेष रूप से वर्ष

सारणी 2: मौद्रिक नीति आश्चर्य के कुछ उदाहरण[5]

एमपीसी की तारीख	1 माह ओआईएस दर (प्रतिशत)			3 माह ओआईएस दर (प्रतिशत)			6 माह ओआईएस दर (प्रतिशत)			9 माह ओआईएस दर (प्रतिशत)			12 माह ओआईएस दर (प्रतिशत)		
	नीति से पहले	नीति के बाद	परिवर्तन	नीति से पहले	नीति के बाद	परिवर्तन	नीति से पहले	नीति के बाद	परिवर्तन	नीति से पहले	नीति के बाद	परिवर्तन	नीति से पहले	नीति के बाद	परिवर्तन
फर 07, 2019	6.45	6.31	-0.14	6.57	6.44	-0.13	6.51	6.38	-0.13	6.51	6.38	-0.13	6.53	6.39	-0.14
अक्टू 05,2018	6.86	6.57	-0.29	7.00	6.73	-0.27	7.32	7.10	-0.22	7.44	7.25	-0.19	7.56	7.39	-0.17
फर 08, 2017	6.14	6.26	0.12	6.21	6.35	0.14	6.20	6.36	0.16	6.21	6.37	0.16	6.19	6.39	0.20
दिसं 07, 2016	5.97	6.21	0.24	6.00	6.23	0.23	5.98	6.23	0.25	5.98	6.21	0.23	5.97	6.21	0.24

[3] इन परिपक्वता काल के लिए धनात्मक अतिरिक्त प्रतिफल कॉल दरों के नीतिगत रिपो दर से थोड़ा कम रहने के कारण हो सकता है जिसकी वजह चलनिधि परिस्थितियां हो सकती हैं।

[4] यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि बैंकों के प्रमुख हिस्से ओआईएस बाजार में सक्रिय भागीदार नहीं हैं। एक दृष्टिकोण यह है कि भारत में ओआईएस संविदा में शामिल संस्थाएं संभवतः ब्याज दर अपेक्षाओं पर प्रति कॉल लेने की तुलना में इसे चलनिधि के दृष्टिकोण से अधिक देख सकती हैं, और अतिरिक्त प्रतिफल अनकदी के लिए अधिक प्रीमियम हो सकता है। हम इसे हमारे संज्ञान में लाने के लिए डॉ. गोलक नाथ को अभिस्वीकृत करना चाहेंगे।

[5] 07 फरवरी 2019 की नीति के लिए, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मार्केट होल्ड के खिलाफ नीतिगत दर को कम करने का फैसला किया, जबकि 05 अक्टूबर, 2018 पॉलिसी के लिए, एमपीसी ने बाजार की दर की अपेक्षा के विपरीत नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। 07 दिसंबर 2016 के साथ-साथ 08 फरवरी 2017 की नीति के लिए एमपीसी का निर्णय दर में कटौती होने की बाजार की अपेक्षा के विपरीत नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखना था।

2000 (29 मई 2000 को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) योजना शुरू होने एवं स्थिर होने), 2006/7, 2008 (वैश्विक वित्तीय संकट), 2013 ('टेपर टैंट्रम') और 2016 (निर्दिविष्ट बैंक नोटों की वापसी) के लिए।[6] हम पाते हैं कि वैश्विक वित्तीय संकट और 'टेंपरेंट ट्रैंट्रम' के मद्देनजर वर्ष 2008 से 2013 के दौरान मौद्रिक नीति में हुए अप्रत्याशित परिवर्तन ने 'अतिरिक्त प्रतिलाभ' को अच्छा-खासा प्रभावित किया।

V. निष्कर्ष

लॉयड (2018) द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया को अपनाकर, इस लेख में पता लगाया गया है कि भारत में ओआईएस दरें 1, 9 और 12 महीने की परिपक्वता काल के लिए नीतिगत रिपो दर के बारे में बाजार की प्रत्याशा का सटीक माप प्रदान करती हैं। वैश्विक वित्तीय संकट और 'टेंपरेंट ट्रैंट्रम' के मद्देनजर वर्ष 2008 से 2013 के दौरान मौद्रिक नीति में अप्रत्याशित बदलाव ने सामान्य समय के विपरीत ओआईएस बाजार में 'अतिरिक्त प्रतिलाभ' को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया। भले ही नीति में बदलाव के सटीक समय को न बताता हो लेकिन यह भारत में ओआईएस दरों को मौद्रिक नीति की दिशा का अच्छा भविष्यवक्ता माना जाता है।

संदर्भ

Bernanke, B. S., and K. N. Kuttner (2005), "What explains the stock market's reaction to Federal Reserve policy?", *The Journal of Finance*, 60(3): 1221-1257.

Choy, W. K. (2003), "Introducing overnight indexed swaps", *Reserve Bank of New Zealand Bulletin*, 66(1): 34-39.

Fischer, Stanley (2017), "Monetary Policy Expectations and Surprises", accessed from https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/fischer20170417a.htm

Fixed Income, Money Market and Derivatives Association of India, (2016), *Handbook of Market Practices*, FIMMDA, April, page 35.

Joyce, M. and A. Meldrum (2008), "Market expectations of future Bank Rate", *Bank of England Quarterly Bulletin*, Q3.

Kuttner, K. N. (2001), "Monetary policy surprises and interest rates: Evidence from the Fed funds futures market", *Journal of Monetary Economics*, 47(3): 523-544.

Lloyd, S. (2018), "Overnight index swap market-based measures of monetary policy expectations", *Bank of England Working Paper.*

Reserve Bank of India (1999), "Forward Rate Agreements/ Interest Rate Swaps", *RBI Notification*, July 7, accessed from https://rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=2051&Mode=0.

--- (2013), "Standardisation of Interest Rate Swap Contracts", *RBI Notification*, January 28, accessed from https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=7828&Mode=0

Zulen, A. A. and O. Wibisono (2018). Measuring stakeholders' expectations for the central bank's policy rate. In *workshop on "Big data for central bank policies"*, Bank Indonesia, Bali, July (pp. 23-25). Accessed from https://www.bis.org/ifc/publ/ifcb50_19.pdf

[6] कृपया डमी संबंधी विवरण के लिए अनुबंध सारणी 2 देखें।

अनुबंध

अनुबंध सारणी 1: दैनिक बारंबारता पर भारतीय ओआईएस संविदा पर स्पष्ट औसत वास्तविक प्रतिलाभ *(जारी)*

पैनल ए: भारत ओआईएस संविदा									
परिपक्वता काल	**1 माह**	**2 माह**	**3 माह**	**4 माह**	**5 माह**	**6 माह**	**7 माह**	**8 माह**	**9 माह**
$\widehat{\alpha_n}$	**5.33**	11.43***	7.81***	12.86***	17.49***	6.51**	19.23***	11.59***	**2.08**
[टी-सांख्यिकी]	**[1.44]**	[3.50]	[2.62]	[3.44]	[5.38]	[2.15]	[5.42]	[3.83]	**[0.637]**
परिपक्वता काल	**10 माह**	**11 माह**	**1 वर्ष**	**2 वर्ष**	**3 वर्ष**	**4 वर्ष**	**5 वर्ष**	**7 वर्ष**	**10 वर्ष**
$\widehat{\alpha_n}$	7.92**	**5.17**	**4.40**	-26.28***	-43.34***	-71.17***	-94.33***	-182.01***	-260.49***
[टी-सांख्यिकी]	[2.43]	**[1.53]**	**[1.24]**	[-5.21]	[-7.78]	[-12.75]	[-17.24]	[-40.26]	[-43.18]
पैनल बी: 2000 डमी के साथ भारत ओआईएस संविदा[1]									
परिपक्वता काल	**1 माह**	**2 माह**	**3 माह**	**4 माह**	**5 माह**	**6 माह**	**7 माह**	**8 माह**	**9 माह**
$\widehat{\alpha_n}$	4.92	11.75***	8.65***	-	-	7.73**	-	-	**2.29**
[टी-सांख्यिकी]	[1.34]	[3.62]	[2.93]	-	-	[2.54]	-	-	**[0.69]**
2000 डमी	23.84	-15.22	-33.90	-	-	-33.04*	-	-	**-12.94**
[टी-सांख्यिकी]	[0.54]	[-0.44]	[-1.07]	-	-	[-1.68]	-	-	**[-0.45]**
परिपक्वता काल	**10 माह**	**11 माह**	**1 वर्ष**	**2 वर्ष**	**3 वर्ष**	**4 वर्ष**	**5 वर्ष**	**7 वर्ष**	**10 वर्ष**
$\widehat{\alpha_n}$	-	-	**3.27**	-	-	-	-	-	-
[टी-सांख्यिकी]	-	-	**[0.89]**	-	-	-	-	-	-
2000 डमी	-	-	**19.61**	-	-	-	-	-	-
[टी-सांख्यिकी]	-	-	**[1.26]**	-	-	-	-	-	-
पैनल सी: 2006 डमी के साथ भारत ओआईएस संविदा[2]									
परिपक्वता काल	**1 माह**	**2 माह**	**3 माह**	**4 माह**	**5 माह**	**6 माह**	**7 माह**	**8 माह**	**9 माह**
$\widehat{\alpha_n}$	5.63***	11.21***	7.90***	9.19***	12.94***	7.69***	-	-	**4.11**
[टी-सांख्यिकी]	[2.70]	[5.84]	[4.21]	[3.92]	[4.96]	[3.16]	-	-	**[1.35]**
2006 डमी	-8.79	5.57	-2.13	111.02	142.28***	-20.49	-	-	**-27.19**
[टी-सांख्यिकी]	[-0.09]	[0.08]	[-0.04]	[1.49]	[2.62]	[-0.61]	-	-	**[-1.21]**
परिपक्वता काल	**10 माह**	**11 माह**	**1 वर्ष**	**2 वर्ष**	**3 वर्ष**	**4 वर्ष**	**5 वर्ष**	**7 वर्ष**	**10 वर्ष**
$\widehat{\alpha_n}$	-	-	7.39**	-15.85***	-35.02***	-72.13***	-123.18***	-205.14***	-246.51***
[टी-सांख्यिकी]	-	-	[2.08]	[-2.78]	[-5.28]	[-9.79]	[-16.32]	[-35.49]	[-20.51]
2006 डमी	-	-	-34.85**	-64.52***	-35.02***	2.89	67.69***	72.71***	-25.03*
[टी-सांख्यिकी]	-	-	[-2.13]	[-6.44]	[-3.02]	[0.27]	[6.62]	[10.50]	[-1.93]
पैनल डी: 2007 डमी के साथ भारत ओआईएस संविदा[3]									
परिपक्वता काल	**1 माह**	**2 माह**	**3 माह**	**4 माह**	**5 माह**	**6 माह**	**7 माह**	**8 माह**	**9 माह**
$\widehat{\alpha_n}$	4.54**	10.45***	7.19***	9.27***	13.04***	7.29***	11.66***	-	**3.85**
[टी-सांख्यिकी]	[2.09]	[5.35]	[3.78]	[3.94]	[4.98]	[3.00]	[4.04]	-	**[1.27]**
2007 डमी	26.84	28.54	16.15	100.73	128.87**	-15.04	142.47***	-	**-25.08**
[टी-सांख्यिकी]	[0.26]	[0.37]	[0.26]	[1.46]	[2.51]	[-0.40]	[4.89]	-	**[-1.05]**
परिपक्वता काल	**10 माह**	**11 माह**	**1 वर्ष**	**2 वर्ष**	**3 वर्ष**	**4 वर्ष**	**5 वर्ष**	**7 वर्ष**	**10 वर्ष**
$\widehat{\alpha_n}$	-	-	6.82*	-16.31***	-36.70***	-72.22***	-118.80***	-205.78***	-247.04***
[टी-सांख्यिकी]	-	-	[1.93]	[-2.88]	[-5.57]	[-9.93]	[-15.35]	[-35.41]	[-20.08]
2007 डमी	-	-	-29.98*	-63.97***	-28.66**	3.25	58.38***	73.34***	-23.65*
[टी-सांख्यिकी]	-	-	[-1.74]	[-6.20]	[-2.42]	[0.29]	[5.71]	[10.61]	[-1.78]

अनुबंध सारणी 1: दैनिक बारंबारता पर भारतीय ओआईएस संविदा पर स्पष्ट औसत वास्तविक प्रतिलाभ *(जारी)*

पैनल ई: 2008 डमी के साथ भारत ओआईएस संविदा[4]									
परिपक्वता काल	**1 माह**	**2 माह**	**3 माह**	**4 माह**	**5 माह**	**6 माह**	**7 माह**	**8 माह**	**9 माह**
$\widehat{\alpha_n}$	5.69	11.67***	7.14**	10.06***	13.02***	3.48	-	-	-3.19
[टी-सांख्यिकी]	[1.50]	[3.49]	[2.32]	[2.83]	[4.02]	[1.19]	-	-	[-1.09]
2008 डमी	-12.97	-6.87	16.98	49.19***	80.88***	57.41***	-	-	78.86***
[टी-सांख्यिकी]	[-1.08]	[-0.51]	[1.46]	[4.12]	[6.25]	[2.73]	-	-	[3.18]
परिपक्वता काल	**10 माह**	**11 माह**	**1 वर्ष**	**2 वर्ष**	**3 वर्ष**	**4 वर्ष**	**5 वर्ष**	**7 वर्ष**	**10 वर्ष**
$\widehat{\alpha_n}$	-	-	-3.10	-49.45***	-68.70***	-99.16***	-114.37***	-220.06***	-326.38***
[टी-सांख्यिकी]	-	-	[-1.01]	[-11.24]	[-12.42]	[-15.42]	[-15.32]	[-61.12]	[22.34]
2008 डमी	-	-	92.08***	145.28***	106.72***	85.63***	46.78***	67.48***	67.66***
[टी-सांख्यिकी]	-	-	[3.92]	[8.65]	[7.57]	[7.65]	[4.42]	[8.83]	[4.28]
पैनल एफ़: 2013 डमी के साथ भारत ओआईएस संविदा[5]									
परिपक्वता काल	**1 माह**	**2 माह**	**3 माह**	**4 माह**	**5 माह**	**6 माह**	**7 माह**	**8 माह**	**9 माह**
$\widehat{\alpha_n}$	5.25	10.76***	7.86***	14.78***	20.74***	8.56***	28.93***	22.58***	5.86*
[टी-सांख्यिकी]	[1.39]	[3.22]	[2.60]	[4.35]	[6.63]	[2.82]	[9.58]	[12.31]	[1.77]
2013 डमी	3.65	23.88**	-1.74	-28.22	-44.22**	-44.65	-70.74***	-67.59***	-58.46***
[टी-सांख्यिकी]	[0.44]	[2.53]	[-0.09]	[-1.46]	[-2.36]	[-2.47]	[-4.78]	[-5.06]	[-4.15]
परिपक्वता काल	**10 माह**	**11 माह**	**1 वर्ष**	**2 वर्ष**	**3 वर्ष**	**4 वर्ष**	**5 वर्ष**	**7 वर्ष**	**10 वर्ष**
$\widehat{\alpha_n}$	22.94***	22.40***	9.88***	-8.86	-12.42**	-23.76***	-31.25***	-148.56***	-
[टी-सांख्यिकी]	[11.98]	[11.25]	[2.72]	[-1.63]	[-1.98]	[-3.72]	[-4.94]	[-50.68]	-
2013 डमी	-77.13***	-81.82***	-73.68***	-114.63***	-134.50***	-143.61***	-147.04***	-42.16***	-
[टी-सांख्यिकी]	[-6.73]	[-7.68]	[-6.38]	[-12.42]	[-14.79]	[-15.97]	[-16.95]	[-6.74]	-
पैनल जी: 2016 डमी के साथ भारत ओआईएस संविदा[6]									
परिपक्वता काल	**1 माह**	**2 माह**	**3 माह**	**4 माह**	**5 माह**	**6 माह**	**7 माह**	**8 माह**	**9 माह**
$\widehat{\alpha_n}$	5.42	11.48***	7.85***	13.20***	17.97***	6.45**	20.47***	11.25***	1.36
[टी-सांख्यिकी]	[1.45]	[3.46]	[2.57]	[3.65]	[5.23]	[2.05]	[5.17]	[3.24]	[0.39]
2016 डमी	-6.77	-3.30	-2.07	-7.20	-8.86**	1.71	-11.62***	2.68	13.95***
[टी-सांख्यिकी]	[-1.51]	[-0.73]	[-0.50]	[-1.64]	[-2.17]	[0.47]	[-2.66]	[0.64]	[3.07]
परिपक्वता काल	**10 माह**	**11 माह**	**1 वर्ष**	**2 वर्ष**	**3 वर्ष**	**4 वर्ष**	**5 वर्ष**	**7 वर्ष**	**10 वर्ष**
$\widehat{\alpha_n}$	5.89	2.02	3.21	-31.81***	-55.79***	-83.20***	-94.24***	-164.65***	-299.36***
[टी-सांख्यिकी]	[1.54]	[0.50]	[0.85]	[-5.48]	[-8.64]	[-12.75]	[-14.68]	[-25.73]	[-104.56]
2016 डमी	12.69***	17.82***	18.91***	39.99***	76.32***	61.71***	-0.41	-48.39***	64.73***
[टी-सांख्यिकी]	[2.73]	[3.65]	[3.88]	[6.29]	[10.92]	[6.06]	[-0.03]	[-6.43]	[6.69]

अनुबंध सारणी 1: दैनिक बारंबारता पर भारतीय ओआईएस संविदा पर स्पष्ट औसत वास्तविक प्रतिलाभ *(समाप्त)*

पैनल एच: सभी डमी के साथ भारत ओआईएस संविदा									
परिपक्वता	**1 माह**	**2 माह**	**3 माह**	**4 माह**	**5 माह**	**6 माह**	**7 माह**	**8 माह**	**9 माह**
$\widehat{\alpha_n}$	5.27**	10.89***	8.01***	7.83***	11.04***	8.15***	22.52***	24.17***	2.04
[टी-सांख्यिकी]	[2.54]	[5.25]	[4.71]	[3.83]	[4.95]	[3.99]	[11.40]	[11.47]	[0.82]
2000 डमी	23.49	-14.35	-33.27	-	-	-36.46*	-	-	-12.68
[टी-सांख्यिकी]	[0.54]	[-0.42]	[-1.05]	-	-	[-1.72]	-	-	[-0.44]
2006 डमी	-112.81**	-72.94*	-71.44**	138.54*	180.58***	-43.05***	183.08***	-	-32.41**
[टी-सांख्यिकी]	[-2.00]	[-19.2]	[-2.53]	[1.84]	[3.26]	[-2.75]	[5.91]	-	[-2.15]
2007 डमी	130.47	96.29	82.65	-26.15**	-36.39***	25.32	-37.97	-	8.00
[टी-सांख्यिकी]	[1.39]	[1.40]	[1.54]	[-2.38]	[-3.39]	[0.80]	[-4.07]	-	[0.37]
2008 डमी	-12.55	-6.09	16.10	51.42***	82.87***	52.74**	-	-	73.64***
[टी-सांख्यिकी]	[-1.09]	[-0.46]	[1.42]	[4.44]	[6.50]	[2.52]	-	-	[2.97]
2013 डमी	3.63	23.75***	-1.89	-21.26	-34.51*	-44.25**	-64.32***	-69.18***	-54.64***
[टी-सांख्यिकी]	[0.48]	[2.63]	[-0.11]	[-1.11]	[-1.85]	[-2.47]	[-4.39]	[-5.16]	[-3.93]
2016 डमी	-6.63**	-2.72	-2.23	-1.83	-1.93	0.01	-13.66***	-10.25***	13.27***
[टी-सांख्यिकी]	[-2.04]	[-0.75]	[-0.69]	[-0.56]	[-0.62]	[0.00]	[-5.07]	[-3.23}	[3.44]
परिपक्वता	**10 माह**	**11 माह**	**1 वर्ष**	**2 वर्ष**	**3 वर्ष**	**4 वर्ष**	**5 वर्ष**	**7 वर्ष**	**10 वर्ष**
$\widehat{\alpha_n}$	24.01***	23.14***	2.30	-22.64***	-31.78***	-29.03**	44.42***	-211.75***	-395.29***
[टी-सांख्यिकी]	[10.49]	[9.52]	[0.74]	[-3.47]	[-2.97]	[-2.29]	[3.16]	[-18.37]	[-22.53]
2000 डमी	-	-	20.58	-	-	-	-	-	-
[टी-सांख्यिकी]	-	-	[1.34]	-	-	-	-	-	-
2006 डमी	-	-	-57.18***	-19.98**	-105.43***	-31.02	71.07**	-	-
[टी-सांख्यिकी]	-	-	[-4.41]	[2.27]	[-10.32]	[-1.54]	[2.49	-	-
2007 डमी	-	-	30.08*	-86.72***	9.89	-50.28***	-158.31***	-	-
[टी-सांख्यिकी]	-	-	[1.66]	[-8.76]	[1.06]	[-2.61]	[-5.79]	-	-
2008 डमी	-	-	86.68***	151.66	116.86***	65.66***	-24.18**	65.16***	95.93***
[टी-सांख्यिकी]	-	-	[3.68]	[9.43]	[7.93]	[5.08]	[-2.10]	[5.86]	[5.54]
2013 डमी	-78.21***	-82.56***	-66.10***	-100.85	-119.26***	-162.42***	-253.81***	-8.31	68.91***
[टी-सांख्यिकी]	[-6.79]	[-7.68]	[-5.79]	[-10.18]	[-10.09]	[-13.95]	[-18.59]	[-0.76]	[6.98]
2016 डमी	-5.43	-3.30	19.81***	30.82***	61.67***	85.21***	81.55***	-	-
[टी-सांख्यिकी]	[-1.55]	[-0.89]	[4.51]	[4.39]	[5.58]	[7.86]	[8.46]	-	-

*, ** और *** क्रमशः 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत पर महत्व को दर्शाते हैं।

अनुबंध सारणी 2: प्रयुक्त डमी पर विवरण

डमी	प्रथम नीतिगत कार्रवाई की तारीख	अंतिम नीतिगत कार्रवाई की तारीख	डमी का मान
डी2000	22 जुलाई 2000	25 अक्तूबर 2000	डमी 22 **जून** 2000 से 25 अक्तूबर 2000 तक 1 का मान लेता है और 1 महीने के ओआईएस के लिए शून्य होता है; 22 **मई** 2000 से 25 अक्तूबर 2000 तक और 2 महीने के ओआईएस पर शून्य और इसी तरह।
डी2006	12 दिसंबर 2006	16 जुलाई 2007	उपरोक्त के समान कार्यनीति।
डी2007	01 फरवरी 2007	31 जुलाई 2007	
डी2008	20 अक्तूबर 2008	21 अप्रैल 2009	
डी2013	20 सितंबर 2013	28 जनवरी 2014	
डी2016	08 नवंबर 2016	31 दिसंबर 2016	

अनुबंध चार्ट 1: दैनिक बारंबारता पर भारतीय ओआईएस संविदा पर स्पष्ट औसत वास्तविक प्रतिलाभ *(जारी)*

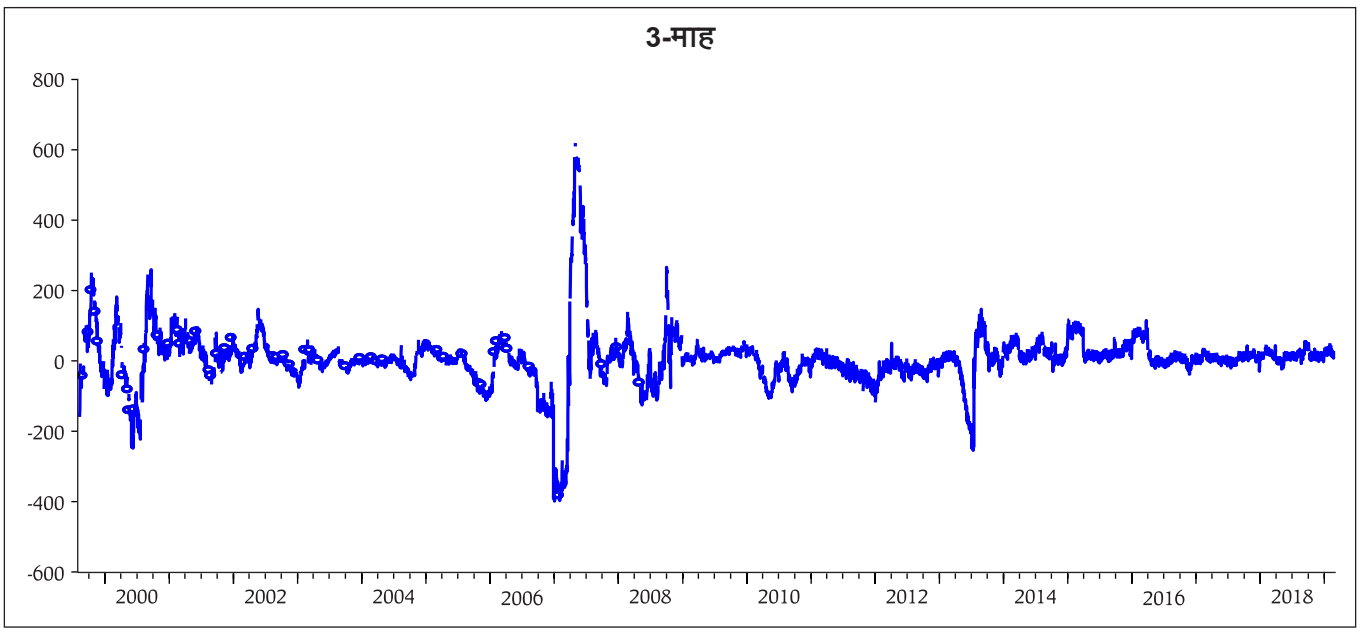

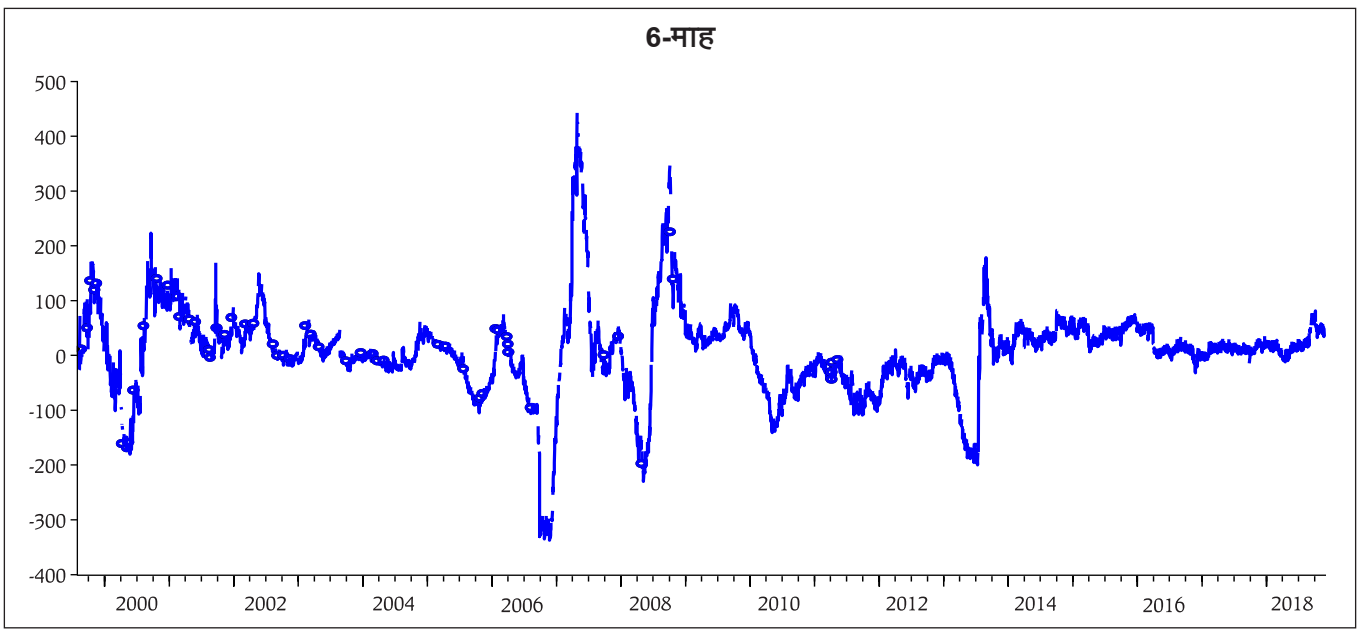

अनुबंध चार्ट 1: दैनिक बारंबारता पर भारतीय ओआईएस संविदा पर स्पष्ट औसत वास्तविक प्रतिलाभ *(समाप्त)*

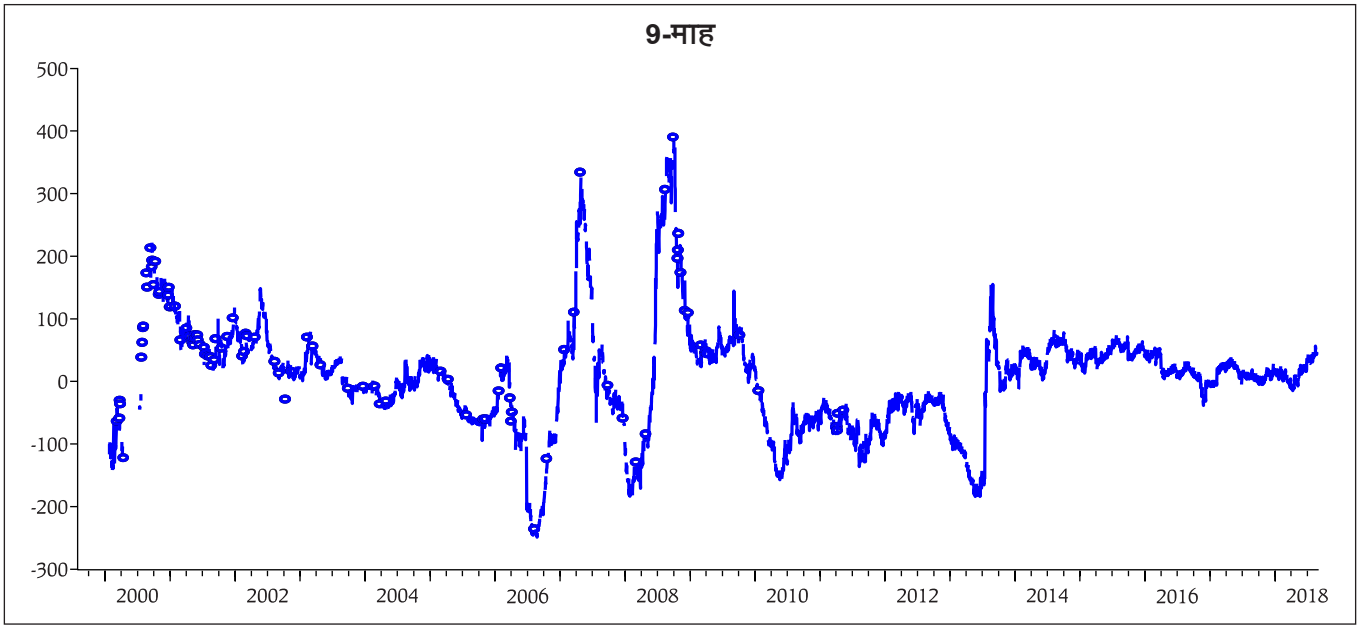

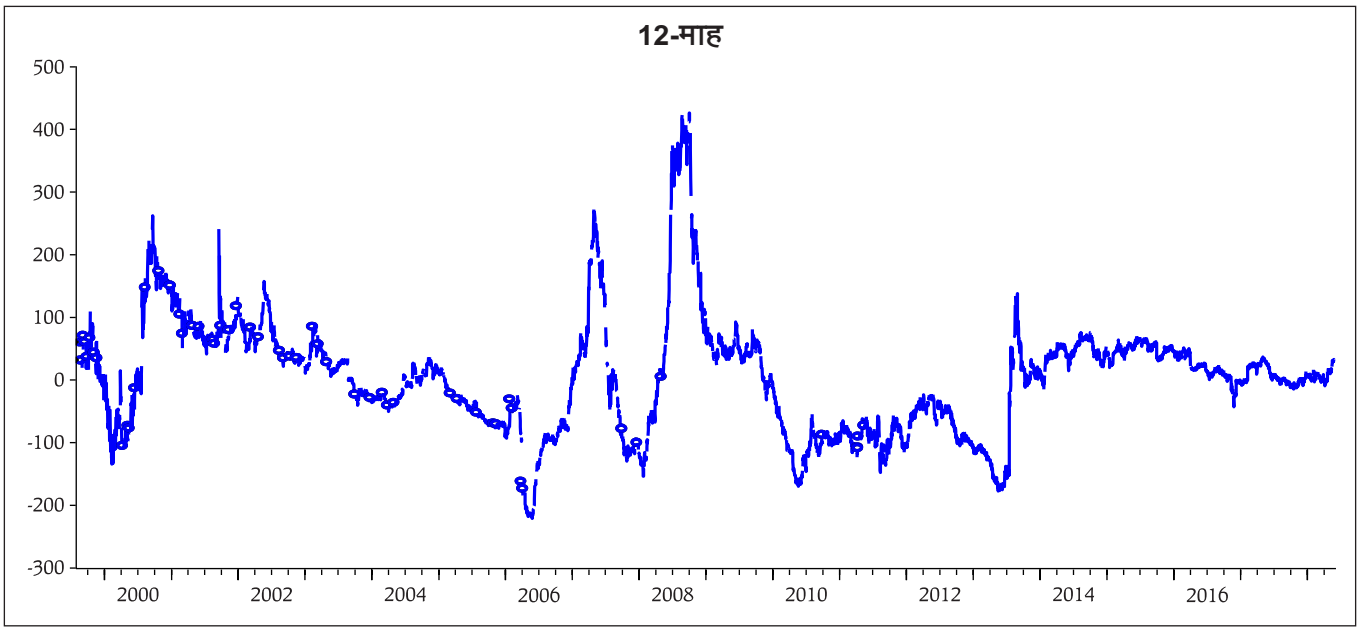

*क्या बाजार को ज्यादा पता है? पीबीआर के नजरिए से भारत का बैंकिंग क्षेत्र**

यह लेख भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के कीमत-बही अनुपात (पीबीआर) के निर्धारकों के लिए एक जांच-पड़ताल है। हमारे अनुभवजन्य विश्लेषण से संकेत मिलता है कि पीबीआर में भिन्नताओं का संबंध वित्तीय और आर्थिक चक्रों के साथ है। इसमें बैंकों के 'फ्रैंचाइज़ी मूल्य' को भी शामिल किया गया है और बैंकों की लाभप्रदता और व्यवहार्यता से संबंधित संकेतकों के साथ घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। इसलिए, इस लेख से पता चलता है कि पीबीआर को बैंक मूल्य के वैकल्पिक पैमाना के रूप में माना जा सकता है।

भूमिका

बैंक का मूल्य पता करने का उपयुक्त पैमाना क्या है? यद्यपि बैंकिंग गतिविधियों के विभिन्न आयामों (जैसे कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात, आस्ति गुणवत्ता के उपाय, जेड-स्कोर, लाभप्रदता और चलनिधि संकेतक) के कई आयाम हैं, तथापि इनमें से कोई भी व्यापक रूप से बैंकों के अंतर्निहित कारोबार मॉडल की व्यवहार्यता को नहीं दर्शाता है। यह मुख्य रूप से दो कारणों से होता है: पहला, ऋण मध्यस्थता के अपने प्रमुख कार्य को करते हुए बैंक उधारकर्ताओं और क्षेत्रों के बारे में निजी जानकारी जुटाते हैं। बैंकों के लिए, इस गतिविधि से मिलने वाले किराए या अर्ध-किराए अमूर्त आस्ति हैं (चोसाकोस और गॉर्टन, 2017)। इन सूचनात्मक अर्ध-किराए को आमतौर पर बैंकों के निजी "चार्टर मूल्य" या "विशेष अधिकार मूल्य" कहा जाता है (मार्कस, 1984)। प्रवेश के लिए बाधाओं या प्रवेश को सीमित करने वाली बाजार संरचना के कारण विशेष अधिकार मूल्य भी उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, बैंक, अन्य फर्मों के विपरीत, वित्तीय प्रणाली में अपनी अनूठी भूमिका को देखते हुए अधिक कड़े नियमों के अधीन हैं। इसलिए, कई मानक बैंकिंग संकेतक विनियामकीय वातावरण में परिवर्तन के कारण बदल सकते हैं; जरूरी नहीं कि वे बैंकों की सेहत में मूलभूत परिवर्तन को प्रतिबिंबित करें[1]। इस संदर्भ को देखते हुए, हम तर्क देते हैं कि बैंकों के कीमत-बही अनुपात (पीबीआर) को उनकी सेहत, स्थिरता और मूल्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए नियोजित किया जा सकता है।

पीबीआर को किसी फर्म के कुल बही मूल्य के सापेक्ष इक्विटी के बाजार मूल्य के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। यह टोबिन के Q की भावना के समान है - जिसे प्रतिस्थापन लागत पर बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। एक अपेक्षाकृत उच्च (निम्न) पीबीआर की व्याख्या आमतौर पर अंतर्निहित स्टॉक के अधिमूल्य (वाजिब से कम दाम रखना) के रूप में की जाती है। हालांकि यह व्याख्या गैर-वित्तीय फर्मों के लिए समझ में आता है जो अपेक्षाकृत कम विनियमित हैं और उत्पाद विशिष्टीकरण और नवाचार के लिए उनमें अधिक संभावनाएं हैं, वहीं वित्तीय फर्मों के लिए पीबीआर के निहितार्थ अलग और शायद अधिक महत्वपूर्ण हैं। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए, आस्तियों के बही मूल्य को अक्सर बाजार के लिए आस्तियों के कुछ वर्गों को चिह्नित करने की प्रथा के कारण बाजार मूल्य के करीब हो सकता है (बोगदानोवा, फेंडर एंड टैक, 2018)। इसके अलावा, मूल्यह्रास भौतिक आस्ति की तुलना में वित्तीय आस्तियों के लेखांकन में एक सीमित भूमिका निभा सकता है *(पूर्वोक्त)*। क्रॉस-सेक्शनल विविधता बैंकों के बीच सीमित हो सकता है, जिसे उत्पाद विशिष्टीकरण, निधियों की लागत और विनियामकीय इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा मापा जाता है। प्रभावी रूप से, उनका पीबीआर इस बात को कैप्चर कर सकता है कि वे ऋण जोखिम मूल्यांकन और निगरानी के मामले में स्प्रेड[2] को कितना बेहतर बनाते हैं और वे कितने कुशल हैं। दूसरे शब्दों में, अमूर्त आस्तियों द्वारा संचालित, उनके बही मूल्य से बहुत ज्यादा बैंकों के मूल्य का प्रदर्शन उनके प्रदर्शन से अधिक हो सकता है जैसा कि आर्थिक अभिकारकों द्वारा राशि की उपयोगिता, आस्ति-देयता प्रबंधन और समाधान संभावनाओं में उनकी प्रभावशीलता के आधार पर किया जाता है।

---

* यह लेख भारतीय रिज़र्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के भानु प्रताप, रंजॉय गुहा नेगी और जिबीन जोस द्वारा तैयार किया गया है। लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और रिज़र्व बैंक के विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं।

[1] इसके अलावा, गुडहार्ट का नियम कहता है कि जब कोई उपाय एक लक्ष्य बन जाता है, तो यह एक अच्छा उपाय नहीं रह जाता है - या दूसरे शब्दों में, यह अपनी सूचनात्मक सामग्री खो देता है।

[2] स्प्रेड = निधियों पर प्रतिलाभ - निधियों की लागत। निधियों पर प्रतिलाभ में ऋण और निवेश पर अर्जित ब्याज शामिल होगा; निधियों की लागत में जमाराशियां और उधारियों पर ब्याज शामिल है।

इसके अतिरिक्त, पीबीआर को बैंकों में लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं के मानकों को प्रतिबिंबित करने के तौर पर माना जा सकता है (बोगदानोवा, फेंडर एंड टेकट्स, 2018)। चूंकि बैंकों को ऋण और परिचालन जोखिमों (जैसे धोखाधड़ी) का सामना करना पड़ता है, जिससे संभावित रूप से बड़े और अचानक नुकसान होते हैं, इसलिए उनके ऋण पोर्टफोलियो का मूल्य और कमाई इस तरह के नुकसान के सही लेखांकन के अधीन होने चाहिए। वास्तव में, क्रेडिट जोखिम की पहचान में देरी और नुकसान का पता बाद में चलने के कारण भारत और अन्य देशों में बैंकिंग परेशानियों की विशेषता रही है (हुईझींग एवं लिवेन, 2012; विश्वनाथन, 2018)।

बैंक की लाभप्रदता और सुदृढ़ता का मूल्यांकन करने के लिए बाजार-आधारित उपाय को नियोजित करने के लिए सैद्धांतिक समर्थन कुशल बाजार परिकल्पना से आता है, जो बताता है कि सुरक्षा कीमतें पूरी तरह से उपलब्ध जानकारी को दर्शाती हैं (फामा, 1970)। इसका अर्थ यह होगा कि हमारे मामले में बाजार आधारित माप की सूचना देने वाली सामग्री - पीबीआर - किसी भी तुलन-पत्र-आधारित माप की तुलना में अधिक होने की संभावना है। एक व्यवसायी के दृष्टिकोण से, उच्च आवृत्ति पर बाजार डेटा की उपलब्धता और नई जानकारी के लिए उनकी संवेदनशीलता वित्तीय संस्थानों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के पीबीआर को एक उपयोगी मीट्रिक बना सकती है। भारतीय वित्तीय प्रणाली के बैंक-केंद्रित स्वरूप को देखते हुए, इस तरह के मूल्यांकन में बैंकों के पीबीआर की भूमिका को शायद ही समझा जा सकता है। न केवल बैंकों बल्कि वित्तीय क्षेत्र के प्रदर्शन का आकलन करने में पीबीआर की क्षमता के बावजूद, यह घोष (2009) और हेरवाडकर एवं प्रताप (2019) के अपवाद के साथ साहित्य में शायद ही अध्ययन किया गया है। अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में, बैंकों की पीबीआर और बैंक की विशेषताओं के साथ इसके अंतर्संबंधों के बारे में साहित्य की एक बड़ी संस्था मौजूद है (कैलोमीरिस और निसिम, 2014; चेसाकोस और गॉर्टन, 2017; डेमसेट्ज़, सैडेनबर्ग, और स्ट्रहान, 1996; और सरीन एंड समर्स, 2016))।

इसलिए, इस लेख में हमारा उद्देश्य वर्ष 2002-2017 की अवधि के लिए भारत में बैंकों के लिए पीबीआर के वाहकों का मूल्यांकन करके इस शोध अंतराल को भरना है। यहां हमारा प्राथमिक उद्देश्य बैंक मूल्य के माप के रूप में पीबीआर की वांछनीयता पर साक्ष्य प्रदान करना है। विशेष रूप से, हमने जांच किया है कि क्या पीबीआर प्रासंगिक तुलन-पत्र और समष्टि-वित्तीय सूचना को अमूर्त आस्तियों के अतिरिक्त शामिल करने में सक्षम है। लेख का शेष भाग निम्नानुसार विभाजित किया गया है: खंड II में मौजूदा साहित्य का विहंगम दृष्टि प्रदान किया गया है; खंड III में अनुभवजन्य विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है; और खंड IV में निष्कर्षों पर चर्चा की गयी है।

II. पीबीआर: मौजूदा साहित्य क्या कहता है?

बैंकों के चार्टर मूल्य पर पहले के अध्ययन अमेरिका में निक्षेप बीमा और बैंकिंग उद्योग के नियंत्रण के संदर्भ में थे (मार्कस, 1984; कीली 1990; और, डेमसेट्ज़, सैडेनबर्ग और स्ट्रहान, 1996)। इस प्रारंभिक साहित्य में दो मुख्य विचारों पर गौर किया गया था। पहले दृष्टिकोण में कहा गया था कि निक्षेप बीमा की मौजूदगी में बैंक अत्यधिक जोखिम उठा सकते हैं, जिससे अंतत: परिसमापन के मद्देनजर अमूर्त आस्तियों के नुकसान को अनदेखा किया जा सकता है। दूसरे दृष्टिकोण ने माना कि बैंक अपने अमूर्त आस्तियों के मूल्य को ध्यान में रखते हैं, और इस प्रकार चार्टर मूल्य और अन्य बैंक विशेषताओं के बीच के अंतर का विश्लेषण करते हैं। इन शोध-पत्रों के प्रमुख अनुभवजन्य निष्कर्षों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है: अधिक बाजार शक्ति वाले बैंक, जो बड़े बाजार-बही अनुपात में परिलक्षित होते हैं, आस्ति के सापेक्ष अधिक पूंजी रखते हैं; उनके पास चूक जोखिम कम था जैसा कि बड़े पैमाने पर कम जोखिम वाले प्रीमियमों में दर्शाया गया था, जो निक्षेप अबीमित जमा प्रमाण-पत्र थे; और बैंकों के विशेषाधिकार मूल्य और उनके जोखिम लेने के बीच विपरीत संबंध प्रतीत होते हैं।

वर्ष 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद अमेरिकी बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में कई शोध-पत्रों ने इन सवालों पर फिर से गौर किया, जिसमें मुख्य रूप से (ए) बाजार और बही मूल्यों के बीच उत्पन्न बड़े अंतर की जांच और (बी) संकट के दौरान अमेरिकी बैंकों का समग्र बाजार मूल्यांकन में नाटकीय और लगातार गिरावट, की जांच की गयी है। साहित्य ने इन प्रवृत्तियों का कारण दबावग्रस्त आस्तियों की पहचान करने में देरी करना, विपदाग्रस्त आस्तियों के मूल्य को बढ़ा-चढ़ा कर बताने वाली तोड़-मरोड़ कर की गयी वित्तीय रिपोर्टिंग और विनियामकीय पूंजी के साथ-साथ

अमूर्त आस्तियों, जैसे कि ग्राहक संबंध एवं अचिन्हित आकस्मिक दायित्वों के मूल्य में गिरावट को बताया है (ह्यूइज़िंग और लायवेन 2012; कैलोमिरिस और निसिम, 2014)।

साहित्य में एक और पहलू कि भी जांच की गयी कि क्या प्रमुख विनियामकीय हस्तक्षेप संकट के बाद किए गए थे, जैसे कि विनियामकीय पूंजी एवं लीवरेज में बदलाव और दबाव परीक्षण ने बैंकों द्वारा जोखिम कम कर दिया था। उस समय प्रचलित मान्यता के विपरीत, वित्तीय बाजार की जानकारी ने इस दृष्टिकोण के लिए बहुत कम समर्थन प्रदान किया कि प्रमुख वित्तीय संस्थान संकट से पहले काफी सुरक्षित थे। स्पष्टीकरण में प्रमुख वित्तीय संस्थानों के विशेषाधिकार मूल्य में एक नाटकीय गिरावट की ओर इशारा किया गया था, जो नए नियमों के कारण हुआ था। यह निष्कर्ष निकाला गया था कि विशेषाधिकार मूल्य में इस गिरावट ने वित्तीय संस्थानों को प्रतिकूल झटके के लिए अधिक संवेदनशील बना दिया (सरीन और ग्रीष्मकाल, 2016)।[3] अभी हाल ही में, बोगदानोवा, फेंडर और टैकट्स (2018) ने कैलारिस और निसिम (2014) के विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को एक बहु-देशीय व्यवस्था तक ले गए और निष्कर्ष निकाला कि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बैंक मूल्यांकन को बढ़ाने वाले कारकों में उल्लेखनीय रूप से बदलाव नहीं हुआ है।

जहां तक भारत से संबंधित साहित्य का सवाल है, घोष (2009) और हेरवाडकर एवं प्रताप (2020) के अध्ययन ने बैंकों के पीबीआर की जांच की है। घोष (2009) ने बैंकों द्वारा चार्टर मूल्य और जोखिम के बीच के अंतर का पता लगाया। उन्होंने वर्ष 1996-2006 की अवधि के लिए बैंक चार्टर मूल्यों को प्रभावित करने वाले प्रणालीगत और संस्थान-विशिष्ट कारकों की जांच की और बाजार एकाग्रता (दोनों जमा और ऋण स्तरों पर), बैंक के आकार और संचालन दक्षता को अपने प्रमुख प्रभावशाली कारकों के रूप में पाया। हेरवाडकर और प्रताप (2020) ने कुशल बाजार परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए वित्तीय बाजार संकेतकों में से एक संकेतक के रूप में पीबीआर का उपयोग किया है। विशेष रूप से, उन्होंने इस बात का परीक्षण किया कि क्या इक्विटी बाजार बैंकिंग दबाव के बारे में कोई प्रमुख जानकारी प्रदान करते हैं और उन्होंने पाया कि समवर्ती रूप से दबाव में बाजार मूल्य निर्धारित करने में सक्षम हैं, लेकिन अग्रिम तौर पर नहीं। हालांकि, अन्य बाजार-आधारित उपायों के सापेक्ष, पीबीआर आसन्न संकट के एक बेहतर संकेतक के रूप में उभरा है, खासकर निजी बैंकों के लिए।

III. प्रायोगिक विश्लेषण

हालिया और ऐतिहासिक प्रवृत्ति

वर्ष 2020 की शुरुआत से, कोविड-19 महामारी के फैलाने से घरेलू और वैश्विक वित्तीय बाजारों को झटका लगा था। जहां भारतीय इक्विटी बाजारों ने पहले दो महीनों के दौरान सावधानी से कदम रखा, वहीं मार्च 2020 में इक्विटी सूचकांकों में गिरावट देखी गई। चार्ट 1 निफ्टी बैंक सूचकांक, निफ्टी पीएसयू बैंक सूचकांक और निफ्टी प्राइवेट बैंक सूचकांक के पीबीआर में दैनिक उतार-चढ़ाव को दर्शाता है, जो क्रमशः भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के मूल्यांकन को दर्शाता है[4]। कोविड-19 मामलों के बढ़ने के साथ ऐसा देखा गया था कि देश के आगामी लॉकडाउन से हफ्तों पहले, मार्च 2020 की शुरुआत में बैंकिंग क्षेत्र के बाजार मूल्यांकन में भारी गिरावट आयी थी। सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए प्रतिचक्रीय उपायों की वजह से बाद के महीनों में पीबीआर स्थिर और निर्धारित सीमा के अंदर थे, भले ही यह सीमा वर्ष की शुरुआत में मूल्यांकन की तुलना में काफी कम हो। इसके बाद, मुख्य रूप से निजी बैंकों द्वारा संचालित समग्र बैंकिंग क्षेत्र का मूल्यांकन महामारी के सदमे से बेशक उबर रहा है। दूसरी ओर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बाजार मूल्य अपने महामारी-पूर्व स्तर से नीचे बना हुआ है[5]।

भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कमजोर सन्निकट आर्थिक दृष्टिकोण को देखते हुए, हमने पिछले दो दशकों में देखे गए बैंकों के पीबीआर में इसी तरह के बदलावों और बैंकिंग क्षेत्र

[3] चॉसाकोस और गॉर्टन (2017) में इसी तरह के निष्कर्ष पाए जा सकते हैं जिसमें उन्होंने टोबिन के Q का उपयोग करके बैंक की सेहत का मूल्यांकन किया।

[4] निफ्टी बैंक सूचकांक एक बेंचमार्क प्रदान करता है जो भारतीय बैंकों के पूंजी बाजार के प्रदर्शन को बताता है, जिसमें सबसे अधिक चलनिधि और बड़े भारतीय बैंकिंग स्टॉक शामिल हैं। इसी तरह, निफ्टी पीएसयू बैंक सूचकांक और निफ्टी प्राइवेट बैंक सूचकांक को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें - *https://www.niftyindices.com/indices/equity/sectoral-indices.*

[5] 5 नवंबर 2020 के अंत तक।

चार्ट 1: कीमत-बही अनुपात (वाईटीडी) में दैनिक उतार-चढ़ाव

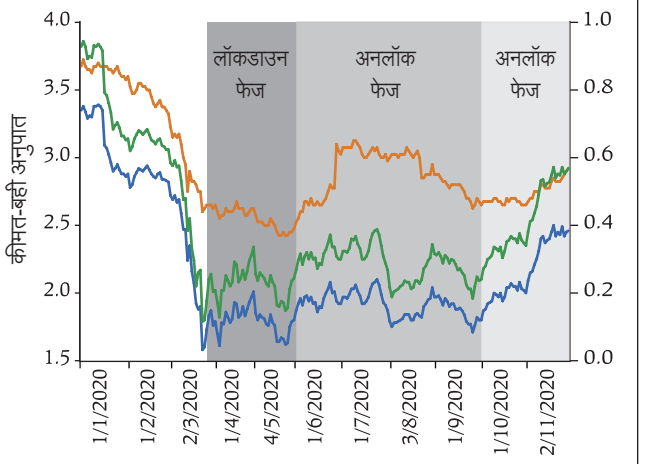

स्रोत: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई); लेखक की गणना

चार्ट 2: कीमत-बही अनुपात में ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव

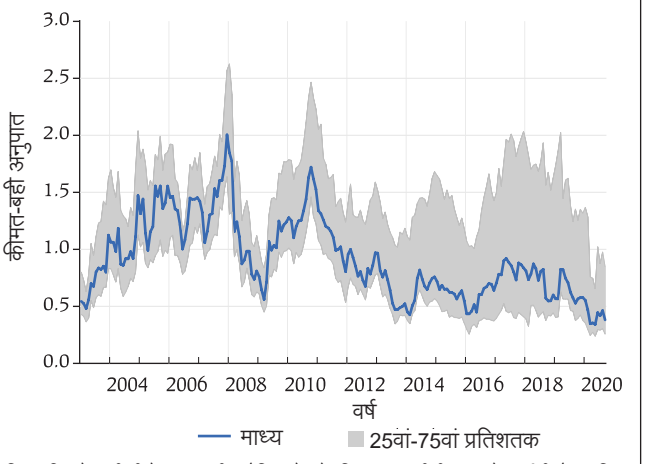

टिप्पणी: ठोस नीली रेखा भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए माध्य पीबीआर को दर्शाती है जबकि छायांकित धूसर भाग अंतश्चतुर्थक रेंज यानि 25वीं -75वीं प्रतिशतक रेंज पीबीआर डेटा पर आधारित है।

स्रोत: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई); लेखक की गणना

के मूल्यांकन में मौजूदा गिरावट का तुलना किया है। चार्ट 2 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के समग्र मूल्यांकन को दर्शाता है, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध भारतीय एससीबी के औसत पीबीआर द्वारा मापा जाता है। चार्ट सूचीबद्ध भारतीय बैंकों के लिए पीबीआर वितरण की अन्तःचतुर्थक रेंज को भी इंगित करता है। व्यापक टिप्पणी इस प्रकार हैं। पहला, वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान बैंक मूल्यांकन में एक समान लेकिन तेज गिरावट देखी गई थी। दूसरा, संकट के उपरांत त्वरित रिकवरी के बाद, बैंकों के निचले चतुर्थक और मध्य समूह के लिए पीबीआर 2012 के बाद से लगातार नीचे बना हुआ है। यह अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के उच्च अनुपात के साथ बैंकिंग क्षेत्र के समग्र सेहत का संकेत है[6]। तीसरा, बैंकों के शीर्ष, औसत और निचले चतुर्थक समूहों के बीच के मूल्यों का अंतर वैश्विक वित्तीय संकट के आसपास अपेक्षाकृत कम था। हालाँकि, तब से इसमें विस्तार हुआ है। जैसा कि पहले कहा गया था, कीमत-बही अनुपात में बदलाव दबावग्रस्त आस्तियों की भविष्यवाणी करने में सक्षम हैं, खासकर निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में (हेरवाडकर और प्रताप, 2020)।

[6] चूंकि सभी चतुर्थांशों के लिए मूल्यांकन समान प्रवृत्ति दर्शाते हैं, इसलिए बैंकिंग क्षेत्र का औसत मूल्यांकन बाहरी से प्रभावित नहीं होता है।

भारतीय बैंकों के पीबीआर के वाहकों को निर्धारित करने के लिए, हम व्याख्यात्मक चर का एक सेट मानते हैं, जिसमें बैंक-स्तर के साथ-साथ समष्टि-वित्तीय संकेतक शामिल हैं (कैलोमिरिस और निसिम, 2014; बोग्डानोवा, फेंडर और टैकट्स, 2018)। यह अपेक्षा की जाती है कि किसी बैंक की कीमत-बही मूल्य सकारात्मक रूप से निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पर निर्भर करती है और बैंक की लाभप्रदता और आस्ति की गुणवत्ता के संकेतक के रूप में लिए गए कुल दबावग्रस्त आस्ति अनुपात (सकल अग्रिमों के अनुपात) पर नकारात्मक रूप से निर्भर करती है। इसके अलावा, मूल्यांकन एक बैंक की कारोबारी गतिविधियों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और इसलिए हम व्याख्यात्मक चर के रूप में कुल ब्याज-सहित जमाराशियाँ और ब्याज-रहित जमाराशियाँ (दोनों को कुल आस्ति के अनुपात के रूप में लिया गया है) शामिल हैं। ब्याज-सहित जमाराशियों का एक बड़ा हिस्सा खाते के रखरखाव और लगाए गए ब्याज पर अधिक खर्च होगा, और इस तरह यह बैंक के मूल्यांकन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। दूसरी ओर, यह निधीयन के स्थिर स्रोत के दृष्टिकोण से बैंक के लिए शुभ हो सकता है। इसलिए, जमाराशि और बैंक मूल्यांकन के बीच अनुभवजन्य संबंध अलग-अलग कार्य-क्षेत्र में भिन्न हो सकते हैं।

आमतौर पर, उच्च स्तर के विनियामकीय पूंजी वाले बैंकों को वित्तीय रूप से मजबूत माना जाता है। इस प्रकार, हम अपने मॉडल में कुल जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) को शामिल करते हैं और प्रत्याशा करते हैं कि यह बैंक के मूल्यांकन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। बैंक का आकार कुल आस्तियों से नियंत्रित होता है। अंत में, हमने कारोबार और मूल्यांकन के वित्तीय चक्र संचालकों के रूप में आउटपुट अंतर और ऋण की तुलना में जीडीपी अंतर को शामिल किया है[7]। स्कैटर प्लॉट्स पीबीआर और अपेक्षित लाइनों के साथ व्याख्यात्मक चर के बीच एक मजबूत सहसंबंध का पता चलता है (चार्ट 3)।

चार्ट 3: कीमत-बही अनुपात और इसके निर्धारक – बिन स्कैटर प्लॉट्स[8]

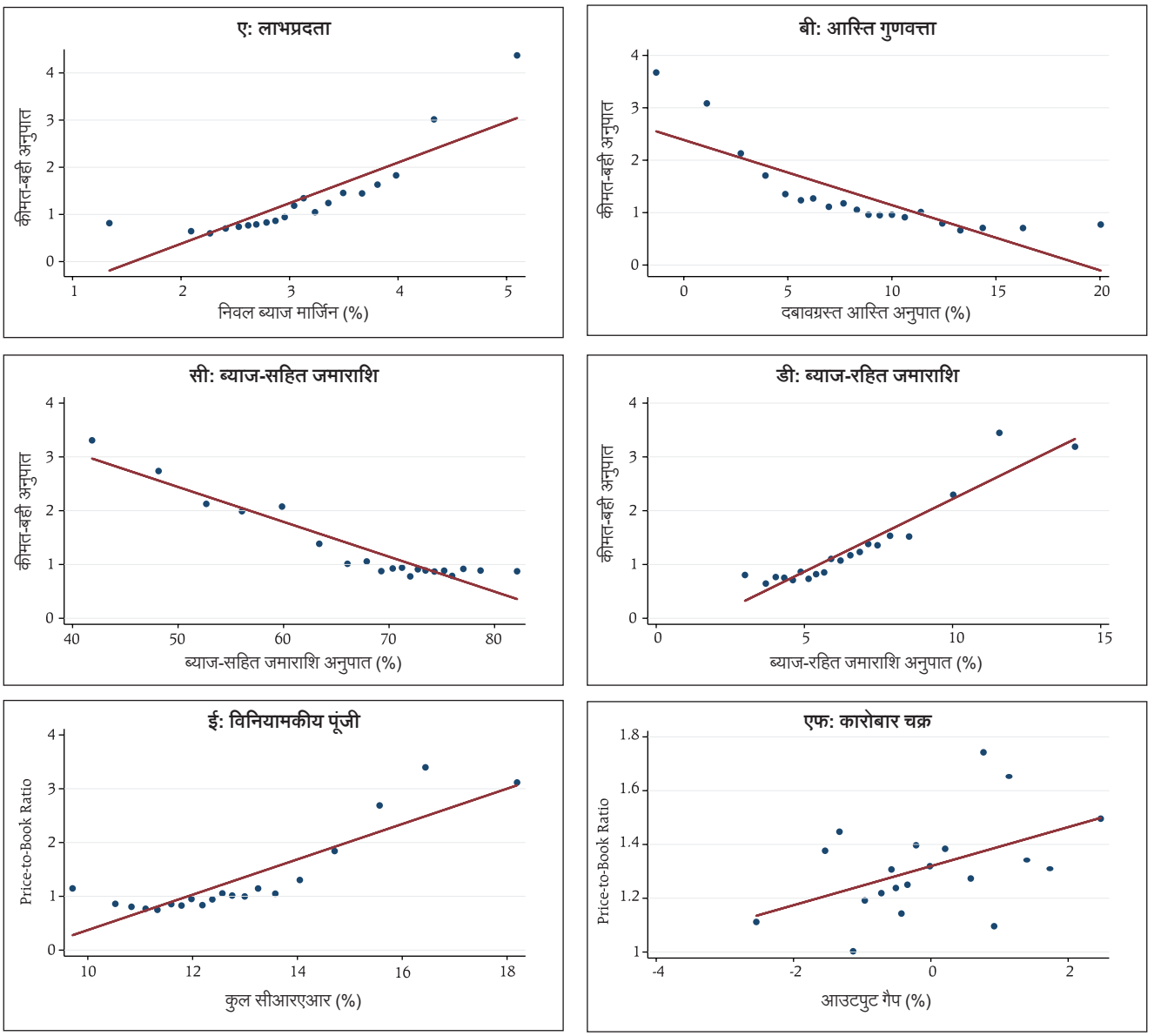

टिप्पणी: बैंक और समय निश्चित प्रभावों के लिए उपरोक्त गणना नियंत्रण करती है।

स्रोत: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई); लेखक की गणना

[7] आउटपुट गैप भारत के लिए तिमाही वास्तविक जीडीपी संबंधी एक मानक होड्रिक-प्रेसकॉट फिल्टर-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके प्राप्त किया गया है।

[8] बिन्ड स्कैप्लेट्स दो चर के बीच के रिश्ते की परिकल्पना करने का एक नन-पैरामीट्रिक तरीका प्रदान करते हैं। बिनस्कैटर, x-अक्ष चर को समान-आकार वाले डिब्बे में समूहित करता है, प्रत्येक बिन के भीतर x-अक्ष और y-अक्ष चर के माध्य की गणना करता है, फिर इन डेटा बिंदुओं का एक स्कैल्प बनाता है। परिणाम सशर्त अपेक्षा फ़ंक्शन का एक नन-पैरामीट्रिक विजुअलाइजेशन है। यह संबंध स्थापित करने से पहले कोवरिएट के लिए नियंत्रण करने की भी अनुमति देता है।

कीमत-बही अनुपात और उसके निर्धारकों के बीच संबंधों की औपचारिक रूप से जांच करने के लिए हमने एक निश्चित प्रभाव पैनल प्रतिगमन फ्रेमवर्क का उपयोग किया है[9]। हम बोगदानोवा, फेंडर और टकसैट (2018) के विस्तारित मॉडल का उपयोग इस प्रकार करते हैं:

$$PBR_{it} = \alpha_i + \beta_1 SAR_{it} + \beta_2 IBdep_{it} + \beta_3 NIBdep_{it} + \beta_4 NIM_{it} + \beta_5 CRAR_{it} + \beta_6 Assets_{it} + \beta_7 Ygap_t + \beta_8 creditgap_t + \varepsilon_{it}$$

पीबीआर t समय पर बैंक के कीमत-बही अनुपात i को दर्शाता है, α_i समय-अपरिवर्तित, बैंक निश्चित प्रभाव और β_i संबंधित ढलान गुणांक को दर्शाता है। हमारे नमूने में वर्ष 2002-2017 के दौरान भारत में सक्रिय 39 सूचीबद्ध बैंक शामिल हैं[10]। इस मॉडल में व्याख्यात्मक चर के रूप में निम्नलिखित शामिल हैं: दबावग्रस्त आस्तिअनुपात (एसएआर), ब्याज-सहित जमाराशि अनुपात (आईबीडीईपी), ब्याज-रहित जमाराशि अनुपात (एनआईबीडीपी), निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम), जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर), कुल आस्ति (प्राकृतिक लघुगणक में), आउटपुट गैप (Yगैप) और क्रेडिट-टू-जीडीपी गैप (क्रेडिटगैप)। हमारे मॉडल के लिए अंतर्निहित डेटा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) से प्राप्त किए गए हैं। हमने वर्ष 2002 की पहली तिमाही से वर्ष 2017 की चौथी तिमाही तक के डेटा का उपयोग करके उपरोक्त मॉडल का अनुमान लगाया है। मानक त्रुटियों को बैंक-स्तर पर क्लस्टर किया गया है[11]।

सारणी ए1 (अनुबंध) बैंकों के पूर्ण नमूने के लिए हमारे प्रतिगमन विश्लेषण से प्राप्त परिणाम को बताता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए अलग-अलग अनुमान प्रदान किए गए हैं। हम पाते हैं कि बैंक की लाभप्रदता बैंक के बाजार मूल्यांकन को बढ़ावा देती है, जबकि खराब आस्ति गुणवत्ता, यानी, बैंक के तुलन-पत्र पर उच्च दबाव वाली आस्तियां औसतन इसके मूल्यांकन को प्रभावित कर सकती हैं। जब उप-वर्गों के बीच तुलना की जाती है, तो सार्वजनिक बैंकों के मामले में लाभप्रदता और निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में आस्ति की गुणवत्ता उनके पीबीआर के सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण चालकों के रूप में उभरती है। इसी तरह, जहां ब्याज-सहित जमाराशियों के अनुपात का मूल्यांकन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है, वहीं ब्याज-रहित जमाराशियों के एक उच्च अनुपात में बैंक के बाजार मूल्यांकन में सुधार होता है। यद्यपि विनियामकीय पूंजी का मूल्यांकन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, फिर भी सिद्धांत के अनुरूप, यह प्रभाव पारंपरिक स्तरों पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। यह देखते हुए कि बैंकों को सीआरएआर का न्यूनतम स्तर बनाए रखना आवश्यक है, यह परिणाम आश्चर्यजनक नहीं है। इससे पता चलता है कि विभिन्न बैंकों की बाजार धारणा तब तक समान है जब तक वे पूंजी के वांछित स्तर को बनाए रखते हैं। दूसरी तरफ, पीबीआर और बैंक पूंजी के बीच संबंध गैर-रैखिक भी हो सकता है जो हमारे रैखिक मॉडल द्वारा अन्यथा शामिल नहीं किया जाता है। एक सकारात्मक आउटपुट गैप आमतौर पर बैंक ऋण की मजबूत मांग का संकेत है, जो बैंकिंग कारोबार के लिए शुभ हो सकता है। हमारे मॉडल में आउटपुट गैप पर एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक गुणांक इस बिंदु को पुष्ट करता है। दूसरी ओर, एक बड़े और सकारात्मक ऋण-जीडीपी अंतर अक्सर बैंकिंग क्षेत्र में संकट का कारण पाया जाता है जो ऋण और आस्ति मूल्य बुलबुले को रेखांकित करते हैं। इस तर्क के अनुसार, ऋण-जीडीपी अंतर हमारे मॉडल के अनुसार एक नकारात्मक गुणांक को दर्शाता है। हालांकि, शायद घरेलू बैंकिंग क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रमुख उपस्थिति के कारण, ऋण-जीडीपी अंतर केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजी क्षेत्र के समकक्षों के मामले में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अनुमानित मॉडल भारत में बैंकों के लिए पीबीआर की व्याख्या करने की अपनी क्षमता को रेखांकित करते हुए एक उचित समंजन-सुष्ठुता दिखाता है।

IV. निष्कर्ष

इस लेख में भारतीय संदर्भ में पीबीआर से संबंधित तीन निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं: पहला, पीबीआर में भिन्नताएं वित्तीय और समष्टि-आर्थिक चक्रों के साथ संबंध रखती हैं; दूसरा, यह बैंकों के चार्टर मूल्य को शामिल करता है; तीसरा, पीबीआर बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता और व्यवहार्यता से संबंधित विभिन्न

[9] फिक्स्ड इफेक्ट पैनल मॉडल का चुनाव हौसमैन टेस्ट द्वारा समर्थित था।

[10] यह विश्लेषण 39 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के एक बैंक-स्तरीय पैनल डेटासेट पर आधारित है, जिसमें 24 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और 15 निजी क्षेत्र के बैंक शामिल हैं। विदेशी बैंकों को विश्लेषण से बाहर रखा गया है क्योंकि वे सूचीबद्ध संस्थाएं नहीं हैं।

[11] अतिरिक्त नैदानिक जांचों ने समविसारित और असंबद्ध त्रुटियों का समर्थन नहीं किया। इसलिए, मॉडल का अनुमान मजबूत मानक त्रुटियों के साथ समायोजित किया गया था जो विषमविसारिता और स्वसहसंबंध के लिए समायोजित किया गया था।

संकेतकों के साथ एक मजबूत संबंध रखता है। जैसा कि यह एक वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध है, तुलन-पत्र आंकड़ों के विपरीत बैंकों का पीबीआर नीतिगत उद्देश्यों के लिए एक उपयोगी मीट्रिक हो सकता है। यह वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न खंडों की सेहत का आकलन करने में इस तरह के उपाय का और मूल्यांकन के लिए भी मामला बनाता है, जो कि बही और बाजार-आधारित मूल्यांकन मीट्रिक को जोड़ती है। कोविड-19 महामारी के बाद, भारतीय बैंकों के पीबीआर में तेजी से गिरावट देखी गई। बैंकों के बाजार मूल्यांकन में गिरावट को रोक दिया गया था, और हाल ही में, बैंकिंग क्षेत्र के लिए पीबीआर ने कायापलट करना शुरू कर दिया है। यह अर्थव्यवस्था में और विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र में विश्वास को बहाल करने में प्रतिचक्रीय नीतियों द्वारा निभाई गई भूमिका को रेखांकित करता है।

संदर्भ

Bogdanova, B., Fender, I., & Takáts, E. (2018), The ABCs of bank PBRs. *BIS Quarterly Review*, pp. 81-95.

Calomiris, C. W., & Nissim, D. (2014). Crisis-related shifts in the market valuation. *Journal of Financial Intermediation*, 400-435.

Chousakos, K. T., & Gorton, G. B. (2017, February). *http://www.nber.org/papers/w23167.* Retrieved from http://www.nber.org/:http://www.nber.org/papers/w23167

Demsetz, R. S., Saidenberg, M. R., & Strahan, P. E. (1996, October). Banks with Something to Lose: The Disciplinary Role of Franchise Value. *Economic Policy Review, Federal Reserve Bank of New York.*

Diamond, D. W. (1984). Financial Intermediation and Delegated Monitoring. *The Review of Economic Studies*, 393-414.

Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. *The Journal of Finance*, 383-417.

Ghosh, S. (2009). Charter value and risk-taking: evidence from Indian banks. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 270-286.

Gorton, G., & Pennacchi, G. (1990). Financial Intermediaries and Liquidity Creation. *The Journal of Finance*, 49-71.

Herwadkar, S. S., & Pratap, B. (2019). Can financial markets predict banking distress? Evidence from India. *Reserve Bank of India Occassional Papers*, 65-90.

Huizinga, H., & Laeven, L. (2012). Bank valuation and accounting discretion during a financial crisis. *Journal of Financial Economics*, 614-634.

Keeley, M. C. (1990). Deposit Insurance, Risk, and Market Power in Banking. *The American Economic Review*, 1183-1200.

Marcus, A. J. (1984). Deregulation and bank financial policy. *Journal of Banking and Finance*, 557-565.

Sarin, N., & Summers, L. H. (2016, September 15-16). Have big banks gotten safer. *Brookings Papers on Economic Activity.*

Vishwanathan, N. S. (2018, April 18). *https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1055.* Retrieved from https://www.rbi.org.in/: https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Speeches/PDFs/NIBMS180420186468CF423F80468784A4E51BAD19924F.PDF

अनुबंध
सारणी ए1: कीमत-बही अनुपात विश्लेषण – प्रतिगमन अनुमान

चर वस्तुएँ	पूर्ण नमूना	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी बैंक
स्वतंत्र / आश्रित	पीबीआर (1)	पीबीआर (2)	पीबीआर (3)
एनआईएम	0.12** (0.054)	0.031* (0.015)	0.18 (0.12)
एसएआर	-0.028*** (0.0067)	-0.0063 (0.0049)	-0.043*** (0.010)
आईबी जमाराशि	-0.0033 (0.0062)	-0.0072 (0.0045)	-0.0025 (0.0085)
एनआईबी जमाराशि	0.066*** (0.020)	0.020 (0.015)	0.076*** (0.016)
कुल सीआरएआर	0.020 (0.018)	0.013 (0.014)	0.0074 (0.024)
कुल आस्तियां	0.21** (0.077)	-0.64*** (0.12)	0.24** (0.10)
आउटपुट गैप	0.073*** (0.016)	0.056*** (0.011)	0.099*** (0.019)
ऋण-जीडीपी गैप	-0.0035 (0.012)	-0.015** (0.0067)	-0.0099 (0.017)
स्थिरांक	-1.69** (0.79)	8.78*** (1.64)	-1.49 (1.03)
एडीजे. आर²	0.904	0.712	0.886
बीआईसी	1112.3	-167.9	772.1
एफ़-स्टैट	18.20	25.25	72.94
बैंक एफ़ई	Y	Y	Y
एन	1364	792	572

कोष्ठकों में मानक त्रुटियां; * p <0.10, ** p <0.05, *** p <0.01: मानक त्रुटियां बैंक-स्तर पर क्लस्टर की जाती हैं।

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

अवसरिक शृंखला

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	95
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	96
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	97
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय/विक्रय	98
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	99
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	99
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	100
7	मुद्रा स्टॉक ($एम_3$) के स्रोत	101
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	102
9	कुल चलनिधि राशियां	102
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	103
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	103
12	वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण	104
13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश	104
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	105
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	106
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	107
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	108
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)	109
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	109
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	109
21	थोक मूल्य सूचकांक	110
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)	114
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	114
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	115
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	115
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	116
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	117
28	वाणिज्यिक पत्र	117
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	117
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	118

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	119
32	विदेशी मुद्रा भंडार	119
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	119
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	120
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	120
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	121
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार	121
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमरीकी डॉलर)	122
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	123
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	124
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	125
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	126
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	127
	अवसरिक श्रृंखला	
44	लघु बचत	129
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	130
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	131
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	132
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	133
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	134

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।
– = शून्य/नगण्य
प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2019-20	2019-20		2020-21	
		ति1	ति2	ति1	ति2
	1	2	3	4	5
1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	4.1	4.8	4.3	-22.8	-7.0
1.1.1 कृषि	4.3	3.0	3.5	3.4	3.4
1.1.2 उद्योग	-2.0	3.8	-0.2	-33.8	0.1
1.1.3 सेवाएं	6.4	5.5	6.1	-24.3	-11.1
1.1क अंतिम खपत व्यय	5.9	5.6	7.8	-19.2	-13.3
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	5.4	4.6	-3.9	-47.1	-7.3
	2019-20	2019		2020	
		नवं.	दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	-0.8	2.1	0.4	-1.9	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	7.9	9.5	9.7	10.7	10.8
2.1.2 ऋण	6.1	7.2	7.0	5.9	6.3
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	6.1	7.2	6.9	5.9	6.2
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	10.6	8.6	12.9	19.3	17.3
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	9.4	12.4	10.2	15.3	14.9
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	8.9	9.8	10.4	12.5	12.4
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.25	18.50	18.50	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.6	4.8	4.8	3.8	3.7
3.4 ऋण-जमा अनुपात	76.4	75.5	76.2	72.2	73.1
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	60.3	22.5	39.0	11.0	23.9
3.6 निवेश-जमा अनुपात	27.6	28.3	28.7	30.5	30.4
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	36.2	62.4	74.1	73.6	72.0
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	4.40	5.15	5.15	4.00	4.00
4.2 रिवर्स रिपो दर	4.00	4.90	4.90	3.35	3.35
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	4.65	5.40	5.40	4.25	4.25
4.4 बैंक दर	4.65	5.40	5.40	4.25	4.25
4.5 आधार दर	8.15/9.40	8.95/9.40	8.45/9.40	7.40/8.80	7.30/8.80
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	7.40/7.90	7.65/8.10	7.65/8.00	6.60/7.10	6.55/7.10
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	5.90/6.40	6.25/6.60	6.20/6.40	4.90/5.50	4.90/5.50
4.8 बचत जमा दर	3.00/3.50	3.25/3.50	3.25/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	5.05	5.03	5.11	3.10	3.24
4.10 91-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	4.36	4.99	5.03	2.93	3.08
4.11 182-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	4.97	5.12	5.22	3.26	3.34
4.12 364-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	4.94	5.14	5.30	3.39	3.46
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	6.71	6.65	6.78	5.84	5.89
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिआ					
5.1 भा.रु.-अमरीकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	74.84	71.73	71.22	73.80	73.58
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	82.64	78.98	79.19	88.02	89.81
5.3 फारवर्ड प्रीमिआ अमरीकी डॉलर 1-माह (%)	8.98	3.35	3.96	3.36	3.84
3-माह (%)	5.93	3.35	3.90	3.52	3.75
6-माह (%)	5.05	3.76	4.38	4.23	4.35
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	4.76	5.5	7.4	6.9	4.6
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	7.54	8.6	9.6	5.2	3.6
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	1.69	0.6	2.8	1.6	1.2
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	6.77	7.6	11.5	2.7	-1.6
6.3.2 ईंधन और पावर	-1.63	-7.3	0.4	-9.9	-8.7
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	0.29	-0.8	-0.3	3.0	4.2
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	-7.65	-11.8	-6.5	-13.3	7.6
7.2 निर्यात	-5.09	-1.3	-2.7	-8.6	0.1

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिज़र्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2019-20	2020	2021				
		जन.	जन. 1	जन. 8	जन. 15	जन. 22	जन. 29
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	2412993	2284695	2743696	2771243	2783749	2784521	2780045
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	10	11	13	13	12	14	13
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	**2413003**	**2284706**	**2743710**	**2771256**	**2783761**	**2784535**	**2780058**
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	103439	95254	116876	118959	113828	114934	114391
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2308718	2188733	2625902	2651381	2669031	2668713	2664788
1.2.3 रुपया सिक्का	846	719	932	916	902	889	879
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	–	–	–	–	–	–	–
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	1187409	994030	1492712	1456944	1448893	1468254	1512883
2.1.1.1 केंद्र सरकार	100	101	100	101	101	100	101
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	43	42	43	42	43	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	536186	550704	474193	452435	483618	463150	476349
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7603	6841	5954	5183	5653	5316	6536
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3445	3002	2633	2524	2545	2594	2619
2.1.1.7 अन्य बैंक	32641	31707	26586	27358	26532	26966	26397
2.1.1.8 अन्य	605100	400909	978453	969246	923863	956388	987112
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	2291	724	4751	55	6539	13697	13726
2.1.2 अन्य देयताएं	1350333	1161436	1460301	1472530	1449770	1447525	1440272
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	**2537742**	**2155466**	**2953013**	**2929474**	**2898663**	**2915779**	**2953154**
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	10	11	13	13	12	14	13
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1006357	955641	1362382	1347801	1318350	1318405	1357052
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	50477	73545	–	–	–	–	–
2.2.3.2 राज्य सरकारें	1967	1210	5569	5460	9955	5868	4769
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	285623	16915	77140	77097	77193	84607	84597
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.6 नाबार्ड	–	–	25101	25101	26181	26181	26181
2.2.3.7 एक्जिम बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.8 अन्य	10064	4416	10379	9159	7491	6643	6643
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	2300	724	15727	5105	6531	6522	6521
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.4.2 सरकारी खज़ाना बिल	–	–	–	–	–	–	–
2.2.5 निवेश	1042951	983670	1295851	1296212	1295768	1308793	1308808
2.2.6 अन्य आस्तियां	137993	119334	160851	163525	157182	158745	158570
2.2.6.1 सोना	127644	111665	153679	156417	149671	151125	150412

*: डेटा अनंतिम है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर	एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाज़ार स्थिरीकरण योजना	विक्रय	क्रय	दीर्घावधि रिपो परिचालन	लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन#	म्यूचुअल फंड के लिए विशेष चलनिधि सुविधा	एनबीफ्सी/ एचएफसीएस के लिए विशेष चलनिधि योजना **	निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9+10+ 11+12+13-2-4-7-8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
दिसं. 1, 2020	-	695417	-	-	21	–	-	-	-	-	-	-	-	-695396
दिसं. 2, 2020	-	702615	-	-	0	2200	-	-	-	-	-	-	-492	-700907
दिसं. 3, 2020	-	735303	-	-	8	–	-	-	-	-	-	-	-	-735295
दिसं. 4, 2020	-	694192	-	-	0	–	-	-	-	-	-	-	-	-694192
दिसं. 5, 2020	-	17282	-	-	1129	–	-	-	-	-	-	-	-	-16153
दिसं. 6, 2020	-	24	-	-	125	–	-	-	-	-	-	-	-	101
दिसं. 7, 2020	-	681403	-	-	96	–	-	-	-	-	-	-	-	-681307
दिसं. 8, 2020	-	677259	-	-	0	–	-	-	-	-	-	-	-	-677259
दिसं. 9, 2020	-	669171	-	-	2	–	-	-	-	-	-	-	-98	-669267
दिसं. 10, 2020	-	741423	-	-	35	–	-	-	-	-	-	-	-	-741388
दिसं. 11, 2020	-	735725	-	-	0	–	-	-	5	-	-	-	-	-735720
दिसं. 12, 2020	-	987	-	-	114	–	-	-	-	-	-	-	-	-873
दिसं. 13, 2020	-	299	-	-	37	–	-	-	-	-	-	-	-	-262
दिसं. 14, 2020	-	722898	-	-	10	-2001	-	-	-	-	-	-	-66	-724955
दिसं. 15, 2020	-	707651	-	-	26	–	-	-	-	-	-	-	-522	-708147
दिसं. 16, 2020	-	603875	-	-	32	–	-	-	-	-	-	-	-189	-604032
दिसं. 17, 2020	-	624914	-	-	21	2300	-	-	-	-	-	-	-550	-623143
दिसं. 18, 2020	-	570190	-	-	1	–	-	10000	10000	-	-	-	-	-570189
दिसं. 19, 2020	-	26816	-	-	124	–	-	-	-	-	-	-	-	-26692
दिसं. 20, 2020	-	1483	-	-	208	–	-	-	-	-	-	-	-	-1275
दिसं. 21, 2020	-	589587	-	-	0	–	-	-	-	-	-	-	-49	-589636
दिसं. 22, 2020	-	607671	-	-	0	–	-	-	-	-	-	-	-	-607671
दिसं. 23, 2020	-	616455	-	-	3	–	-	-	-	-	-	-	-373	-616825
दिसं. 24, 2020	-	620625	-	-	50	–	-	–	10000	-	-	-	-	-610575
दिसं. 25, 2020	-	7521	-	-	158	–	-	-	-	-	-	-	-	-7363
दिसं. 26, 2020	-	3194	-	-	39	–	-	-	-	-	-	-	-	-3155
दिसं. 27, 2020	-	3910	-	-	11	–	-	-	-	-	-	-	-	-3899
दिसं. 28, 2020	-	650376	-	-	7	–	-	-	-	-	-	-	-20	-650389
दिसं. 29, 2020	-	669600	-	-	244	–	-	-	-	-	-	-	-551	-669907
दिसं. 30, 2020	-	669284	-	-	11	473	-	-	-	-	-	-	-	-668800
दिसं. 31, 2020	-	737314	-	-	0	-40	-	10000	10000	-	-	-	-	-737354

नोटः # लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) और लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) शामिल है। ऋणात्मक(-) चिन्ह बैंकों द्वारा किए गए पुर्नभुगतान को दर्शाते हैं।

** 01 जुलाई 2020 के आरबीआई अधिसूचना संख्या 2020-21/01 के अनुसार

ऋणात्मक चिन्ह (-) विशेष चलनिधि योजना में आरबीआई के निवेश के लिए प्राप्त परिपक्वता आय को दर्शाते हैं।

और ऋणात्मक(-) चिन्ह बैंकों द्वारा किए गए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेन्ट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2019-20	2019	2020	
		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	45097	4360	10261	3991
1.1 क्रय (+)	72205	5374	14289	10014
1.2 विक्रय (-)	27108	1014	4028	6023
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	312005	30894	76326	29439
3 संचयी (मार्च के के अंत से) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	45097	29741	68388	72379
(करोड़ ₹)	312005	205303	509189	538628
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	-4939	-1875	28344	39792

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेन्ट में परिचालन

मद	2019-20	2019	2020	
		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	7713	1690	0	3985
1.2 विक्रय (-)	7713	1690	0	3985
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	-500	400	780	1962

सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	31 दिसंबर 2020 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	4625	2483	2142
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	3817	0	3817
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	39140	0	39140
4. 1 वर्ष से अधिक	4713	10020	-5307
कुल (1+2+3+4)	**52295**	**12503**	**39792**

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2019-20	2020						2021
		जन. 31	अग. 28	सितं. 25	अक्टू. 23	नवं. 20	दिसं. 18	जन. 29
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	1262	2340	300	50	6	266	1	0
2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुर्नवित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	10000	2800	4900	4900	4900	4900	4900	4900
3.2 बकाया	4782	1872	0	0	-	0	0	0
4 अन्य								
4.1 सीमा	-	-	65000	65000	65000	75000	82500	75000
4.2 बकाया	-	-	34166	37691	36488	33234	34760	32205
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	6044	4212	34466	37741	36494	33500	34761	32205

टिप्पणी: 1. अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा अर्थात एक्ज़िम बैंक को 22 मई 2020 से पुनः शुरू कर दिया।

2. अन्य के लिए पुनर्वित सुविधा, अर्थात भारिबैंक अधिनियम 1934 के नाबार्ड/ सिड़बी/एनएचबी यू /एस 17 (4 एच), 17 अप्रैल 2020 से।

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा भंडार की मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2019-20	2019	2020		
		दिसं. 20	नवं. 20	दिसं. 4	दिसं. 18
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	2349748	2180601	2673534	2677852	2681512
1.1 संचलन में नोट	2420964	2245888	2743952	2746809	2749859
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	25605	25435	25798	25875	25875
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	97563	91465	96958	95575	94965
2 जनता की जमाराशियां	1776200	1507935	1674841	1755511	1728417
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	1737692	1473956	1632938	1713632	1686628
2.2 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	33979	41904	41879	41788
3 एम$_1$ (1 + 2)	**4125948**	**3688536**	**4348375**	**4433363**	**4409929**
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	150963	141786	150963	150963	150963
5 एम$_2$ (3 + 4)	**4276911**	**3830322**	**4499338**	**4584326**	**4560892**
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	12674016	12374442	13589563	13719924	13645443
7 एम$_3$ (3 + 6)	**16799963**	**16062978**	**17937939**	**18153286**	**18055372**
8 कुल डाकघर जमाराशियां	433441	409246	433441	433441	433441
9 एम$_4$ (7 + 8)	**17233404**	**16472224**	**18371380**	**18586727**	**18488813**

सं. 7: मुद्रा भंडार ($एम_3$) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2019	2020		
		दिसं. 20	नवं. 20	दिसं. 4	दिसं. 18
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	**4960362**	**4919683**	**5691514**	**5824949**	**5637236**
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	992192	979921	1023947	1091996	980473
1.1.1 सरकार पर दावे	1047808	1002864	1293290	1295887	1290946
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1045314	1001608	1282559	1285311	1284643
1.1.1.2 राज्य सरकारें	2494	1256	10731	10576	6303
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियां	55616	22943	269343	203891	310473
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	55573	22901	269301	203849	310431
1.1.2.2 राज्य सरकारें	43	42	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	3968170	3939762	4667567	4732953	4656763
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	**11038644**	**10599642**	**11092385**	**11154689**	**11204826**
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	13166	6702	12173	10876	11205
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	11025478	10592940	11080212	11143813	11193621
2.2.1 वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	10370861	9947444	10434880	10497687	10547037
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	637776	625750	635516	636230	636368
2.2.3 वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	16842	19746	9815	9896	10216
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	**3801036**	**3431339**	**4546855**	**4552849**	**4565412**
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	3590402	3222839	4249125	4255119	4267681
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	3590636	3223060	4249368	4255362	4267926
3.1.2 विदेशी देयताएं	234	221	243	243	245
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	210634	208500	297731	297731	297731
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	**26348**	**26178**	**26541**	**26618**	**26618**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	**3026427**	**2913863**	**3419355**	**3405819**	**3378721**
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1378342	1123096	1464944	1467815	1478577
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1648085	1790767	1954411	1938004	1900144
$एम_3$ (1+2+3+4-5)	**16799963**	**16062978**	**17937939**	**18153286**	**18055372**

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2019	2020		
		दिसं. 20	नवं. 20	दिसं. 4	दिसं. 18
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	4125948	3688536	4348375	4433363	4409929
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	9745776	9178476	10389164	10532985	10476478
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	16923893	16207404	18036372	18240715	18142693
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	2349748	2180601	2673534	2677852	2681512
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	14226198	13673824	15056913	15268348	15167848
1.2.1 मांग जमाराशियां	1737692	1473956	1632938	1713632	1686628
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	12488506	12199867	13423975	13554716	13481220
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5619828	5489940	6040789	6099622	6066549
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	169419	156633	66156	67848	67260
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	6868678	6709927	7383186	7455094	7414671
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	33979	41904	41879	41788
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	309439	319001	264021	252637	251545
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	16857025	16399881	17737777	17932777	17794787
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4960362	4919683	5691514	5824949	5637236
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	992192	979921	1023947	1091996	980473
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	3968170	3939762	4667567	4732953	4656763
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11896663	11480199	12046263	12107828	12157551
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	13166	6702	35419	36709	37338
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11883497	11473497	12010844	12071119	12120213
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	846284	871958	919780	916991	917177
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26348	26178	26541	26618	26618
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3612303	3207853	4366249	4430736	4461072
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	3222839	4249125	4255119	4267681
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	21900	-14986	117124	175618	193391
2.4 पूंजी खाता	2670439	2465133	2900745	2896087	2872234
2.5 अन्य मदें (निवल)	901344	961375	1193449	1253329	1267551

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2019-20	2019	2020		
		दिसं.	अक्टू.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
1 एन एम$_3$	**16923893**	**16207404**	**17894503**	**18036372**	**18142693**
2 डाकघर जमाराशियां	433441	409246	433441	433441	433441
3 एल$_1$ (1 + 2)	**17357334**	**16616650**	**18327944**	**18469813**	**18576134**
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	57479	54287	35341	34778	34795
4.1 सावधि मुद्रा उधार	7928	3078	3114	2645	2645
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	46249	46887	28700	28600	28865
4.3 सावधि जमाराशियां	3302	4322	3528	3533	3285
5 एल$_2$ (3 + 4)	**17414812**	**16670937**	**18363285**	**18504591**	**18610929**
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	31905	31905	..	..	31905
7 एल$_3$ (5 + 6)	**17446717**	**16702842**	..	..	**18642834**

टिप्पणी: 1. नवंबर 2019 के बाद से, वित्तीय संस्थानों की देनदारियों पर अद्यतन डेटा इस सारणी में शामिल किया गया है, और इसलिए, पिछले डेटा के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती हैं।

2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कालम के आंकड़े कुल में नहीं जुड़ सकते।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2019	2020		
		दिसं. 20	नवं. 20	दिसं. 4	दिसं. 18
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	2447312	2272066	2770493	2773427	2776477
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां	543888	603702	504678	510556	522176
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	505131	562488	471488	476750	488262
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	33979	41904	41879	41788
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	3029707	2909747	3317074	3325862	3340442
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	791299	783826	506353	511940	524719
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	992192	979921	1023947	1091996	980473
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	989741	978707	1013258	1081462	974212
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	–	–	–	–	–
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	–	–	–	–	–
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1044468	1000832	1281765	1284536	1283889
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1044468	1000832	1281765	1284536	1283889
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	846	776	794	775	754
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	55573	22901	269301	203849	310431
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	2451	1214	10689	10534	6261
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-214059	-202797	-553013	-616765	-493092
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण और अग्रिम	-214059	-202797	-529767	-590932	-466959
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	13166	6702	35419	36709	37338
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	5920	1615	–	1	1
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	–	–	23246	25833	26133
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26348	26178	26541	26618	26618
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	3222839	4249125	4255119	4267681
2.3.1 सोना	230527	192925	267074	263660	272328
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3359893	3029931	3982068	3991476	3995371
2.4 पूंजी खाता	1165066	992085	1288399	1285203	1292910
2.5 अन्य मदें (निवल)	213276	131011	176545	182612	185667

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

Item	2019-20	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2019	2020				
		दिसं. 27	नवं. 27	दिसं. 4	दिसं. 11	दिसं. 18	दिसं. 25
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	3029707	2884942	3313212	3325862	3307522	3340442	3314105
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	2447312	2270344	2770773	2773427	2785027	2776477	2778076
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां	543888	581929	497195	510556	480231	522176	493293
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	32669	45244	41879	42264	41788	42736
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	992192	989412	1036501	1091996	1113815	980473	1011641
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-214059	-245924	-545484	-590932	-632742	-466959	-524695
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	13166	6443	11175	10876	11153	11205	11205
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	3252164	4246261	4255119	4249129	4267681	4263000
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26348	26238	26618	26618	26618	26618	26618
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1378342	1143391	1461859	1467815	1460451	1478577	1473664

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार/ माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2019	2020		
		दिसं. 20	नवं. 20	दिसं. 4	दिसं. 18
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	13381983	12834306	14204846	14417880	14314737
1.1.1 मांग जमाराशियां	1617003	1354800	1511516	1592092	1564598
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	11764979	11479505	12693330	12825788	12750139
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5294241	5165777	5711999	5771605	5737562
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	169419	156633	66156	67848	67260
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	6470739	6313728	6981332	7054184	7012576
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	309439	319001	264021	252637	251545
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	14967529	14543529	15782139	15905302	15878534
2.1.1 सरकार को ऋण	3738696	3712898	4423853	4487564	4411845
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11228833	10830631	11358285	11417739	11466689
2.1.2.1 बैंक ऋण	10370861	9947444	10434880	10497687	10547037
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	10319097	9862301	10345924	10401774	10453884
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	11997	8862	11115	10579	9678
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	8653	11330	1472	1445	1759
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	837321	862996	910818	908028	908214
2.2 वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	21900	-14986	117124	175618	193391
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	315641	278216	348921	401376	418715
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	185510	174575	165588	165208	164224
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	108231	118628	66208	60551	61101
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	899410	846401	1087871	1153125	1040155
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	536186	562488	471488	476750	488262
2.3.2 उपलब्ध नकदी	87260	81116	86616	85443	84934
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	-275964	-202797	-529767	-590932	-466959
2.4 पूंजी खाता	1481202	1448878	1588175	1586713	1555153
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	716216	772759	930091	976815	990645
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	495445	441325	570401	541866	553551
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	66273	45986	62737	65878	69435

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 27, 2020 की स्थिति	2019	2020		
		दिसं. 20	नवं. 20	दिसं. 4	दिसं. 18
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	3747349	3724228	4425325	4489009	4413605
2 वाणिज्यिक पत्र	104526	94864	86031	79386	75341
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	14106	11593	11380	11296	11241
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	75415	66237	71284	71278	70834
3.3 अन्य	5734	5515	5416	5419	5409
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	125710	125665	122662	122385	127646
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	226559	235604	304812	310703	313097
4.3 अन्य	191690	197796	144171	143303	142560
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	35610	45966	35089	33726	29618
5.2 वित्तीय संस्थाएं	97665	79261	130912	130531	132469

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /नियत शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक			
	2019-20	2019	2020		2019-20	2019	2020	
		दिसं.	नवं.	दिसं.		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6	7	8
सूचना देने वाले बेंकों की संख्या	219	219	209	208	142	142	133	132
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	**320240**	**272087**	**263597**	**269497**	**314513**	**267210**	**258506**	**264487**
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	239943	196871	208057	208106	234348	192175	203177	203319
1.2 बैंकों से उधार राशि	64001	62874	38428	44060	64001	62839	38428	44058
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	16295	12341	17112	17331	16163	12196	16901	17110
2 अन्य के प्रति देयताएं	**14905949**	**14354171**	**15790007**	**15790480**	**14480607**	**13939154**	**15360598**	**15357605**
2.1 कुल जमाराशियां	13975551	13474498	14910668	14904878	13567492	13076253	14497351	14488370
2.1.1 मांग	1653242	1424297	1607263	1601873	1617003	1390204	1571913	1565783
2.1.2 मीयादी	12322309	12050201	13303405	13303005	11950489	11686049	12925438	12922587
2.2 उधार	313908	331782	273826	256946	309439	327452	269599	252891
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	616491	547891	605513	628656	603676	535449	593647	616344
3 रिज़र्व बैंक से उधार	**285623**	**30427**	**77097**	**77318**	**285623**	**30427**	**77097**	**77318**
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अन्य	285623	30427	77097	77318	285623	30427	77097	77318
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	643038	646500	570650	557539	623446	628399	555320	542590
4.1 उपलब्ध नकदी	89671	89265	95569	86846	87260	86982	93420	84872
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	553367	557235	475081	470693	536186	541417	461900	457719
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	**323680**	**291147**	**265221**	**264541**	**260238**	**231299**	**205772**	**204254**
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	181460	178108	181343	180735	155401	151715	147544	147352
5.1.1 चालू खाते में	17204	18565	14432	17216	14457	16197	12122	15174
5.1.2 अन्य खातों में	164256	159543	166911	163519	140945	135518	135422	132178
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	43335	37935	28331	31389	20273	17203	7305	8512
5.3 बैंकों को अग्रिम	38266	34044	21766	21270	30531	28279	21321	20573
5.4 अन्य आस्तियां	60619	41060	33782	31146	54032	34102	29602	27817
6 निवेश	**3865544**	**3880225**	**4556799**	**4537328**	**3747349**	**3765269**	**4424629**	**4403341**
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	3850819	3859887	4548980	4528800	3738696	3751590	4423189	4401696
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	14724	20338	7819	8528	8653	13678	1441	1645
7 बैंक ऋण	**10705336**	**10287168**	**10807692**	**10929733**	**10370861**	**9967797**	**10473053**	**10590986**
7क खाद्यान्न ऋण	82172	112463	123083	126156	51763	85433	92681	95755
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	10480934	10072725	10636795	10756373	10149509	9756870	10304077	10419618
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	26214	25082	23595	22894	25658	24406	23324	22629
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	147209	132488	99543	101639	145683	130664	98638	100728
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	20866	24282	17346	18020	20458	23872	17093	17727
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	30114	32591	30414	30808	29554	31985	29922	30285

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 27, 2020	2019	2020		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		दिसं. 20	नवं. 20	दिसं. 18	2020-21	2020
	1	2	3	4	5	6
1 सकल बैंक ऋण	**9263134**	**8822209**	**9286902**	**9341368**	**0.8**	**5.9**
1.1 खाद्यान्न ऋण	**51590**	**84863**	**88662**	**92840**	**80.0**	**9.4**
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	**9211544**	**8737346**	**9198240**	**9248528**	**0.4**	**5.9**
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	**1157796**	**1139092**	**1230526**	**1245685**	**7.6**	**9.4**
1.2.2 उद्योग	**2905151**	**2794372**	**2753281**	**2760220**	**–5.0**	**-1.2**
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	381825	365398	364515	369963	–3.1	1.2
1.2.2.2 मझौले	105598	107166	124028	123550	17.0	15.3
1.2.2.3 बड़े	2417728	2321808	2264738	2266707	–6.2	-2.4
1.2.3 सेवाएं	**2594945**	**2370600**	**2569834**	**2579184**	**–0.6**	**8.8**
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	144466	140438	154752	154988	7.3	10.4
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	20051	18597	19120	19115	–4.7	2.8
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	45977	44745	51309	51234	11.4	14.5
1.2.3.4 नौवहन	6557	6548	5329	7341	12.0	12.1
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	177085	172553	128577	128465	–27.5	-25.6
1.2.3.6 व्यापार	552392	513987	575549	589454	6.7	14.7
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	263397	228558	275279	285895	8.5	25.1
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	288995	285429	300270	303559	5.0	6.4
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	229770	219585	233150	230859	0.5	5.1
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	807383	728561	788222	789981	–2.2	8.4
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	611264	525586	613826	607747	–0.6	15.6
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	**2553652**	**2433282**	**2644599**	**2663439**	**4.3**	**9.5**
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	9298	5450	6937	7092	–23.7	30.1
1.2.4.2 आवास	1338964	1289637	1383427	1393500	4.1	8.1
1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	79496	64441	64512	65332	–17.8	1.4
1.2.4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	5334	5072	4655	4867	–8.8	-4.0
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	108094	105905	114307	110350	2.1	4.2
1.2.4.6 शिक्षा	65745	66895	65180	64680	–1.6	-3.3
1.2.4.7 वाहन ऋण	220609	213601	228758	230232	4.4	7.8
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	726112	682281	776823	787386	8.4	15.4
1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**2897461**	**2787852**	**2934836**	**2953810**	**1.9**	**6.0**
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1146624	1133239	1214929	1220970	6.5	7.7
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	1149394	1061953	1122053	1131858	–1.5	6.6
1.2अ.2.1 विनिर्माण	381826	365398	364515	369963	–3.1	1.2
1.2अ.2.2 सेवाएं	767568	696555	757538	761895	–0.7	9.4
1.2अ.3 आवास	449945	456989	462488	467047	3.8	2.2
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	38237	35104	32644	32024	–16.2	-8.8
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	51906	53215	51506	50576	–2.6	-5.0
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	388	395	588	605	55.9	53.2
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	731409	711799	766575	753038	3.0	5.8
1.2अ.8 निर्यात ऋण	16114	15152	12916	13748	–14.7	-9.3

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 27, 2020	2019	2020		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		दिसं. 20	नवं. 20	दिसं. 18	2020-21	2020
	1	2	3	4	5	6
1 उद्योग	**2905151**	**2794372**	**2753281**	**2760220**	**–5.0**	**–1.2**
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	**43927**	**42741**	**43831**	**44943**	**2.3**	**5.2**
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	**154146**	**145578**	**147775**	**155884**	**1.1**	**7.1**
1.2.1 चीनी	27382	24541	20291	19802	–27.7	–19.3
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	19240	20071	18354	19210	–0.2	–4.3
1.2.3 चाय	5375	5458	5809	5828	8.4	6.8
1.2.4 अन्य	102149	95508	103321	111044	8.7	16.3
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	**16522**	**15034**	**14454**	**14425**	**–12.7**	**–4.1**
1.4 वस्त्र	**192424**	**189152**	**186774**	**190989**	**–0.7**	**1.0**
1.4.1 सूती वस्त्र	89283	85688	84853	87749	–1.7	2.4
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	2116	2215	2429	2529	19.5	14.2
1.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	26074	26170	27251	27991	7.4	7.0
1.4.4 अन्य वस्त्र	74951	75079	72241	72720	–3.0	–3.1
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	**11098**	**10949**	**11404**	**11285**	**1.7**	**3.1**
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	**12233**	**12067**	**12795**	**12953**	**5.9**	**7.3**
1.7 काग़ज़ और काग़ज़ से बने उत्पाद	**30965**	**30697**	**33986**	**34364**	**11.0**	**11.9**
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	**75834**	**53536**	**60025**	**57646**	**–24.0**	**7.7**
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	**202949**	**177427**	**177799**	**175733**	**–13.4**	**–1.0**
1.9.1 उवर्रक	49066	34375	37894	38224	–22.1	11.2
1.9.2 औषधि और दवाइयां	53427	49839	48875	48791	–8.7	–2.1
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	42233	39154	39564	36151	–14.4	–7.7
1.9.4 अन्य	58223	54059	51466	52567	–9.7	–2.8
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	**50415**	**49164**	**49523**	**49924**	**–1.0**	**1.5**
1.11 कांच और कांच के सामान	**8777**	**8784**	**8785**	**9014**	**2.7**	**2.6**
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	**58689**	**58502**	**57993**	**57002**	**–2.9**	**–2.6**
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	**350325**	**337587**	**334078**	**329620**	**–5.9**	**–2.4**
1.13.1 लोहा और स्टील	262396	254848	245072	242421	–7.6	–4.9
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	87929	82739	89006	87199	–0.8	5.4
1.14 सभी अभियांत्रिकी	**157259**	**158648**	**137233**	**142764**	**–9.2**	**–10.0**
1.14.1 इलेक्ट्रानिक्स	30159	33145	27488	31260	3.7	–5.7
1.14.2 अन्य	127100	125503	109745	111504	–12.3	–11.2
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	**82606**	**82840**	**86153**	**84886**	**2.8**	**2.5**
1.16 रत्न और आभूषण	**59515**	**60452**	**60910**	**62988**	**5.8**	**4.2**
1.17 निर्माण	**104288**	**102579**	**101379**	**102896**	**–1.3**	**0.3**
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	**1053913**	**1029417**	**1007085**	**1003014**	**–4.8**	**–2.6**
1.18.1 पावर	559774	562025	551731	553388	–1.1	–1.5
1.18.2 दूरसंचार	143760	134310	103550	98574	–31.4	–26.6
1.18.3 सड़क	190676	186870	201550	202504	6.2	8.4
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	159703	146212	150254	148548	–7.0	1.6
1.19 अन्य उद्योग	**239266**	**229218**	**221299**	**219890**	**–8.1**	**–4.1**

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2019-20	2019	2020						
		नवं. 29	सितं. 25	अक्टू. 09	अक्टू. 23	अक्टू. 30	नवं. 06	नवं. 20	नवं. 27
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	32	31	31	31	31	31	31	31
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	**124101.8**	**66868.2**	**126143.1**	**126795.8**	**127166.1**	**127348.2**	**126623.2**	**126400.7**	**124182.3**
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	**26213.8**	**18928.5**	**22274.4**	**23152.3**	**20866.1**	**22714.0**	**22228.4**	**21539.4**	**22657.4**
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	5295.0	5355.2	4189.6	4308.6	3860.0	4028.2	4299.3	4178.6	3926.9
2.1.1.2 अन्य	14,523.6	10421.3	13472.0	13419.2	13039.0	13517.3	12827.8	13208.0	13223.4
2.1.2 बैंकों से उधार	100.0	0.0	229.9	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	6295.2	3152.0	4382.9	5354.5	3967.1	5168.5	5101.3	4152.8	5507.1
2.2 मीयादी देयताएं	**167684.5**	**114341.6**	**172128.5**	**172383.8**	**174055.4**	**172354.2**	**171935.1**	**171251.9**	**170392.8**
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	56564.0	56951.2	56835.6	57391.0	57259.1	56969.6	56563.3	55366.5	57870.7
2.2.1.2 अन्य	109578.2	56447.0	112671.1	113376.6	114127.1	113830.9	113795.4	113192.7	110958.9
2.2.2 बैंकों से उधार	630.2	0.0	673.0	656.5	749.9	629.9	629.9	635.6	629.9
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	912.1	943.4	1948.9	959.6	1919.2	923.8	946.4	2057.1	933.2
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	52772.2	46823.1	57927.2	58455.2	56285.3	55909.0	56918.9	57068.0	58359.7
4.1 मांग	13764.4	13300.6	14065.7	14318.1	13606.7	13041.1	13813.2	14207.1	14440.6
4.2 मीयादी	39007.8	33522.5	43861.5	44137.2	42678.5	42867.9	43105.7	42860.9	43919.1
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	**9428.2**	**6022.9**	**7000.4**	**6955.6**	**6734.9**	**7238.4**	**7031.6**	**6877.4**	**7131.8**
5.1 उपलब्ध नकदी	750.5	315.8	555.1	528.6	572.3	558.9	552.9	576.0	546.8
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	8677.8	5707.1	6445.3	6426.9	6162.6	6679.5	6478.6	6301.4	6585.0
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	**1521.7**	**798.7**	**988.1**	**795.4**	**824.5**	**935.7**	**837.1**	**822.1**	**897.3**
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	**50626.9**	**33158.4**	**59312.3**	**59137.6**	**59110.5**	**58774.4**	**60209.9**	**59731.1**	**60795.8**
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	**25283.9**	**20120.9**	**26346.6**	**25721.7**	**24240.2**	**24871.2**	**24593.9**	**23939.7**	**24676.4**
9 बैंक ऋण (10.1+11)	**110905.5**	**64244.0**	**111857.3**	**111842.7**	**110711.2**	**111109.5**	**110024.6**	**110526.4**	**110246.6**
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	**110901.5**	**64242.2**	**111841.4**	**111826.8**	**110695.3**	**111093.5**	**110008.6**	**110510.4**	**110230.7**
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	81300.1	80806.6	79397.4	81562.1	82624.9	82258.8	83798.2	84174.2	84270.3
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	4.0	1.8	15.9	15.9	15.9	16.0	16.0	16.0	16.0

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2019-20			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	दिसं. '19	नवं.'20	दिसं.'20(अ)	दिसं.'19	नवं.'20	दिसं.'20(अ)	दिसं.'19	नवं.'20	दिसं.'20(अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	**146.3**	**149.6**	**147.5**	**154.3**	**164.5**	**159.6**	**156.3**	**167.0**	**163.4**	**155.0**	**165.4**	**161.0**
1.1 अनाज और उत्पाद	140.7	143.2	141.4	142.8	144.6	143.4	144.9	149.0	148.0	143.5	146.0	144.9
1.2 मांस और मछली	163.3	161.4	162.6	165.3	188.5	187.5	164.5	195.7	194.9	165.0	191.0	190.1
1.3 अंडा	142.1	145.7	143.5	149.5	173.4	173.4	153.7	178.3	178.5	151.1	175.3	175.4
1.4 दूध और उत्पाद	146.5	146.0	146.3	148.7	154.0	154.0	147.5	154.2	154.5	148.3	154.1	154.2
1.5 तेल और चर्बी	127.1	121.8	125.1	127.5	150.0	154.8	122.7	140.7	144.1	125.7	146.6	150.9
1.6 फल	144.0	148.8	146.2	144.3	145.9	147.0	147.2	149.7	152.6	145.7	147.7	149.6
1.7 सब्जी	163.5	187.8	171.7	209.5	225.2	188.0	231.5	240.9	206.9	217.0	230.5	194.4
1.8 दाल और उत्पाद	133.7	132.0	133.1	138.8	159.5	159.5	137.2	161.5	162.2	138.3	160.2	160.4
1.9 चीनी और उत्पाद	112.0	113.4	112.5	113.6	114.4	113.8	114.7	117.1	116.3	114.0	115.3	114.6
1.10मसाले	145.6	145.1	145.5	149.1	163.5	164.4	148.0	161.9	163.1	148.7	163.0	164.0
1.11गैर नशीले पेय पदार्थ	138.8	130.2	135.2	139.3	153.4	156.1	130.8	143.3	146.0	135.8	149.2	151.9
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	157.6	156.7	157.2	158.3	163.6	164.3	157.7	166.1	167.2	158.0	164.8	165.6
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	**166.3**	**169.0**	**167.0**	**167.8**	**183.6**	**184.6**	**170.4**	**190.2**	**192.1**	**168.5**	**185.4**	**186.6**
3 कपड़ा और जूते	**151.3**	**143.7**	**148.3**	**151.9**	**156.3**	**156.8**	**144.6**	**149.6**	**150.2**	**149.0**	**153.6**	**154.2**
3.1 कपड़ा	152.0	145.7	149.5	152.6	157.0	157.5	146.8	151.9	152.5	150.3	155.0	155.5
3.2 जूते	146.9	132.4	140.9	147.3	151.6	152.4	132.8	136.7	137.3	141.3	145.4	146.1
4 आवास	--	**152.2**	**152.2**	--	--	--	**152.8**	**158.4**	**157.7**	**152.8**	**158.4**	**157.7**
5 ईंधन और लाइट	**148.6**	**131.5**	**142.2**	**149.9**	**148.7**	**151.1**	**133.6**	**137.9**	**142.8**	**143.7**	**144.6**	**148.0**
6 विविध	**145.6**	**135.9**	**140.9**	**147.1**	**155.2**	**155.9**	**137.7**	**146.9**	**147.6**	**142.5**	**151.2**	**151.9**
6.1 घरेलू सामान और सेवा	150.6	138.7	145.0	151.2	153.4	153.9	139.8	145.5	145.8	145.8	149.7	150.1
6.2 स्वास्थ्य	153.6	142.1	149.3	154.8	161.6	162.5	143.2	152.9	154.2	150.4	158.3	159.4
6.3 परिवहन और संचार	132.6	122.2	127.1	135.0	146.4	147.5	125.2	135.5	136.9	129.8	140.7	141.9
6.4 मनोरंजन	148.3	135.9	141.3	149.5	153.9	155.2	136.8	144.3	145.5	142.3	148.5	149.7
6.5 शिक्षा	159.8	150.9	154.5	161.1	162.9	163.6	151.9	156.9	156.4	155.7	159.4	159.4
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	139.2	138.4	138.9	140.6	156.6	156.2	140.2	157.9	157.7	140.4	157.1	156.8
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**147.3**	**145.1**	**146.3**	**152.3**	**160.7**	**158.5**	**148.3**	**156.9**	**156.0**	**150.4**	**158.9**	**157.3**

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।
अ: अनंतिम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2019-20	2019	2020	
				दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	--	–	119.9	118.8
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	980	1014	1060	1047
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	–	986	1019	1065	1053

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2019-20	2019	2020	
		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	37018	38092	50429	49444
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	42514	44576	62256	64757

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2019	2020		
			दिसं.	अक्टू.	नवं. (अ)	दिसं. (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	**100.000**	**121.8**	**123.0**	**123.6**	**124.2**	**124.5**
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	**22.618**	**143.3**	**148.9**	**151.8**	**151.2**	**146.5**
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	**15.256**	**155.8**	**162.6**	**171.5**	**169.0**	**160.8**
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	159.6	163.5	158.1	158.8	157.5
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	174.7	195.6	223.9	213.2	179.2
1.1.1.3 दूध	4.440	146.7	148.5	154.6	154.7	154.3
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	147.0	149.2	151.7	149.6	151.3
1.1.1.5 मसाले	0.529	143.9	154.1	152.9	156.5	153.4
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	144.0	143.5	167.5	166.9	164.4
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	**4.119**	**128.7**	**134.0**	**129.8**	**137.7**	**138.2**
1.1.2.1 फाइबर	0.839	128.2	123.7	114.5	119.8	123.5
1.1.2.2 तिलहन	1.115	151.4	152.9	158.0	162.0	164.4
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	104.8	105.4	109.8	113.9	114.3
1.1.2.4 फूल	0.204	238.0	348.3	231.7	308.3	285.0
1.1.3 खनिज	**0.833**	**154.5**	**147.6**	**153.3**	**145.5**	**153.3**
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	147.4	137.5	146.8	136.8	146.8
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	179.0	182.6	176.1	176.1	176.1
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	**2.410**	**85.3**	**88.2**	**63.8**	**64.0**	**67.5**
1.2 ईंधन और बिजली	**13.152**	**102.2**	**103.2**	**90.9**	**91.3**	**94.2**
1.2.1 कोल	**2.138**	**125.3**	**126.5**	**126.4**	**126.5**	**127.0**
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	138.1	141.9	141.7	141.9	141.9
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.0	119.0	119.0	119.0	119.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	129.1	131.1	131.1	131.1	131.1
1.2.2 खनिज तेल	**7.950**	**92.3**	**91.3**	**75.8**	**76.5**	**81.1**
1.2.3 बिजली	**3.064**	**111.8**	**117.9**	**105.3**	**105.3**	**105.3**
1.3 विनिर्मित उत्पाद	**64.231**	**118.3**	**118.0**	**120.4**	**121.3**	**123.0**
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	**9.122**	**133.9**	**137.0**	**140.5**	**142.1**	**143.7**
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	137.5	135.8	137.2	136.9	137.7
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस,मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	136.1	136.6	135.1	136.0	135.4
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	114.3	115.0	120.4	122.4	121.8
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	119.3	126.4	140.6	147.1	153.9
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	145.0	149.5	144.7	144.6	146.1
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	146.3	147.5	142.8	142.0	141.5
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	135.5	133.7	107.8	110.9	117.2
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	133.5	134.6	138.1	138.6	139.2
1.3.1.9 चीनी,गुड़ और शहद	1.163	118.3	119.3	118.6	118.6	118.6
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	127.2	128.0	127.8	129.8	126.0
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	132.7	123.4	131.3	131.6	128.8
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	139.7	138.5	183.2	174.8	163.7
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	132.4	135.7	145.8	146.6	149.1
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	128.7	129.1	130.0	130.4	133.7
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	159.9	159.7	140.6	140.4	137.9
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	173.6	175.7	169.9	171.0	171.5
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	**0.909**	**123.6**	**123.7**	**123.7**	**124.2**	**123.2**
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	117.8	118.6	120.1	120.2	119.4
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	125.7	125.8	124.4	126.0	124.3
1.3.2.3 शीतल पेय,मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	130.5	129.5	128.5	128.5	128.1
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	**0.514**	**153.4**	**151.0**	**157.6**	**156.1**	**156.9**
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	153.4	151.0	157.6	156.1	156.9

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(जारी)*

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2019	2020		
			दिसं.	अक्टू.	नवं. (अ)	दिसं. (अ)
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	**4.881**	**117.7**	**116.0**	**114.8**	**116.4**	**118.3**
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	107.9	105.1	102.5	105.1	107.7
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	130.1	129.3	130.1	130.3	132.1
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	114.5	114.8	113.7	114.7	114.2
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	134.5	135.5	131.4	132.3	132.8
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	143.1	145.8	156.8	157.2	159.5
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	116.8	116.0	115.2	114.7	114.7
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	**0.814**	**138.3**	**139.2**	**138.3**	**139.6**	**139.0**
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	139.2	140.2	137.1	138.4	137.9
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉस्चिटेड वस्त्र	0.221	135.9	136.7	141.4	142.7	142.0
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	**0.535**	**118.6**	**118.4**	**117.7**	**118.8**	**118.5**
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	105.5	104.6	102.0	103.0	100.4
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	136.3	135.9	137.9	138.3	139.0
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	120.3	120.4	119.9	121.2	121.7
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	**0.772**	**133.7**	**133.0**	**133.7**	**134.9**	**134.7**
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	122.2	120.5	120.3	119.9	121.1
1.3.7.2 विनियर शीट,प्लायवुड का विनिर्माण,लॅमिन बोर्ड,पार्टिकल बोर्डऔर अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	135.5	135.7	135.0	136.6	136.3
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	176.2	177.8	189.6	189.5	188.5
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	125.7	121.2	125.5	127.5	126.2
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	**1.113**	**121.1**	**118.9**	**119.4**	**119.6**	**120.7**
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	125.0	122.7	120.9	121.5	122.5
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	115.0	112.1	121.3	122.8	123.0
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	121.2	120.0	114.9	113.2	115.5
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	**0.676**	**150.6**	**151.2**	**155.9**	**153.5**	**158.4**
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	150.6	151.2	155.9	153.5	158.4
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	**6.465**	**117.5**	**116.2**	**116.8**	**117.7**	**119.3**
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	119.9	116.8	115.8	116.6	118.7
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	123.1	123.9	123.1	122.9	123.6
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिथेंटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	112.4	109.0	115.1	118.5	121.6
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	122.6	121.8	125.6	125.7	125.8
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	114.7	113.9	113.0	112.9	115.9
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट,सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	118.6	118.7	120.8	120.8	121.4
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	114.2	113.6	113.2	114.7	114.6
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	97.9	96.1	89.3	91.6	95.7
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	**1.993**	**127.3**	**127.8**	**130.5**	**131.2**	**131.1**
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	127.3	127.8	130.5	131.2	131.1
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	**2.299**	**108.5**	**108.2**	**110.0**	**110.8**	**113.2**
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब,रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.9	98.3	97.8	96.7	98.0
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	93.5	93.9	91.6	93.2	93.4
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	115.4	115.2	118.8	120.2	123.6
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	**3.202**	**116.7**	**115.5**	**116.5**	**117.1**	**117.3**
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	124.5	125.1	127.8	126.4	127.6
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	108.7	106.9	109.0	110.3	109.7
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	102.8	103.7	105.7	113.3	110.8
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	113.9	113.3	108.0	108.0	109.7
1.3.13.5 सीमेन्ट,चूना और प्लास्टर	1.645	119.5	118.0	119.4	119.5	120.1

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(जारी)*

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2019	2020		
			दिसं.	अक्टू.	नवं. (अ)	दिसं. (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट,सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	121.6	122.2	124.7	125.6	127.2
1.3.13.7 पत्थरों को काटना,आकार देना और संवारना	0.234	120.2	119.1	120.1	121.5	121.1
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	86.6	80.6	77.6	81.3	75.2
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	**9.646**	**106.2**	**103.6**	**108.9**	**110.8**	**115.5**
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	100.6	96.6	105.3	107.9	116.0
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	107.7	102.8	111.2	113.2	120.8
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	95.1	93.7	96.0	99.4	103.0
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	105.5	102.4	108.0	109.6	117.3
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	108.7	103.4	115.6	117.5	123.9
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	102.8	99.5	102.7	104.9	114.4
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	102.9	98.5	106.1	106.0	107.7
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	126.2	126.5	123.4	128.9	130.7
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	107.0	105.8	111.5	113.5	116.9
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	112.8	113.4	108.9	108.9	108.9
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	146.5	149.7	143.4	145.4	146.5
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	**3.155**	**115.5**	**115.2**	**114.6**	**115.8**	**118.0**
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	113.9	112.8	112.3	113.1	114.9
1.3.15.2 धातु से बने टैंक,जलाशय और डिब्बे	0.660	124.4	124.9	125.4	126.9	132.7
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर	0.145	104.7	106.3	98.6	98.7	97.2
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	100.5	99.8	96.2	99.4	100.6
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	100.5	100.5	102.6	102.9	104.7
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	124.0	123.7	124.2	125.4	125.9
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	**2.009**	**110.4**	**109.9**	**108.9**	**108.2**	**109.2**
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	98.1	97.8	98.9	99.2	100.3
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	135.0	135.0	135.2	134.0	134.4
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	117.0	118.9	114.2	114.4	114.6
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स	0.641	98.8	96.7	96.5	94.7	95.8
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	111.5	111.1	106.1	106.1	109.6
1.3.16.6 हाथ घडी और दीवार घडी	0.076	139.1	139.7	141.7	141.7	141.7
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	103.6	101.4	102.5	102.5	102.5
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	110.2	110.9	95.7	95.7	95.2
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	**2.930**	**111.3**	**110.8**	**112.6**	**113.4**	**115.0**
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	109.0	108.2	111.6	112.8	115.0
1.3.17.2 बैटरी और एक्युम्युलेटर	0.236	117.0	116.0	119.3	118.9	117.9
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	109.9	109.2	97.2	98.0	99.4
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रानिक और बिज़ली के वायर और केबल	0.428	109.7	109.8	114.5	115.6	119.3
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	111.1	110.3	110.7	110.8	109.5
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	119.9	120.4	118.6	118.9	119.8
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	108.6	108.5	109.0	110.3	111.6
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	**4.789**	**113.1**	**113.0**	**114.2**	**113.7**	**114.5**
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन,एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	104.8	105.5	105.7	105.5	107.0
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	119.9	120.1	120.4	120.3	120.6
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	111.2	111.2	111.0	111.2	111.7
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	110.1	109.7	113.3	110.5	113.5
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	80.0	80.6	81.4	81.7	83.6
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने –उतारने वाले उपकरण	0.285	111.5	111.9	114.0	112.4	113.8

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(समाप्त)*

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2019	2020		
			दिसं.	अक्टू.	नवं. (अ)	दिसं. (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	130.9	129.0	130.6	128.2	127.2
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	120.6	121.1	121.2	121.6	121.9
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	108.1	109.0	108.1	108.1	107.7
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.1	74.8	75.3	75.3	75.9
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	125.2	125.6	128.4	128.4	131.9
1.3.18.13 कपड़ा,परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	119.7	117.2	121.6	123.3	123.4
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	126.3	126.2	129.5	128.3	129.1
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	66.0	65.4	65.4	64.4	65.9
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	**4.969**	**114.5**	**115.3**	**117.6**	**117.8**	**118.4**
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	115.2	115.0	119.6	119.9	120.5
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	113.7	115.6	115.4	115.5	116.1
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	**1.648**	**118.0**	**118.4**	**126.7**	**127.5**	**127.6**
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली –वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.8	158.8	158.8
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टाक	0.110	106.4	106.6	104.7	104.7	104.6
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	114.3	114.7	125.6	126.5	126.5
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाडी	0.117	128.9	130.5	128.6	128.7	129.5
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	126.1	127.0	127.7	127.7	128.1
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	**0.727**	**130.9**	**130.3**	**132.5**	**132.9**	**134.0**
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	130.9	130.3	132.5	132.9	134.0
1.3.22 अन्य विनिर्माण	**1.064**	**112.7**	**114.4**	**135.9**	**136.1**	**135.9**
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	109.9	111.6	134.3	134.5	134.3
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	174.0	172.7	166.4	170.2	164.3
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	129.7	131.4	131.9	130.8	131.9
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	136.9	138.2	140.7	142.8	143.0
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	162.1	162.5	168.1	168.1	168.1
2 खाद्य सूचकांक	**24.378**	**147.6**	**153.0**	**159.9**	**158.9**	**154.4**

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)

उद्योग	भारांक	2018-19	2019-20	अप्रैल-नवंबर		नवंबर	
				2019-20	2020-21	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	130.1	129.0	128.1	108.3	128.8	126.3
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	107.9	109.6	101.9	89.2	112.7	104.5
1.2 विनिर्माण	77.63	131.5	129.6	129.5	107.1	130.6	128.4
1.3 बिजली	7.99	156.9	158.4	161.8	154.4	139.9	144.8
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	126.1	127.0	124.4	110.3	124.5	121.3
2.2 पूंजीगत माल	8.22	108.4	93.3	94.2	64.9	91.1	84.6
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	126.2	137.7	135.8	112.5	140.9	136.7
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	141.7	136.6	135.4	111.5	134.5	135.5
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	130.4	119.0	123.2	88.6	116.7	115.9
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	145.5	145.3	144.0	136.2	150.2	149.1

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-दिसंबर			
	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (वास्तविक)	2019-20 (वास्तविक)	बजट अनुमानों का प्रतिशत	
				2020-21	2019-20
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	**1555153**	**1088580**	**1146897**	**70.0**	**62.0**
1.1 कर राजस्व (निवल)	1344501	962399	904944	71.6	60.1
1.2 करेतर राजस्व	210652	126181	241953	59.9	70.0
2 पूंजीगत प्राप्तियां	**46497**	**33098**	**31025**	**71.2**	**38.0**
2.1 ऋण की वसूली	14497	14202	12925	98.0	77.8
2.2 अन्य प्राप्तियां	32000	18896	18100	59.1	27.8
3 कुल प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	**1601650**	**1121678**	**1177922**	**70.0**	**61.0**
4 राजस्व व्यय	3011142	1971173	1854125	65.5	78.9
4.1 ब्याज भुगतान	692900	472171	424314	68.1	67.9
5 पूंजी व्यय	439163	308974	255522	70.4	73.2
6 कुल व्यय (4+5)	**3450305**	**2280147**	**2109647**	**66.1**	**78.2**
7 राजस्व घाटा (4-1)	**1455989**	**882593**	**707228**	**60.6**	**141.6**
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	**1848655**	**1158469**	**931725**	**62.7**	**121.5**
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	**1155755**	**686298**	**507411**	**59.4**	**358.0**

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय बजट 2020-21

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2019-20	2019	2020					
		दिसं. 27	नवं. 20	नवं. 27	दिसं. 4	दिसं. 11	दिसं. 18	दिसं. 25
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	10165	15629	2357	2001	1880	1802	2464	2158
1.2 प्राथमिक व्यापारी	9190	13566	11215	12584	16619	15492	16791	13914
1.3 राज्य सरकारें	8173	55446	70680	71680	77175	81155	85090	90891
1.4 अन्य	48004	105392	125634	121644	114736	112981	108705	109744
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	66419	69389	140282	126536	120915	116464	109976	107133
2.2 प्राथमिक व्यापारी	43302	26616	39002	38808	40106	37358	35041	34064
2.3 राज्य सरकारें	13386	6945	4233	4233	4238	4248	4273	4273
2.4 अन्य	22465	19404	93761	94013	85323	79194	74474	65892
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	49660	58261	138677	140904	143582	145947	146971	148927
3.2 प्राथमिक व्यापारी	70672	58889	120149	120831	124369	122587	120465	120863
3.3 राज्य सरकारें	11945	21790	15627	16367	12367	12377	12417	16217
3.4 अन्य	70576	55247	132045	131253	126130	127249	129964	128915
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	155112	140863	119046	159713	116075	101257	130411	144840
4.4 अन्य	617	372	198	233	352	834	351	478
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	423957	506574	893661	880853	867438	856852	846630	842989

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2020-21										
दिसं. 2	9000	67	43425	11841	26	8999	11841	20840	99.25	3.0473
दिसं. 9	9000	138	56310	7545	31	8996	7545	16540	99.23	3.1092
दिसं. 16	9000	104	51631	12856	20	8994	12856	21850	99.23	3.1275
दिसं. 23	9000	111	52600	18234	27	8997	18234	27231	99.23	3.1092
दिसं. 30	9000	76	35481	5	29	8995	5	9000	99.24	3.0790
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2020-21										
दिसं. 2	3000	54	14144	8	16	2992	8	3000	98.37	3.3229
दिसं. 9	3000	82	18007	3	31	2997	3	3000	98.36	3.3532
दिसं. 16	3000	105	20951	4	30	2996	4	3000	98.36	3.3501
दिसं. 23	3000	80	16870	6	26	2994	6	3000	98.36	3.3501
दिसं. 30	3000	64	17482	794	17	2988	794	3781	98.36	3.3439
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2020-21										
दिसं. 2	4000	60	16170	0	3	4000	0	4000	96.73	3.3947
दिसं. 9	4000	61	15534	1	31	3999	1	4000	96.67	3.4498
दिसं. 16	4000	77	14350	2	19	3998	2	4000	96.68	3.4458
दिसं. 23	4000	77	13354	3800	36	4000	3800	7800	96.67	3.4574
दिसं. 30	4000	70	11325	0	31	4000	0	4000	96.67	3.4571

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार		दरों का दायरा	भारित औसत दरें
		उधार लेना/उधार देना	उधार लेना/उधार देना
		1	2
दिसंबर	1, 2020	1.90-3.40	3.08
दिसंबर	2, 2020	1.90-3.40	3.10
दिसंबर	3, 2020	1.90-3.40	3.09
दिसंबर	4, 2020	1.50-3.40	3.02
दिसंबर	5, 2020	2.50-3.45	2.92
दिसंबर	7, 2020	1.90-3.40	3.03
दिसंबर	8, 2020	1.90-3.50	3.09
दिसंबर	9, 2020	1.90-3.50	3.15
दिसंबर	10, 2020	1.90-3.50	3.17
दिसंबर	11, 2020	1.90-3.50	3.13
दिसंबर	14, 2020	1.90-3.50	3.15
दिसंबर	15, 2020	1.90-3.50	3.21
दिसंबर	16, 2020	1.90-3.45	3.20
दिसंबर	17, 2020	1.90-3.45	3.21
दिसंबर	18, 2020	1.90-3.45	3.20
दिसंबर	19, 2020	2.50-3.90	2.88
दिसंबर	21, 2020	1.90-3.50	3.23
दिसंबर	22, 2020	1.90-3.50	3.26
दिसंबर	23, 2020	1.90-3.50	3.25
दिसंबर	24, 2020	1.90-3.50	3.23
दिसंबर	28, 2020	1.90-3.50	3.20
दिसंबर	29, 2020	1.90-3.50	3.15
दिसंबर	30, 2020	1.90-3.50	3.25
दिसंबर	31, 2020	1.90-3.60	3.31
जनवरी	1, 2021	1.90-3.55	3.18
जनवरी	2, 2021	2.50-3.25	2.76
जनवरी	4, 2021	1.90-3.75	3.18
जनवरी	5, 2021	1.90-3.50	3.15
जनवरी	6, 2021	1.90-3.50	3.16
जनवरी	7, 2021	1.90-3.50	3.19
जनवरी	8, 2021	1.90-3.50	3.18
जनवरी	11, 2021	1.90-3.50	3.19
जनवरी	12, 2021	1.90-3.50	3.19
जनवरी	13, 2021	1.90-3.50	3.19
जनवरी	14, 2021	1.90-3.50	3.24
जनवरी	15, 2021	1.90-3.50	3.19

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2019	2020			
	दिसं. 20	नवं. 6	नवं. 20	दिसं. 4	दिसं. 18
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	160669.00	76335.00	67680.00	69440.00	68770.00
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	13837.13	1686.58	791.91	6298.55	8003.34
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	4.97-5.84	3.83-3.84	3.35-4.54	3.08-4.63	3.08-4.44

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2019	2020			
	दिसं. 31	नवं. 15	नवं. 30	दिसं. 15	दिसं. 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	414906.30	389427.10	373146.10	390613.25	365185.05
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	83567.75	57001.85	64386.20	102307.55	87488.25
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	4.99-13.18	3.09-11.32	2.79-8.80	2.65-12.61	3.06-12.73

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	2019-20	2019	2020					
		दिसं. 27	नवं. 20	नवं. 27	दिसं. 4	दिसं. 11	दिसं. 18	दिसं. 25
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	26815	27553	10765	12157	8164	13477	17573	16769
2 नोटिस मुद्रा	3660	238	4103	632	4170	648	4625	354
3 मीयादी मुद्रा	790	939	755	687	462	218	627	618
4 सीबीएलओ / त्रिपक्षीय रिपो	300691	339731	515057	411117	521592	406200	529871	426080
5 बाजार रिपो	221719	230092	380750	273258	388895	314587	366239	295246
6 कार्पोरेट बांड में रिपो	2468	1528	8110	1208	1150	304	2468	1055
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	66546	57482	57492	85488	51369	53172	58809
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	93960	70654	54335	70609	67565	68202	54656	43125
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	5800	5891	5400	4965	4981	3845	3888	4522
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	3720	6094	758	1555	4702	5260	4342	3635
10.2 182-दिवसीय	2380	1577	8518	7120	3138	5799	5776	4478
10.3 364-दिवसीय	2900	1019	11587	4704	2743	2549	2505	1894
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	2310							
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	111070	85234	80598	88953	83128	85656	71166	57652
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	–	4670	5196	4325	265	902	4459	2578

टिप्पणी : मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) खंड को समाप्त किया गया तथा उसके स्थान पर 5 नवंबर 2018 से त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2019-20		2019-20 (अप्रै.-दिसं.)		2020-21 (अप्रै.-दिसं.)*		दिसं. 2019		दिसं. 2020*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	**72**	**64926**	**56**	**61035**	**47**	**89441**	**4**	**1264**	**4**	**1652**
1ए प्रीमियम	70	43259	55	39411	47	85708	4	1033	4	1487
1.1 पब्लिक	57	9867	45	9780	31	28527	4	1264	3	1353
1.1.1 प्रीमियम	55	9434	44	9373	31	25576	4	1033	3	1199
1.2 राइट्स	15	55059	11	51255	16	60914	–	–	1	299
1.2.1 प्रीमियम	15	33825	11	30038	16	60132	–	–	1	288
2 अधिमान शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3 बांड और डिबेंचर	**34**	**14984**	**27**	**11746**	**10**	**3871**	**3**	**2519**	–	–
3.1 परिवर्तनीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अपरिवर्तनीय	34	14984	27	11746	10	3871	3	2519	–	–
3.1.1 पब्लिक	34	14984	27	11746	10	3871	3	2519	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4 कुल (1+2+3)	**106**	**79910**	**83**	**72781**	**57**	**93312**	**7**	**3783**	**4**	**1652**
4.1 पब्लिक	91	24851	72	21526	41	32398	7	3783	3	1353
4.2 राइट्स	15	55059	11	51255	16	60914	–	–	1	299

टिप्पणी: अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम है।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2019-20	2019	2020				
			दिसं.	अग.	सितं.	अक्टू.	नवं.	दिसं.
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड ₹	2219332	192984	170329	202583	183535	174559	199771
	मिलियन अमरीकी डॉलर	313288	27107	22810	27569	24985	23519	27145
1.1 तेल	करोड ₹	292252	25854	14292	26511	12117	11412	17278
	मिलियन अमरीकी डॉलर	41276	3632	1914	3608	1650	1538	2348
1.2 तेल से इतर	करोड ₹	1927080	167130	156037	176072	171417	163148	182493
	मिलियन अमरीकी डॉलर	272011	23476	20896	23961	23335	21982	24797
2 आयात	करोड ₹	3360954	281881	231601	224168	247051	247857	313408
	मिलियन अमरीकी डॉलर	474709	39594	29474	30307	33632	33395	42586
2.1 तेल	करोड ₹	925168	76311	48104	42808	44081	46525	70516
	मिलियन अमरीकी डॉलर	130550	10719	6441	5826	6001	6269	9582
2.2 तेल से इतर	करोड ₹	2435787	205570	183497	181361	202970	201332	242891
	मिलियन अमरीकी डॉलर	344159	28875	23033	24481	27631	27126	33004
3 व्यापार शेष	करोड ₹	-1141623	-88896	-61272	-21585	-63517	-73298	-113637
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-161422	-12487	-6664	-2738	-8647	-9876	-15441
3.1 तेल	करोड ₹	-632916	-50456	-33812	-16297	-31964	-35113	-53238
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-89274	-7087	-4526	-2218	-4351	-4731	-7234
3.2 तेल से इतर	करोड ₹	-508707	-38440	-27460	-5288	-31553	-38184	-60399
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-72148	-5399	-2137	-520	-4295	-5145	-8207

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2020			2021			
		जन. 24	दिसं. 18	दिसं. 25	जन. 1	जन. 8	जन. 15	जन. 22
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	**करोड ₹**	**3328631**	**4274948**	**4272332**	**4276976**	**4293062**	**4269145**	**4271528**
	मिलियन अमरीकी डॉलर	**466693**	**581131**	**580841**	**585324**	**586082**	**584242**	**585334**
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड ₹	3087772	3955679	3953337	3957808	3968594	3956894	3956665
	मिलियन अमरीकी डॉलर	432919	537727	537474	541642	541791	541507	542192
1.2 स्वर्ण	करोड ₹	204812	272327	270026	270554	275376	263499	266058
	मिलियन अमरीकी डॉलर	28715	37020	36711	37026	37594	36060	36459
	मात्रा (मैट्रिक टन)	634.97	676.65	676.65	676.65	676.65	676.65	676.65
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1046	1049	1049	1049	1049	1049	1049
	करोड ₹	10290	11142	11108	11035	11100	11046	11038
	मिलियन अमरीकी डॉलर	1443	1515	1510	1510	1515	1512	1513
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड ₹	25757	35800	37862	37578	37992	37706	37767
	मिलियन अमरीकी डॉलर	3615	4870	5145	5145	5181	5163	5171

अंतर, यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से है।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2019-20	2019	2020		2019-20	2020-21
		दिसं.	नवं.	दिसं.	अप्रै.-दिसं.	अप्रै.-दिसं.
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	**130581**	**133138**	**139264**	**140419**	**5862**	**7826**
1.1 एफसीएनआर (बी)	24244	24018	21925	22104	848	-2140
1.2 एनआर (ई) आरए	90367	92889	100070	100856	3562	8767
1.3 एनआरओ	15969	16230	17268	17459	1452	1199

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2019-20	2019-20	2020-21	2019	2020	
		अप्रै.-दिसं.	अप्रै.-दिसं.	दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	**43013**	**31050**	**40522**	**4326**	**5650**	**6526**
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1. 1.1.2)	**56006**	**40821**	**48445**	**5512**	**6840**	**7337**
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	**74390**	**55135**	**67542**	**7464**	**10105**	**9221**
1.1.1.1.1 इक्विटी	51734	37811	52894	4778	8635	7741
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	3265	3028	320	45	48	55
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	39364	28460	45638	3646	7355	7039
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	7348	5281	5512	967	1112	527
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	1757	1042	1423	120	120	120
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	14175	10403	11403	1197	1197	1197
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	8482	6922	3246	1489	273	284
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	**18384**	**14315**	**19097**	**1952**	**3265**	**1884**
1.1.1.2.1 इक्विटी	18212	14150	19068	1916	3263	1882
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	173	165	28	36	2	3
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	**12993**	**9771**	**7924**	**1186**	**1190**	**811**
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	7572	5464	4421	600	641	594
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3151	2363	2403	263	263	263
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5674	3730	3673	532	407	468
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	3403	1787	2574	209	122	514
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	**1403**	**15148**	**28413**	**-611**	**9427**	**8403**
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	–	–	–	–	–	–
1.2.2 एफआईआई	552	15295	30192	-510	9763	8598
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	–	–	–	–	–	–
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	-851	147	1779	101	336	195
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	**44417**	**46198**	**68934**	**3715**	**15077**	**14929**

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2019-20	2019	2020		
		दिसं.	अक्टू.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	**18760.69**	**1563.72**	**938.37**	**942.44**	**1149.17**
1.1 जमाराशियां	623.37	42.38	23.34	23.32	35.33
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	86.43	4.85	3.85	3.53	5.05
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	431.41	27.57	22.80	25.39	38.76
1.4 उपहार	1907.71	150.90	108.89	110.55	145.15
1.5 दान	22.33	0.89	1.29	0.65	0.67
1.6 यात्रा	6955.98	620.32	272.98	253.26	322.25
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	3439.74	276.74	162.64	160.81	217.30
1.8 चिकित्सा उपचार	33.90	2.68	3.66	2.92	2.82
1.9 विदेश में शिक्षा	4991.07	420.45	333.45	355.77	373.32
1.10 अन्य	268.75	16.93	5.47	6.24	8.54

सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)

मद	2018-19	2019-20	2020		2021
			जनवरी	दिसंबर	जनवरी
	1	2	3	4	5
40-मुद्रा समूह (आधार: 2015-16=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	97.45	98.00	96.91	92.96	93.81
1.2 रीर	100.63	103.20	104.09	103.31	104.26
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	97.13	97.38	96.35	92.80	93.37
2.2 रीर	100.29	102.88	104.00	103.13	103.75
6-मुद्रा समूह (व्यापार -भारित)					
1 आधार : 2015-16=100					
1.1 नीर	94.19	94.92	94.02	87.13	87.34
1.2 रीर	100.29	103.60	104.86	101.56	101.81
2 आधार : 2018-19 =100					
2.1 नीर	100.00	100.78	99.82	92.50	92.73
2.2 रीर	100.00	103.30	104.56	101.27	101.52

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण

(राशि अमरीकी मिलियन डॉलर में)

मद	2019-20	2019	2020	
		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1292	109	87	95
1.2 राशि	38011	1257	2045	2994
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	41	4	-	-
2.2 राशि	14921	840	-	-
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1333	113	87	95
3.2 राशि	52932	2097	2045	2994
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	6.00	4.70	5.48	4.59
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारित औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.34	1.41	1.87	1.65
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-25.00	0.00-25.00	0.00-10.30	0.00-13.00

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	जुला.-सितं. 2019			जुला.-सितं. 2020 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**303790**	**298671**	**5118**	**304250**	**272682**	**31568**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**161553**	**169132**	**-7579**	**150955**	**135448**	**15507**
1.1 पण्य	**79952**	**119602**	**-39650**	**75591**	**90375**	**-14784**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**81601**	**49530**	**32070**	**75364**	**45072**	**30292**
1.2.1 सेवाएं	52777	31836	20941	49902	28733	21169
1.2.1.1 यात्रा	7643	6031	1611	2020	2737	-717
1.2.1.2 परिवहन	5181	6009	-828	5410	4759	651
1.2.1.3 बीमा	602	354	248	590	537	53
1.2.1.4 जीएनआईई	169	298	-128	144	190	-46
1.2.1.5 विविध	39182	19144	20038	41738	20510	21228
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	23247	2182	21064	25069	2769	22299
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	10878	11211	-333	11624	12379	-755
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1239	594	645	1003	1107	-104
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	635	354	281	661	355	306
1.2.2 अंतरण	21986	2034	19952	20421	2023	18398
1.2.2.1 आधिकारिक	50	286	-236	36	258	-221
1.2.2.2 निजी	21936	1748	20188	20385	1766	18619
1.2.3 आय	6838	15660	-8822	5041	14316	-9275
1.2.3.1 निवेश आय	5434	14997	-9563	3596	13615	-10020
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1404	663	741	1445	700	745
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**142237**	**128657**	**13580**	**152658**	**137234**	**15424**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**85751**	**75960**	**9791**	**97269**	**65689**	**31581**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	15650	8336	7314	30475	5892	24583
2.1.1.1 भारत में	14875	4482	10393	29501	2450	27051
2.1.1.1.1 इक्विटी	10113	4446	5668	23989	2445	21544
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3464		3464	4024	0	4024
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1298	37	1262	1488	5	1483
2.1.1.2 विदेश में	775	3854	-3079	974	3442	-2468
2.1.1.2.1 इक्विटी	775	1703	-928	974	1391	-417
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	788	-788	0	808	-808
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1363	-1363	0	1243	-1243
2.1.2 संविभाग निवेश	70101	67625	2476	66794	59796	6998
2.1.2.1 भारत में	68312	66307	2005	66420	58684	7736
2.1.2.1.1 एफआईआई	68312	66307	2005	66420	58684	7736
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	48252	51608	-3355	55007	48183	6824
2.1.2.1.1.2 ऋण	20059	14699	5361	11413	10501	912
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	1789	1318	471	375	1113	-738
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**21544**	**18472**	**3072**	**20225**	**24468**	**-4243**
2.2.1 बाह्य सहायता	1802	1366	435	3201	1330	1870
2.2.1.1 भारत द्वारा	2	29	-27	2	28	-26
2.2.1.2 भारत को	1800	1338	462	3199	1302	1897
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	9011	5728	3283	8362	12659	-4297
2.2.2.1 भारत द्वारा	1287	1082	205	769	1005	-235
2.2.2.2 भारत को	7724	4646	3078	7593	11654	-4061
2.2.3 भारत को अल्पावधि	10731	11378	-646	8662	10479	-1817
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	10731	10940	-209	8662	9770	-1108
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	437	-437	0	709	-709
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**23881**	**25699**	**-1818**	**18850**	**30025**	**-11175**
2.3.1 वाणिज्य बैंक	23881	25364	-1483	18837	30025	-11188
2.3.1.1 आस्तियां	9914	10148	-235	7295	16747	-9451
2.3.1.2 देयताएं	13967	15216	-1249	11541	13279	-1737
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	13458	11178	2280	10311	8377	1934
2.3.2 अन्य	0	335	-335	13	0	13
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	2	-2	0	2	-2
2.5 अन्य पूंजी	11061	8523	2538	16314	17050	-737
3 भूल-चूक		**882**	**-882**	**637**	0	**637**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**5118**	**-5118**	0	**31568**	**-31568**
4.1 आईएमएफ				0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)		5118	-5118	0	31568	-31568

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	जुला.-सितं. 2019			जुला.-सितं. 2020 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**2139568**	**2103519**	**36049**	**2263084**	**2028270**	**234814**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**1137803**	**1191185**	**-53382**	**1122840**	**1007492**	**115348**
1.1 पण्य	**563094**	**842346**	**-279252**	**562264**	**672233**	**-109969**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**574709**	**348839**	**225870**	**560576**	**335259**	**225317**
1.2.1 सेवाएं	371704	224219	147485	371185	213726	157459
1.2.1.1 यात्रा	53826	42478	11348	15024	20359	-5335
1.2.1.2 परिवहन	36488	42320	-5833	40241	35397	4843
1.2.1.3 बीमा	4243	2494	1749	4385	3994	391
1.2.1.4 जीएनआईई	1193	2096	-904	1074	1414	-339
1.2.1.5 विविध	275955	134831	141124	310461	152561	157899
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	163725	15370	148355	186466	20598	165868
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	76611	78960	-2348	86464	92076	-5612
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	8729	4187	4543	7462	8233	-771
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	4475	2494	1981	4914	2638	2275
1.2.2 अंतरण	154844	14327	140517	151896	15051	136845
1.2.2.1 आधिकारिक	349	2014	-1665	269	1916	-1647
1.2.2.2 निजी	154495	12313	142182	151627	13134	138492
1.2.3 आय	48161	110294	-62133	37495	106483	-68988
1.2.3.1 निवेश आय	38270	105623	-67353	26745	101274	-74529
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	9891	4671	5220	10750	5209	5541
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**1001765**	**906125**	**95640**	**1135504**	**1020778**	**114725**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**603940**	**534984**	**68957**	**723512**	**488607**	**234905**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	110224	58709	51515	226681	43826	182855
2.1.1.1 भारत में	104766	31568	73198	219436	18223	201213
2.1.1.1.1 इक्विटी	71226	31310	39916	178436	18184	160252
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	24395	0	24395	29930		29930
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	9145	258	8886	11070	39	11032
2.1.1.2 विदेश में	5458	27141	-21682	7245	25603	-18358
2.1.1.2.1 इक्विटी	5458	11997	-6538	7245	10348	-3103
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5548	-5548	0	6009	-6009
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	9596	-9596	0	9247	-9247
2.1.2 संविभाग निवेश	493716	476275	17441	496831	444780	52050
2.1.2.1 भारत में	481114	466993	14122	494044	436504	57540
2.1.2.1.1 एफआईआई	481114	466993	14122	494044	436504	57540
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	339837	363469	-23632	409153	358396	50757
2.1.2.1.1.2 ऋण	141277	103523	37754	84891	78108	6783
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	12602	9283	3320	2786	8276	-5490
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**151732**	**130099**	**21633**	**150435**	**181998**	**-31563**
2.2.1 बाह्य सहायता	12689	9624	3065	23807	9895	13911
2.2.1.1 भारत द्वारा	14	201	-187	12	208	-197
2.2.1.2 भारत को	12675	9423	3252	23795	9687	14108
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	63463	40344	23119	62198	94158	-31960
2.2.2.1 भारत द्वारा	9066	7623	1444	5722	7473	-1751
2.2.2.2 भारत को	54397	32721	21675	56476	86685	-30209
2.2.3 भारत को अल्पावधि	75580	80132	-4551	64430	77945	-13515
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	75580	77050	-1470	64430	72671	-8241
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	3081	-3081	0	5273	-5273
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**168191**	**180998**	**-12807**	**140212**	**223336**	**-83124**
2.3.1 वाणिज्य बैंक	168191	178639	-10448	140113	223336	-83222
2.3.1.1 आस्तियां	69820	71474	-1654	54265	124564	-70299
2.3.1.2 देयताएं	98370	107165	-8794	85848	98771	-12923
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	94785	78728	16056	76699	62311	14387
2.3.2 अन्य	0	2359	-2359	99	0	99
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	15	-15	0	15	-15
2.5 अन्य पूंजी	77902	60029	17873	121345	126824	-5479
3 भूल-चूक	0	**6210**	**-6210**	**4740**		**4740**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**36049**	**-36049**	0	**234814**	**-234814**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	36049	-36049		234814	-234814

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	जुला.-सितं. 2019			जुला.-सितं. 2020 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	**161551**	**169104**	**-7553**	**150953**	**135423**	**15531**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**132729**	**151438**	**-18709**	**125493**	**119109**	**6385**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**79952**	**119602**	**-39650**	**75591**	**90375**	**-14784**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	79293	115248	-35955	75243	84287	-9044
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	658	0	658	348	0	348
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		4354	-4354	0	6088	-6088
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**52777**	**31836**	**20941**	**49902**	**28733**	**21169**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	58	33	25	68	11	56
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	44	253	-208	35	204	-169
1.अ.ख.3 परिवहन	5181	6009	-828	5410	4759	651
1.अ.ख.4 यात्रा	7643	6031	1611	2020	2737	-717
1.अ.ख.5 निर्माण	677	714	-37	589	563	26
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	602	354	248	590	537	53
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1239	594	645	1003	1107	-104
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	248	1776	-1528	313	1456	-1143
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	23947	2654	21293	25793	3290	22503
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	10878	11211	-333	11624	12379	-755
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	551	923	-372	530	817	-287
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	169	298	-128	144	190	-46
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	1539	984	555	1782	683	1099
1.आप्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**6838**	**15660**	**-8822**	**5041**	**14316**	**-9275**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1404	663	741	1445	700	745
1.आ.2 निवेश आय	4379	14782	-10403	2808	13314	-10507
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1763	7056	-5293	1327	8038	-6711
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	54	3760	-3706	49	2126	-2076
1.आ.2.3 अन्य निवेश	602	3951	-3349	78	3150	-3072
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	1960	15	1945	1354	1	1353
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	1055	215	840	788	301	487
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**21984**	**2006**	**19978**	**20419**	**1998**	**18421**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	21936	1748	20188	20385	1766	18619
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	21291	1336	19955	19711	1287	18424
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	645	412	233	674	479	195
1.इ.2 सामान्य सरकार	48	258	-210	35	232	-198
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**90**	**190**	**-100**	**109**	**197**	**-87**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	9	93	-84	8	100	-92
2.2 पूँजी अंतरण	81	97	-16	101	96	5
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**142149**	**133614**	**8535**	**152550**	**168631**	**-16081**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**15650**	**8336**	**7314**	**30475**	**5892**	**24583**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	14875	4482	10393	29501	2450	27051
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	13577	4446	9131	28013	2445	25568
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	10113	4446	5668	23989	2445	21544
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3464		3464	4024	0	4024
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1298	37	1262	1488	5	1483
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1298	37	1262	1488	5	1483
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	775	3854	-3079	974	3442	-2468
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	775	2491	-1716	974	2199	-1225
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	775	1703	-928	974	1391	-417
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		788	-788	0	808	-808
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1363	-1363	0	1243	-1243
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		1363	-1363	0	1243	-1243
3.2 संविभाग निवेश	**70101**	**67625**	**2476**	**66794**	**59796**	**6998**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	68312	66307	2005	66420	58684	7736
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	48252	51608	-3355	55007	48183	6824
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	20059	14699	5361	11413	10501	912
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	1789	1318	471	375	1113	-738
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**7395**	**7138**	**257**	**9664**	**12339**	**-2675**
3.4 अन्य निवेश	**49003**	**45398**	**3605**	**45617**	**59035**	**-13418**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	13458	11513	1945	10325	8377	1948
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	335	-335	13	0	13
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	13458	11178	2280	10311	8377	1934
3.4.2.3 सामान्य सरकार				0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र				0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	21235	21281	-45	20088	35637	-15549
3.4.3अ भारत को ऋण	19946	20170	-224	19317	34605	-15287
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	1289	1111	178	771	1033	-262
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	54	71	-17	78	62	16
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	10731	11378	-646	8662	10479	-1817
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	3524	1155	2369	6464	4480	1984
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार			0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	**5118**	**-5118**	0	**31568**	**-31568**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण				0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए				0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए				0	0	0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	5118	-5118	0	31568	-31568
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**142149**	**133614**	**8535**	**152550**	**168631**	**-16081**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	71843	67071	4772	94110	66340	27770
4.2 ऋण लिखत	66783	60270	6513	51976	66242	-14267
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	3524	6273	-2750	6464	36048	-29584
5. निवल भूल-चूक		**882**	**-882**	**637**	0	**637**

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(करोड़ ₹)

मद	जुला.-सितं. 2019			जुला.-सितं. 2020 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	**1137790**	**1190988**	**-53198**	**1122827**	**1007305**	**115522**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**934798**	**1066564**	**-131766**	**933449**	**885959**	**47490**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**563094**	**842346**	**-279252**	**562264**	**672233**	**-109969**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	558456	811684	-253228	559675	626945	-67270
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	4638	0	4638	2588	0	2588
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	30661	-30661		45287	-45287
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**371704**	**224219**	**147485**	**371185**	**213726**	**157459**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	408	235	173	505	85	420
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	310	1779	-1468	263	1519	-1256
1.अ.ख.3 परिवहन	36488	42320	-5833	40241	35397	4843
1.अ.ख.4 यात्रा	53826	42478	11348	15024	20359	-5335
1.अ.ख.5 निर्माण	4770	5031	-261	4383	4186	197
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4243	2494	1749	4385	3994	391
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	8729	4187	4543	7462	8233	-771
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	1749	12511	-10762	2330	10833	-8503
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	168656	18693	149963	191855	24472	167382
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	76611	78960	-2348	86464	92076	-5612
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	3882	6503	-2621	3944	6078	-2135
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1193	2096	-904	1074	1414	-339
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	10839	6933	3906	13255	5078	8178
1.आप्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**48161**	**110294**	**-62133**	**37495**	**106483**	**-68988**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	9891	4671	5220	10750	5209	5541
1.आ.2 निवेश आय	30842	104107	-73266	20884	99036	-78152
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	12418	49694	-37276	9869	59790	-49921
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	380	26481	-26100	366	15810	-15445
1.आ.2.3 अन्य निवेश	4241	27830	-23589	579	23428	-22848
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	13803	103	13700	10070	7	10063
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	7428	1515	5913	5861	2238	3623
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**154831**	**14130**	**140701**	**151883**	**14863**	**137020**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	154495	12313	142182	151627	13134	138492
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	149953	9410	140544	146616	9573	137043
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	4542	2903	1639	5011	3561	1450
1.इ.2 सामान्य सरकार	336	1817	-1481	257	1729	-1472
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**632**	**1337**	**-705**	**813**	**1463**	**-649**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	63	656	-593	62	747	-685
2.2 पूँजी अंतरण	569	680	-112	751	716	36
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**1001146**	**941034**	**60112**	**1134703**	**1254317**	**-119614**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**110224**	**58709**	**51515**	**226681**	**43826**	**182855**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	104766	31568	73198	219436	18223	201213
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	95621	31310	64312	208366	18184	190182
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	71226	31310	39916	178436	18184	160252
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	24395	0	24395	29930		29930
3.1.अ.2 ऋण लिखत	9145	258	8886	11070	39	11032
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	9145	258	8886	11070	39	11032
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	5458	27141	-21682	7245	25603	-18358
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	5458	17544	-12086	7245	16356	-9111
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	5458	11997	-6538	7245	10348	-3103
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	5548	-5548		6009	-6009
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	9596	-9596	0	9247	-9247
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	9596	-9596		9247	-9247
3.2 संविभाग निवेश	**493716**	**476275**	**17441**	**496831**	**444780**	**52050**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	481114	466993	14122	494044	436504	57540
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	339837	363469	-23632	409153	358396	50757
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	141277	103523	37754	84891	78108	6783
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	12602	9283	3320	2786	8276	-5490
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**52083**	**50270**	**1813**	**71882**	**91780**	**-19898**
3.4 अन्य निवेश	**345123**	**319731**	**25392**	**339309**	**439117**	**-99808**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	94785	81087	13697	76798	62311	14486
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	2359	-2359	99	0	99
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	94785	78728	16056	76699	62311	14387
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0			
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0			
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	149558	149878	-320	149419	265077	-115658
3.4.3अ भारत को ऋण	140478	142055	-1577	143686	257396	-113711
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	9080	7823	1257	5734	7681	-1947
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	383	501	-117	580	462	117
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	75580	80132	-4551	64430	77945	-13515
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	24817	8134	16683	48082	33321	14761
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0			0
3.5 आरक्षित आस्तियां	**0**	**36049**	**-36049**	**0**	**234814**	**-234814**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0			
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0			
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0			
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	36049	-36049	0	234814	-234814
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**1001146**	**941034**	**60112**	**1134703**	**1254317**	**-119614**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	505985	472376	33609	700013	493455	206557
4.2 ऋण लिखत	470345	424475	45870	386609	492727	-106118
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	24817	44183	-19366	48082	268134	-220052
5. निवल भूल-चूक	**0**	**6210**	**-6210**	**4740**	**0**	**4740**

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2019-20		2019		2020			
			सितं.		जून		सितं.	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	182957	418243	176244	417145	185898	419426	188366	455989
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	118442	395426	114834	398819	120322	395835	121546	430881
1.2 अन्य पूंजी	64515	22817	61410	18327	65577	23591	66820	25108
2 संविभाग निवेश	3847	246701	4541	260195	4303	241581	5041	253289
2.1 इक्विटी	602	134778	2344	144039	830	138961	1906	149095
2.2 ऋण	3246	111923	2197	116155	3474	102621	3136	104195
3 अन्य निवेश	52422	427272	54980	428886	53694	432321	64921	432817
3.1 व्यापार ऋण	1460	104276	1633	106581	1271	104001	2917	102193
3.2 ऋण	6741	179601	7892	174823	7435	184391	9048	180264
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	26011	130761	27563	133105	27741	132942	34864	137519
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	18210	12634	17892	14378	17247	10987	18092	12841
4 रिज़र्व्स	477807		433707		505702		544687	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	717033	1092216	669472	1106226	749597	1093328	803016	1142095
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-375183		-436754		-343730		-339079

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वित्त वर्ष 2019-20	2019	2020		वित्त वर्ष 2019-20	2019	2020	
		दिसं.	नवं.	दिसं.		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)	–	2.83	2.45	2.62	–	12196681	10692192	15757032
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	–	1.04	0.79	1.00	–	8085475	6942678	10816866
1.1.1 आउटराईट	–	0.61	0.48	0.51	–	853262	727023	772886
1.1.2 रेपो	–	0.21	0.12	0.25	–	2950776	1762647	4089804
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	–	0.21	0.19	0.24	–	4281437	4453008	5954176
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	–	1.75	1.64	1.58	–	3831685	3625849	4651382
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	–	0.04	0.02	0.04	–	279520	123665	288785
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)	–	–	–	–	–	–	–	–
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	–	136.02	137.80	163.48	–	10316937	7987655	10659120
1.1 ग्राहक लेनदेन	–	133.82	136.13	161.72	–	8847761	6802206	9058136
1.2 इंटरबैंक लेनदेन	–	2.20	1.67	1.75	–	1469176	1185449	1600984
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.7)	–	20029.81	30269.97	31735.80	–	2440749	2986234	3393355
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	–	0.84	0.93	1.03	–	35	54	61
2.2 एपीबीएस $	–	1369.14	927.29	1018.90	–	6000	4400	8180
2.3 आईएमपीएस	–	2564.67	3391.14	3556.93	–	210934	276459	292325
2.4 एनएसीएच जमा $	–	674.26	1114.23	1741.20	–	79028	96069	118309
2.5 एनईएफटी	–	2336.88	2734.10	3076.15	–	1942231	2218252	2558304
2.6 यूपीआई @	–	13084.02	22102.28	22341.58	–	202521	390999	416176
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	–	0.80	0.91	0.88	–	14	15	14
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.4)	–	790.71	944.24	922.53	–	72455	78709	81871
3.1 भीम आधार पे @	–	7.37	9.39	8.90	–	112	181	187
3.2 एनएसीएच नामे $	–	769.31	869.63	840.43	–	72306	78433	81576
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	–	14.02	65.22	73.21	–	37	96	108
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	–	6615.52	5633.00	5729.81	–	149688	163940	166029
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	–	2036.64	1662.58	1737.79	–	65736	62350	63487
4.1.1 पीओएस आधारित $	–	1181.09	874.82	914.20	–	35157	30495	28961
4.1.2 अन्य $	–	855.55	787.76	823.59	–	30579	31855	34526
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	–	4578.88	3970.43	3992.02	–	83953	101591	102542
4.2.1 पीओएस आधारित $	–	2634.18	2112.56	2165.50	–	39740	42289	39437
4.2.2 अन्य $	–	1944.70	1857.87	1826.52	–	44213	59302	63105
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	–	5073.44	4193.78	4363.90	–	18922	16704	18201
5.1 वालेट	–	3652.64	3420.83	3550.29	–	15835	12717	13439
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	–	1420.80	772.96	813.60	–	3088	3987	4762
5.2.1 पीओएस आधारित $	–	121.90	39.38	42.79	–	1012	1111	1215
5.2.2 अन्य $	–	1298.91	733.57	770.81	–	2076	2877	3547
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	–	865.46	596.35	719.40	–	646583	494383	618015
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	–	864.44	596.35	719.40	–	645573	494383	618015
6.2 अन्य	–	1.02	0.00	0.00	–	1010	–	–
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	–	33374.94	41637.35	43471.44	–	3328398	3739970	4277471
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	–	33510.96	41775.15	43634.92	–	13645335	11727625	14936592
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	–	32645.50	41178.79	42915.52	–	12998751	11233243	14318576

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व. 2019-20	2019	2020		वि. व. 2019-20	2019	2020	
		दिसं.	नवं.	दिसं.		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	–	14322.15	24198.24	25199.49	–	493342	820024	899401
1.1 इंट्रा-बैंक $	–	1280.66	2191.98	2183.03	–	101679	165155	174603
1.2 इंटर-बैंक $	–	13041.49	22006.26	23016.46	–	391663	654869	724798
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	–	2736.82	2814.17	3137.64	–	3040781	3419474	4032311
2.1 इंट्रा-बैंक @	–	626.66	585.09	637.64	–	1438853	1653359	1934396
2.2 इंटर-बैंक @	–	2110.16	2229.09	2500.00	–	1601928	1766114	2097916
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	–	6518.97	5913.87	5709.96	–	293087	280560	269614
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना $	–	8.91	4.64	5.01	–	422	231	246
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	–	6481.81	5883.59	5680.44	–	291704	279417	268475
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	–	28.25	25.63	24.51	–	961	912	894
4 पीओएस पर नकद निकासी $ (4.1 से 4.2)	–	78.52	37.91	39.89	–	148	143	149
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	–	71.47	32.33	34.53	–	134	137	142
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	–	7.05	5.58	5.37	–	14	6	6
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	–	326.35	684.78	715.03	–	9163	18820	19671
5.1 एईपीएस @	–	326.35	684.78	715.03	–	9163	18820	19671

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	वि.व. 2019-20	2019	2020	
		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	–	8606.57	9528.15	9468.15
1.1 क्रेडिट कार्ड	–	553.33	601.13	603.97
1.2 डेबिट कार्ड	–	8053.24	8927.02	8864.18
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	–	17625.43	20443.15	20823.65
2.1 वालेट @	–	16615.68	18857.67	19159.52
2.2 कार्ड @	–	1009.75	1585.48	1664.13
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	–	2.32	2.34	2.33
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम $	–	2.10	2.09	2.08
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम $	–	0.22	0.25	0.25
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	–	2.42	3.57	3.56
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	–	49.88	54.19	57.41
6 भारत क्यूआर @	–	17.13	30.46	32.00
7 यूपीआई क्यूआर *	–	–	697.82	752.30

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।

* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड़ शामिल है।

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।

2. 31 जनवरी 2020 से ईसीस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिल दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक श्रृंखला

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2018-19	2019		2020	
			फर.	जन.	जन.	फर.
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	**प्राप्तियां**	**115714**	**9839**	**15814**	**15184**	**16911**
	बकाया	**918459**	**899191**	**1015010**	**1030037**	**1046766**
1.1 कुल जमाराशियां	**प्राप्तियां**	**91108**	**7130**	**12117**	**11091**	**11460**
	बकाया	**618418**	**606920**	**693812**	**704903**	**716363**
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	31037	2360	3455	3106	2690
	बकाया	140247	134863	150462	153568	156258
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	-31	-19	-31	-25	-20
	बकाया	3107	2877	2984	2959	2939
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	53	0	-827	-2	-3
	बकाया	10	-8	-18	-20	-23
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	10967	928	1753	1712	1887
	बकाया	192658	191653	203460	205172	207059
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	13990	1184	2070	2133	2131
	बकाया	55708	54446	69464	71597	73728
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	25000	2451	4296	3999	4494
	बकाया	124292	121687	152622	156621	161115
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	71534	70179	86344	88247	90327
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	5910	5824	6749	6854	6970
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	6901	6910	7328	7397	7464
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	39947	38774	52201	54123	56354
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	10081	215	1401	168	281
	बकाया	102401	101407	114842	115010	115291
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	11	11	0	0	0
	बकाया	-26	-26	-25	-25	-25
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	21	21	21	21	21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	**प्राप्तियां**	**16067**	**1732**	**3326**	**3524**	**3937**
	बकाया	**221517**	**219257**	**240900**	**244267**	**248022**
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	11318	1262	2272	2458	2619
	बकाया	98492	94795	110050	112508	115127
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	334	3	0	0	1
	बकाया	263	300	-289	-289	-288
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-18678	-1609	-971	-1713	-1120
	बकाया	19303	21232	6782	5069	3949
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	23018	2065	2025	2782	2452
	बकाया	93630	91314	113273	116055	118507
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	93	12	0	-1	0
	बकाया	2	-47	-179	-180	-180
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-18	-1	0	-2	-15
	बकाया	-80	-82	-82	-84	-99
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	9907	11745	11345	11188	11006
1.3 लोक भविष्य निधि	**प्राप्तियां**	**8539**	**977**	**371**	**569**	**1514**
	बकाया	**78524**	**73014**	**80298**	**80867**	**82381**

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।
टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियाँ हैं अर्थात सकल प्राप्तियाँ माइनस सकल भुगतान।

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2019		2020		
	सितं	दिसं	मार्च	जून	सितं
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	**6314426**	**6512659**	**6486585**	**6704983**	**7137069**
1. वाणिज्य बैंक	39.66	39.05	40.41	38.98	38.55
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.42	0.39	0.39	0.36	0.34
3. बीमाकृत कंपनियां	24.86	24.90	25.09	26.24	25.33
4. म्यूच्युअल फंड	0.77	1.53	1.43	2.02	2.42
5. सहकारी बैंक	2.01	1.97	1.90	1.86	1.86
6. वित्तीय संस्थाएं	1.15	1.14	0.53	1.19	1.42
7. कॉरपोरेट	0.92	0.84	0.81	0.78	0.94
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	3.31	3.33	2.44	1.79	2.05
9. भविष्य निधियां	4.87	4.93	4.72	4.96	4.77
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	14.99	14.72	15.13	14.70	15.00
11. अन्य	7.05	7.23	7.17	7.11	7.32
11.1 राज्य सरकार	1.99	1.97	2.05	1.99	1.86

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2019		2020		
	सितं	दिसं	मार्च	जून	सितं
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	**2905169**	**3047353**	**3265990**	**3393099**	**3564979**
1. वाणिज्य बैंक	32.53	32.46	34.99	33.54	34.60
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.72	0.64	0.76	0.74	0.54
3. बीमाकृत कंपनियां	33.39	32.50	31.63	30.85	30.26
4. म्यूच्युअल फंड	1.12	1.20	1.14	1.74	1.96
5. सहकारी बैंक	4.24	4.16	4.12	4.38	4.19
6. वित्तीय संस्थाएं	0.33	0.31	0.11	1.96	1.92
7. कॉरपोरेट	0.28	0.31	0.30	0.31	0.39
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.05	0.04	0.02	0.02	0.02
9. भविष्य निधियां	22.36	23.66	22.22	21.70	21.31
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	4.98	4.73	4.71	4.78	4.80
11.1 राज्य सरकार	0.16	0.17	0.18	0.18	0.18

खज़ाना बिल					
श्रेणी	2019		2020		
	सितं	दिसं	मार्च	जून	सितं
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	**538041**	**514588**	**538409**	**881362**	**982286**
1. वाणिज्य बैंक	50.81	45.19	61.06	46.11	53.50
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.92	2.07	2.26	1.48	2.16
3. बीमाकृत कंपनियां	5.55	5.76	7.45	4.64	4.06
4. म्यूच्युअल फंड	14.08	20.42	13.24	23.45	19.90
5. सहकारी बैंक	2.55	2.07	2.55	1.95	1.63
6. वित्तीय संस्थाएं	1.82	2.12	0.58	1.67	1.34
7. कॉरपोरेट	1.57	1.66	1.89	1.43	1.63
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. भविष्य निधियां	0.01	0.01	0.02	0.05	0.00
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	11.27	4.80
11. अन्य	21.70	20.70	10.95	7.95	10.99
11.1 राज्य सरकार	17.91	16.36	6.22	4.35	7.76

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (सं.अ.)	2020-21 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	**3760611**	**4265969**	**4515946**	**5040747**	**5875914**	**6470254**
1.1 गतिविधियां	2201287	2537905	2635110	2882758	3486519	3818358
1.1.1 राजस्व	1668250	1878417	2029044	2224367	2708218	2920507
1.1.2 पूंजी	412069	501213	519356	596774	694262	794599
1.1.3 ऋण	120968	158275	86710	61617	84038	103252
1.2 गैर गतिविधियां	1510810	1672646	1812455	2078276	2295105	2556504
1.2.1 राजस्व	1379727	1555239	1741432	1965907	2171963	2421566
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	648091	724448	814757	894520	969344	1091617
1.2.2 पूंजी	127306	115775	69370	111029	121159	132961
1.2.3 ऋण	3777	1632	1654	1340	1984	1977
1.3 अन्य	48514	55417	68381	79713	94290	95393
2. कुल प्राप्तियां	**3778049**	**4288432**	**4528422**	**5023352**	**5779396**	**6524526**
2.1 राजस्व प्राप्तियां	2748374	3132201	3376416	3797731	4338225	4828088
2.1.1 कर प्राप्तियां	2297101	2622145	2978134	3278947	3547958	3951657
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1440952	1652377	1853859	2030050	2157126	2436871
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	852271	965622	1121189	1246083	1386652	1510287
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	3878	4146	3086	2814	4180	4500
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	451272	510056	398282	518783	790267	876430
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	35779	33220	34224	36273	33272	30911
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	59827	69063	142433	140287	129507	232172
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	16561	20942	42213	44667	62499	18302
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	43266	48122	100219	95621	67008	213870
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	**952410**	**1064704**	**997097**	**1102729**	**1408183**	**1409995**
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	939662	1046708	989167	1097210	1403250	1405373
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	231090	617123	144792	387091	518093	-----
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	60472	195816	-144847	325987	190241	-----
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	708572	429585	844375	710119	885156	-----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	12748	17997	7931	5519	4933	4622
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	939662	1046708	989167	1097210	1403250	1405373
3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)	673298	689821	794856	795845	962386	1105573
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	80015	35038	71222	88961	213430	213430
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	35261	45688	42351	51004	42900	42529
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-3322	-6436	18423	-18298	-241	2978
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	13470	17792	25138	66289	32949	35987
3ख.1.6 नकद शेष	-17438	-22463	-12476	17395	96518	-54272
3ख.1.7 अन्य	158378	287268	49653	96014	55309	59147
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	12748	17997	7931	5519	4933	4622
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	*27.3*	*27.7*	*26.4*	*26.6*	*28.9*	*28.8*
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	*27.4*	*27.9*	*26.5*	*26.5*	*28.4*	*29.0*
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	*20.0*	*20.3*	*19.7*	*20.0*	*21.3*	*21.5*
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	*16.7*	*17.0*	*17.4*	*17.3*	*17.4*	*17.6*
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	*6.9*	*6.9*	*5.8*	*5.8*	*6.9*	*6.3*

...: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बज़ट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	दिसंबर 2020 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	999	30	1128	26	955	3
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	133	17	26	10	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	1078	29	183	9
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	131	8	33	1	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	2505	15	-	-	-	-
16	मणिपुर	50	28	201	27	79	7
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	4	5	28	5	-	-
19	नगालैंड	171	31	271	26	81	15
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	595	28	397	13	-	-
23	राजस्थान	1502	16	126	2	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	940	28	1379	20	1037	13
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	दिसंबर 2020 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खज़ाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	8471	833	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1577	2	--	-
3	असम	4625	55	--	-
4	बिहार	7131	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	4528	--	1	4550
6	गोवा	608	306	--	-
7	गुजरात	7419	494	--	-
8	हरियाणा	1426	1232	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	2300
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखंड	185	--	--	-
12	कर्नाटक	4324	--	--	33000
13	केरल	2198	--	--	-
14	मध्य प्रदेश	--	938	--	-
15	महाराष्ट्र	42090	436	--	35000
16	मणिपुर	387	103	--	-
17	मेघालय	681	37	9	-
18	मिज़ोरम	508	40	--	-
19	नगालैंड	1678	34	--	-
20	उड़ीसा	12815	1486	86	19045
21	पुदुचेरी	300	--	--	807
22	पंजाब	949	--	8	-
23	राजस्थान	--	--	129	2000
24	तमिलनाडु	6790	--	40	14762
25	तेलंगाना	5800	1257	--	-
26	त्रिपुरा	381	9	--	-
27	उत्तराखंड	3237	81	--	-
28	उत्तरप्रदेश	763	--	180	-
29	पश्चिम बंगाल	9015	544	214	-
	कुल	**127889**	**7888**	**666**	**111464**

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2018-19		2019-20		2020-21						2020-21 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
						अक्टूबर		नवंबर		दिसंबर			
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल	निवल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	30200	23824	42415	33444	6000	5417	2000	1417	5000	4708	44250	38710
2	अरुणाचल प्रदेश	719	693	1366	1287	-	-	53	53	-	-	481	481
3	असम	10595	8089	12906	10996	2000	2000	2500	2500	1100	1100	8900	8900
4	बिहार	14300	10903	25601	22601	4000	4000	4000	4000	-	-	20000	19000
5	छत्तीसगढ़	12900	12900	11680	10980	2000	1000	2000	2000	2000	2000	8000	7000
6	गोवा	2350	1850	2600	2000	200	-	300	300	354	354	2354	2054
7	गुजरात	36971	27437	38900	28600	3000	1000	5500	3500	1500	1500	29780	21823
8	हरियाणा	21265	17970	24677	20677	2000	1200	2000	2000	-	-	22500	19900
9	हिमाचल प्रदेश	4210	2108	6580	4460	1500	1500	1000	1000	1000	1000	4000	3200
10	जम्मू और कश्मीर	6684	4927	7869	6760	500	500	1605	1605	500	500	7310	5810
11	झारखंड	5509	4023	7500	5656	2600	2600	-	-	1000	1000	3600	3100
12	कर्नाटक	39600	32183	48500	42500	8000	6000	8000	5400	10000	7500	55000	47900
13	केरल	19500	13984	18073	12617	-	-	636	-364	3000	1500	19566	17066
14	मध्य प्रदेश	20496	15001	22371	16550	3000	3000	4000	4000	4000	2000	22000	20000
15	महाराष्ट्र	20869	3107	48498	32998	11000	8673	5500	350	-	-	65000	52800
16	मणिपुर	970	667	1757	1254	-	-	-	-	180	180	880	880
17	मेघालय	1122	863	1344	1070	250	250	-	-100	365	325	1415	1225
18	मिज़ोरम	0	-123	900	745	-	-	232	232	100	100	774	674
19	नगालैंड	822	355	1000	423	250	150	314	314	220	220	1284	1084
20	उड़ीसा	5500	4500	7500	6500	-	-	-	-1000	-	-	3000	2000
21	पुदुचेरी	825	475	970	470	125	125	200	-	100	100	650	450
22	पंजाब	22115	17053	27355	18470	2785	535	3321	1871	3307	1507	21523	13323
23	राजस्थान	33178	20186	39092	24686	3000	1730	3761	3261	5000	5000	39211	32129
24	सिक्किम	1088	795	809	481	-	-	312	312	-	-	927	927
25	तमिलनाडु	43125	32278	62425	49826	6000	4125	4000	3375	5000	3175	63000	52744
26	तेलंगाना	26740	22183	37109	30697	3000	2583	3573	3156	7000	6792	36534	32574
27	त्रिपुरा	1543	1387	2928	2578	300	300	413	413	600	600	1713	1613
28	उत्तराखंड	46000	33307	69703	52744	8000	5524	4000	4000	8000	6922	33500	19713
29	उत्तरप्रदेश	6300	5289	5100	4500	1200	1200	-	-	-	-	3700	3000
30	पश्चिम बंगाल	42828	30431	56992	40882	3500	2500	4000	3500	5500	5500	35000	25500
	कुल	478323	348643	634521	487454	74210	55912	63219	47094	64826	53583	555852	455579

- : शून्य

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

http://nsdp.rbi.org.in के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्वर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्ज़िम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकडे सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

एनएम$_2$ और एनएम$_3$ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामि ल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थांओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल$_1$ और एल$_2$ मासिक आधार पर और एल$_3$ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंति म उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकडें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकडें अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकडें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामि ल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि. 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी.केका.प्लान. बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अतंरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी सस्थांओं/शाखाओं के बीच के ऋण सबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ो से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का सकेंतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है ।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं ।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -
   - बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल है।
   - जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए है, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया हैं।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है ।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है ।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं ।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है । तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है ।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है ।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 29 मई 2020 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2020-21 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बज़ट 2020-21 से लिया गया है।
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।
1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुन:चुकौती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकौती से संबंधित है।
1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।
2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।
3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।
3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।
3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।
यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।
3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।
3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों (364-दिन के खज़ाना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपार्श्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।
राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।
प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।
-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।
नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारो में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामि ल हैं।
--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (**https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618**) में उपलब्ध हैं।

'वर्तमान सांख्यिकी' का टाइम सीरिज डाटा https://dbie.rbi.org.in पर उपलब्ध है।
विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2021	₹300 एक प्रति (कांउटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष रियायती दर*) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित@) ₹2,520 (एक वर्ष रियायती दर@)	15 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंडबुक 2019-20	₹650 (सामान्य) ₹700 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक 2019-20	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2020-21 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (कांउटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकांउट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (कांउटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (कांउटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (कांउटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयनः दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (कांउटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड. 39,2018	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 1 और 2,2019	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 41, सं. 1, 2020	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर्स; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (कांउटर पर)	50 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (http://dbie.rbi.org.in)।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।

* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

@ इलेक्ट्रानिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते है, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेशः

1. बिकी हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमि क और शैक्षिक सस्थांओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अकं उपलब्ध नहीं है।
4. प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण (सोमवार से शुक्रवार) तक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंज़िल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मंबुई - 400 001 में किया जाएगा। बिक्री अनुभाग का सपंर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेलः spsdepr@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रेषणपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंज़िल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मंबुई - 400 001।

   एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैंक
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रातिशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. **कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdepr@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।**